



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2017/आश्विन 7, 1939

No. 377]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2017/ASVINA 7, 1939

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2017

सं. 1सीए(5)/68/2017— चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् के 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

68वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् को 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 68वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। 1 जुलाई, 1949 को संसद् के एक अधिनियम द्वारा संस्थान के प्रारंभ से लेखांकन वृत्ति का अत्यधिक विकास हुआ है। संस्थान, जिसे केवल 1700 सदस्यों के साथ स्थापित किया गया था, आज की तारीख में उसके सदस्यों की संख्या 2,70,000 तथा 1 जुलाई, 2017 को छात्रों की संख्या 8,05,000 से अधिक हो गई है। यह रिपोर्ट, परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2016-2017 के दौरान की महत्वपूर्ण गतिविधियों और साथ ही संस्थान के 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं की विशिष्टियों को उपदर्शित करती है। परिषद् इस अवसर पर इस रिपोर्ट में, इस अवधि के और जुलाई, 2017 की प्रारंभिक अवधि तक के दौरान, सदस्यों और छात्रों के संबंध में की गई प्रमुख पहलों, महत्वपूर्ण घटनाओं, सांख्यिकीय आंकड़े, आयोजित की गई संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के व्यौरों को भी समाविष्ट करती है। परिषद्, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की वृत्ति के समाज में विद्यमान वर्तमान सम्मान के लिए सदस्यों और छात्रों की सराहना करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति सदस्यों और छात्रों द्वारा एक साथ मिलकर उपदर्शित की गई उत्कृष्टता, स्वतंत्रता और ईमानदारी के द्वारा हुई है।

1. परिषद्

तेइसवीं परिषद् का गठन 12 फरवरी, 2016 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। वर्तमान में, परिषद् 32 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए 8 सदस्यों से मिलकर बनी है। तेइसवीं परिषद् की संरचना पृथक् रूप से दर्शित की गई है।

2. परिषद् की समितियां

परिषद् ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17 के निबंधनानुसार 12 फरवरी, 2017 को वृत्ति संबंधी विषयों के बारे में स्थायी और अन्य अस्थायी समितियों/बोर्डों का गठन किया था। 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न समितियों की 261 बैठकें आयोजित की गई थीं।

3. संपरीक्षक

मैसर्स हिंगोराणी एम. एंड कं., और मैसर्स खन्ना और आनंदनम वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आईसीएआई के संयुक्त संपरीक्षक थे।

4. स्थायी समिति

4.1 कार्यपालक समिति

कार्यपालक समिति आईसीएआई की परिषद् की स्थायी समितियों में से एक है। इस समिति के कृत्यों को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 175 में विहित किया गया है। इन कृत्यों में से कुछ कृत्य आर्टिकल और संपरीक्षा सहायकों तथा रजिस्टर में सदस्यों के नामांकन, नामों का हटाया जाना, नामों को वापस प्रविष्ट किया जाना, व्यवसाय प्रमाणपत्र का रद्दकरण, लेखांकन वृत्ति से भिन्न किसी अन्य कारबार या व्यवसाय में नियोजित होने के लिए अनुमति प्रदान करने से संबंधित हैं। समिति आईसीएआई के कार्यालयों के अनुरक्षण के अलावा संस्थान की संपत्ति, आस्तियों और निधियों की अभिरक्षक भी है।

4.2 वित्त समिति

वित्त समिति, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई है, अन्य बातों के साथ, सत्य और सही लेखाओं को रखे जाने, वार्षिक बजट तैयार करने, निधियों के निवेश, निधियों से राजस्व और पूंजी दोनों प्रकार के व्ययों के लिए आहरण करने से संबंधित और अनुषंगी गतिविधियों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करती है।

4.3 परीक्षा समिति

परीक्षा समिति, परीक्षाओं से संबंधित परिषद् के सभी कृत्यों का निर्वहन करती है। समिति ने, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाओं और फाइनल परीक्षाओं का 2 मई से 22 मई, 2016 के दौरान देश भर में और विदेशों में क्रमशः 461 और 359 केन्द्रों पर सुचारु रूप से संचालन किया था। उक्त मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

मई 2016					
		मध्यवर्ती (आईपीसी)		फाइनल	
क्रम सं.	प्रवर्ग	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
I	छात्र, जो केवल समूह I की परीक्षा में बैठे	65672	6028	37194	5382
II	छात्र, जो केवल समूह II की परीक्षा में बैठे	56742	4004	36906	7864
III	छात्र, जो दोनों समूहों की परीक्षा में बैठे				
(क)	छात्र, जिन्होंने या तो केवल समूह I या केवल समूह II की परीक्षा उत्तीर्ण की	47979	8325	40180	6190
(ख)	छात्र, जिन्होंने दोनों समूहों की परीक्षा उत्तीर्ण की		2295		4565
	योग		20652		24001

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाओं और फाइनल परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन 1 से 16 नवंबर, 2016 के दौरान देश भर में और विदेशों में क्रमशः 438 और 347 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था। उक्त मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाएं और फाइनल परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

नवंबर 2016					
क्रम सं.	प्रवर्ग	मध्यवर्ती (आईपीसी)		फाइनल	
		परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
I	छात्र, जो केवल समूह I की परीक्षा में बैठे	69653	13424	37200	2655
II	छात्र, जो केवल समूह II की परीक्षा में बैठे	62123	18701	36896	4545
III	छात्र, जो दोनों समूहों की परीक्षा में बैठे				
(क)	छात्र, जिन्होंने या तो केवल समूह I या केवल समूह II की परीक्षा उत्तीर्ण की	47766	12434	36768	2976
(ख)	छात्र, जिन्होंने दोनों समूहों की परीक्षा उत्तीर्ण की		3109		1280
	योग		47668		11456

इसके अलावा, सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) संबंधी परीक्षाओं को 19 जून, 2016 और 18 दिसम्बर, 2016 को, विदेशों और देश भर में क्रमशः 416 और 326 परीक्षा केन्द्रों पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। उक्त सीपीटी परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

निम्नलिखित तारीख को आयोजित सीपीटी	परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थी	उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी
19 जून, 2016	107058	41727
18 दिसम्बर, 2016	70321	32658

प्रबंध लेखांकन पाठ्यक्रम (एमएसी)(भागI), निगम प्रबंध पाठ्यक्रम (सीएमसी)(भागI), कर प्रबंध पाठ्यक्रम (टीएमसी)(भागI), बीमा और जोखिम प्रबंध (आईआरएम) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल और डब्ल्यूटीओ) में अर्हतापश्च पाठ्यक्रम संबंधी परीक्षाओं का सफल आयोजन भी नवम्बर, 2016 में किया गया था।

वर्ष के दौरान, अर्हतापश्च पाठ्यक्रम - सूचना प्रणाली संपरीक्षा - निर्धारण परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन 25 जून, 2016 को देश भर में 55 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था। एक अन्य सूचना प्रणाली संपरीक्षा - निर्धारण परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन 24 दिसंबर, 2016 को देश भर में 56 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था।

उक्त परीक्षाओं को देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

आईएसए निर्धारण परीक्षा आयोजित की थी	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
25 जून, 2016	1464 (पुराना)	111 (पुराना)
	1636 (नया)	717 (नया)
24 दिसंबर, 2016	1256 (पुराना)	90 (पुराना)
	2158 (नया)	439 (नया)

अंतर्राष्ट्रीय कराधान - निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) को प्रारंभ करना :-- आईसीएआई ने अपने सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान - निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) संबंधी एक नया अर्हता-पश्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किया था और उक्त पाठ्यक्रम की पहली परीक्षा का आयोजन नवंबर, 2016 के दौरान किया गया था। परीक्षा में उपस्थित होने वाले 103 सदस्यों में से 56 सदस्यों ने उसे उत्तीर्ण किया था।

आईसीएआई अपनी परीक्षा प्रणालियों में, प्रश्नपत्र निर्धारित करने के प्रक्रम से आरंभ करते हुए परिणामों की घोषणा तक की प्रणालियों में निरंतर रूप से सुधार करता रहा है, जिससे परीक्षा प्रणाली की सत्यनिष्ठा और संतता, जो कि पिछले छह दशकों से सुविख्यात है, अक्षुण्ण बनी रहे तथा उसे और अधिक मजबूत तथा विकसित किया जा सके।

आईसीएआई की परीक्षाएं सीए पाठ्यचर्या के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विषय के संबंध में अवधारणात्मक समझ और साथ ही व्यावहारिक प्रयोग की जांच करती हैं, जिससे छात्रों को पणधारियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में समर्थ बनाया जा सके। प्रश्नों की पूर्व अनुमानता की संभावनाओं को यथासंभव रूप से दूर रखते हुए छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आईसीएआई की परीक्षाएं लगातार यह सुनिश्चित करती रहीं हैं कि अर्हित छात्र सुयोग्य वृत्तिक बन सकें।

विशेष परीक्षा : निम्नलिखित विदेशी वृत्तिक लेखांकन निकायों के साथ किए गए परस्पर मान्यता करारों/समझौता ज्ञापनों से उद्भूत होने वाली विशेष परीक्षाओं का, जिनमें उक्त निकायों के सदस्य, जो कि हमारे संस्थान की सदस्यता को प्राप्त करने के लिए इच्छुक थे, सफलतापूर्वक आयोजन 21 और 22 जून, 2016 को नई दिल्ली में किया गया था :

1. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू)
2. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ आस्ट्रेलिया (आईसीए आस्ट्रेलिया)
3. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स इन आस्ट्रेलिया (सीपीए आस्ट्रेलिया)
4. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स इन आयरलैंड (सीपीए आयरलैंड)
5. कैनेडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीआईसीए)

इसके अतिरिक्त, आईसीएआई ने न्यूजीलैंड इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एनजेडआईसीए) के साथ हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

उपरोक्त विशेष परीक्षा, उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन के सदस्यों के लिए भी खुली है।

छात्र परीक्षा जीवन चक्र प्रबंध संबंधी वेब इंटरफेस :--

आईसीएआई ने एक छात्र परीक्षा जीवन चक्र प्रबंध संबंधी वेब इंटरफेस नामक एकीकृत वेब इंटरफेस प्रारंभ किया था, जहां सीए के छात्र एकल उपयोक्ता पहचान और पासवर्ड का उपयोग करते हुए विभिन्न परीक्षा संबंधी सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत द्वितीय अंक सूचियां/ उत्तीर्ण प्रमाणपत्र/प्रतिलिपियों, केंद्र/ माध्यम/समूह में परिवर्तन के लिए आवेदन, प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड करना, परिणामों की जांच करना और परिणाम के पश्चात् उत्तर-पुस्तिकाओं के सत्यापन/उनकी प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना आदि भी हैं।

नए परीक्षा केन्द्र : छात्रों द्वारा उनके आवास से निकटतम स्थानों पर परीक्षाएं देने को सुकर बनाने के विचार से निम्नानुसार नए परीक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई थी:

सीए मध्यवर्ती और फाइनल परीक्षाओं के लिए खोले गए नए परीक्षा केंद्र :

- (क) मई, 2016 से आगे की परीक्षाओं के लिए : शिमोगा और मलाप्पुरम्
- (ख) मई, 2017 से आगे की परीक्षाओं के लिए : हरिद्वार और निज़ामाबाद

सीपीटी परीक्षाओं के लिए खोले गए नए परीक्षा केंद्र :

- (क) जून, 2016 की परीक्षा से : शिमोगा, मलाप्पुरम् और सतना
- (ख) जून, 2017 की परीक्षा से : बदलापुर, बांसवाड़ा, भिवंडी, बुरहानपुर, चंद्रपुर, छिंदवाड़ा, गोंडिया, हल्दवानी, हरिद्वार, इच्छलकरंजी, जालना, जूनागढ़, मंदसौर, मुजफ्फरपुर, निज़ामाबाद, पालघर, परभानी, रतनागिरि, रीवा और यवतमाल

4.4 अनुशासन समिति

भारत में लेखांकन वृत्ति की विश्वसनीयता, अखंडता और छवि को बनाए रखने के निरंतर प्रयासों के भाग रूप में आईसीएआई ने, आईसीएआई के विनियामक ढांचे में एक सुदृढ़ और क्रियाशील अनुशासन तंत्र स्थापित किया है, जिसमें कार्यवाहियों को एक सुपरिभाषित प्रक्रिया के माध्यम से आरंभ किया जाता है और उन्हें उनके युक्तियुक्त अंत तक पहुंचाया जाता है। यह तंत्र सतत रूप से यह सुनिश्चित करते हुए कि अपराधी दंडित हो, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है।

वर्ष 2006 में किए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के संशोधनों के परिणामस्वरूप, आईसीएआई के अनुशासन तंत्र में, अनुशासन संबंधी मामलों के संचालन हेतु उपबंधों और प्रक्रियाओं में कतिपय महत्वपूर्ण और आमूलचूल परिवर्तन किए गए थे। तदनुसार, आज की तारीख तक आईसीएआई का अनुशासन तंत्र अपने दो अर्ध-न्यायिक तंत्रों के माध्यम से अनुशासनात्मक कृत्यों का निर्वहन करता है, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन गठित किया गया है, अर्थात् :-

(i) अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) ; और

(ii) अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन)।

वर्ष 2016-17 में पहली बार जांच के लिए लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे की प्रक्रिया को बनाए रखने के विचार से अनुशासन समिति की दो खंडपीठों, अर्थात् खंडपीठ-1 और खंडपीठ-2 का गठन किया गया था। इस संबंध में, खंडपीठ-1, अध्यक्ष, आईसीएआई की अध्यक्षता में लोक हित के मामलों के अलावा पश्चिमी/उत्तरी क्षेत्रों से संबंधित मामलों की जांच कर रही थी। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष, आईसीएआई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ-2 दक्षिणी/पूर्वी/मध्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों की जांच कर रही थी।

जहां तक 2006 में किए गए संशोधन से पूर्व लंबित मामलों का संबंध है, धारा 21घ के अधीन सांक्रांतिक उपबंध लागू होते हैं, वहीं अनुशासन समिति धारा 21घ के अधीन, अधिनियम और तदधीन विरचित विनियमों के पूर्ववर्ती उपबंधों के निबंधनानुसार ऐसे लंबित शेष मामलों के संबंध में कार्रवाई करती है। अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन)/अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) और अनुशासन समिति (धारा 21घ के अधीन) के क्रियाकलापों के संक्षिप्त विवरण को नीचे उल्लिखित किया गया है।

धारा 21क के अधीन अनुशासन बोर्ड

अनुशासन बोर्ड का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक और अन्य अवचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और/या ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए भी जहां सदस्यों को निदेशक (अनुशासन) द्वारा प्रथम दृष्टया रूप से किसी अवचार का दोषी नहीं पाया जाता है।

यद्यपि, बोर्ड को 12 फरवरी, 2016 को गठित किया गया था, किंतु इसने वास्तविक रूप से मई, 2016 से कार्यकरण आरंभ कर दिया था क्योंकि सरकार के नामनिर्देशितियों को अप्रैल, 2016 में नियुक्त कर दिया गया था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों पर 11 बैठकों की थी। इन बैठकों में, बोर्ड ने 30 मामलों, जिनके अंतर्गत पूर्व वर्षों में बोर्ड द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे, में अपनी जांच पूरी की थी। 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 की इस अवधि के दौरान अनुशासन बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए गए मामलों से संबंधित आंकड़ों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.*
क)	की गई बैठकों की संख्या	11 (11)
ख)	विनिश्चित किए गए ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिनमें प्रथमदृष्टया रूप से निदेशक (अनुशासन) की राय पूरी की गई थी।	162 (198)
ग)	उपरोक्त में से ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन्हें आगे और जांच के लिए निर्दिष्ट किया गया था	37 (44)
घ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें जांच पूरी कर ली गई थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान निर्दिष्ट किया गया था)	30 (18)
ङ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें दंड दिया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान निर्दिष्ट किया गया था)	8 (7)

* कोष्ठक में दी गई संख्या पिछले वर्ष को प्रदर्शित करती है।

वर्ष के दौरान, बोर्ड ने जुलाई, 2016 में की गई उसकी बैठक में उसके द्वारा लिए गए विनिश्चय के निबंधनानुसार, आईसीएआई के अनुशासन तंत्र में अंतर्लित जटिलताओं पर विचार करने के लिए एक पृथक् समूह को गठित करने का विनिश्चय किया था। तदनुसार, संस्थान के अध्यक्ष द्वारा सीए संजय कुमार अग्रवाल, केंद्रीय परिषद् के सदस्य के समन्वयन के अधीन, ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और तदधीन विरचित नियमों के अधीन उपबंधित किए गए अनुसार अनुशासन तंत्र से सुसंगत परिवर्तन

किए जाने की आवश्यकता है, अंतर्वर्तित जटिलताओं की जांच करने और उसके पश्चात् चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और तदधीन विरचित नियमों में संशोधनों के संबंध में सुझाव देने के लिए एक समूह का गठन किया गया था।

समूह ने उसे सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए तीन बैठकों की थी और अपनी रिपोर्ट मई, 2017 में हुई परिषद् की बैठक में उसे प्रस्तुत की थी। परिषद् ने समूह द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया था। तीन वृत्तिक संस्थानों के अनुशासन तंत्र से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए, समूह की रिपोर्ट, परिषद् द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के साथ कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2017 में गठित उच्च स्तरीय समिति के साथ साझा की गई थी।

धारा 21ख के अधीन अनुशासन समिति

अनुशासन समिति का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21ख के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक अवचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो केवल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची और दोनों- पहली तथा दूसरी अनुसूची, के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि, समिति को 12 फरवरी, 2016 को गठित किया गया था, किंतु इसने वास्तविक रूप से मई, 2016 से कार्यकरण आरंभ कर दिया था क्योंकि सरकार के नामनिर्देशितियों को अप्रैल, 2016 में नियुक्त कर दिया गया था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, समिति ने देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित स्थानों पर 18 बैठकें (खंडपीठ- 1 : 8 बैठकें और खंडपीठ- 2 : 10 बैठकें) की थी। पूर्वोक्त बैठकों के अनुक्रम के दौरान, समिति ने 48 मामलों में अपनी जांच पूरी की थी, जिसके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे। 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा विनिश्चित किए गए मामलों से संबंधित आंकड़ों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं. **
क)	की गई बैठकों की संख्या	18 (28)
ख)	विनिश्चित किए गए ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिनमें प्रथमदृष्टया रूप से निदेशक (अनुशासन) की राय पूरी की गई थी।	53 (70)
ग)	उपरोक्त में से ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन्हें आगे और जांच के लिए निर्दिष्ट किया गया था	55* (64)
घ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें जांच पूरी कर ली गई थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान निर्दिष्ट किया गया था)	48 (94)
ङ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें दंड दिया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान निर्दिष्ट किया गया था)	23 (28)

** कोष्ठक में दी गई संख्या पिछले वर्ष को प्रदर्शित करती है।

* इसके अंतर्गत अनुशासन बोर्ड द्वारा अनुशासन समिति को निर्दिष्ट मामले भी हैं।

प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति के निबंधनानुसार, जिसने त्वरित संचार को समर्थ बनाया है, परिवर्तनशील समय को ध्यान में रखते हुए तथा आईसीएआई की परिषद् द्वारा ई-सुनवाईयों को प्रारंभ करने के प्रस्ताव के लिए अपना सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए जाने पर, समिति वर्तमान में नियमों का संशोधन करने के लिए कार्यवाही कर रही है, जिससे कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के लिए इस संबंध में पद्धतियों को अधिनियमित किया जा सके। नियमों में संशोधन, जब उन्हें स्थापित किया जाए, त्वरित पद्धति से सुनवाईयों का संचालन करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होंगे, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में अनुशासन संबंधी मामलों का त्वरित रीति में निपटारा हो सकेगा तथा सकल लागत और लगने वाले समय में कमी आएगी।

धारा (21घ) के अधीन अनुशासन समिति

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21घ के उपबंधों के अधीन कार्यरत अनुशासन समिति, 2006 में अधिनियम में किए गए संशोधनों से पूर्व लंबित शेष मामलों के संबंध में जांच करती है और परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसे सदस्यों के, जिनके मामले उसे परिषद् द्वारा प्रथमदृष्टया राय बनाए जाने पर पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के अधीन निर्दिष्ट किए गए हैं, विरुद्ध अनुशासन संबंधी जांच करने के अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इस समिति ने 03 बैठकों का आयोजन किया था और वह उसके समक्ष लंबित चार शेष मामलों में सुनवाईयों को पूरा करने और प्रक्रियाओं में तेजी लाने का कार्य कर रही है।

ऐसे मामले, जिन पर पुराने अनुशासन तंत्र के अधीन कार्यवाही की गई थी [धारा 21(घ)]

1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 की अवधि के दौरान परिषद् और अनुशासन समिति के समक्ष रखे गए मामलों से संबंधित आंकड़े :

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.*
1.	(i) पूर्वोक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या (समिति के समक्ष जांच के लिए लंबित कुल 04 मामलों में से) (ii) पूर्वोक्त अवधि के दौरान की गई बैठकें	01 (-) 03 (02)
2.	अनुशासन समिति की ऐसी रिपोर्टों की संख्या, जिन पर परिषद् द्वारा विचार किया गया था (इनके अंतर्गत उन मामलों की रिपोर्टें भी हैं, जिन पर पूर्व वर्षों के दौरान सुनवाई की गई थी)	04 (09)
3.	उपरोक्त में से,— (क) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को पहली अनुसूची में दोषी पाया गया था किंतु चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(4) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व परिषद् के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु उपयुक्त पाया गया था (ख) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को दूसरी अनुसूची और/या अन्य अवचार के लिए दोषी पाया गया है किंतु जिनके मामले को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(5) के अधीन उच्च न्यायालयों को निर्दिष्ट किया जाना है। (ग) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची/ अन्य अवचार के लिए दोषी पाया गया है (घ) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें मामला आगे और जांच हेतु अनुशासन समिति को वापस निर्दिष्ट किया गया है (ङ) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को किसी अवचार के लिए दोषी नहीं पाया गया है	01 (01) 01 (-) शून्य (-) शून्य (-) 02 (08)
4.	ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें ऐसे प्रत्यर्थियों के संबंध में धारा 21(4) के अधीन आदेश पारित किया गया था, जिन्हें पहली अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया था	शून्य (01)
5.	उच्च न्यायालय द्वारा धारा 21(6) के अधीन निपटाए गए मामलों की संख्या	19 (10)

* कोष्ठक में दी गई संख्या पिछले वर्ष को प्रदर्शित करती है।

5. तकनीकी और वृत्तिक विकास**5.1 लेखांकन मानक बोर्ड (ए.एस.बो.)**

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रमुख क्रियाकलाप आरंभ/पूरे किए गए हैं :

I. वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का उन्नयन :

(क) आईसीएआई ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा तारीख 30 मार्च, 2016 की अधिसूचना द्वारा कंपनियों के लिए अधिसूचित संशोधनों के तत्समान गैर-निगम अस्तित्वों के लिए निम्नलिखित संशोधित लेखांकन मानक जारी किए हैं :

- एएस 2, सूचियों का मूल्यांकन
- एएस 4, तुलन-पत्र की तारीख के पश्चात् आने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं
- एएस 6, वापस लिया गया अवक्षयण
- एएस 10, संपत्ति संयंत्र और उपस्कर
- एएस 13, निवेशों के लिए लेखांकन

- एएस 14, सम्मेलन के लिए लेखांकन
- एएस 21, समेकित वित्तीय विवरण
- एएस 29, प्रावधान आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के संबंध में प्रभावी हैं।

(ख) आईएफआरएस में किए गए संशोधनों के समरूप भारतीय लेखांकन मानकों को अद्यतन करना :

- इंड एएस 7 नकद प्रवाहों का विवरण, में संशोधनों, आईएएस 7 नकद प्रवाहों का विवरण में किए गए संशोधनों के तत्समान और इंड एएस 102, अंश आधारित संदायों में संशोधनों को सम्यक् प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् एमसीए को प्रस्तुत किया गया था। इन संशोधनों को तारीख 17 मार्च, 2017 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2017 के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- वसूल न की गई हानियों के लिए आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता - इंड एएस 12, आय-कर में संशोधनों का एनएसीएएस द्वारा अनुमोदन
- परिषद्, आईसीएआई द्वारा अनुमोदित संशोधन
 - इंड एएस 115, ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व के संबंध में संशोधनों का स्पष्टीकरण
 - इंड एएस 40, निवेश संपत्ति में निवेश संपत्ति के अंतरणों से संबंधित संशोधन
 - इंड एएस 21, विदेशी मुद्रा संव्यवहार और अग्रिम विचार, के परिशिष्ट ख को तैयार करना
 - इंड एएस में वार्षिक सुधार - इंड एएस 112 और 28 में संशोधन (आईएएसबी द्वारा जारी आईएफआरएस मानकों में वार्षिक सुधारों 2014-2016 चक्र के तत्समान)

(ग) विद्यमान लेखांकन मानकों के उन्नयन के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा, ताकि उन्हें इंड एएस के सदृश बनाया जा सके और इस संबंध में निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए :

- समुन्नत एएस 7, नकद प्रवाहों का विवरण और एएस 8, लेखांकन नीतियां, लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियां, का एनएसीएएस द्वारा अनुमोदन।
- विभिन्न समुन्नत लेखांकन मानकों को तैयार करना प्रगति पर है, उदाहरणार्थ वित्तीय लिखतों संबंधी मानक।
- इंड एएस-अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की इंड एएस-अनुरूप अनुसूची 3 (प्रभाग 2) को एमसीए को प्रस्तुत किया गया था, जिसे 6 अप्रैल, 2016 को अधिसूचित किया गया है।
- गैर-बैंककारी वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की इंड एएस अनुरूप अनुसूची 3 को तैयार किया गया है, जिस पर राष्ट्रीय लेखांकन मानक संबंधी सलाहकार समिति (एनएसीएएस) द्वारा विचार किया गया था और उसका अनुमोदन भी किया गया था।

II. कार्यान्वयन संबंधी समर्थन

निम्नलिखित मार्गदर्शन टिप्पण/बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न/उदघोषणाएं जारी की गई थी :

- संयुक्त और तैयार किए गए वित्तीय विवरणों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण
- भू-संपदा संव्यवहारों के लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (ऐसे अस्तित्वों के लिए, जिन्हें इंड एएस लागू है)
- विद्यमान लेखांकन मानक एएस 30, वित्तीय लिखतें : मान्यता और मापमान, एएस 31, वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण और एएस 32, वित्तीय लिखतें : प्रकटन को वापस लिए जाने से संबंधित उदघोषणा
- लाभांश वितरण कर के संबंध में व्यवहार किए जाने से संबंधित बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न
- इंड एएस 109 में प्रयुक्त "विक्रय की गैर-मामूली संख्या" या "मूल्य में सारहीन" पदों के स्पष्टीकरण संबंधी बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न

- समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अपेक्षाओं से संबंधित बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न
- इंड एएस 101, भारतीय लेखांकन मानकों का प्रथम बार अपनाया जाना, के अधीन संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की समझी गई लागत संबंधी बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न

III. अंतर्राष्ट्रीय पहलें : दीर्घ अवधि भागीदारियां बनाना

(क) आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मंचों पर भागीदारी की थी, जैसे कि :

- 8-9 मई, 2017 के दौरान आईसीएआई भवन, मुंबई में आईएएसबी के उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह (ईईजी) की तेरहवीं बैठक की मेजबानी की थी, जिसमें आईएएसबी और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, अर्थात् ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 'सुक्ष्म अस्तित्वों संबंधी मुद्दे-वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी चुनौतियां' विषय पर एक पत्र प्रस्तुत किया गया था।
- 4-5 अप्रैल, 2016 के दौरान टोरंटो, कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक निर्धारक मंच (आईएफएसएस) की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आईएफएसएस के अधीन आईएएसबी की कार्ययोजना और मूलभूत घटनाओं, वृत्तिक निर्णय और "संभावना के निबंधन", आईएफएसएस के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों (आईएएसबी) और विभिन्न अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई थी।
- 26-27 सितंबर, 2016 के दौरान लंदन में विश्व मानक निर्धारकों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था और 3-4 नवंबर, 2016 के दौरान जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह की बैठक का आयोजन किया गया था।
- 2-3 मार्च, 2017 के दौरान ताइवान में अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक निर्धारक मंच (आईएफएसएस) की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने लाभांशों के वितरण के संबंध में आय-कर का व्यवहार विषय पर एक पत्र प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त, उच्च महंगाई दर, आईएफएसएस के संबंध में संगततः लागू किया जाना, "बृहत्त" मानकों का कार्यान्वयन और विभिन्न अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई थी।
- 3 से 6 अक्टूबर, 2016 के दौरान जिनेवा में आयोजित आईएसएआर, यूएनसीटीएडी के 33वें सत्र में, आईसीएआई ने भारत में आईएफएसएस 15 मानक के अभिसरण में अंतर्वलित कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों और व्यावहारिक विचारणों के संबंध में भारत की स्थिति को उपदर्शित करते हुए 'आईएफएसएस 15 – ग्राहकों के साथ संविदाओं की मान्यता से राजस्व' के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण किया था।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी निम्नलिखित उद्भासन प्रारूपों/चर्चा पत्रों पर टीका-टिप्पणियों को आईएएसबी को प्रस्तुत किया गया था :

- आईएफएसएस मानक 2015-2017 चक्र में वार्षिक सुधार संबंधी उद्भासन प्रारूप
- पूर्व में धारित हितों के लिए कारवार और लेखांकन की परिभाषा संबंधी उद्भासन प्रारूप (आईएफएसएस 3 और आईएफएसएस 11 में संशोधन)
- विचार किए जाने के लिए अनुरोध : 2015 कार्यसूची परामर्श
- ऋणात्मक प्रतिकर के साथ पूर्व संदाय विशिष्टियां (आईएफएसएस 9 में प्रस्तावित संशोधन)

(ग) अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ परस्पर क्रिया

- 13 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में आईएफएसएस संस्थापक न्यासी संयुक्त पणधारी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड और आईएफएसएस संस्थापन से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए थे।
- 14 अक्टूबर, 2016 को आईसीएआई के नेतृत्व ने भी विभिन्न मुद्दों जैसे कि कारव आउट की आवश्यकता और उन्हें हटाना, आईसीएआई और आईएफएसएस संस्थापन के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना आदि पर विचार-विमर्श करने के लिए आईएएसबी और आईएफएसएस संस्थापन से गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक की थी। श्री हेनरी रीस, निदेशक, आईएएसबी के साथ हुई बैठक में कतिपय तकनीकी मुद्दों पर भी परिचर्चा की गई थी।

IV. विनियामक निकायों के साथ संतुलित संबंध बनाना :

- बैंकों द्वारा इंड एएस के कार्यान्वयन में अंतर्वलित मुद्दों पर आरबीआई द्वारा तैयार किए गए एफएक्यू पर टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत की गई थी।

- आरईआईटी और इन्व आईटी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के संबंध में 'सतत प्रकटनों' के लिए आईसीएआई के प्रतिनिधि की अगुवाई में एक समूह की सिफारिशों को सेबी द्वारा गठित 'लेखांकन संनियमों संबंधी समिति' को प्रस्तुत किया गया था।
- एएस 11 के उपबंधों के संदर्भ में बैंकों की विदेशी शाखाओं से संचयित लाभों को स्वदेश भेजने के संबंध में विचार प्रस्तुत किए गए थे।
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को प्रारूप संमिश्र टैरिफ और लेखांकन विनियम, 2015 के संबंध में विचार प्रस्तुत किए गए थे।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को साम्या और संबंधित निवेशों में लेखांकन नीति और निवेश के लिए लेखांकन की पद्धति के संबंध में टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत की गई थी।

V. अन्य पहलें

- 9 मई, 2017 को इंड एएस 109 के अधीन 'सेवा रियायत ठहरावों' और 'प्रत्याशित प्रत्यय हानि माडल' से संबंधित 'उभरते हुए आईएफआरएस (इंड एएस) संबंधी चुनौतियों' के विषय पर आईसीएआई-ईईजी संयुक्त पणधारियों के लिए एक अर्ध-दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 90 आईसीएआई सदस्यों, ईईजी के प्रतिनिधियों और अन्य पणधारियों ने बहचड़ कर भाग लिया था।
- 21 अप्रैल, 2017 को एएसबी के 40 वर्ष पूरा होने के अवसर पर 12 जून, 2017 को एक आयोजन की मेजबानी की गई थी, जिसमें एएसबी, एनएसीएस के पूर्व अध्यक्षों तथा केंद्रीय परिषद् के सदस्यों को एक परस्पर क्रियाशील सत्र के लिए आमंत्रित किया गया था तथा 'लेखांकन मानक बोर्ड – लेखांकन सुधारों में 1977 से 2017 तक अगुवाई' शीर्षक वाली एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया था, जिसमें एएसबी के उसकी स्थापना से ही इतिहास और उपलब्धियों का वर्णन है।

5.2 स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक संबंधी समिति

स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक संबंधी समिति (सीएसएलबी) मार्च, 2005 से स्थानीय निकायों हेतु लेखांकन मानक (एसएलबी) तैयार कर रही है, जो स्थानीय निकायों के लिए उत्तम लेखांकन नीतियों को अधिकथित करते हैं और जो उनकी वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे तथा संगतत और समतुलनीयता का भी आगाज करेंगे।

महत्वपूर्ण क्रियाकलाप :

⇒ जारी किए गए एसएलबी :

- एसएलबी 18, 'खंड रिपोर्टिंग' – प्रारंभिक उद्भासन प्रारूप एसएलबी को टीका-टिप्पणियों के लिए जारी किया गया था
- एसएलबी 20, 'संबद्ध पक्षकार प्रकटन'
- 'स्थानीय निकायों के लिए साधारण प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अवधारणात्मक ढांचे' को तैयार करना
- एसएलबी ने निम्नलिखित के संबंध में भी टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत की थी :

⇒ शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी) के निम्नलिखित दस्तावेजों :

- आईजीएस 4, 'सरकार के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरण'
- आस्तियों संबंधी सलाह का प्रारूप,

- 28 और 29 मई, 2016 तथा 4 और 5 जून, 2016 को जयपुर में, आईसीएआई की जयपुर शाखा के सहयोग से राजस्थान सरकार के पदधारियों के लिए 'प्रोदभवन लेखांकन और लेखांकन मानक' विषय पर लेखांकन मानक बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से एक चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
- निम्नलिखित राज्यों के यूएलबी के पदधारियों की सक्षमता निर्माण के लिए 'शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में लेखांकन में सुधार तथा दोहरी प्रविष्टि प्रोदभवन लेखांकन प्रणाली के कार्यान्वयन' के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम :

⇒ पंजाब : 18-19 अगस्त, 2016 के दौरान चंडीगढ़ में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान के साथ संयुक्त रूप से

- ⇒ उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) : 23-24 सितंबर, 2016 के दौरान नई दिल्ली में एनडीएमसी के साथ संयुक्त रूप से
- ⇒ हिमाचल प्रदेश : 21-22 अक्टूबर, 2016 के दौरान शिमला में शहरी विकास निदेशालय, शिमला के साथ संयुक्त रूप से
- ⇒ झारखंड : 26-27 अक्टूबर, 2016 के दौरान रांची में नगर प्रशासन निदेशालय, शहरी विकास और आवासन विभाग, झारखंड सरकार के साथ संयुक्त रूप से

भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा इन कार्यक्रमों की अत्यधिक सराहना की गई थी।

- 21 फरवरी, 2017 को चेन्नई में स्थानीय निधि विभाग, तमिलनाडु के संपरीक्षकों के लिए 'स्थानीय निकायों में संपरीक्षा' विषय पर स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग के सहयोग से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

5.3 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (ए.ए.एस.बी.)

- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड ने मंत्रालयों और विनियामकों को निम्नलिखित अंतःनिवेश/अभ्यावेदन/सुझाव प्रस्तुत किए थे :
 - कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को, एमसीए द्वारा जनता की टीका-टिप्पणियों के लिए जारी प्रारूप कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (कारो 2016) के संबंध में टीका-टिप्पणियां
 - भारतीय रिजर्व बैंक को :
 - (i) शहरी सहकारी बैंकों की संपरीक्षक की रिपोर्ट का दृष्टांतमक प्रारूप।
 - (ii) बैंकों के कानूनी केंद्रीय संपरीक्षकों के संपरीक्षा संबंधी कर्तव्यों के आबंटन के संबंध में विचार।
 - (iii) लेखांकन मानक (एएस) 15, 'कर्मचारी फायदे', के अनुसार अस्वस्थता छुट्टी के लेखांकन पर विचार।

बोर्ड ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रकाशन निकाले थे :

- विशेष प्रयोजनों के लिए रिपोर्टों या प्रमाणपत्रों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षित 2016)
- समेकित वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षित 2016)
- कंपनी विवरणिकाओं में रिपोर्टों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षित 2016)
- बैंकों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षित 2017)
- भारतीय लेखांकन मानकों के अधीन संक्रमणाकालीन चरण के लिए संपरीक्षक की रिपोर्ट संबंधी कार्यान्वयन गाइड
- वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लघुतर, कम जटिल कंपनियों के विनिर्दिष्ट प्रतिनिर्देश से संपरीक्षा संबंधी कार्यान्वयन गाइड
- कंपनी (संपरीक्षा और संपरीक्षक) संशोधन नियम, 2017 के नियम 11(घ) के अधीन संपरीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के संशोधन संबंधी कार्यान्वयन गाइड
- गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों की संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड (पुनरीक्षित 2016)
- क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड से प्राप्त सुझाव के आधार पर बोर्ड ने क्वालिटी पुनर्विलोकनों के संचालन संबंधी तकनीकी गाइड को तैयार किया है।
- बोर्ड ने सेबी (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अधीन रिपोर्टें जारी करते समय संपरीक्षा संबंधी मानकों और पुनर्विलोकन नियोजनों को लागू करने संबंधी क्रियान्वयन गाइड को तैयार किया था।
- बोर्ड ने कारो 2016, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रिपोर्टिंग लेखांकन मानकों और अन्य संपरीक्षा संबंधी पहलुओं के संबंध में सदस्यों में जागरूकता और वृत्तिक अभिवृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए देश भर में अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इन कार्यक्रमों का आयोजन इंदौर, राजकोट, हैदराबाद, कोयम्बटूर, जयपुर, कोलकाता, रायपुर, उदयपुर, तूतीकोरन, ब्यावर, सूरत, चेन्नई, विशाखापट्टनम, इलाहाबाद, भोपाल, सिलिगुड़ी, जमशेदपुर, मुंबई, अलवर, गांधी धाम, मदुरै, बिलासपुर, धनबाद, आगरा, भुज, बरेली, मथुरा, पाली, संबलपुर, मेरठ और ग्वालियर में किया गया था।

- बोर्ड ने दिसंबर, 2016 में जयपुर में “संपरीक्षा और उससे परे” विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में 2000 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था।
- बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बैंक शाखा संपरीक्षाओं से संबंधित सदस्यों की शंकाओं का समाधान करने के लिए एक आनलाइन बैंक संपरीक्षा विशेषज्ञ पैनल का गठन किया था।
- बोर्ड ने समय-समय पर सदस्यों से प्राप्त संपरीक्षा पहलूओं से संबंधित विभिन्न शंकाओं के उत्तर/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए थे।
- बोर्ड ने सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित उद्घोषणाओं/स्पष्टीकरणों को जारी किया था :
 - समेकित वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा संबंधी पुनरीक्षित मार्गदर्शन टिप्पण के पैरा 17 में संशोधन के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण।
 - एसए 701 और पुनरीक्षित एसए 700,705,706 की पुनरीक्षित प्रभावी तारीख के संबंध में महत्वपूर्ण उद्घोषणा।
 - एसक्यूसी – 1 के अधीन नियोजन भागीदार के चक्रानुक्रम और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन संपरीक्षक के चक्रानुक्रम से संबंधित अपेक्षा में संक्रमणाकालीन समय अंतराल के संबंध में स्पष्टीकरण।
- बोर्ड ने जनता की टीका-टिप्पणियों के लिए संपरीक्षा संबंधी निम्नलिखित मानकों के उद्भासन प्रारूपों को जारी किया था :
 - पुनरीक्षित एसए 299, ‘संयुक्त संपरीक्षाएं’।
 - पुनरीक्षित एसए 720, ‘अन्य जानकारी के संबंध में संपरीक्षक के उत्तरदायित्व’।
- अध्यक्ष, एएएसबी ने जून, 2017 में न्यूयार्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड की राष्ट्रीय मानक निर्धारकों के साथ वार्षिक बैठक (आईएएसबी-एनएसएस बैठक) में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था।
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एएएसबी ने निम्नलिखित बैठकों में भी आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था :
 - सितंबर, 2016 में, हांगकांग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड की बैठक।
 - दिसंबर, 2016 में, न्यूयार्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड की बैठक।
 - मार्च, 2017 में लीमा, पेरू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड की बैठक।
 - जून, 2017 में, न्यूयार्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड की बैठक।

5.4 बैंककारी, वित्तीय सेवा और बीमा समिति

- समिति ने, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) के पद हेतु आवेदनों को प्राप्त करते समय व्यवसायरत सदस्यों के अनुभव को उद्योग में कार्यरत सदस्यों के तत्समान समझे जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) को एक अभ्यावेदन भेजा।
- समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने 12 जून, 2017 को श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्री के साथ बैठक की थी।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को, भारत सरकार/पीएफआरडीए द्वारा आरंभ की गई विभिन्न पेंशन स्कीमों के संबंध में साधारण जनता में जागरूकता का प्रसार करने के लिए एक अभ्यावेदन भेजा गया था।
- समिति के अध्यक्ष ने 7 जून, 2016 को एशियाई विकास बैंक के वरिष्ठ वित्तीय नियंत्रण अधिकारी के साथ बैठक की थी और एडीबी के विभिन्न उद्यमों के लिए आईसीएआई और उसके सदस्यों की सेवाओं की प्रस्थापना की थी।
- समिति ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्य के रूप में आईसीएआई के एक प्रतिनिधि को सम्मिलित किए जाने के विषय पर विचार करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) को एक अभ्यावेदन भेजा था।
- समिति के अध्यक्ष ने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य (अर्थशास्त्र) के साथ परस्पर हित के विषय पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की थी।
- समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने 18 अप्रैल, 2016 को मुंबई में, भारतीय मर्चेन्ट्स चैम्बर द्वारा आयोजित 8वें बैंककारी और वित्त सम्मेलन के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित किया था।

- आईसीएआई, समिति के माध्यम से 24 अगस्त, 2016 को मुंबई में गर्वनेंस नाओ (सब टीवी समूह) द्वारा आयोजित “भारतीय बैककारी सुधार सभा, 2016” के लिए “ज्ञान भागीदार” था।
- समिति ने 21 अप्रैल, 2017 को मुंबई में, एनएसडीएल के सहयोग से पूंजी बाजार विषय पर एक अर्ध-दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया था।
- समिति ने 14 मई, 2016 को नई दिल्ली में, “परियोजना मूल्यांकन, वित्त पोषण और नियंत्रण” विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था।
- समिति ने क्रमशः 26 जुलाई, 2016 और 13 दिसंबर, 2016 को परियोजना लागत प्राक्कलन और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए सम्यक् परिश्रमिता संबंधी वेबकास्टों का आयोजन किया था।
- 29 अप्रैल से 21 मई, 2017 के दौरान (केवल सप्ताहांत पर) मुंबई, चेन्नई, नोएडा में विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के तीन बैचों का आयोजन किया गया था।
- 24-28 मई, 2017 के दौरान मुंबई में, डीआईआरएम तकनीकी परीक्षा में उत्तीर्ण आईसीएआई के सदस्यों के लिए एक अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 26 जुलाई, 2017 तक डीआईआरएम पाठ्यक्रम के लिए 4994 रजिस्ट्रीकरण प्राप्त हुए थे।
- समिति कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईपीएफ) के तत्वाधान में अपनी विभिन्न कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (पीओयू) के माध्यम से निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों (आईएपी) का आयोजन करके समाज और राष्ट्र को सक्रिय रूप से योगदान दे रही है। 1 अप्रैल, 2016 से 11 फरवरी, 2017 की अवधि के दौरान कुल मिलाकर ऐसे 764 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु – तत्कालीन संघ के माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार ने 16 जून, 2016 को समिति द्वारा आयोजित निवेशक जागरूकता कार्यक्रम, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी की एर्नाकुलम शाखा द्वारा की गई थी, का उद्घाटन किया था। माननीय कृषि, खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार बलियान ने भी इस अवसर की शोभा बढ़ाई थी।
- समिति अपनी विभिन्न कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (पीओयू) के माध्यम से ‘बंबई स्टॉक एक्सचेंज- निवेशक संरक्षण निधि (बीएसई-आईपीएफ)’ के सहयोग से निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस अवधि के दौरान, बंबई स्टॉक एक्सचेंज की निवेशक संरक्षण निधि के समर्थन से ईओयू द्वारा कुल पांच निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- समिति ने 1 अप्रैल, 2016 से 11 फरवरी, 2017 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 9 बैचों का संचालन किया था।
- इस अवधि के दौरान समिति ने 2 वेबकास्टों का भी आयोजन किया था।

5.5 व्यवसाय में लगे सदस्यों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति

व्यवसाय में लगे सदस्यों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति (सीसीबीएमपी) का सृजन फरवरी 2010 में किया गया था। समिति का अंततोगत्वा उद्देश्य सीए फर्मों और साथ ही लघु तथा मध्यम व्यवसायियों को सुदृढ़ बनाना है। समिति का प्रमुख कृत्य, प्रबंध परामर्शी सेवा फर्मों की नेटवर्किंग, विलयन और स्थापना के माध्यम से समेकन करके सीए फर्मों के बीच सक्षमता निर्माण के संबंध में जागरूकता का सृजन करना और बेहतर लेखांकन, संपरीक्षा और नैतिक मानकों के समेकन और स्थायित्व के फायदों के संबंध में कार्यशालाओं, सभाओं और शिखर सम्मेलनों का आयोजन करके यूनियन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना है।

आईसीएआई के विजन के अनुरूप, जो ‘भारतीय चार्टर्ड लेखांकन वृत्ति’ को विश्व स्तरीय वित्तीय सक्षमताओं, बेहतर शासन और प्रतिस्पर्धियों के बीच मूल्यवान न्यासी के रूप में स्थापित करना है, समिति का मोटो भारतीय सीए फर्मों की सुदृढीकरण और लघु तथा मध्यम व्यवसायियों के सशक्तिकरण के माध्यम से उनकी सक्षमता निर्माण करना है, जो उनकी वृत्तिक सक्षमता को विकसित तथा उसका उन्नयन करके प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार, समिति निम्नलिखित मुद्दों के संबंधी में कार्यवाही करती है :

- सीए फर्मों के सुदृढीकरण के लिए संहिता तैयार करना।
- एसएमपी के सशक्तिकरण के लिए उपायों और मार्गों की पहचान करना।

- मानक व्यवसाय से संबंधित ज्ञान और कौशल सेट को समुन्नत तथा अद्यतन करना ।
- एसएमपी के लिए व्यवसाय संबंधी क्षेत्रों का विकास करना ।
- उभरते क्षेत्रों में एसएमपी की भूमिका की पहचान करना ।
- वृत्ति के नए क्षेत्रों में व्यवसाय को सुकर बनाने के लिए तकनीकी सामग्री को विकसित करना ।
- सीए फर्मों और एसएमपी के लिए आईटी उन्नत कार्यालय प्रबंध और संपरीक्षा उपकरणों को उपलब्ध कराना ।
- वृत्ति का पुनर्निर्माण करना और उत्तम अवसंरचना तथा वित्त के साथ सीए फर्मों की स्थापना करना ।
- व्यवसायियों और सीए फर्मों के लिए सामाजिक सुरक्षा और बीमा संरक्षण का प्रबंध करना ।

किए गए क्रियाकलाप :

- **आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों के लिए विशेष कीमत पर 'क्विक हील टोटल सिक्योरिटी फार पीसी' उपलब्ध कराना**

समिति ने सदस्यों की एक एंटी वायरस साफ्टवेयर तक पहुंच को समर्थ बनाने के उद्देश्य से क्विक हील टेक्नोलॉजिस प्रा.लि., पुणे के साथ करार किया है कि वह 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2017 तक आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए एकल उपयोक्ता के लिए 1200/- रुपये धन लागू करें के विशेष रियायती मूल्य पर क्विक हील टोटल सिक्योरिटी उपलब्ध कराएगा, जिसके ब्यौरे <http://www.icai.org/post.html?post id=11505> पर उपलब्ध हैं ।

- **आफिस प्रोटेक्शन शील्ड बीमा**

सीसीबीएमपी के पास आईसीएआई के सदस्यों के लिए आफिस प्रोटेक्शन शील्ड बीमा स्कीम है । यह स्कीम आईसीएआई के व्यवसायरत सदस्यों/फर्मों के लिए 18 सितंबर, 2013 से प्रभावी है । इसके ब्यौरे <http://www.icai.org/post.html?post id=10097> पर उपलब्ध हैं ।

- **मोटर यान बीमा**

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से विशेष निबंधनों के साथ मोटर यान बीमा उपलब्ध कराए जाने का ठहराव किया गया है । यह मोटर यान बीमा आधिकारिक रूप से सदस्यों के लिए तैयार किया गया है किंतु इसे आईसीएआई के छात्रों और कर्मचारियों को भी विस्तारित किया गया है । इसके ब्यौरे <http://www.icai.org/post.html?post id=12760> पर उपलब्ध हैं ।

- **आईसीएआई कनेक्ट – आईसीएआई के सदस्यों के लिए एक स्व सेवा पोर्टल**

समिति ने आईसीएआई कनेक्ट, आईसीएआई के सदस्यों के लिए एक स्व सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है । पूर्वोक्त एकल पटल स्व सेवा की विशिष्टियों में निजी प्रोफाइल और फर्म के संविधान, आईसीएआई की उदघोषणाओं, आईसीएआई को संदत्त फीसों और विनियामक प्रभारों के ब्यौरों, माई आर्टिकल्स के ब्यौरों को देखना, विनियामक प्ररूपों और आवेदनों की प्रास्थिति को ट्रेक करना, ई-सेवाओं, माई फर्मों, माई साफ्टवेयर, लेटर्स और प्रमाणपत्रों, प्रत्यय किए गए सीपीई घंटों, नेटवर्क करने, विलयन और निर्विलयन संबंधी दिशा-निर्देशों आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करना सम्मिलित है ।

- **आईसीएआई के सदस्यों द्वारा उठाई गई वृत्तिक शंकाओं के समाधान के लिए ई-समाधान पोर्टल**

आईसीएआई के सदस्यों द्वारा उठाई गई वृत्तिक शंकाओं के समाधान के लिए ई-समाधान पोर्टल का शुभारंभ किया गया था । पैनलबद्ध वृत्तिक, सदस्यों द्वारा वृत्ति के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में उठाई गई वृत्तिक शंकाओं का उत्तर देंगे । इसके लिए सदस्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपनी शंकाओं को रजिस्टर करने के लिए एसएसपी में लॉगइन करें और 'ई समाधान' पर क्लिक करें ।

- **समिति की अनन्य वेबसाइट www.icai.org.in**

सीसीबीएमपी ने एक वेबसाइट, अर्थात् www.icai.org.in को विकसित किया है, जहां फर्मों और व्यवसायी परिषद् द्वारा अधिकथित सनियमों के अनुसार अपने पोर्टलों का सृजन कर सकते हैं । यह वेबसाइट सीए फर्मों के लिए एक ऐसा मंच उपलब्ध कराती है, जहां वे अपनी फर्मों के ब्यौरे अपलोड कर सकती हैं और इस प्रकार उन्हें सदस्यों और विश्व भर में व्यवसायरत सीए फर्मों तक पहुंच बनाने का अवसर प्राप्त होता है ।

यह वेबसाइट आईसीएआई के सदस्यों और सीए फर्मों के सुदृढीकरण के लिए भी एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करती है, जो

नेटवर्किंग, विलयन और व्यवसाय के निगम रूप जैसे सुदृढीकरण उपायों को उपलब्ध कराती है। इस वेबसाइट पर सदस्य अन्य सदस्यों और फर्मों के पोर्टल को देख सकते हैं और समान सोच वाले व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए और स्वयं का विकास करने के लिए हाथ मिला सकते हैं।

- आईसीएआई के वरिष्ठ सदस्यों के लिए पोर्टल www.seniormembers.icai.org

समिति ने एक वेबसाइट अर्थात् www.seniormembers.icai.org को विकसित किया है। यह वेबसाइट आईसीएआई के वरिष्ठ सदस्यों को, उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् नमनीय कार्य घंटों के समनुदेशन और साथ ही पूर्णकालिक कार्य प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। साथ ही यह पोर्टल उद्योग की, ऐसे अनुभव प्राप्त योग्य पूल तक पहुंच स्थापित करने में सहायता करेगा, जिस तक सामान्य अनुक्रम में अन्यथा पहुंच संभव नहीं हो सकती थी। उक्त पोर्टल आईसीएआई के सभी वरिष्ठ सदस्यों के लिए उपयोगी और सुगम सिद्ध होगा।

- नेटवर्किंग और विलयन – पुनरीक्षित दिशानिर्देश

सीसीवीएमपी ने नेटवर्किंग के माध्यम से सीए फर्मों के सुदृढीकरण में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों पर विचार किया है। सीसीवीएमपी ने सदस्यों और फर्मों द्वारा नेटवर्किंग संबंधी पुनरीक्षित दिशानिर्देशों को सुगम रूप से अपनाए जाने को सुकर बनाने के लिए उन्हें उपयुक्त रूप से अंतिम रूप प्रदान किया है। नेटवर्किंग के पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के ब्यौरे <http://www.icai.org/post.html?post id=7710> पर उपलब्ध हैं। विलयन संबंधी नियमों के ब्यौरों को www.icai.org.in पर अपलोड किया गया है।

- वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' नगरों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा किए गए वृत्तिक कार्यों के लिए फीस से संबंधित पुनरीक्षित न्यूनतम सिफारिश किए गए मान संबंधी ब्राशर

- समिति ने वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' नगरों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा किए गए वृत्तिक कार्यों के लिए फीस से संबंधित पुनरीक्षित न्यूनतम सिफारिश किए गए मान संबंधी ब्राशर तैयार किया है। पूर्वोक्त ब्राशर <http://www.icai.org/post.html?post id=7252> पर उपलब्ध है।

- धन प्रबंध और वित्तीय योजना संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति, सदस्यों के लिए करियर संबंधी नए अवसरों में अभिवृद्धि करने के लिए धन प्रबंध और वित्तीय योजना संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन कर रही है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य, सदस्यों को धन प्रबंध के सिद्धांतों से सुसज्जित करना और साथ ही प्रभावी निवेश रणनीति तैयार करने और व्यवहारिक प्रक्रियात्मक पहलुओं से सुपरिचित कराना और ऐसे सक्षमता स्तर का निर्माण करना है जिससे सदस्यों को वित्तीय परामर्शी और सलाहकार के रूप में स्थापित किया जा सके। पाठ्यक्रम के ब्यौरे <http://www.icai.org/post.html?post id=11179&c id=240> पर उपलब्ध हैं।

लाइव वेबकास्ट

- समिति ने निम्नलिखित के संबंध में लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया था
 - धन प्रबंध और निवेश रणनीतियां
 - शोधन अक्षमता अधिनियम
 - “बैंक संपरीक्षा के विशेष संदर्भ से व्यवसायियों की सक्षमता निर्माण संबंधी उपाय”
 - “इंड एएस के अधीन उचित मूल्य मापमान के विशेष संदर्भ से व्यवसायियों की सक्षमता निर्माण संबंधी उपाय”
 - “इंड एएस : व्यवहारिक उपयोजन और उभरती हुई प्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ से व्यवसायियों की सक्षमता निर्माण संबंधी उपाय”
 - “एफसीआरए और जीएसटी के विशेष संदर्भ से व्यवसायियों की सक्षमता निर्माण संबंधी उपाय”
 - न्यास और आईटी अधिनियम के अधीन कराधान के विशेष संदर्भ से व्यवसायियों की सक्षमता निर्माण संबंधी उपाय

समिति के कार्यक्रम

समिति ने पूरे वर्ष में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिसके अंतर्गत कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, आवासीय कार्यक्रमों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन था।

महिला सदस्य सशक्तिकरण समूह

- क) महिला चार्टर्ड अकाउंटेंटों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए परिषद् की महिला सदस्य सशक्तिकरण उप-समूह पिछले तीन वर्ष से निरंतर कार्य कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला सदस्यों के विकास के लिए योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना है। यह उप समूह विभिन्न कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/ सम्मेलनों आदि का आयोजन करके महिला सीए के साधारण फायदे के लिए अपनी महिला सदस्यों को सशक्त बनाने के अपने उद्देश्य के प्रति कटिबद्ध है।

इस उप समूह द्वारा एक समर्पित पोर्टल, “महिला सदस्यों के लिए पोर्टल” को भी बनाया रखा जा रहा है, जो महिला सदस्यों को एक ऐसा माध्यम उपलब्ध कराता है, जिसके द्वारा वे अपनी अपेक्षाओं को पोस्ट कर सकती हैं और उनके लिए उपलब्ध नमनीय कार्य घंटों के विकल्पों का पता लगा सकती हैं। इसका उद्देश्य महिला सदस्यों को उनकी जानकारी को अद्यतन बनाने तथा अपने विचारों तथा चिंताओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक सामान्य मंच उपलब्ध कराना भी है।

- ख) इस उपसमूह ने “महिला चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए संगोष्ठी” का भी आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी 11 मार्च, 2017 को बंगलौर में एसआईआरसी की बंगलौर शाखा द्वारा की गई थी। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता – एक पर्यावलोकन स्वालपा अडजस्ट मादी – अपने स्वयं के मस्तिष्क की शांति हेतु जीएसटी संबंधी एक पर्यावलोकन – अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में आमूल-चूल सुधार – दिवस का विषय और फिटनेस, छवि की ब्रांडिंग और स्वयं का विकास जैसे सत्र भी सम्मिलित थे। सम्मेलन का शुभारंभ श्रीमती करंदलाजे, संसद् सदस्य और पूर्व ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री, कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में लगभग 200 महिला सदस्यों ने भाग लिया था।

युवा सदस्य सशक्तिकरण समूह

आईसीएआई की व्यवसायरत सदस्यों की सक्षमता निर्माण संबंधी समिति का युवा सदस्य सशक्तिकरण समूह (वाईएमईजी), युवा सीए के लिए, जहां तक तकनीकी और वृत्तिक कौशलों का संबंध है, उसके द्वारा समाज की उभरती अपेक्षाओं पर खरा उतरने में और उनके बीच सक्षमता निर्माण को समर्थ बनाने के लिए उनकी सहायता करने हेतु पहले करने का प्रयास करता है।

I. संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/सम्मेलन/आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ वेबकास्ट :

समूह ने देश भर में ऐसे विभिन्न समकालीन विषयों पर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए फायदाप्रद है, अर्थात् स्टार्ट अप और उद्यमशीलता, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, जीएसटी, आय प्रकटन स्कीम, 2016, न्यायालयीन संपरीक्षा, आय-कर, ई-वाणिज्य और क्लाउड संगणना, आईसीडीएस और अपीलों को तैयार करना आदि के संबंध में 23 संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों का आयोजन किया था। विभिन्न विषयों पर सात वेबकास्टों के अलावा समकालीन विषयों पर दो आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था।

- II. **वाईएमईजी ज्ञान पोर्टल :** वाईएमईजी पोर्टल युवा सीए को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है, जहां से वे वाईएमईजी के क्रियाकलापों से जुड़ सकते हैं और सक्रिय रूप से उनमें भाग ले सकते हैं तथा उनमें भागीदारी कर सकते हैं (www.ymec.in)। इस पोर्टल में विभिन्न विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं जैसे कि होने वाले आयोजन, सलाह, लेख, तकनीकी और प्रेरणादायक वीडियो, ज्ञान केंद्र, उपयोगी लिंक, कार्यक्रमों का संग्रह आदि। वाईएमईजी ने सफल उद्यमियों के प्रेरक संदेशों वाले पांच वीडियो और सिविल सेवक बनने के लिए युवा सदस्यों को प्रेरित करने वाला एक वीडियो भी अपलोड किया है।

- III. **ई-पुस्तिका – युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए उपयोगी वृत्तिक जानकारी –** वाईएमईजी ने ई-पुस्तिका के रूप में युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों, चाहे वे व्यवसाय में हों या सेवा में, के फायदे के लिए उपयोगी जानकारी का ई-पाठ जारी किया है। इस ई-पुस्तिका में विभिन्न विषय सम्मिलित किए गए हैं, जैसे कि – सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसर, विभिन्न दिशानिर्देश, अर्थात् व्यवसाय का निगम रूप, नेटवर्क फर्म, विज्ञापन, वेबसाइट, संपरीक्षा, इंड एस संबंधी मानकों जैसे तकनीकी विषय, जेनरिक आंतरिक संपरीक्षा गाइड आदि को सम्मिलित किया गया है। यह ई-पुस्तिका वाईएमईजी पोर्टल (www.ymec.in) पर उपलब्ध है।

- IV. **ई-न्यूज लैटर :** वाईएमईजी ने ई-न्यूज लैटर की पहले त्रैमास की दूसरी जिल्द (अप्रैल 2016 से जून, 2016) को प्रकाशित किया है। इसमें वाईएमईजी समिति के द्वारा आयोजित सभी क्रियाकलापों/कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/वेबकास्टों और आगामी क्रियाकलापों के व्यौरे अंतर्विष्ट हैं।

5.6 सतत् वृत्तिक शिक्षा संबंधी समिति

समिति ने सदैव अपने सदस्यों को ऐसे वृत्तिक और प्रौद्योगिकी संबंधी परिवर्तनों के संबंध में, जो इस परिवर्तनशील आर्थिक वातावरण में पूरे विश्व में निरंतर हो रहे हैं, जागरूक बनाने तथा उनसे अवगत कराने का प्रयास किया है और यह प्रक्रिया कक्षा पठन, ई-पठन पद्धति, घरेलू कार्यपालक विकास कार्यक्रम, वेबकास्ट, जागरूकता कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों, आदि के माध्यम से पूरी की जाती है।

समिति का मुख्य उद्देश्य, आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ऐसे उपायों को अपनाना, उन्हें निष्पादित और क्रियान्वित करना है, जिससे सदस्यों को सामयिक ज्ञान से अवगत कराया जा सके।

वैश्विक अपेक्षाओं से कदम मिलाकर चलने के लिए, सीपी अपेक्षाएं आईसीएआई के सभी सदस्यों, चाहे वे व्यवसाय में हों अथवा सेवारत हों, के लिए आज्ञापक हैं और इस प्रणाली की मानीटरी और प्रबंध वैज्ञानिक रूप से किया जाता है।

1. सदस्यों के पठन और वृत्तिक विकास के लिए ठोस तंत्र :-

• सीपीई विवरण का पुनरीक्षण

अपने सदस्यों को अपेक्षित वृत्तिक सक्षमता बनाए रखने में समर्थ बनाने और इस प्रकार उनके द्वारा दी जाने वाली वृत्तिक सेवाओं में उच्च क्वालिटी और मानकों को सुनिश्चित करने के विचार से आईसीएआई के सभी सदस्यों के लिए, चाहे वे व्यवसाय में हों या सेवा में, आईसीएआई की परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सीपीई प्रत्यय घंटों की अपेक्षाओं को पूरा करना आज्ञापक है।

वैश्विक अपेक्षाओं और व्यवहारों के अनुरूप सीपीई प्रत्यय घंटों की अपेक्षाओं को सदस्यों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए पुनरीक्षित किया गया था और वे (1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2019) के तीन वर्षों के चालू ब्लॉक से लागू होंगी। सदस्यों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए सीपीई प्रत्यय घंटों की अपेक्षाओं को पुनरीक्षित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :

प्रवर्ग	विद्यमान (सीपीई घंटे) 31.12.2016 तक	पुनरीक्षित (सीपीई घंटे) (01.01.2017 से प्रभावी)
अ. सीओपी धारण करने वाले सभी सदस्य (जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है) (सिवाय उनके, जो विदेश में रह रहे हैं)	90 (संरचित – 60 घंटे और असंरचित 30 घंटे)	120 (संरचित – 60 घंटे और असंरचित 60 घंटे)
आ. सीओपी धारण न करने वाले सभी सदस्य (जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है) और जो विदेश में रह रहे हैं (चाहे वे सीओपी धारण कर रहे हैं अथवा नहीं)	45 संरचित या असंरचित (सदस्य की इच्छानुसार) [10+10+10]+15 तीन वर्ष के ब्लॉक में किसी भी समय	60 संरचित या असंरचित (सदस्य की इच्छानुसार) [15+15+15]+15 तीन वर्ष के ब्लॉक में किसी भी समय
इ. सीओपी धारण करने वाले सभी सदस्य (जिनकी आयु 60 वर्ष और उससे अधिक है)	70 संरचित या असंरचित (सदस्य की इच्छानुसार) [10+20+20]+20 तीन वर्ष के ब्लॉक में किसी भी समय	90 संरचित या असंरचित (सदस्य की इच्छानुसार) [20+20+20]+30 तीन वर्ष के ब्लॉक में किसी भी समय

सदस्यों को छूट

क) किसी सदस्य को केवल ऐसे विशिष्ट कलेंडर वर्ष के लिए ही छूट प्राप्त है, जिसके दौरान वह पहली बार सदस्यता प्राप्त करता है।

ख) निम्नलिखित वर्ग के सदस्यों को सीपीई प्रत्यय घंटों की अपेक्षा से छूट प्राप्त है :

- सीओपी धारण न करने वाले सभी सदस्य (जिनकी आयु 60 वर्ष और उससे अधिक है)
- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और अधिकरणों के न्यायाधीश
- संसद् सदस्य/एमएलए/एमएलसी
- राज्यों के राज्यपाल
- केंद्र और राज्य सिविल सेवाएं

- उद्यमी [वृत्तिक सेवाओं से भिन्न कारबार (विनिर्माण) संगठनों के स्वामी]
- न्यायिक अधिकारी
- सैन्य सेवा के सदस्य

ग) अस्थायी छूट

- महिला सदस्यों को, उनके गर्भधारण के आधार पर एक कलेंडर वर्ष के लिए
- शारीरिक रूप से दिव्यांग के लिए मामला-दर-मामला आधार पर, जिनकी निःशक्तता कम से कम चालीस प्रतिशत और उससे अधिक है [भारतीय चिकित्सा परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसे डाक्टर, जिसके पास सुसंगत विशेषज्ञता है, जैसा कि उसकी स्नातकोत्तर अर्हताओं (एमडी, एमएस आदि) से साबित होता है, के चिकित्सा प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित]
- सीपीईसी द्वारा विनिर्दिष्ट या अनुमोदित की जाने वाली किसी लंबी गंभीर बीमारी/रोग या अन्य दिव्यांगता से पीड़ित सदस्य [भारतीय चिकित्सा परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसे डाक्टर, जिसके पास सुसंगत विशेषज्ञता है, जैसा कि उसकी स्नातकोत्तर अर्हताओं (एमडी, एमएस आदि) से साबित होता है, के चिकित्सा प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित]

घ) कोई सदस्य या सदस्यों का कोई वर्ग, जिसे समिति अपने नेतांत विवेकाधिकार से, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विनिर्दिष्ट रूप से या सामान्य रूप से पूर्ण/अंशकालिक छूट प्रदान करती है, जो उसकी राय में ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को विवरण यथाविनिर्दिष्ट सीपीई घंटों की अपेक्षाओं को पूरा करने से निवारित करती है।

• सीपीई पोर्टल का नवीकरण और आईसीएआई मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सीपीई क्रियाकलापों का एकीकरण

सीपीई समिति ने, सीपीई क्रियाकलापों के संबंध में सदस्यों को और अधिक बेहतर उपयोक्ता मित्र तथा मोबाइल के अनुरूप कार्यकरण उपलब्ध कराए जाने को सुकर बनाने हेतु अपने सीपीई पोर्टल (www.cpeicai.org) को नवीकृत किया है। “सीपीई कार्यक्रम” के नाम से ज्ञात एक खंड/टैब उपलब्ध कराके सीपीई क्रियाकलापों को “आईसीएआई मोबाइल ऐप” से भी जोड़ा गया है। अब सदस्य, अपनी सुविधा के अनुसार कहीं पर भी और किसी भी समय उपरोक्त सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसकी मुख्य विशिष्टियां निम्नानुसार है :--

• आगामी कार्यक्रमों के व्यौरों के बारे में जानें	• आयोजनों की सुविधा के संबंध में कुंजी शब्दों नगरवार, पीओयूवार, विषयवार ढूंढें
• सीपीई कार्यक्रमों के संबंध में एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना सुविधा सेट करें	• असंरचित पठन क्रियाकलापों के अधीन सीपीई घंटों का दावा करने के लिए आनलाइन व्यौरे प्रस्तुत करें
• अपने सीपीई घंटों के प्रत्यय के बारे में जानें	• सीपीई ई-न्यूज लैटर
• वेबकास्टों को देखें	• पृष्ठभूमि सामग्री देखें

• सीपीई कार्यक्रमों की गुणवत्ता की प्रभावी मानीटरी और आयोजन के लिए सीपीई मार्गदर्शनों का पुनरीक्षण :--

सीपीई कार्यक्रमों की गुणवत्ता की प्रभावी मानीटरी और आयोजन के लिए सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों हेतु संनियमों, मार्गदर्शनों और निदेशों को पुनरीक्षित किया गया था। पूरा विवरण सीपीई पोर्टल पर उपलब्ध है :

• सीपीई कलेंडर

वर्ष 2017-18 के लिए सीपीई कलेंडर को अंतिम रूप प्रदान किया गया था, जिसमें वृत्तिक हित के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 750 से अधिक विषय सम्मिलित थे।

• वैश्विक सत्ता बनना :

सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (पीओयू) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से 14 सीपीई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरों/संगोष्ठियों का आयोजन ताशकंद और सेंट पीटर्सबर्ग (रूस), पराग (केंद्रीय यूरोप), सिंगापुर, क्वालालम्पुर (मलेशिया), थिम्पू (भूटान), पटायी और बैंकाक (थाइलैंड) और बाली (इंडोनेशिया) में किया गया था।

2. ब्रांड और क्षमता निर्माण :

आईसीएआई, अपने सदस्यों को चुनौतियाँ का प्रभावी रूप से सामना करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उन्हें समकालीन ज्ञान और कौशल से लैस करने हेतु सदस्यों के लिए उभरती वृत्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के मद्दे सदैव सक्रिय रहा है। समिति सदस्यों को, उनकी सक्षमता के मूल क्षेत्रों में होने वाली नवीनतम घटनाओं से अद्यतन बनाने और उन्हें वृत्तिक विकास तथा राष्ट्रीय हितों से संबंधित नए और उभरते क्षेत्रों से सुपरिचित कराने के लिए सदस्यों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न पहलें करती रही है। इनमें से कुछ मील के पत्थर निम्नानुसार हैं :

➤ सीपीई राष्ट्रीय लाइव वेबकास्ट

सीपीई समिति द्वारा वृत्ति और राष्ट्रीय हित से संबंधित उभरते विषयों, अर्थात् मुद्रा का विमुद्रीकरण, पर्यावलोकन, आईसीडीएस का लागू होना और उसकी विवक्षाएं तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के अधीन अप्रकटित आय के लिए प्रस्तावित संशोधन विधेयक के संबंध में 3 राष्ट्रीय लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया गया था।

➤ राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण आयोजन

- अप्रैल, 2016 के पश्चात् से सीपीई समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर आदि पर 21 सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था जिनकी मेजबानी देश के भिन्न-भिन्न भागों में आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं द्वारा की गई थी।
- आईसीएआई की सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों द्वारा सदस्यों के लिए देश भर में और विदेशों में वृत्तिक हितों के विभिन्न विषयों पर 9,973 सीपीई कार्यक्रमों का, जिनमें 46,806 सीपीई घंटे समाविष्ट थे, आयोजन किया गया था। उपरोक्त कार्यक्रमों में 9,38,513 सदस्यों ने भाग लिया था और उन्हें 49,92,963 सीपीई घंटे अनुदत्त किए गए थे।
- आईसीएआई की केंद्रीय समितियों के माध्यम से सदस्यों के लिए आईसीएआई के जीएसटी, धन प्रतिशोधन विधियों, धन प्रबंध और वित्तीय योजना, बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा, न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने आदि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों से संबंधित 209 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- आईसीएआई की केंद्रीय समितियों के माध्यम से सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए), बीमा और जोखिम प्रबंध में डिप्लोमा (डीआईआरएम) और अंतर्राष्ट्रीय कराधान आदि संबंधी 114 अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

➤ नई सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (पीओयू) को प्रारंभ करना

सीपीईसी द्वारा मुफसिल/दुरस्थ स्थानों में अवस्थित सदस्यों को उनके निकट स्थानों पर सीपीई क्रियाकलापों में भाग लेने में सहायता करने के लिए 34 और सीपीई पीओयू आरंभ किए गए थे, जिससे भारत और विदेशों में 588 सीपीई पीओयू का एक सुदृढ़ नेटवर्क स्थापित हो गया है।

3. पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति ने 28-29 सितंबर तथा 1 अक्टूबर, 2016 के दौरान पावर फाइनंस कारपोरेशन लिमिटेड के परिसरों में "इंड एएस" विषय पर पीएफसी के पदधारियों के एक घरेलू कार्यपालक विकास कार्यक्रम (आईएचईडीपी) का आयोजन किया था।

4. समाज की सहायता करना – राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता

आईसीएआई, देश के विभिन्न भागों में, सरकार की नई पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन का समर्थन करने के लिए अपने सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों के सुदृढ़ नेटवर्क आधार के माध्यम से निम्नलिखित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है :

- विमुद्रीकरण, काला धन, बेनामी संव्यवहार और अप्रकटित आय संबंधी 367 कार्यक्रम।
- देश के विभिन्न भागों में जीएसटी संबंधी 3001 कार्यक्रम।
- रेरा (भू-संपदा विनियामक अधिनियम) संबंधी 184 कार्यक्रम।
- आईसीडीएस (आय की संगणना और प्रकटन मानक) संबंधी 369 कार्यक्रम।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी 113 कार्यक्रम।
- कंपनी अधिनियम संबंधी 197 कार्यक्रम।
- निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी 14 कार्यक्रम।
- 21 जून को, जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तनाव प्रबंध, जीवन शैली प्रबंध, जहां योग जीवन का सही मार्ग है, कार्य जीवन संतुलन आदि विषयों पर 22 सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन।

- 3 जून, 2016 को, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संबंधी एक उद्घाटन कार्यक्रम जैसा एक बृहत्त आयोजन भी किया गया था।

5. अन्य पहलें

- त्रैमासिक ई-न्यूज लैटर “सीपीई बुलेटिन” को निकाला गया था, जिससे हाल ही की ऐसी पहलों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके, जो समिति द्वारा की गई हैं और उसे सदस्यों, पीओयू और अन्यो की जानकारी के लिए आईसीएआई की वेबसाइट और साथ ही सीपीई पोर्टल पर रखा गया था।
- पुनरीक्षित सीपीई मैनुअल निकाला गया था, जिसमें परिषद् और सीपीई समिति द्वारा समय-समय पर कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (पीओयू) के लिए जारी दिशानिर्देश, संनियम, निदेश आदि अंतर्विष्ट थे, जो सीपीई पोर्टल – www.cpeicai.org पर उपलब्ध हैं।
- सीपीई पीओयू द्वारा नियोजित सीपीई संसाधन व्यक्तियों के राष्ट्रीय डाटाबेस (विषयवार) को अद्यतन किया गया है और सीपीई पीओयू के उपयोग के लिए उनके संपर्क के व्यौरों को भी उसमें सम्मिलित किया गया है और वे सीपीई पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

5.7 निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति

निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति, वृत्ति के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और उसका उद्देश्य सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के साथ एक समुचित निगम व्यवस्था को सुकर बनाना है। समिति नियमित रूप से मार्गदर्शन टिप्पण, पृष्ठभूमि सामग्री, रिपोर्टें, निगम विधियों और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के संबंध में व्याख्या और प्रतिनिर्देशों को तैयार करती है और जारी करती है। समिति, निगम विधियों और उनके अधीन जारी नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं, स्कीमों, अनुसूचियों की वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों की तुलना में समीक्षा करती है और सरकार के संबद्ध मंत्रालयों को उपयुक्त अभ्यावेदन/ सुझाव प्रस्तुत करती है और इस प्रकार विधि बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी करती है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को अभ्यावेदन

क. कंपनी अधिनियम, 2013

समिति, कंपनी अधिनियम, 2013 के सुचारु कार्यान्वयन के लिए नियमिति रूप से कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ परस्पर क्रिया करती है। समिति ने विभिन्न विषयों पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय को लगभग 33 अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे। किए गए महत्वपूर्ण अभ्यावेदनों में से कुछ निम्नलिखित विषयों से संबंधित थे :-

- i. एमसीए-21 आनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण दस्तावेजों को फाइल करने में विलंब के लिए उद्धृत अतिरिक्त फीस, यदि कोई हो, को माफ करना।
- ii. सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी फर्मों के लिए सुगम एगजिट स्कीम/एलएलपी समाधान स्कीम को आरंभ करना।
- iii. संपरीक्षकों द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में रिपोर्ट किए जाने [धारा 143(3)(i)] और समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने [धारा 129(3)] से असूचीबद्ध और प्राइवेट कंपनियों को छूट प्रदान करना।
- iv. किन्हीं आस्ति – मूल्यांकन मानकों का मूल्यांकन करते समय ऐसे मूल्यांकन मानकों के, जिन्हें आईसीएआई द्वारा विरचित किया जाएगा, लागू होने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 17 – रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संबंधी प्रारूप नियमों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 17 के नियम 17.6(iv) के अनुसार मूल्यांकक मानकों को विहित करने हेतु विचार में लिया जा सकेगा।
- v. कंपनी अधिनियम, 2013 के निम्नलिखित अध्यायों के अधीन प्रारूप नियमों के संबंध में तारीख 4 मई, 2016 के अभ्यावेदन :
 - राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी)
 - उत्पीड़न का निवारण और प्रबंध, तथा
 - समझौते, समामेलन और ठहराव

- vi. अनुसचिवीय मानक – 1 (निदेशक बोर्ड की बैठकें) और अनुसचिवीय मानक – 2 (साधारण बैठकें) के प्रारूप संशोधनों के संबंध में तारीख 10 मई, 2016 का अभ्यावेदन।
- vii. एमसीए-21 आनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल में कठिनाई और कंपनी के सृजन में कठिनाई।
- viii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 442 के अनुसार मध्यकों और सुलककारों के रूप में पैलबद्ध होने के लिए विधिक वृत्तिकों और चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु अर्हक अनुभव में अंतर।
- ix. कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ उपबंधों के अधीन प्राह्वेट कंपनियों को आगे और छूटें देने के संबंध में प्रारूप अधिसूचना।
- x. कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत इंडाएएस के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे।

ख. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

वर्ष 2016-17 के दौरान समिति ने, निम्नलिखित विषयों के संबंध में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय को 7 अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे -

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसार दिवाला वृत्तिक के रूप में कार्य करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करना।
- 28 अक्तूबर, 2016 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से संबंधित प्रारूप विनियम।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसार आईसीएआई द्वारा दिवाला वृत्तिक अभिकरण का सृजन।
- दिवाला वृत्तिक अभिकरण के लिए रजिस्टर करने हेतु दस करोड़ रुपए की सकल आवर्त के मानदंड को शिथिल करना।
- नवंबर, 2016 में दिवाला वृत्तिक अभिकरण के शासी बोर्ड की संरचना और उसके पूंजी अभिदाय के संबंध में सुझाव।
- सीमित अवधि रजिस्ट्रीकरण में दिवाला वृत्तिक बनने के लिए पात्रता मानदंड से संबंधित स्पष्टीकरण।
- भारतीय लागत लेखा संस्थान द्वारा विरचित दिवाला वृत्तिक अभिकरण (आईपीए) की वेबसाइट का समान नाम और यूआरएल होने के संबंध में अभ्यावेदन। आईसीडब्ल्यूआई से यह कथन करने का अनुरोध किया गया है कि वह अपने अभिकरण का नाम और अपनी वेबसाइट के यूआरएल में भी परिवर्तन करे ताकि दुविधा से बचा जा सके।

2. बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न :

समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के संबंध में फरवरी, 2017 में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों को जारी किया था।

3. वित्त संबंधी माननीय संसदीय स्थायी समिति के समक्ष कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 की परीक्षा के संबंध में प्रस्तुतिकरण और मौखिक सुनवाई :

- वित्त संबंधी माननीय संसदीय स्थायी समिति ने आईसीएआई को कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 के संबंध में सुझाव देने के लिए अनुरोध किया था। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों से संबंधित मुद्दों और चिंताओं के संबंध में आईसीएआई के सुझावों को वित्त संबंधी माननीय संसदीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय स्थायी समिति ने 3 जून, 2016 को विधेयक की परीक्षा के संबंध में आईसीएआई के विशेषज्ञ विचारों को सुनने का विनिश्चय किया था।
- 30 अगस्त, 2016 को समिति के साथ दूसरी बैठक की गई थी, जहां आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया था।

4. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का क्रियान्वयन

समिति, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 तथा उसके विनियमों का क्रियान्वयन करने के लिए सरकार के साथ निकट रूप से कार्य करती रही है।

5. आईसीएआई के भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान का सृजन

- समिति ने आईसीएआई की ओर से ऐसे दिवाला वृत्तिकों का, जो परिसमापन और शोधन अक्षमता की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, नामांकन करने के लिए एक दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रूप में आईसीएआई के भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई) का सृजन किया था। आईसीएआई आईपीए को संघ के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा 28

नवंबर, 2016 को दिल्ली में भारत के प्रथम दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था।

- दिवाला वृत्तिकों के ऐसे प्रथम सेट को, जिन्होंने 29 और 30 नवंबर, 2016 तक आईसीएआई के आईआईआईपी के साथ नामांकन किया था, 30 नवंबर, 2016 को सचिव, एमसीए द्वारा दिवाला वृत्तिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे।
- भारत के दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अनुसार दिवाला वृत्तिक बनने के लिए सीमित ने दिवाला परीक्षा हेतु तैयारी करने के लिए पठन प्रबंध प्रणाली को जारी किया गया है, जहां दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, कंपनी अधिनियम, 2013, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, भागीदारी अधिनियम, 1932, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, माल का विक्रय अधिनियम, 1930, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनः संरचना प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 जैसे विभिन्न अधिनियमों और (आरबीआई की) निगम ऋण पुनः संरचना स्कीम और दबाव युक्त आस्तियों की व्यवहार्य संरचना संबंधी स्कीम (एस4ए) के आधार पर पीपीटी को तैयार किया गया था। इसके अतिरिक्त, अभ्यास परीक्षा और साथ ही मोक परीक्षा के रूप में अधिनियमों में से प्रत्येक के लिए बहु चयन प्रश्नोत्तर तैयार किए गए थे।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति द्वारा आईसीएआई के सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के संबंध में नवीनतम घटनाओं/परिवर्तनों/संशोधनों से अवगत कराने और उनसे संबंधित जानकारी से लैस करने के लिए एक पहल की है, जिसके अंतर्गत देश भर में परस्पर क्रियाशील बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वेबकास्टों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 आदि से संबंधित अध्ययन जानकारी के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

7. आईसीएडब्ल्यू का आईसीएआई दिवाला वृत्तिक अभिकरण के लिए ज्ञान भागीदार बनना

द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स ने आईसीएआई दिवाला वृत्तिक अभिकरण के लिए ज्ञान भागीदार बनने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

8. मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने आठ वर्ष पूर्व शुरू हुए मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के अब तक कुल 67 बैचों का संचालन किया है। आज की तारीख तक कुल 3400 सदस्यों ने स्वयं को इस पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत किया है।

5.8 प्रत्यक्ष कर समिति

प्रत्यक्ष कर समिति ने विमुद्रीकरण-पश्च परिस्थितियों में और आय घोषणा स्कीम, 2016 के विषय में सरकार की सहायता करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :-

क. आयोजित कार्यक्रम

- आईसीएआई ने आय घोषणा स्कीम, 2016 के संबंध में विभिन्न नागरिकों और सदस्यों संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था। ऐसे कुछ कार्यक्रमों के व्यौरे निम्नानुसार हैं :-
 - 2 जुलाई, 2016 को देश भर में 125 से अधिक स्थानों पर आयोजन, जिसमें 15,000 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया था। माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने सीबीडीटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री अतुलेश जिन्दल की अध्यक्षता में सीबीडीटी के सभी बड़े अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम के दौरान श्रोताओं को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में सुश्री रानी सिंह नायर, तत्कालीन सदस्य (एलएनटी) भी सम्मिलित थी। सुश्री प्रज्ञा सहाय सक्सेना, जेएस (टीपीएल)-1, श्री वी. आनंद राजन, जेएस (टीपीएल)-2, सीए राजेश कुमार भूत, सीआईटी (ए), सीए आनंद कुमार केडिया, सीआईटी ने भी इस अवसर की शोभा बढ़ाई थी और श्रोताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया था।
 - श्री हसमुख अधिया, राजस्व सचिव और सीए नीलेश शिवजी विक्रमसे, तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने पुणे में 2 जुलाई, 2016 को सदस्यों को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक सदस्यों और नागरिकों ने भाग लिया था।

- 10 जुलाई, 2016 को अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम की संघ के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और डा. हसमुख अधिया, राजस्व सचिव, राजस्व विभाग ने गुजरात के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के साथ शोभा बढ़ाई थी, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंटों, अधिवक्ताओं, व्यापार और उद्योग जगत से सदस्यों सहित लगभग 2500 नागरिकों ने भाग लिया था।
- 23 जुलाई, 2016 को बंगलूरु में आयोजित एक कार्यक्रम की संघ के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और डा. हसमुख अधिया, राजस्व सचिव, राजस्व विभाग ने शोभा बढ़ाई थी। इस कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंटों, कंपनी सचिवों, अधिवक्ताओं, व्यापार और उद्योग जगत से सदस्यों सहित लगभग 1500 नागरिकों ने भाग लिया था।
- 1 सितंबर, 2016 को मुंबई में आईसीएआई द्वारा फिक्की के साथ संयुक्त रूप से आईडीएस और स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम के संबंध में एक परस्पर क्रियाशील सत्र का आयोजन किया गया था। इस सत्र को संघ के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और सुश्री रानी सिंह नायर, तत्कालीन अध्यक्ष, सीबीडीटी द्वारा संबोधित किया गया था।

ख. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को अभ्यावेदन

समिति समय-समय पर सीबीडीटी को विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत करती रही है। सीबीडीटी को अभ्यावेदित विषयों में से कुछ इस प्रकार हैं :

- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 276ख के मद्दे कर कटौतीकर्ताओं के समक्ष आने वाली कठिनाई के संबंध में, जिसके कारण केंद्रीय सरकार के प्रत्यय में कर जमा करने में विलंब के लिए अभियोजन कार्यवाहियां की जा सकती हैं।
- प्ररूप सं. 3गघ में संशोधन।
- ऐसी अपीलों को, जिन्हें 1.3.2016 से 15.05.2016 की अवधि के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल नहीं किया गया था, अपितु जिन्हें आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 249 के अधीन विहित समयावधि के भीतर वैयक्तिक रूप से फाइल किया गया था, सीआईटी (अपील) द्वारा नामंजूर न किए जाने।
- आईसीडीएस और आय-कर अधिनियम के सरलीकरण से संबंधित अन्य उपायों के संबंध में आईसीएआई के प्रारंभिक विचारों/मुद्दों / सुझावों को न्यायमूर्ति ईश्वर समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने।
- मुक्त डिजिटल अनुभव उपलब्ध कराने के लिए, फार्म सं. 60 को डिजिटल रूप से स्वीकार किए जाने को, अधिमानी रूप से आधार आधारित ई-अधिप्रमाणन पर अनुज्ञात किए जाने।
- धारा 143(2) में संशोधन और उसके परिणामस्वरूप अधिसूचना सं. 105/2016, तारीख 16.11.16 को जारी किए जाने और ऐसे संशोधन को प्रभावी किए जाने से पूर्व उपयुक्त जांच प्रक्रिया को स्थापित करने।
- आनलाइन रूप से नकदी जमा करने की पुष्टि करने हेतु विमुद्रीकरण के पश्चात् प्राप्त हुए ई-मेल/एसएमएस के कारण निर्धारितियों के समक्ष आने वाले वास्तविक मुद्दों को स्पष्ट करने हेतु बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए जाने और प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय का विस्तार किए जाने।
- धारा 269धम के उपबंधों के लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए जाने। यद्यपि, किसी बैंक, सहकारी बैंक या किसी डाकघर बचत बैंक से दो लाख रुपए से अधिक नकदी को निकाले जाने से संबंधित एक अधिसूचना सीबीडीटी द्वारा जारी की गई थी, फिर भी निर्धारितियों के समक्ष कतिपय अन्य चिंताएं उत्पन्न हो रही थीं, जिनका नीचे कथन किया गया है और जिनके बारे में उक्त अभ्यावेदन के द्वारा विचार व्यक्त किए गए थे :
 - “किसी एक घटना या अवसर से संबंधित संव्यवहार” पद के संबंध में स्पष्टीकरण।
 - निर्धारितियों के समक्ष आने वाली वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए नियम 6घघ के अनुरूप अपवाद।
 - बैंककारी चैनलों, जिसके अंतर्गत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई-वालेट भी हैं, के माध्यम से किए गए संदायों को एक स्पष्टीकरण जारी करके अनुमति प्रदान करने।
- धारा 271ज के अधीन प्रस्तावित शास्ति को वापस लिए जाने का अनुरोध करने। सीबीडीटी के अध्यक्ष, राजस्व सचिव और माननीय वित्त मंत्री के साथ विभिन्न बैठकें भी की गई थी, जिनमें संभावी कठिनाईयों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई थी। चूंकि धारा 271ज के उपबंधों को अधिनियमित कर दिया गया है, इसलिए आईसीएआई ने यह अनुरोध किया है कि अंतःस्थापित धारा 271ज के कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सामने आने वाली वास्तविक कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रशासनिक अनुदेश, दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

- एसएफटी को प्रस्तुत करने के प्रथम अनुपालन के कारण उदभूत होने वाली कठिन समस्याओं पर विचार करते हुए और साथ ही कतिपय मुद्दों पर मार्गदर्शन/स्पष्टता की कमी को ध्यान में रखते हुए, प्ररूप 61क में वित्तीय संव्यवहारों का विवरण (एसएफटी) प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 31 मई, 2017 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2017 करने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था।
- वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से धारा 56(2)(भ) और 50गक को अंतःस्थापित किए जाने के कारण उदभूत होने वाले, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2)(भ) और धारा 50गक के प्रयोजनों के लिए कोट न किए गए साम्या शेयरों के मूल्यांकन के संबंध में प्रारूप संशोधन नियमों के संबंध में अंतःनिवेश उपलब्ध कराना।
- तारीख 13 जून, 2017 के एक अभ्यावेदन द्वारा अध्यक्ष, सीबीडीटी को, भू-संपदा संव्यवहारों से संबंधित प्रारूप आईसीडीएस के संबंध में अंतःनिवेश उपलब्ध कराए गए थे।

ग. मंत्रालय/सीबीडीटी के साथ बैठकें

- सरकार द्वारा संस्थान आईसीएआई की पूरे भारत वर्ष में फैली उसकी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से आय घोषणा स्कीम (आईडीएस), 2016 के संबंध में जागरूकता का सृजन करने के लिए उसके सहयोग मांगे जाने के संबंध में, तत्कालीन माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण के साथ 07.06.2016 को नई दिल्ली में एक बैठक की गई थी।
- टीडीएस/टीसीएस से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 20.09.2016 को टीडीएस संबंधी स्थायी समिति के साथ बैठक की गई थी। उपाध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति ने उक्त बैठक में भाग लिया था।
- बजट 2017 के संबंध में आईसीएआई द्वारा की गई सिफारिशों के सार की रूपरेखा तैयार करने के लिए 7 नवंबर, 2016 को एक बजट-पूर्व बैठक का आयोजन किया गया था। इस बजट-पूर्व बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष, सीबीडीटी द्वारा की गई थी और इसमें आईसीएआई के अन्य प्रतिनिधियों के साथ अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति ने भी भाग लिया था। उक्त बैठक के दौरान वित्त मंत्रालय को बजट-पूर्व ज्ञापन, 2017 प्रस्तुत किया गया था। प्रारंभिक सुझावों के संबंध में एक पावर पाइंट प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया गया था।
- 03.05.2017 को उपाध्यक्ष, आईसीएआई, अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति, अध्यक्ष, आईसीएआई की अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति ने अध्यक्ष, सीबीडीटी के साथ एक बैठक की थी। उक्त बैठक में अध्यक्ष, सीबीडीटी के साथ निम्नलिखित विषयों पर ब्यौरेवार चर्चा की गई थी :
 - धारा 271ज के समुचित प्रशासन के लिए सीबीडीटी द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्टें या प्रमाणपत्रों में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धारा 271ज के अधीन शास्ति के उद्ग्रहण के लिए प्रारूप दिशानिर्देश।
 - असम और मेघालय के निवासी निर्धारितियों को धारा 139कक(3) के अधीन छूट प्रदान करने का अनुरोध करने वाला अभ्यावेदन।
 - 'हिन्दुस्तान' समाचार-पत्र के हिन्दी संस्करण में प्रकाशित समाचार में रिपोर्ट किए गए अनुसार कपटपूर्ण व्यवहारों में संलिप्त 17500 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंटों, जिन्होंने कपटपूर्ण व्यवहार करके वृत्ति की छवि को कलंकित किया है, की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध करने वाला पत्र, जिससे आईसीएआई द्वारा इन सदस्यों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। अनुवर्ती कार्रवाईयों के बावजूद भी समाचार-पत्र या सीबीडीटी से ऐसी कोई सूची अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

घ. संघीय बजट से संबंधित क्रियाकलाप

क) समिति ने, अप्रत्यक्ष कर समिति और अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से 1 फरवरी, 2017 को संघीय बजट, 2017 में अंतर्वर्तित कर प्रस्तावों के संबंध में एक 'लाइव वेबकास्ट' का आयोजन किया था, जिसमें विशेषज्ञों ने विस्तार से बजट प्रस्तावों पर परिचर्चा की थी। लगभग 2500 सदस्यों ने इस वेबकास्ट को देखा था।

ख) 2 फरवरी, 2017 को संघीय बजट, 2017 के संबंध में आईसीएआई की सभा

2 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में संघीय बजट, 2017 में अंतर्वर्तित विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के संबंध में परिचर्चा करने के लिए संघीय बजट, 2017 संबंधी आईसीएआई की एक सभा का आयोजन किया गया था। इस विशेष तकनीकी सत्र के दौरान श्री संतोष कुमार गंगवार, संघ के माननीय राज्य वित्त मंत्री ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई थी तथा श्री हसमुख अधिया, माननीय राजस्व सचिव, श्री सुशील चंद्रा, अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और श्री राम तीरथ, सदस्य (बजट

और जीएसटी), केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई थी। श्री संतोष कुमार गंगवार, संघ के माननीय राज्य वित्त मंत्री तथा श्री हंसमुख अधिया, माननीय राजस्व सचिव ने आईडीएस स्कीम को सफल बनाने के लिए आईसीएआई के द्वारा किए गए प्रयासों और उसके द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के प्रशासन और संग्रहण में दिए जाने वाले उसके सतत समर्थन के लिए उसकी सराहना की थी। बजट वार्ता सत्र के दौरान सीए वेद जैन, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए. (डा.) गिरिश आहूजा, सीए. अशोक बत्रा और सीए. जे.के. मित्तल ने सदस्यों को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम का भी लाइव वेबकास्ट किया गया था। लगभग 1000 सदस्यों ने भौतिक रूप से उपस्थित होकर और 5000 से अधिक सदस्यों ने वेबकास्ट के माध्यम से पूरे विश्व में इस कार्यक्रम में भाग लिया था/ को देखा था।

ग) बजट-पश्च ज्ञापन, 2017 को प्रस्तुत करना

1 फरवरी, 2017 को, माननीय वित्त मंत्री द्वारा संसद् के संघीय बजट 2017-18 को प्रस्तुत किए जाने के अनुसरण में, बजट, 2017 के प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से उद्भूत होने वाले मुद्दों के संबंध में सुझावों को समेकित करने के लिए उपाय किए गए थे। बजट-पश्च ज्ञापन में सम्मिलित किए जाने के लिए प्राप्त सुझावों पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् 27.02.2017 को अध्यक्ष, आईसीएआई के हस्ताक्षर के अधीन वित्त मंत्रालय को बजट-पश्च ज्ञापन, 2017 प्रस्तुत किया गया था।

ड. अन्य पहलें

➤ 1 सितंबर, 2016 को “ई-फाइलिंग-कर संपरीक्षा रिपोर्टें और विवरणियां” विषय पर एक लाइव वेबकास्ट

समिति ने 1 सितंबर, 2016 को “ई-फाइलिंग-कर संपरीक्षा रिपोर्टें और विवरणियां” विषय पर एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया था। अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति, आईसीएआई ने आईसीएआई के प्रतिनिधि के रूप में इस वेबकास्ट का संचालन किया था। सदस्यों को “ई-फाइलिंग-कर संपरीक्षा रिपोर्टें और विवरणियों” के संबंध में अंतःनिवेश उपलब्ध कराने के अतिरिक्त श्री रमेश कृष्णामूर्ति, अपर डीजीआईटी (प्रणाली) ने सदस्यों को आय-कर विभाग द्वारा की गई निम्नलिखित ई-पहलों के संबंध में भी अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई थी :

- ई-फाइलिंग वॉल्ट और इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) – करदाता सेवाओं को मजबूत करने के लिए हाल ही में की गई पहलें
- ई-निर्धारण – करदाताओं और आय-कर विभाग के बीच ई-संसूचना हेतु
- ई-निवारण – आय-कर विभाग द्वारा आरंभ की गई विशेष ई-शिकायत समाधान प्रणाली
- ई-सहयोग – करदाताओं से आय-कर कार्यालय में उपस्थित होने की अपेक्षा किए बिना आय-कर विवरणियों में मेल न खाने वाली किसी प्रविष्टि का समाधान करने के लिए आनलाइन तंत्र
- ई-टीडीएस – टीडीएस विवरणियों की आनलाइन फाइलिंग

➤ प्रत्यक्ष कर समिति का ई-न्यूज लैटर

समिति ने अपने ई-न्यूज लैटर का प्रथम संस्करण निकाला था। इस ई-न्यूज लैटर में आय घोषणा स्कीम, 2016 के संबंध में परिपत्रों के साथ सीबीडीटी द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचनाओं और प्रैस विज्ञप्तियों को भी सम्मिलित किया गया था और साथ ही उसमें एफएक्यू, आईसीडीएस के आस्थगन संबंधी उद्घोषणा आदि भी अंतर्विष्ट थे। इस ई-न्यूज लैटर को वेबसाइट <http://resource.cdn.icai.org/42951dtc32707main.pdf> पर रखा गया है।

➤ साफा देशों में राजकोषीय और टैरिफ विधियों के तुलनात्मक पुनर्विलोकन के संबंध में अंतःनिवेश प्रस्तुत करना :

समिति को साफा से यह अनुरोध प्राप्त हुआ था कि वह साफा देशों में राजकोषीय और टैरिफ विधियों के तुलनात्मक पुनर्विलोकन के संबंध में भारत से संबंधित जानकारी का पुनर्विलोकन और उसे अद्यतन करे। तदनुसार, वांछित समय-सीमा के भीतर साफा अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई थी।

➤ कारबार करने की सुगमता – करों के संदाय से संबंधित प्रश्नोत्तर –विश्व बैंक रिपोर्ट – सर्वेक्षण

24.03.2017 को उपाध्यक्ष, आईसीएआई और अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा वैशाली, गाजियाबाद में अपर डीजीआईटी (प्रणाली) के साथ एक बैठक की गई थी। यह सूचित किया गया था कि विश्व बैंक ‘कारबार करने’ के संबंध में एक सर्वेक्षण कर रहा था। ‘कारबार करने’ संबंधी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह का एक प्रमुख प्रकाशन है और इसे विश्व भर की सरकारों द्वारा बड़ी

दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाता है। तदनुसार, विभाग ने यह अनुरोध किया था कि सदस्य विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्नोत्तरों को फाइल करके सर्वेक्षण में भाग लें।

च. संगोष्ठियां/सम्मेलन/कर जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं

समिति ने इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष करें से संबंधित विषयों पर देश भर में 22 संगोष्ठियों/सम्मेलनों/ वेबकास्टों/व्याख्यान बैठकों आदि का आयोजन किया था।

5.9 आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. तथा आर्थिक सलाह संबंधी समिति

भारत-अफ्रीका भागीदारी : आईसीएआई की अफ्रीकी महाद्वीप राष्ट्रों के राजदूतों/ उच्चायुक्तों के साथ सभा और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग शिखर सम्मेलन : विभिन्न उपयोक्ता समूहों के बीच एक अंतरापृष्ठ उपलब्ध कराने के लिए और भारत तथा अफ्रीकी राष्ट्रों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. संबंधी समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति के साथ संयुक्त रूप से 8 अगस्त, 2016 को नई दिल्ली में, भारत में अफ्रीकी दूतावासों के राजदूतों/उच्चायुक्तों तथा अफ्रीका में विकासात्मक हित रखने वाले पणधारियों के साथ इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ, दोनों पक्षों की ओर से दो राष्ट्रों के बीच व्यापार और उद्योग, कारबार करने के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग, लेखांकन, संपरीक्षा, निगम वित्त और संबद्ध क्षेत्रों में सक्षमता निर्माण के लिए ज्ञान और संसाधनों के परस्पर आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, लेखांकन वृत्ति और निगम क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई थी।

विभिन्न शासकीय प्राधिकरणों/विनियामकों को अभ्यावेदन : समिति ने माध्यस्थम्, मध्यकता और सुलह संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की मान्यता और आईसीएआई द्वारा रखे गए मध्यस्थों के पैनल को भारत सरकार द्वारा रखे गए मध्यकों या सुलहकारों के पैनल के साथ समझे गए चार्टर्ड अकाउंटेंटों के रूप में पैनलबद्ध करने, चार्टर्ड अकाउंटेंटों को व्यापार चिह्न नियम, 2002 के नियम 150 के अधीन अनुज्ञात करने ; “शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व में अभिवृद्धि” के विषय में किए गए प्रारंभिक अध्ययन को लोकप्रिय बनाने, विदेशी व्यापार नीति, 2015-20 के मध्यावधि पुनर्विलोकन के संबंध में अंतःनिवेश उपलब्ध कराने, भारत-पेरू, भारत-श्रीलंका के बीच चले रहे अंतर-मंत्रालयीय पणधारी परामर्श प्रक्रिया में माल, सेवाओं और निवेशों के क्षेत्र में व्यापार करारों में सेवा बातचीत की भारतीय वांछा-सूची को तैयार करने में अंतःनिवेश उपलब्ध कराने, महाराष्ट्र भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा सरकार के नियंत्रणाधीन विकास प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों के वित्त विभागों के अध्यक्षों को मान्यता प्रदान करने हेतु जारी तारीख 31.05.2017 के परिपत्र सं. 2/2017 के संबंध में अभ्यावेदन आदि के लिए संबद्ध प्राधिकरणों को विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे।

अध्ययन समूह : एफडीआई और संबद्ध विधियों तथा आरईआरडीए सहित फेमा के संबंध में विद्यमान प्रकाशनों को पुनरीक्षित करने ; प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों/ नौसिखिया कार्यशालाओं/वेबकास्ट/शैक्षणिक पहलों/संबद्ध क्षेत्रों में प्रकाशनों को जारी करने की संभाव्यता/साध्यता का पता लगाने के लिए विभिन्न अध्ययन समूहों का गठन किया गया था।

कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सम्मेलन/वेबकास्ट : फेमा, आईपीआर विधियों, रेरा, व्यवसाय के गैर-पारंपरिक क्षेत्रों आदि जैसे समकालीन विषयों के संबंध में चार वेबकास्टों, तीन सम्मेलनों और दो कार्यशालाओं का आयोजन करके सदस्यों की बीच जागरूकता का सृजन किया गया था।

पुनरीक्षित पृष्ठभूमि सामग्री : माध्यस्थम्, मध्यकता और सुलह संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए पुनरीक्षित पृष्ठभूमि सामग्री को जारी किया गया था, जिससे सदस्यों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

धन शोधन निवारण विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : विभिन्न क्षेत्रों में काले धन के सृजन को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों और पहलों को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में सरकार के साथ निकट रूप से कार्य करने और सरकार को धन शोधन निवारण के उद्देश्य की पूर्ति में सहायता करने के विचार से, समिति ने आईसीएआई के सदस्यों को इस क्षेत्र में सुसज्जित करने के उद्देश्य से धन शोधन निवारण विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धन शोधन निवारण विशेषज्ञ) को आरंभ किया था और उसकी रुपरेखा के अनुसार धन शोधन निवारण विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दूसरे बैच का संचालन किया था। इस मूल्यांकन परीक्षा हेतु 42 सदस्य उपस्थित हुए थे और उन्होंने उसे अर्हित किया था।

माध्यस्थम्, मध्यकता और सुलह संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

माध्यस्थम् और उससे संबंधित विषयों के संबंध में गठित समूह की सिफारिशों के अनुसार माध्यस्थम्, मध्यकता और सुलह संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए यथा पुनरीक्षित और अद्यतन पृष्ठभूमि सामग्री को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था।

व्यापक सिद्धांतमक पहलूओं के अलावा, इस पृष्ठभूमि सामग्री में बहु मामला अध्ययनों के साथ व्यवहारिक और प्रक्रियात्मक पहलू भी अंतर्विष्ट हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 442 के अधीन सितंबर, 2016 में अधिसूचित नियमों में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए मध्यकता और सुलह से संबंधित पृथक् अध्याय अंतर्विष्ट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, माध्यस्थम् के लिए कानूनी उपबंधों और प्रक्रियाओं को माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित) के उपबंधों, उनसे संबंधित परिचर्चाओं और मामला विधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से संबंधित सामग्रियों, प्रमुख माध्यस्थम् संस्थाओं – घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय की सूची और लैटिन भाषा की विधिक शब्दावली को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

आईटीएल और डब्ल्यूटीओ संबंधी अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम की पुनः संरचना

समिति ने परिषद् के अनुमोदन से भाग 2 को समाप्त करते हुए, स्कीम को पुनरीक्षित किया है और केवल भाग 1 के पूरा किए जाने पर, पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने संबंधी प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उपबंध किया है।

5.10 नैतिक मानक बोर्ड

आईसीएआई की परिषद् ने, सदस्यों के लिए नैतिक मानकों को स्थापित करने और दिशानिर्देश जारी करने के लिए दिसंबर, 1975 में नैतिक मानक समिति (जो अब नैतिक मानक बोर्ड के रूप में ज्ञात है) का गठन किया था।

बोर्ड का मिशन, उत्कृष्टता, स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा के दीर्घकालिक नैतिक आदर्शों को अक्षुण्ण रखते हुए और साथ ही सदस्यों के सम्मान और हितों की संरक्षा करने के लिए तथा सदस्यों हेतु एक क्रियाशील और समकालीन नैतिक संहिता और नैतिक व्यवहार को तैयार करने के प्रति कार्य करना है।

नैतिक संहिता को अद्यतन बनाने के अलावा बोर्ड के अन्य प्रकाशनों में 'नैतिकता संबंधी मुद्दों पर एफ.ए.क्यू.' और 'संपरीक्षकों की स्वतंत्रता पर मार्गदर्शन टिप्पण', सम्मिलित हैं। बोर्ड सदस्यों के लिए मूलभूत सिद्धांतों, जैसे सत्यनिष्ठा, विषय निष्ठता, सक्षमता और व्यावसायिकता में जन चेतना और विश्वास को प्रोत्साहित करता है। यह वृत्ति के सदस्यों को, उनके समक्ष दिन-प्रतिदिन की परिस्थितियों में आने वाली दुविधाओं के संबंध में सलाह देता है। सदस्य नैतिक सहायता पटल, ई सहायता और ईएसबी पोर्टल, अर्थात् esb.icaai.org के माध्यम से हमारे तक पहुंच बना सकते हैं।

क्रियाकलाप/पहलें

1. बोर्ड ने परिषद् को – आईईएसबीए (लेखपालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानक बोर्ड) नैतिक संहिता, 2017 के नवीनतम संस्करण के उपबंधों, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा अन्य घटनाओं के आलोक में नैतिक संहिता के पुनरीक्षण की सिफारिश की है। ये सिफारिशें परिषद् के विचाराधीन हैं।
2. बोर्ड ने आईसीएआई के निर्वाचित, सहयोजित और नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों के लिए भी आचार-संहिता जारी की है, जो 1.1.2017 से प्रभावी है।
3. सदस्यों के लिए "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी) संनियम, जो सभी अधिप्रमाणन कृत्यों के लिए आज्ञापक हैं, को 1.1.2017 से प्रभावी बनाया गया है। इससे पूर्व, ये संनियम सिफारिशात्मक प्रकृति के थे। आज्ञापक और पुनरीक्षित संनियम धन शोधन निवारण की दशा में एक बड़ा कदम है।
4. व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा कोचिंग/अध्यापन क्रियाकलापों के विज्ञापन के प्रतिषेध संबंधी 18.05.2017 की उदघोषणा जारी की है।

5.11 विशेषज्ञ सलाहकार समिति

लेखांकन कारबार की भाषा है, जिसका उपयोग वित्तीय कार्यों के संबंध में उसके शेयर धारकों, संभावी निवेशकों, ग्राहकों और शासकीय विनियामकों सहित विभिन्न पणधारियों से संसूचना के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। वित्तीय रिपोर्टों को तैयार और प्रस्तुत करते समय लेखांकन वृत्तिकों के समक्ष बहुधा ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जहां किसी विशिष्ट परिस्थिति/संव्यवहारों के संबंध में लेखांकन सिद्धांतों को लागू और क्रियान्वित करने में विभिन्न कठिनाईयां उदभूत होती हैं। आईसीएआई के सदस्यों को ऐसी विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों को लागू और क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान करने हेतु, आईसीएआई की परिषद् ने वर्ष 1975 में विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया था, जो इस प्रयोजन के लिए विरचित सलाहकार सेवा नियमों के अनुसार उसके सदस्यों से प्राप्त होने वाली शंकाओं का उत्तर देती है। ये नियम आईसीएआई की वेबसाइट पर हाइपर लिंक

[http://www.icaai.org/new_category.html?c_id=142] के अधीन उपलब्ध हैं।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा दी गई रायों को, शंका के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों, सुसंगत विधिक स्थिति और उस तारीख को विद्यमान आईसीएआई के लेखांकन/संपरीक्षा मानकों, मार्गदर्शक टिप्पणों और किन्हीं अन्य उद्घोषणाओं के आधार पर तैयार किया जाता है और उन्हीं आधारों पर समिति द्वारा विशिष्ट राय को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। राय को अंतिम रूप प्रदान किए जाने की तारीख को प्रत्येक राय के साथ उपदर्शित किया जाता है।

समिति, विभिन्न लेखांकन/संपरीक्षा संबंधी मुद्दों के संबंध में उद्योग, व्यवसाय में लगे उसके सदस्यों और साथ ही विनियामक और शासकीय प्राधिकरणों जैसे कि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय आदि को स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ राय प्रदान करके निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करती रही है। 1.4.2016 से 30.06.2017 की अवधि के दौरान, समिति ने आईसीएआई के सदस्यों से प्राप्त प्रश्नों पर 28 रायों को और विनियामकों/शासकीय प्राधिकारियों से प्राप्त विभिन्न लेखांकन संबंधी मुद्दों पर 5 रायों को अंतिम रूप दिया था। इस अवधि के दौरान, समिति ने 20 दिसंबर, 2016 को अपनी 200वीं बैठक का भी आयोजन किया था। समिति के लिए यह एक मील का पत्थर आयोजन था, इसलिए आईसीएआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने इस अवसर पर सदस्यों को संबोधित किया था। समिति को स्थापित किए जाने की तारीख से उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को अंतर्विष्ट करने वाला एक ब्राशर भी जारी किया गया था।

समिति द्वारा जारी सभी रायों को राय सारसंग्रह में भी प्रकाशित किया जाता है। अब तक सारसंग्रह की 35 जिल्दों को विक्रय हेतु जारी किया जा चुका है। सभी रायों के सारसंग्रह की सभी 35 जिल्दों में अंतर्विष्ट लगभग 1400 रायों को सम्मिलित करने वाली एक सीडी को, जिसमें वांछित विषय (विषयों) के संबंध में रायों का पता लगाने और/या किसी विशिष्ट अवधि के दौरान जारी की गई रायों को खोजने के लिए आधुनिक और प्रयोक्ता अनुकूल लक्षण सम्मिलित किए गए हैं, भी जारी किया गया है, जो रायों के सारसंग्रह की जिल्द 35 के साथ उपलब्ध है।

समिति द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई कुछ राय, जिनमें व्यापक वृत्तिक हित अंतर्विलित होता है, आईसीएआई के जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के प्रत्येक अंक में प्रकाशित की जाती हैं। समिति की हाल ही की राय को आईसीएआई की वेबसाइट पर समिति के ज्ञान आदान-प्रदान संबंधी पृष्ठ पर भी रखा जाता है।

5.12 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड

वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी), देश में वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों में सुधार लाने के अपने प्रयासों के भागरूप में विभिन्न उद्यमों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करता है। बोर्ड का उद्देश्य उत्तम वित्तीय रिपोर्टिंग की परिस्थितियों को बनाए रखना और साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तम शासन में पारदर्शिता का संवर्धन करना भी है, जो संपरीक्षित वित्तीय विवरणों में निवेशकों के विश्वास के संवर्धन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड विभिन्न विनियामकों, अर्थात् भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की अर्हित संपरीक्षा रिपोर्ट पुनर्विलोकन समिति (क्यूएआरसी) का भी सूचीबद्ध उद्यमों की महत्वपूर्ण संपरीक्षा अर्हताओं के पुनर्विलोकन में और भारत निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं के पुनर्विलोकन में सहायता करता है और साथ ही समय-समय पर विनियामकों द्वारा उसे विनिर्दिष्ट अन्य मामलों का भी पुनर्विलोकन करता है।

बोर्ड स्व:विवेकानुसार चयन के आधार पर या विनियामक द्वारा निर्दिष्ट मामलों या ऐसे मामलों में जहां मीडिया में गंभीर लेखांकन संबंधी अनियमितताओं को रिपोर्ट किया गया है, चुने गए विभिन्न उद्यमों के वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन करता है। इसे एक प्रभावी तंत्र के रूप में मानते हुए परिषद् द्वारा बोर्ड को इस बात के लिए सशक्त किया गया है कि वह उद्यमों के संपरीक्षकों से ऐसी जानकारी मांग सकता है, जिसके संदर्भ में मीडिया और/या विनियामक द्वारा गंभीर लेखांकन और/या संपरीक्षा संबंधी अनियमितताओं को विशिष्ट रूप से दर्शित/निर्दिष्ट किया गया है।

किए गए पुनर्विलोकन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड ने स्व:विवेक के अनुसार या विशेष रूप से चुने गए 95 मामलों का पुनर्विलोकन पूरा किया है इसकी तुलना में पिछले वर्ष की संख्या में 65 मामले थे। इनमें ऐसे बड़े निगमों के वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन सम्मिलित है, जहां मीडिया द्वारा वित्तीय अनियमितताओं को रिपोर्ट किया गया था।

समाज के प्रति योगदान – राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता

बोर्ड भारत में विद्यमान वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी व्यवहारों में सुधार करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। विनियामक, उसके द्वारा विभिन्न समनुदेशनों को पूरा करने के अनुरोध के साथ उससे संपर्क कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के भागीदार के रूप में बोर्ड द्वारा

निष्पादित महत्वपूर्ण समनुदेशन निम्नानुसार हैं :

- भारत निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर, बोर्ड ने विभिन्न राजनैतिक दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन किया है। इस वर्ष भी आयोग ने बोर्ड से यह अनुरोध किया था कि वह कम से कम छह ऐसे राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन करे, जो मान्यताप्राप्त दल हैं और जिनकी आय/व्यय 10 करोड़ रुपए से अधिक है। तदनुसार, बोर्ड ने राजनैतिक दलों के 33 वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन किया था और उसने उन सभी मामलों पर विचार किया था।
- सेबी ने आईसीएआई से यह अनुरोध किया था कि वह ऐसे अस्तित्वों का, जो अप्राधिकृत संग्रहणात्मक निवेश स्कीमें चला रहे हैं, पता लगाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करने हेतु अध्ययन प्रारंभ करे, जिससे एमसीए को निवारक कार्रवाई करने में सहायता प्राप्त हो सके। बोर्ड ने इस संबंध में सेबी के साथ एक वार्ता की थी जिसके आधार पर बोर्ड ने सेबी से प्राप्त हुए 50 मामलों से संबंधित जानकारी का प्रारंभिक पुनर्विलोकन किया था। बोर्ड, उक्त अध्ययन के लिए सेबी से आगे और जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रक्रिया कर रहा है।

वित्तीय रिपोर्टिंग संव्यवहारों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम

बोर्ड ने पुनर्विलोकन कौशलों के संबंध में सदस्यों के ज्ञान में अभिवृद्धि करने और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में उन्हें अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आईसीएआई की विभिन्न शाखाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग संव्यवहारों के संबंध में 3 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिसमें 197 सदस्यों ने भाग लिया था।

5.13 अप्रत्यक्ष कर समिति

अप्रत्यक्ष कर समिति ने जीएसटी के कार्यान्वयन को सुकर बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके द्वारा किए गए क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :--

1. समिति ने सरकार को निम्नलिखित अंतःनिवेश/सुझाव प्रस्तुत किए हैं :

- (i) आदर्श जीएसटी विधि, पुनरीक्षित आदर्श जीएसटी विधि, जीएसटी अधिनियम और जीएसटी प्रारूप नियमों के संबंध में सुझाव।
- (ii) राज्य वित्त मंत्री की सशक्त समिति के समक्ष “संक्रमणाकालीन मुद्दे और आईजीएसटी” विषय पर प्रस्तुतिकरण।
- (iii) सीबीईसी और राज्य वित्त मंत्री की सशक्त समिति के समक्ष “जीएसटी संबंधी नीति विषयक मुद्दे, जिसके अंतर्गत समतुल्य सिद्धांत को कार्य योग्य बनाना भी है” विषय पर प्रस्तुतिकरण।
- (iv) जीएसटी के प्रशासनिक मुद्दों के समाधान के लिए तंत्र – आईसीएआई ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जीएसटी के प्रशासन के लिए पैर आधारित तंत्र का सुझाव दिया था।
- (v) दिल्ली सरकार को दिल्ली में वित्त और अर्थव्यवस्था पर जीएसटी व्यवस्था के प्रभाव संबंधी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना।
- (vi) अप्रत्यक्ष करों के संबंध में इंड एएस के प्रभाव पर आरंभिक अध्ययन रिपोर्ट।
- (vii) उत्पाद-शुल्क विवरणी और वित्तीय विवरण की तुलना में सेवाकर के बीच वार्षिक विवरणी-सह-मुलह विवरण का आरंभिक प्रारूप प्रारूप।
- (viii) अप्रत्यक्ष करों के संबंध में बजट पूर्व और पश्च ज्ञापन, 2017।
- (ix) जीएसटीएन से प्राप्त हुए अनुरोध के आधार पर माल और सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) के संदर्भ में निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराई गई है :
 - क. आईसीएआई के सदस्यों से आईटी फर्मों की सूची एकत्रित की गई थी और उसे प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए जीएसटीएन को उपलब्ध कराया गया था, जिससे आईटी फर्मों जीएसटी के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन कर सकें।
 - ख. जीएसटीएन द्वारा आनलाइन विधिमान्यकरण के लिए आईसीएआई के सदस्यों के वेब आधारित डाटा का आदान-प्रदान।
 - ग. जीएसटीएन द्वारा विकसित जीएसटी के साफ्टवेयर माड्यूल के संबंध में प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करना।

2. सरकार को अभ्यावेदन :

- (i) जीएसटी के अधीन वित्तीय अभिलेख की संपरीक्षा को करने के लिए अनन्य रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंटों को अनुज्ञात करने हेतु ।
- (ii) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 72क के अधीन सेवाकर संबंधी संपरीक्षाओं की संपरीक्षा फीस के पुनरीक्षण हेतु ।
- (iii) आनलाइन सेवाकर विवरणी को फाइल करने की अंतिम तारीख को, जो 25 अप्रैल, 2017 थी, विस्तारित करना ।
- (iv) आयुक्त, वाणिज्यिक कर, दिल्ली को, धारा 58क के अधीन विशेष संपरीक्षा करने के लिए संपरीक्षक के रूप में पैनलबद्ध होने हेतु विक्रय कर विधिज्ञ संगम का सदस्य होने की शर्त को हटाने हेतु ।

3. प्रकाशन - अनुसंधान संबंधी पहलें : समिति ने जीएसटी/सेवाकर/उत्पाद-शुल्क के संबंध में निम्नलिखित नए/पुनरीक्षित प्रकाशन निकाले थे :

- (i) जीएसटी मॉडल विधि संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री
- (ii) पुनरीक्षित मॉडल जीएसटी विधि संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री
- (iii) जीएसटी अधिनियम और प्रारूप नियम, 2017 संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री
- (iv) पुनरीक्षित मॉडल जीएसटी विधि संबंधी बेयर विधि
- (v) जीएसटी अधिनियम और प्रारूप नियम (नियमों) संबंधी बेयर विधि
- (vi) विनिर्माताओं के लिए सरलीकृत जीएसटी गाइड
- (vii) जीएसटी के अधीन ई-वाणिज्य के कराधान संबंधी अध्ययन पत्र
- (viii) पुनरीक्षित मॉडल जीएसटी विधि संबंधी एफएक्यू और एमसीक्यू
- (ix) जीएसटी संबंधी एफएक्यू और एमसीक्यू
- (x) अनुचित समृद्धि अध्ययन पत्र
- (xi) मुकदमा प्रबंध संबंधी पाठ्यक्रम के लिए पृष्ठभूमि सामग्री
- (xii) सीमाशुल्क और एफटीपी संबंधी पाठ्यक्रम के लिए पृष्ठभूमि सामग्री
- (xiii) सेवाकर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए पृष्ठभूमि सामग्री
- (xiv) सेनवेट प्रत्यय संबंधी तकनीकी गाइड
- (xv) समर्थकारी सेवाकर व्यवहार संबंधी कार्यक्रम के लिए पृष्ठभूमि सामग्री
- (xvi) सीबीईसी पद्धतारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री
- (xvii) अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों संबंधी हैंडबुक

4. ई-पहलें

- (i) **जीएसटी संबंधी वीडियो व्याख्यान :** समिति ने आदर्श जीएसटी विधि के सभी विषयों से संबंधित वीडियो व्याख्यान विकसित किए थे और उन्हें अपनी वेबसाइट तथा आईसीएआई टीवी पर रखा था । समिति ने अपना यू ट्यूब चैनल <https://www.youtube.com/indirecttaxcommittee> भी आरंभ किया है जिसमें उपरोक्त सभी वीडियो रिकार्डिंग माउस के क्लिक पर उपलब्ध हैं और उन्हें आफलाइन रूप से देखने के लिए डाउनलोड भी किया जा सकता है ।
- (ii) **जीएसटी संबंधी ई-पठन :** समिति ने, जीएसटी के लगभग सभी विषयों को सम्मिलित करते हुए रिकार्ड किए गए वीडियो सत्रों के माध्यम से जीएसटी संबंधी ई-पठन को आरंभ किया है ।
- (iii) **अप्रत्यक्ष कर संबंधी वेबकास्ट :** समिति ने अप्रत्यक्ष कर संबंधी मुद्दों पर, जिनमें से अधिकांश जीएसटी से संबंधित थे, उन्नतीस (29) वेबकास्टों का आयोजन किया था ।
- (iv) **जीएसटी में अंतरण की प्रक्रिया और उसके फायदों से संबंधित लघु वीडियो व्याख्यान :** समिति ने सभी पणधारियों के फायदे के लिए जीएसटी में अंतरण की प्रक्रिया के संबंध में और उसके फायदों से संबंधित लघु वीडियो व्याख्यानों को रिकार्ड किया था ।

5. जीएसटी संबंधी आईसीएआई ई-न्यूज लैटर : आईसीएआई अप्रैल, 2017 से अपना जीएसटी संबंधी ई-न्यूज लैटर जारी कर रहा है । अभी तक उसके छह अंक निकाले जा चुके हैं । सातवें अंक को शीघ्र ही जारी किया जाएगा ।

6. जीएसटी संबंधी मानकीकृत पीपीटी : समिति ने संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए और आईसीएआई द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और सत्रों में जीएसटी के सत्र में एकसमानता लाने के लिए मानकीकृत पीपीटी को विकसित किया है ।

7. सरकार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम : सक्षमता निर्माण में सरकार की सहायता करने और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करने के विचार से

समिति ने देश भर में विभिन्न कमीशनरियों में लगभग 20 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

8. व्यापार संगमों के लिए जीएसटी संबंधी परस्पर क्रियाशील कार्यक्रम : समिति ने राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करने की पहल के भागरूप में व्यापार संगमों के लिए जीएसटी संबंधी 19 परस्पर क्रियाशील कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

9. सेवाकर कमीशनरियों के सहयोग से जीएसटी संबंधी आउटरीच कार्यक्रम : समिति ने ज्ञान भागीदार के रूप में जीएसटी संबंधी कलकत्ता, दिल्ली और इलाहाबाद कमीशनरी के सहयोग से चार आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

10. पाठ्यक्रमों, कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि के माध्यम से सदस्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

क) जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

आईसीएआई ने प्रणालीगत रीति में जीएसटी से संबंधित विशेषीकृत और अद्यतन ज्ञान उपलब्ध कराने के विचार से 28 अप्रैल, 2017 को “माल और सेवाकर (जीएसटी) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम” के पहले बैच का संचालन किया है। काफी कम समय में ही इस पाठ्यक्रम के 40 बैचों का संचालन पूरे देश भर में किया गया है जिसमें लगभग 2500 सदस्यों ने भाग लिया है।

ख) जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से

आईसीएआई ने वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से 9 जून, 2017 से 30 जून, 2017 के दौरान जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन किया है, जिसे एक साथ 63 अवस्थानों पर होस्ट किया गया था, जिनमें 1800 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया था।

ग) कार्यक्रम, संगोष्ठियां और सम्मेलन : इस अवधि के दौरान समिति द्वारा 152 कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रमों में 35,000 से अधिक सदस्यों और अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया था।

11. जीएसटी के संबंध में नए वक्ताओं की पहचान और प्रशिक्षण : जीएसटी विधि के संबंध में 500 नए वक्ताओं की पहचान की गई है तथा उन्हें प्रशिक्षित किया गया है जिससे पूरे भारत में इस विशेषज्ञ पूल की संकाय सदस्यता संख्या 800 से अधिक हो गई है।

12. जीएसटी के सुचारू क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए अध्ययन समूह का सृजन : समिति ने पहले ही जीएसटी के सुचारू क्रियान्वयन में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए राज्य स्तरीय जीएसटी संबंधी बीस (20) अध्ययन समूहों का सृजन किया है।

13. अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी संबंधी अद्यतन जानकारी सहित – सदस्यों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के विचार से, जीएसटी सहित अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं, परिपत्रों और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के संक्षिप्त विवरण को नियमित रूप से आईडीटी नेट पर रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के बीच समिति की वेबसाइट www.idtc.icaai.org के माध्यम से परिचालित किया जाता है।

5.14 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति

वृत्ति के समक्ष आने वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों की पहचान करने और प्रैक्टिस गाइडों, प्रशिक्षण सहायिकियों, सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रकाशनों के अलावा सदस्यों के फायदे के लिए अर्हता-पश्च और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और व्यवहारिक कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ईआरपी/ सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का आयोजन करके, उन्हें सदस्यों हेतु फायदाप्रद वृत्तिक अवसरों में परिवर्तित करने के लिए परिषद् ने वर्ष 2000 में एक अस्थायी समिति के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का गठन किया था।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के व्यौरों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

क. न्यायालयीन प्रयोगशाला (आईसीएआई की डाटा विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला)

पहली न्यायालयीन प्रयोगशाला - (डाटा विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला) को 30 जनवरी, 2017 को आईसीएआई भवन, सेक्टर 62, नोएडा में आरंभ किया गया था, जहां सदस्यों को सीएएटी उपकरणों के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समिति वर्तमान आईटी प्रयोगशाला को सुसज्जित करने और सीओई हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, कानपुर और चेन्नई में ऐसी पांच और प्रयोगशालाओं को भी आरंभ करने के लिए प्रक्रिया कर रही है।

ख. नमूना सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए) और न्यायालयीन संपरीक्षा रिपोर्टों संबंधी नए प्रकाशन जारी करना

समिति ने “नमूना सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए) और न्यायालयीन संपरीक्षा रिपोर्टों” संबंधी एक नया प्रकाशन जारी किया है,

जिसका उपयोग सदस्यों द्वारा उनके वृत्तिक समनुदेशनों के दौरान किया जा सकता है। इन रिपोर्टों का उपयोग प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दौरान, उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा पृष्ठभूमि सामग्री के रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इन रिपोर्टों को वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा, जिससे प्रत्येक सदस्य रिपोर्टिंग के मूल्यवर्धन और मानकीकरण के लिए उनका उपयोग कर सके।

ग. “बैंककारी क्षेत्र में कपट के पूर्व संकेत” पर प्रकाशन

समिति “बैंककारी क्षेत्र में कपट के पूर्व संकेत” संबंधी एक प्रकाशन निकालने के लिए कार्य कर रही है। यह प्रकाशन सदस्यों के लिए बैंक संपरीक्षाएं करते समय और न्यायालयीन समनुदेशनों के संबंध में उपयोगी सिद्ध होगा।

घ. आईटी जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन

समिति अनेक आईटी संबंधी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन करती है, जो नमनीय अवधि के होते हैं और जो आईटी संबंधी क्षेत्रों में होने वाली नवीनतम घटनाओं से अवगत होने में सदस्यों की सहायता करते हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति ने 19 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिसमें 1299 सदस्यों ने भाग लिया था।

ङ. डीआईएसए – पात्रता परीक्षा और एफएएफडी – निर्धारण परीक्षा

- समिति ने 13 मई, 2017 को पूरे भारत वर्ष के 39 नगरों में सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम के लिए आईएसए पात्रता परीक्षा का सफलतापूर्वक संचालन किया था जिसमें 2386 सदस्यों ने फार्म भरा था और 2110 सदस्य भिन्न-भिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में बैठे थे।
- समिति ने 25 मार्च, 2014 को पूरे भारत वर्ष के 24 नगरों में द्वितीय एफएएफडी निर्धारण परीक्षा का सफलतापूर्वक संचालन किया था।

च. कार्यशालाएं/संगोष्ठियां

समिति ने सीएएटी उपकरणों, आधुनिक एक्सेल और डाटा-डेश बोर्ड, बिग डाटा एनालिटिक्स और आश्वासन सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि का उपयोग करते हुए कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद आदि में न्यायालयीन विश्लेषण संबंधी अनुभव प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन किया था।

5.15 आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड

आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड द्वारा आंतरिक संपरीक्षकों की तेजी से बदलती जोखिम युक्त परिस्थितियों में समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और तकनीकी की पहचान करने और उन्हें समझने में सहायता करने के लिए वर्ष के दौरान अनेक क्रियाकलाप किए गए हैं।

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों को आज्ञापक बनाए जाने के लिए प्रस्ताव

बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक आंतरिक संपरीक्षा क्रियाकलापों के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराते हैं, आंतरिक संपरीक्षा कार्यपालन के मूल्यांकन के लिए आधार स्थापित करते हैं और संगठनात्मक प्रक्रियाओं और प्रचालनों में सुधार की अभिवृद्धि करते हैं। बोर्ड ने, विधि में परिवर्तनों और विभिन्न पणधारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आंतरिक संपरीक्षा व्यवहार के ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रक्रिया आरंभ की है। बोर्ड ने, मुंबई और दिल्ली में आयोजित सभाओं में सदस्यों के मत/सुझाव प्राप्त करने के पश्चात् “आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों को आज्ञापक बनाए जाने के प्रस्ताव से संबंधित अवधारणा पत्र” परिषद् की स्वीकृति हेतु तैयार किया है।

“आंतरिक संपरीक्षा” की परिभाषा का पुनरीक्षण

बोर्ड ने जुलाई, 2007 में उसके द्वारा जारी की गई “आंतरिक संपरीक्षा” की परिभाषा का पुनरीक्षण करने संबंधी परियोजना को आरंभ किया है। इसका उद्देश्य, संगठनों के शासन, जोखिम और अनुपालन ढांचे में आंतरिक संपरीक्षकों की सदैव बढ़ती भूमिका को विशिष्ट रूप से दर्शित करते हुए परिभाषा को समकालीन बनाना है। पुनरीक्षित प्रारूप परिभाषा संबंधी उद्भासन प्रारूप को बोर्ड द्वारा जारी किया जा रहा है। उसके बाद इसे परिषद् के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाएगा।

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी पुनर्विलोकन और पुनरीक्षित मानक

बोर्ड ने, अभी तक 18 आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक जारी किए हैं। आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) आंतरिक संपरीक्षकों के लिए सर्वोत्तम व्यवहारों की संहिता को अभिव्यक्त करते हैं। ये मानक आंतरिक संपरीक्षा में कार्यपालन मानदंडों के सुदृढीकरण और निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बोर्ड ने एसआईए के पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के लिए एक परियोजना आरंभ की है और

इस प्रयोजन के लिए अध्ययन समूहों का भी गठन किया है।

तकनीकी साहित्य

बोर्ड, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों और तकनीकी गाइडों/मैनुअलों/ ज्ञान पुस्तिकाओं के रूप में उच्च गुणवत्ता वाला तकनीकी साहित्य जारी करके विभिन्न उद्योगों में आंतरिक संपरीक्षकों के रूप में कार्यरत सदस्यों को जागरूक बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड ने निम्नलिखित प्रकाशन और ज्ञान पुस्तिकाओं को जारी किया है :

- बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी मैनुअल (2016 संस्करण)
- आटोमोबाइल उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- आंतरिक संपरीक्षा जांच सूची
- ज्ञान पुस्तिका IV-क्वालिटी आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्टें
- बैंकों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा विमुद्रीकरण संबंधी क्रियाकलापों के पुनर्विलोकन के संबंध में टिप्पण

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- बोर्ड सदस्यों को बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करता है। इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों पर बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 75 बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया है और लगभग 3650 से अधिक सदस्यों ने सफलतापूर्वक इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अर्हित किया है।
- बोर्ड द्वारा उद्यम जोखिम प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : बोर्ड ने नए विषयों और सूचना प्रौद्योगिकी की एक बड़ी मात्रा को समाविष्ट करते हुए इन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए पुनरीक्षित पाठ्यक्रम संरचना को अंतिम रूप प्रदान किया है।

आंतरिक संपरीक्षा के संबंध में जागरूकता के लिए कार्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन

सदस्यों के बीच ज्ञान के प्रसार हेतु एक उपयुक्त मंच उपलब्ध कराने के विचार से बोर्ड ने सदस्यों के फायदे के लिए विभिन्न स्थानों पर 10 कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, परस्पर क्रियाशील बैठकों का आयोजन किया है।

5.16 अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति

क. सरकार को अभ्यावेदन/उसके साथ परस्पर क्रियाएं

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समिति ने निम्नलिखित के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे :

- नए उपयोक्ता प्ररूप सं. 15गक/15गख की बाबत आने वाले मुद्दों
- तारीख 16 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना सं. 93/2015 की बाबत आने वाले मुद्दों
- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 90/90क/91 के अधीन आय-कर की कटौती या अनुतोष प्रदान करने के लिए प्रारूप नियमों और सीबीडीटी द्वारा सृजित ई-वाणिज्य के कराधान संबंधी समिति
- प्रभावी प्रबंध स्थापित करने (पीओईएम) संबंधी दिशानिर्देश

अभ्यावेदनों के अलावा, समिति ने विशेषज्ञ पुनर्विलोकन समिति को भी अपने अंतःनिवेश प्रदान किए थे और साथ ही अंतरराष्ट्रीय कर संबंधी बजट-पूर्व और बजट-पश्च सुझाव भी प्रस्तुत किए थे।

ख. अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/वेबकास्ट

समिति ने देश के विभिन्न अवस्थानों पर अंतरराष्ट्रीय कराधान से संबंधित विभिन्न मुद्दों संबंधी विभिन्न सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और वेबकास्टों का आयोजन किया था। इनके अंतर्गत 9 वेबकास्ट हैं, जिन्हें 3209 सदस्यों और अन्य व्यक्तियों द्वारा देखा गया था तथा 4 सीपीई कार्यक्रम भी हैं, जिनमें 806 सदस्यों ने भाग लिया था।

ग. अंतरराष्ट्रीय कराधान में अर्हता-पश्च डिप्लोमा – समिति ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मुंबई, दिल्ली, बंगलौर, अहमदाबाद, गुडगांव, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई में अंतरराष्ट्रीय कराधान में अर्हता-पश्च डिप्लोमा के 9 बैचों का संचालन किया था। इन बैचों में भाग लेने वाले सदस्यों की कुल संख्या 558 थी।

घ. अन्य पहलें

- समिति ने पूर्वोक्त अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी ई-न्यूज लैटर के तीन संस्करणों को जारी किया था।
- “आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92ड के अधीन रिपोर्ट संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (अंतरण कीमत निर्धारण)” प्रकाशन का पुनरीक्षण। (पुनरीक्षित 2016)
- “अंतर्राष्ट्रीय कराधान के पहलू – एक अध्ययन” प्रकाशन का पुनरीक्षण।
- सदस्यों के लिए कैपिटल लाइन टीपी कारपोरेट डाटा बेस के संबंध में सी-एमटीओएस टेक्नॉलाजिस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ठहराव।
- सीए जर्नल में अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी लेखों का अभिदाय।
- अंतर्राष्ट्रीय कराधान के विषय पर सदस्यों को नियमित रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना।

5.17 कारबार और उद्योग में वृत्तिक अकाउंटेंटों संबंधी समिति

आईसीएआई की कारबार और उद्योग में वृत्तिक अकाउंटेंटों संबंधी समिति (सीपीएबीआई), आईसीएआई और उद्योग के बीच एक सामान्य मंच के सृजन के लिए व्यष्टिक उद्देश्यों का संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ सामंजस्य बिठाने और सीए को उसके पारंपरिक क्षेत्रों से परे कंपनी, कारबार और वाणिज्य के कार्यकरण से संबंधित सभी पहलूओं के संबंध में एक ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करने/स्थापित करने के लिए एक प्रभावी मंच का प्रयोजन सिद्ध करती है। यह समिति उद्योग और कारबार में सेवारत सीए और आईसीएआई के बीच निकट संबंध को प्रोत्साहित करने तथा उसमें अभिवृद्धि करने का कार्य करती है। इसके साथ ही, समिति उन्हें उनके गहन और बहुमुखी ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशलों के लिए उद्योग और अन्य पणधारियों के बीच स्थापित करने का प्रयास करती है। इस प्रयास का समर्थन करने के लिए सीपीएबीआई विभिन्न ज्ञानवर्धन सम्मेलनों, उद्योग बैठकों, आउटरीच कार्यक्रमों का सदस्यों के फायदे के लिए आयोजन कर रही है। सीपीएबीआई के अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों और आईसीएआई जॉब पोर्टल के माध्यम से युवा और अनुभव प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंटों को नियोजन अवसर उपलब्ध कराना, कारबार और उद्योग चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उदाहरणात्मक उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए गौरवशाली आईसीएआई पुरस्कारों का आयोजन करना, वृत्तिक दिलचस्पी के विषयों में साधारण प्रकाशन जारी करना, सीपीई अध्ययन सर्कलों का सृजन करना, ई-न्यूज लैटर का प्रकाशन करना सम्मिलित है, जिनका उद्देश्य सदस्यों को फायदा पहुंचाना है। इस अवधि के दौरान किए गए प्रमुख क्रियाकलापों को नीचे उपदर्शित किया गया है :

कैम्पस नियोजन कार्यक्रम :

अगस्त-सितंबर, 2016 - इसका आयोजन 21 केंद्रों में किया गया था, जिसके लिए 7322 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इसमें 100 संगठनों ने भाग लिया था और कुल 1279 नौकरियों के प्रस्ताव दिए गए थे। घरेलू नौकरी के लिए अधिकतम 24.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष के वेतन (कंपनी को लागत) का तथा अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के लिए 76.32 लाख रुपए प्रतिवर्ष के वेतन का प्रस्ताव किया गया था।

फरवरी-मार्च, 2017 में - इसका आयोजन 21 केंद्रों में किया गया था, जिसके लिए 4081 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इसमें 118 संगठनों ने भाग लिया था और कुल 1273 नौकरियों के प्रस्ताव दिए गए थे। घरेलू नौकरी के लिए अधिकतम 21.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष के वेतन (कंपनी को लागत) का तथा अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के लिए 43.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष के वेतन का प्रस्ताव किया गया था।

आईसीएआई पुरस्कार, 2016 के लिए ज्यूरी की बैठक

समिति ने, 9 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में, आईसीएआई पुरस्कार, 2016 के लिए पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए ज्यूरी की बैठक का आयोजन किया था। श्री के.वी. चौधरी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इस ज्यूरी की बैठक के अध्यक्ष थे।

10वां आईसीएआई – सीएमआईआई कारपोरेट मंच और आईसीएआई पुरस्कार 2016

सीपीएबीआई ने चेन्नई में 19 और 20 जनवरी, 2017 के दौरान वार्षिक (10वीं) निगम मंच की बैठक का आयोजन किया था, जिसमें निम्नलिखित उप-आयोजन सम्मिलित थे :

क) निगम सभा (19 और 20 जनवरी 2017) : उद्योग में लगे सदस्यों के कौशल सेटों में वृद्धि करने और उनके ज्ञान को समृद्ध बनाने के लिए समकालीन विषयों पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया था।

ख) वित्तीय सेवा प्रदर्शनी (19 और 20 जनवरी 2017) – यह एक ऐसा मंच है जहां पूरे भारत वर्ष से चार्टर्ड अकाउंटेंट और निगम एकत्रित होते हैं।

ग) **आईसीएआई पुरस्कार 2016 (20 जनवरी, 2017)** – आईसीएआई पुरस्कार द्वारा उद्योग में ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंटों के उदाहरणात्मक कार्य को सम्मानित किया गया था, जिन्होंने अपने वृत्तिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में उत्कृष्टता को उपदर्शित किया है और जो उद्योग में अन्य व्यक्तियों के लिए आदर्श रूप हैं। थिरु के. पंडिया राजन, माननीय विद्यालय शिक्षा, पुरातत्व, युवा कल्याण क्रीडा विकास विभाग मंत्री, तमिलनाडु सरकार, आईसीएआई पुरस्कार, 2016 के लिए मुख्य अतिथि थे।

5.18 पियर पुनर्विलोकन बोर्ड

पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया, किसी व्यक्ति के वृत्तिक उत्तरदायित्वों के अनुक्रम में संपरीक्षा और आश्वासन सेवाओं का निर्वहन करते समय गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और उसे बनाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और रखे गए अभिलेखों की प्रणालीगत मानीटरी के सिद्धांत पर आधारित है। आईसीएआई के पियर पुनर्विलोकन का मुख्य उद्देश्य आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखना और उसमें अभिवृद्धि करना तथा साथ ही सदस्यों को, उनके कार्यपालन और वृत्तिक कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तथा विभिन्न कानूनी और अन्य विनियामक अपेक्षाओं की पूर्ति के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। पियर पुनर्विलोकन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आईसीएआई के सदस्य आश्वासन सेवा समनुदेशनों को पूरा करते समय ; (क) यथालागू तकनीकी, वृत्तिक और नैतिक मानकों, जिसके अंतर्गत उनसे संबंधित अन्य विनियामक अपेक्षाएं भी हैं, का अनुपालन करते हैं ; और (ख) उनके द्वारा दी जाने वाली आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए दस्तावेजीकरण सहित समुचित प्रणालियां सुस्थापित हैं।

बोर्ड के प्रयास ने पियर पुनर्विलोकनों के प्रभावी कार्यपालन के साथ, न केवल व्यवसायी इकाईयों को, समाज को उनके द्वारा दी जाने वाली उनकी सेवाओं की गुणवत्ता में सतत सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया था अपितु उसे विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों से मान्यता भी प्राप्त हुई थी, जिसे नीचे उल्लिखित किया गया है :--

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध अस्तित्वों के लिए 1 अप्रैल, 2010 से यह आज्ञापक बना दिया है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत सीमित पुनर्विलोकन/कानूनी संपरीक्षा रिपोर्टें केवल उन संपरीक्षकों द्वारा तैयार की जाएंगी, जिन्होंने स्वयं को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अध्यक्षीन किया है और जो आईसीएआई के 'पियर पुनर्विलोकन बोर्ड' द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण कर रहे हैं।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने भी पियर पुनर्विलोकन बोर्ड के कार्य को मान्यता प्रदान की है ; अब वह आवेदन प्ररूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों से उनकी पियर पुनर्विलोकन प्रास्थिति के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे मांगता है, ताकि पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए संपरीक्षा आबंटित की जा सके। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों से सीएंडएजी वार्षिक रूप से आईसीएआई से उन फर्मों के ब्यौरे मांग रहा है, जिन्हें पियर पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुनर्विलोकनों द्वारा किए जाने वाले पुनर्विलोकन कार्य में संगतता और एकसमानता है, बोर्ड उन्हें पुनर्विलोकन हेतु प्रैक्टिस इकाईयां समनुदेशित करने से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है। अभी तक पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने कुल 5715 पुनर्विलोकनों को प्रशिक्षित किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया की बारीकियों और जटिलताओं को समझना, अर्थात् किसी व्यवसायी इकाई का पियर पुनर्विलोकन किस प्रकार किया जाए। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने, उसकी स्थापना से देश भर में 163 पियर पुनर्विलोकन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 7 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

अधिकाधिक फर्मों को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अधीन लाना

पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने भारत में सीए फर्मों की आश्वासन सेवाओं के पुनर्विलोकन के संबंध में एक विनियामक के रूप में विनिर्दिष्ट नए मानदंडों के आधार पर पियर पुनर्विलोकन के लिए अधिकाधिक फर्मों को उसके अधीन लाकर आश्वासन सेवाओं के परिधि क्षेत्र में अभिवृद्धि की है। पियर पुनर्विलोकन नई स्थापित फर्मों के लिए भी आरंभ कर दिया गया है। साथ ही, वित्तीय विवरणों में पाए गए अननुपालनों के ऐसे मामलों का, जो सत्य और उचित मत को प्रभावित नहीं करते हैं, अपितु संपरीक्षक की असावधानी को उपदर्शित करते हैं और जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा पियर पुनर्विलोकन बोर्ड को अग्रेषित किया गया था, तकनीकी पुनर्विलोकनों द्वारा पुनर्विलोकन किया जाता है, जिससे कि सदस्यों द्वारा लागू किया जाने वाला क्वालिटी नियंत्रण ढांचा अभिनिश्चित किया जा सके। ऐसे प्रयास आईसीएआई के विनियामक तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।

हाल ही की घटनाएं

पियर पुनर्विलोकन के परिधि क्षेत्र में अभिवृद्धि करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा उसे और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है और साथ ही और अधिक व्यवसायी इकाईयों का पुनर्विलोकन किया जा रहा है। इस प्रयोजन के मद्दे पियर पुनर्विलोकन संबंधी विवरण को पियर पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित किया गया है और व्यवसायी इकाईयों को भेजे जाने वाले पियर पुनर्विलोकन संबंधी

प्रश्नोत्तरों को भी क्वालिटी नियंत्रण संबंधी मानकों के अनुसार पुनरीक्षित किया गया है। प्रश्नोत्तरों के अनुलग्नक 2 को, 17 मार्च, 2017 और आगे की अवधियों के लिए स्तर 1 तथा स्तर 2 की दशा में पुनर्विलोककों द्वारा भरे जाने को आज्ञापक बनाया गया है, जिससे पुनर्विलोकन की क्वालिटी को मजबूत बनाया जा सके। पियर पुनर्विलोकन मैनुअल भी बोर्ड द्वारा पुनरीक्षणाधीन है। पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने पियर पुनर्विलोककों की फीस का भी पुनरीक्षण किया है जिसका वहन व्यवसायी इकाई द्वारा किया जाता है।

5.19 वृत्तिक विकास समिति

वृत्तिक विकास समिति, वृत्तिक विकास संबंधी आवश्यकताओं का अवधारण करती है और ऐसे मुद्दों तथा अन्य क्षेत्रों की पहचान करती है, जो वृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति, ऐसे नए/विद्यमान क्षेत्रों की खोज करके/ उन्हें लक्षित करके, जहां सदस्यों के वृत्तिक कौशलों का उपयोग किया जा सकता है, सदस्यों के लिए और अधिक वृत्तिक अवसरों का जनन करने के लिए प्रयास करती रही है। समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी अत्यधिक प्रयास किए हैं कि वृत्ति के सभी सदस्यों को समान अवसर उपलब्ध हों। वृत्तिक विकास में अनछुए क्षेत्रों का पता लगाने के अलावा समिति समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बहुल उपयोक्ताओं के साथ संसूचना प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए भी प्रयास करती है और वह उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका के संबंध में भी शिक्षित करती है।

संपरीक्षकों की नियुक्तियों में बैंकों को प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान किया जाना

साफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से बैंक शाखा संपरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में अभ्यावेदनों और की गई बैठकों के अनुसरण में, आरबीआई द्वारा सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को तारीख 13 अप्रैल, 2017 का एक पत्र भेजा गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पीएसबी कानूनी शाखा संपरीक्षकों के चयन और नियुक्ति के विषय में एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीति तथा प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं, जिसे उनकी वेबसाइट पर भी रखा जाए। इस पुनरीक्षित प्रक्रिया के भागरूप में, एसबीए का चयन और नियुक्ति केंद्रीयकृत रूप से संबद्ध बैंक के निगम कार्यालय में की जा सकती है। आरबीआई ने बैंकों को यह सलाह दी थी कि आईसीएआई ने पात्र फर्मों के बीच ऐसी संपरीक्षा के पैरामीटर आधारित आबंटन के लिए एक साफ्टवेयर विकसित किया है और आगे यह और सलाह दी गई थी कि बैंक ऐसे या किसी अन्य समुचित साफ्टवेयर, विशेष रूप से तैयार किया गया या अन्यथा की सहायता से, बैंक बोर्ड/एसीबी द्वारा तैयार/अनुमोदित नियुक्ति संबंधी नीति के निबंधनानुसार संपरीक्षा फर्मों का चयन करने के लिए केंद्रीयकृत रूप से अपने निगम कार्यालय में एसबीए को नियुक्त करने पर विचार कर सकेंगे। इस प्रयोजन के लिए समिति द्वारा एक साफ्टवेयर तैयार किया गया है जो परीक्षण के चरण पर है।

टेंडरिंग प्रक्रिया की मानीटरी के लिए तंत्र

सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने और अधिप्रमाणन कृत्यों के लिए टेंडरिंग प्रणाली की मानीटरी करने के विचार से आईसीएआई की परिषद् द्वारा तारीख 7 अप्रैल, 2016 की एक अधिसूचना जारी की गई है। समिति ने इसके परिणामस्वरूप सदस्यों के साधारण मार्गदर्शन के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों को तैयार किया है। समय-समय पर विभिन्न प्राधिकरणों को पत्र भेजे गए थे ताकि उनका ध्यान परिषद् के इस निर्णय की ओर आकर्षित किया जा सके, जो टेंडरों के लिए प्रत्युत्तर दिए जाने से संबंधित है और इस प्रकार उनसे अनुरोध किया गया था कि वे हमारे सदस्यों की सेवाओं का फायदा उठाने के लिए आईसीएआई पैनल का उपयोग करें।

बहु प्रयोजन पैनलबद्ध प्ररूप और विभिन्न प्राधिकरणों के लिए पैनलों का प्रावधान :

समिति, ऐसे नए/विद्यमान क्षेत्रों की खोज करके/ उन्हें लक्षित करके, जहां सदस्यों के वृत्तिक कौशलों का उपयोग एक उत्पादक और लाभदायक रीति में किया जा सकता है, सदस्यों के लिए और अधिक वृत्तिक अवसरों का जनन करने के लिए प्रयास करती रही है। व्यवहार के अनुसार, समिति ने इस वर्ष भी www.meficai.org पर बहु प्रयोजन पैनलबद्ध प्ररूप को रखा था। एमईएफओ को अधिकाधिक सर्वग्राही बनाने के लिए और अधिकतम जानकारी एकत्रित करने तथा एक केंद्रीयकृत डाटा बेस के माध्यम से उसका प्रसार करने के लिए प्रत्येक प्रयास किए गए। घोषणा को प्रस्तुत करने हेतु अंकीय हस्ताक्षर की सुविधा को पहली बार उपलब्ध कराया गया था। समिति ने विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य अभिकरणों को भी पैनल उपलब्ध कराए थे।

गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और अनिगमित निकायों के कार्यकरण के संबंध में राज्यस्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसी) की बैठक

वर्ष भर गोवा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एनसीटी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, रायपुर, चंडीगढ़ के लिए विभिन्न एसएलसीसी बैठकों का आयोजन किया गया था। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य के लिए गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और अनिगमित निकायों के कार्यकरण के संबंध में विभिन्न उप-राज्यस्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसी) की बैठकें की गई थी।

स्टार्ट अप इंडिया

स्टार्ट अप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका आशय यह है कि देश में नवीनता और स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाए, जो एक वहनीय आर्थिक विकास को संभव बनाएगा और बड़ी मात्रा में नियोजन अवसरों को सृजित करेगा। यह अभियान स्टार्ट अप उद्यमों के लिए बैंक वित्तपोषण का संवर्धन करने, जिससे कि उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाए और नौकरियों के सृजन के साथ स्टार्ट अप को प्रोत्साहित किया जाए, के उद्देश्य से एक कार्ययोजना को क्रियान्वित करने पर आधारित है। आज के युवा उद्यमियों, जो स्वयं को और पारिणामिक रूप से राष्ट्र को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, के समक्ष एक मुख्य चिंता वित्तीय कठिनाईयां हैं, जिससे उनके द्वारा किए जाने वाले कारबार के मूल्यांकन को प्राप्त करने में कठिनाई आती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने इस संबंध में आईसीएआई से सहयोग का अनुरोध किया है। राष्ट्र निर्माण के भागीदार के रूप में समिति ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों का एक पैनल तैयार कर रही है जो न्यूनतम युक्तियुक्त फीस पर यह सेवा प्रदान करने के इच्छुक हैं।

5.20 लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति

लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं का आयोजन किया था :

- वित्त विभाग, तमिलनाडु सरकार के साथ संयुक्त रूप से "एसएलपीई के उच्च स्तरीय वित्त कार्यपालकों" के लिए वित्तीय प्रबंधन संबंधी कार्यशाला
- वित्त विभाग, त्रिपुरा सरकार के सहायक संपरीक्षा/लेखा अधिकारियों और संपरीक्षकों के लिए "आंतरिक/कानूनी संपरीक्षा में सी एंड ए और संपरीक्षा समिति की भूमिका" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- त्रिपुरा सरकार के विभिन्न राज्य पीएसयू के प्रबंध निदेशकों/लेखा अधिकारियों और शहरी स्थानीय निकायों के उपायुक्त/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए "बजटीय और वित्तीय निर्णय लेने" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग के सीपीएसई और एसएलपीई के कार्यपालकों के लिए "कंपनी अधिनियम 2013 में हाल ही में हुए परिवर्तनों – आईएफआरएस" विषय पर कार्यशालाएं
- भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग के साथ संयुक्त रूप से "गैर-वित्त वृत्तियों के लिए वित्त" विषय पर तीन दिन का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- लोक उद्यम के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के साथ संयुक्त रूप से सीपीएसई के सदस्यों में से वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों, जिनके अंतर्गत सीईओ/ सीएफओ/ कृत्यकारी और स्वतंत्र निदेशक भी हैं, के लिए "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उसके फायदे" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के लोक उद्यम सीपीएसई और एसएलपीई के कार्यपालकों के लिए "इंड एस" पर एक दिवसीय कार्यशाला
- भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के लोक उद्यम सीपीएसई और एसएलपीई के कार्यपालकों के लिए "इंड एस" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति ने विभिन्न विषयों पर एक तीन दिवसीय आवासीय पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम और वेबकास्टों का भी आयोजन किया था।

ई-न्यूज लैटर – प्रूडेंस

समिति नियमित रूप से समिति की एक त्रैमासिक ई-संसूचना निकालती रही है, जो "प्रूडेंस" के नाम से ज्ञात है और जिसमें समिति की मुख्य पहलों को विशिष्ट रूप से उपदर्शित किया जाता है और जो लोक वित्त और शासकीय लेखांकन के क्षेत्र में लागू किए गए हाल ही के विनियमों और परिवर्तनों के संबंध में भी अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराता है।

5.21 जन संपर्क और सीएसआर क्रियाकलाप

वर्ष 2016-17 के दौरान, समिति ने अपने मिशन और उद्देश्य के अनुसरण में एक प्रमुख लेखांकन निकाय और एकमात्र विनियामक प्राधिकरण के रूप में आईसीएआई की छवि को विकसित करने, सुदृढ़ बनाने और उसमें अभिवृद्धि करने के प्रयासों को जारी रखा था। समिति ने नियमित रूप से किए जाने वाले कार्यों से अतिरिक्त अपने क्रियाकलापों के क्षेत्र को विस्तारित किया था। वर्ष 2017-18 के लिए समिति को जन संपर्क और सीएसआर समिति के रूप में पुनः गठित किया गया है। पूर्वोक्त अवधि के दौरान पीआर समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित थे :

‘ज्ञान यज्ञ : उत्कृष्टता की तलाश’ विषय पर आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आईसीएआई ने 22-23 अक्टूबर, 2016 के दौरान हैदराबाद में ‘ज्ञान यज्ञ : उत्कृष्टता की तलाश’ विषय पर एक दो दिवसीय आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। पीआर समिति द्वारा सदभाव संदेशों को आमंत्रित किया गया था और उन्हें इस अवसर के अनुस्मारक के रूप में निकाले गए स्मृति चिह्न में प्रकाशित किया गया था। इस समारोह में विदेशों से आए अनेक प्रतिनिधि मंडलों और विभिन्न पणधारियों तथा आईसीएआई के सदस्यों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के संबंध में मुद्रण और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया था।

संघीय बजट 2017

प्रत्येक वर्ष, पीआर समिति संघीय बजट के संबंध में आईसीएआई की प्रतिक्रिया को विभिन्न इलेक्ट्रानिक चैनलों, समाचार पत्रों, मैगजीनों, आदि में सम्मिलित किए जाने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करती है। अध्यक्ष, आईसीएआई ने बजट दिवस पर जी बिजनेस द्वारा आयोजित पैनल परिचर्चाओं में भाग लिया था।

ईयर बुक 2016-2017

आईसीएआई/उसकी समितियों/शाखाओं/प्रादेशिक परिषदों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और उनके द्वारा की गई पहलों को एक व्यापक दस्तावेज में सम्मिलित करते हुए “ईयर बुक” के रूप में एक प्रकाशन निकाला जाता है। सभी समितियों/शाखाओं/प्रादेशिक परिषदों से प्राप्त अंतःनिवेशों को समिति द्वारा ईयर बुक 2016-2017 के लिए संपादित और संकलित किया गया था।

तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

आईसीएआई विभिन्न पहलों को आरंभ करके, जिनके अंतर्गत मैराथन दौड़, तनाव प्रबंध के लिए योग सत्र, पर्यावरण के लिए जागरूकता का सृजन, हरित पहल आदि भी हैं, स्वस्थ जीवन का संवर्धन करने के लिए सदैव अगुवाई करता रहा है। आईसीएआई अपने सर्वत्र फैले सीए सदस्यों और छात्रों के समुदाय के माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री की इस पहल को अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आईसीएआई की पांच प्रादेशिक परिषदों और 110 शाखाओं ने विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोहों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया था, जिनमें 10,000 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था। सदस्यों और छात्रों को योग के स्वास्थ्य संबंधी फायदों से अवगत कराने के लिए 21 जून को समर्पित योग सत्रों का आयोजन किया गया था, जिनमें सदस्यों, छात्रों और उनके परिवारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। भाग लेने वाले व्यक्तियों को व्याख्यानों द्वारा प्रोत्साहित किया गया था, जिनके दौरान विशेषज्ञों ने उनके दैनिक जीवन में योग को सम्मिलित करने पर बल दिया था। अध्यक्ष, आईसीएआई के एक वीडियो संदेश को, जिसमें उन्होंने सीए भ्रातृसंघ को प्रेरित किया था, सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को भेजा गया था, जिसके द्वारा योगा को उनकी दिनचर्या के भागरूप में सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

मीडिया के साथ परस्पर क्रियाएं

मीडिया के साथ परस्पर क्रियाओं में आमने-सामने साक्षात्कारों/प्रेस विज्ञप्तियों/प्रेस सम्मेलनों के माध्यम से अभिवृद्धि हुई थी, जिनके द्वारा मीडिया को निरंतर रूप से किए गए विभिन्न क्रियाकलापों, भ्रातृसंघ, पणधारियों, व्यापार और उद्योग को अंतर्विलित करने वाले मुद्दों के संबंध में नवीनतम घटनाओं के बारे में अध्यक्ष द्वारा आमने-सामने के साक्षात्कारों और टेलीफोन के माध्यम से दिए गए साक्षात्कारों के माध्यम से अवगत कराया गया था।

5.22 अनुसंधान समिति

अनुसंधान समिति आईसीएआई की सर्वाधिक पुरानी गैर स्थायी समितियों में एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। अनुसंधान समिति का मुख्य उद्देश्य, वृत्ति द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का मूल्यवर्धन करने के विचार से लेखांकन और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करना है। यह समिति लेखांकन पहलुओं के संबंध में मार्गदर्शक टिप्पण तैयार करती है, जिन्हें परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जाता है। समिति, साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों के संबंध में तकनीकी गाइडों, अध्ययनों, मोनाग्राफों आदि के रूप में प्रकाशनों को निकालती है। समिति वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में सुधार करने के विचार से अपनी एक उप समिति, शील्ड पैनल के माध्यम से एक वार्षिक प्रतियोगिता, अर्थात् ‘वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार’ का भी आयोजन करती है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार

इन पुरस्कारों को वर्ष 1958 से प्रदान किया जा रहा है। विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में पुरस्कार विजेताओं का चयन एक 3 टियर मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम किया जाता है : सर्वप्रथम प्रारंभिक मूल्यांकन तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा किया जाता है, जिसके पश्चात् शील्ड पैनल द्वारा सूचीबद्ध वार्षिक रिपोर्टों का पुनर्विलोकन किया जाता है और इनका अंतिम पुनर्विलोकन एक बाहरी ज्यूरी द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2015-16 की प्रतियोगिता के लिए ज्यूरी की बैठक 9 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता आईएफआरएस फाउंडेशन के न्यासी और पूर्व अध्यक्ष (सेबी) श्री सी.बी. भावे ने की थी। पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए बैठक में भाग लेने वाले जूरी के अन्य सदस्य में : श्री एच.आर. खान, पूर्व उप गवर्नर (आरबीआई), श्री आर. बंधोपाध्याय, पूर्व सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), सीए. अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, एनएसीएएस और पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए. कमलेश शिवजी विक्रमसे, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, डॉ. आशिष के. भट्टाचार्य, पूर्व प्रोफेसर - आईआईएम, कोलकाता, सीए. उदय फडके, पूर्व अध्यक्ष, वित्त और विधि तथा वित्तीय सेवा क्षेत्र और समूह कार्यपालक बोर्ड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के सदस्य, सीए. निलेश शाह, प्रबंध निदेशक और सीईओ, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड सम्मिलित थे। पुरस्कारों की स्कीम के अनुसार सर्वोत्तम प्रविष्टि और दूसरी सर्वोत्तम प्रविष्टि के लिए क्रमशः एक स्वर्ण शील्ड और एक रजत शील्ड पुरस्कार में प्रदान की जाती है। ऊपर उल्लिखित पुरस्कारों के अलावा सराहनीय प्रविष्टियों के लिए पट्टिकाएं पुरस्कार में दी जाती हैं। हाल ऑफ फेम पुरस्कार ऐसे अस्तित्वों को प्रदान किया जाता है, जो किसी विशिष्ट प्रवर्ग में लगातार पांच स्वर्ण शील्ड का विजेता रहा हो।

‘वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार’ के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए 24 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया था। श्री विनोद राय, अध्यक्ष, बैंक बोर्ड ब्यूरो और भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखापरीक्षक इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। कुल 13 पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिनमें 3 स्वर्ण शील्ड, 3 रजत शील्ड और 7 पट्टिकाएं सम्मिलित थीं।

5.23 इंड एस कार्यान्वयन समिति

इंड एस कार्यान्वयन समिति, वर्ष 2011 में अपने प्रारंभ से ही देश में इंड एस के बारे में ज्ञान और जागरूकता का सृजन करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से कतिपय वर्ग की कंपनियों के लिए और वित्तीय वर्ष 2018-19 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी के लिए आज्ञापक रूप से इंड एस को लागू किए जाने से संबंधित जारी की गई अधिसूचना के अनुसरण में, सदस्यों और अन्य पणधारियों को आईएफआरएस – अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की अत्यावश्यकता विद्यमान है। समिति अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से इंड एस के संपरिवर्तन को सुचारू बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

इंड एस के उसी भावना के साथ, जिसमें उन्हें तैयार किया गया है, कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और साथ ही सदस्यों और अन्य पणधारियों को उपयुक्त मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के विचार से, आईसीएआई की इंड एस कार्यान्वयन समिति, इंड एस के संबंध में शैक्षिक सामग्रियां जारी करती हैं, जिनमें संबंधित इंड एस का संक्षिप्त विवरण और ऐसे मुद्दों को सम्मिलित करते हुए, जिनके मानक के कार्यान्वयन के दौरान बार-बार सामने आने की संभावना है, बहुधा पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) अंतर्विष्ट होते हैं। समिति सभी इंड एस पर शैक्षिक सामग्रियां निकालने के लिए कार्य कर रही हैं।

समिति ने अपने “भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस): एक पर्यावलोकन (पुनरीक्षित 2016)” शीर्षक वाले प्रकाशन का पुनरीक्षण किया था, जिसमें सभी इंड एस का संक्षिप्त पर्यावलोकन और विद्यमान लेखांकन मानकों में इंड एस की तुलना में और आईएफआरएस की तुलना में इंड एस के बीच प्रमुख अंतरों को संक्षिप्त रूप से अंतर्विष्ट किया गया है।

ऐसे विभिन्न मुद्दों, जो सदस्यों, तैयार करने वालों और अन्य पणधारियों द्वारा इंड एस के लागू होने/क्रियान्वयन के संबंध में उठाए जा रहे हैं, पर समय पूर्वक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के लिए इंड एस संपरिवर्तन सुविधा सेवा समूह (आईटीएफजी) का गठन किया गया था। यह समूह समय-समय पर कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए स्पष्टीकारक बुलेटिन निकालता है।

समिति ने, सदस्यों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों का समाधान करने के लिए “इंड एस के कार्यान्वयन संबंधी सहायता - पटल” को भी आरंभ किया है, जिसमें सदस्य अपनी शंकाओं, प्रश्नों और सुझावों को आनलाइन रूप से एक लिंक को क्लिक करके प्रस्तुत कर सकते हैं।

समिति कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करके इंड एस के समुचित कार्यान्वयन के लिए सदस्यों और अन्य पणधारियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करने के लिए पर्याप्त उपाय भी कर रही है।

समिति आईएफआरएस और इंड एस के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर में तथा विदेशों में भी आईएफआरएस संबंधी 12 दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का भी संचालन करती है। इस पाठ्यक्रम की व्यापक सत्र योजना को इस विचार से तैयार किया गया है कि वह सदस्यों को इंड एस के क्षेत्र में सक्षम बनाए। इस अवधि के दौरान इंड एस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 32 बैचों का संचालन किया गया है, जिनमें लगभग 1200 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। अभी तक, लगभग 8000 सदस्यों ने देश भर में और विदेशों में स्थित अवस्थानों पर इंड एस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। समिति ने विभिन्न भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) के संबंध में ई-पठन माड्यूल भी विकसित किए हैं।

समिति देश भर के विभिन्न अवस्थानों पर एक/दो दिवसीय इंड एएस संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है। इन जागरूकता कार्यक्रमों में, आधारीक मानकों, जो इंड एएस के अधीन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उन्हें प्रस्तुत करने के लिए भूमिका स्वरूप हैं, के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, इंड एएस और विद्यमान एएस के बीच अंतर को भी विनिर्दिष्ट रूप से बताया जाता है ताकि सदस्यों और पणधारियों को इस संबंध में शिक्षित किया जा सके कि इंड एएस के अधीन लेखांकन किस प्रकार विद्यमान एएस के अधीन किए जाने वाले लेखांकन से भिन्न होगा। इस अवधि के दौरान देश भर के विभिन्न अवस्थानों पर इंड एएस संबंधी 10 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

समिति विभिन्न विनियामकों, संगठनों, निगम घरानों के लिए इंड एएस संबंधी घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। इस अवधि के दौरान, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) के लिए इंड एएस संबंधी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। समिति ने इंड एएस के संबंध में जागरूकता का सृजन करने के लिए इंड एएस संबंधी वेबकास्टों की एक श्रृंखला का भी संचालन किया था। समिति इंड एएस के संबंध में जागरूकता और ज्ञान का सृजन करने के लिए और इस परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

5.24 संपरीक्षा समिति

संपरीक्षा समिति, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सत्य और उचित हैं, आईसीएआई की वित्तीय सूचना की रिपोर्टिंग प्रक्रिया और प्रकटन का पुनर्विलोकन करती है। यह समिति आईसीएआई की विभिन्न इकाइयों के लिए संपरीक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी है। संपरीक्षा समिति के पास पांच प्रादेशिक संपरीक्षा समितियां भी हैं, जो उसकी प्रादेशिक परिषदों में अवस्थित हैं।

5.25 अंकीय रूपांतरण और प्रक्रिया पुनः इंजीनियरी समूह

- अंकीय रूपांतरण और प्रक्रिया पुनः इंजीनियरी समूह ने आईसीएआई के छात्रों और सदस्यों के लिए आनलाइन विनियामक प्ररूप आरंभ किए हैं। फाउंडेशन/सीपीटी/सीधे प्रवेश/फाइनल पाठ्यक्रम के माध्यम से फाउंडेशन पाठ्यक्रम, मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण हेतु छात्र-बोर्ड आनलाइन रूप से उपलब्ध है। अन्य विनियामक प्ररूपों को विकसित करने के लिए प्रक्रिया की जा रही है और उन्हें चरणों में आरंभ किया जाएगा।
- आईसीएआई मोबाइल एप्लीकेशन आईसीएआई नाओ और आईसीएआई के सामाजिक मीडिया मंच, आईसीएआई के विभिन्न आयोजनों को लोकप्रिय बनाने और प्रमुख उपलब्धियों तथा पहलों का बिना किसी लागत के आधार पर आईसीएआई के छात्रों, सदस्यों और अन्य पणधारियों के बीच प्रचार और प्रसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। आईसीएआई के ट्वीटर अकाउंट <https://twitter.com/theicai> को ट्वीटर द्वारा एक शासकीय ट्वीटर अकाउंट के रूप में सत्यापित किया गया है और उसे ट्वीटर द्वारा सत्यापन के चिह्न के रूप में नीला टिक चिह्न मंजूर किया गया है। आईसीएआई अन्य सोशल मीडिया नेटवर्किंग मंचों जैसे कि फेसबुक, लिंकेडइन, गुगल प्लस और यूट्यूब पर भी उपस्थिति बनाए रखता है, जहां वह सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों और सदस्यों से जुड़ा रहता है।
- अंकीय रूपांतरण और प्रक्रिया पुनः इंजीनियरी समूह ने आईसीएआई की वेबसाइट पर सदस्यों और छात्रों के लिए पेटीएम संदाय गेटवे सेवाओं को समर्थ बनाया है, जहां आनलाइन बैंकिंग और पेटीएम वॉलेट से संबंधित सभी प्रकार के आनलाइन संव्यवहार प्रभार एक वर्ष के लिए निःशुल्क लागत पर अनुज्ञात हैं। आईसीएआई का पेटीएम के साथ नियोजन छात्रों और सदस्यों को एक दक्ष और सुरक्षित संदाय विकल्प उपलब्ध कराएगा।
- अंकीय रूपांतरण और प्रक्रिया पुनः इंजीनियरी समूह (डीटीपीआरजी) ने आईसीएआई के जर्नल "द चार्टर्ड अकाउंटेंट" के "पर्यावरण के अनुकूल बनें" अभियान के कार्यान्वयन में सहायता की थी। आईसीएआई ने अन्य विभागों, अर्थात् परीक्षा के दस्तावेजों का अंकीकरण करके परीक्षा विभाग और दस्तावेज प्रबंध प्रणाली के अंकीय रूपांतरण की योजना तैयार की है।

5.26 क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड

जैसा कि पिछली रिपोर्ट में बताया गया था, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड को केंद्रीय सरकार द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28क के अधीन उसमें निहित शक्तियों के अनुसरण में गठित किया गया था और यह निम्नलिखित कृत्य करेगा :-

1. परिषद् को आईसीएआई के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी के संबंध में सिफारिशें करना ;
2. आईसीएआई के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं, जिसके अंतर्गत संपरीक्षा संबंधी सेवाएं भी हैं, की क्वालिटी का पुनर्विलोकन करना ; और
3. आईसीएआई के सदस्यों का, सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करने और विभिन्न कानूनी तथा अन्य विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु मार्गदर्शन करना।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन परिषद् का एक कृत्य यह है कि वह उसके द्वारा बनाए गए क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की आईसीएआई के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी के संबंध में की गई सिफारिशों पर विचार करे। पूर्वोक्त खंड (ण) यह भी उपबंध करता है कि उसकी वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाईयों के ब्यौरे अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित करे। पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसरण में, यह रिपोर्ट किया जाता है कि रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान परिषद् को सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी के संबंध में क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ख(क) के अधीन 3 प्रतिनिर्देश प्राप्त हुए थे। इनमें से 2 प्रतिनिर्देशों पर परिषद् द्वारा अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 के वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित अपनी बैठकों में विचार किया गया था। इस संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

1. आईसीएआई के अनुशासन तंत्र के अधीन आगे और अन्वेषण करने के लिए निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट किए गए प्रतिनिर्देशों की संख्या – 1
2. ऐसे प्रतिनिर्देशों की संख्या, जहां तकनीकी पुनर्विलोकन की टीका-टिप्पणियों को सदस्यों/फर्मों को सलाह के रूप में जारी करने का विनिश्चय किया गया था – 1
3. ऐसे प्रतिनिर्देशों की संख्या, जिन्हें बंद करने का विनिश्चय किया गया था – शून्य
4. परिषद् के विचारार्थ लंबित प्रतिनिर्देशों की संख्या – 1

5.27 प्रबंधन समिति

प्रबंधन समिति का गठन वर्ष 2015 में परिषद् की एक अस्थायी समिति के रूप में किया गया था। अन्य बातों के साथ, समिति के कृत्यों के अंतर्गत शाखाओं के सृजन, विदेशों में चैप्टरों की स्थापना, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ एमओयू/एमआरए करने, आईसीएआई के केंद्रीय संपरीक्षकों की नियुक्ति, संस्थान के वार्षिक लेखों, केंद्रीय सरकार और अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्दिष्ट मामलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में संशोधन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं से संबंधित मामलों, सदस्यों/सीए फर्मों/एलएलपी/विलयनों/निर्विलयनों/ नेटवर्किंग संबंधी मामलों और संस्थान की अन्य समितियों/विभागों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों, जिनमें प्रशासनिक और नीतिगत विवक्षाएं अंतर्बलित हैं, पर विचार करना और जहां कहीं अपेक्षित हो, परिषद् को अपनी सिफारिशें करना भी है। समिति द्वारा परिषद् को की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें और उसके द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नानुसार हैं :-

क. ऐसे महत्वपूर्ण विषय, जिनके बारे में परिषद् को सिफारिश की गई थी--

- सदस्यों को जारी किए जाने वाले उत्तम विश्वसनीय प्रमाणपत्रों के तत्समान सीए फर्मों द्वारा मांगे जाने वाले उचित और समुचित प्रमाणपत्रों को जारी करना।
- कैलिफोर्निया के सेन फ्रांसिस्को वे क्षेत्र, यूएसए और नीदरलैंड (एमस्टर्डैम) में आईसीएआई के नए चैप्टरों की स्थापना।
- आईसीएआई द्वारा संचालित किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए परिषद्, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के निर्वाचन लड़ने हेतु पात्र बनने से पूर्व एक वर्ष की कूलिंग अवधि।

ख. समिति द्वारा किए गए महत्वपूर्ण विनिश्चय

- अध्ययन बोर्ड की सिफारिश का अनुमोदन कि उच्चतर माध्यमिक बोर्डों की 12वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में सभी तीन विधाओं, अर्थात् वाणिज्य, विज्ञान और कला में पहली दो रैंक अर्जित करने वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण की फीस की दो समान छह मासिक किस्तों में प्रतिपूर्ति की जाए और ऐसे अभ्यर्थियों को, अध्ययन बोर्ड के कैरियर परामर्श संबंधी समूह द्वारा आयोजित कैरियर विशेषज्ञ समारोह में किसी टीए/डीए और ठहरने की लागत के संदाय के बिना प्रमाणपत्र/मेडल प्रदान करके मान्यता दी जाए।
- मृतक भागीदार की गैर-सीए पत्नी को भागीदारी विलेख या किसी अन्य करार के माध्यम से लाभ का अंश प्रदान करना, किंतु उसे फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।
- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के, आरंभ में आईसीएआई भवन, नोएडा 62 में और तत्पश्चात् अन्य अवस्थानों में, न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रशिक्षण सत्रों और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रथम डाटा विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन।
- आईसीएआई के अनुसार सदस्यों की जन्म तारीख और पैन कार्ड के अनुसार आय-कर विवरणियों की ई-फाइलिंग के लिए पैन

कार्ड में जन्म तारीख भिन्न-भिन्न होने की दशा में आईसीएआई के अभिलेखों में पासपोर्ट या आधार कार्ड या दसवीं कक्षा की अंक तालिका/उत्तीर्ण प्रमाणपत्र या दसवीं कक्षा के पश्चात विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तारीख के आधार पर और सदस्यों द्वारा एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उसकी जन्म तारीख में परिवर्तन करना।

- प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को, उनके बैंकों के साथ संपर्क करके उनके विक्रय पटलों पर पीओएस मशीन/ई-वालेट प्रतिष्ठापित करके 1 जनवरी, 2017 से आज्ञापक रूप से कारबार संव्यवहार के लिए नकद रहित प्रणाली को अपनाने और इस प्रकार आने वाले दिनों में पूर्णतया नकद रहित कार्य करने की सलाह देना।

6. अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति (आईएसी)

विदेशों में वृत्तिक अवसरों की मान्यता के लिए पहले

- (i) **14 दिसंबर, 2016 को सीबीएफएस ओमान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर :** 14 दिसंबर, 2016 को, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई संघ के मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान वर्ष 2008 और 2011 में हस्ताक्षरित एमओयू के लिए "कार्योत्तर अनुमोदन" प्रदान किया गया था और साथ ही आईसीएआई और सीबीएफएस ओमान के बीच एमओयू के नवीकरण के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया था।
- (ii) **आईसीएआई की ब्रांड साम्या का वैश्वीकरण :** आईसीएआई के एक विस्तारित अंग के रूप में, आईसीएआई के विदेशी चैंप्टर, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति के मिशन को अग्रसर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण वह विश्व स्तरीय वित्तीय सक्षमताओं, उत्तम शासन और प्रतिस्पर्धात्मकता के निबंधनों में एक मूल्यावान न्यासी के रूप में स्थापित हो गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आईसीएआई के (29वें) यूएसए (सेन फ्रांसिस्को) चैंप्टर का उदघाटन 4 मार्च, 2017 को और आईसीएआई के (30वें) नीदरलैंड (एमस्टर्डैम) चैंप्टर का उदघाटन 1 जून, 2017 को किया गया था।
- (iii) **आईसीएआई का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल**
 - अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट फेडरेशन (आईएफएसी) से एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें अध्यक्ष सुश्री ओलिविया किर्टली और श्री रसेल गुथरी, मुख्य वित्त अधिकारी, आईएफएएस सम्मिलित थे, 23 और 24 जून, 2016 को भारत का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय विनियामकों, अर्थात् भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत के उप-नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के साथ लाभप्रद बातचीत की थी। शासकीय प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठक करने का उद्देश्य, दीर्घकालिक रूप से वैश्विक, भारतीय और विनियामक परिप्रेक्ष्य में संयुक्त रूप से दीर्घकालिक संबंधों की आधारशिला रखने के लिए आईसीएआई के साथ मिलकर भारत में लेखांकन भ्रातृसंघ के साथ निकट तथा और अधिक गहन बातचीत करना था।
 - श्री मार्क चाउ, क्षेत्रीय प्रबंधक, सीपीए ऑस्ट्रेलिया और मिशेल चान, वरिष्ठ कारबार विकास प्रबंधक, सीपीए ऑस्ट्रेलिया ने परस्पर हित के मामलों पर चर्चा करने और दोनों संस्थानों के बीच पहले से ही विद्यमान संबंधों को मजबूत करने के लिए 04 जुलाई, 2016 को आईसीएआई का दौरा किया था। सीपीए ऑस्ट्रेलिया ने 30 जून, 2016 मुंबई में और 2 जुलाई, 2016 को दिल्ली में एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें सीपीए ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय सीपीए को ऑस्ट्रेलिया में उनके लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई थी और यह भी बताया था कि आईसीएआई और सीपीए ऑस्ट्रेलिया के बीच एमआरए पर हस्ताक्षर होने से उन्हें किस प्रकार फायदा हो सकता है।
 - परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए श्री टोनी मेनवारिंग, विदेश मामलों के कार्यकारी निदेशक, सीआईएमए ने 11 मार्च, 2016 को आईसीएआई का दौरा किया और सीआईएमए के प्रबंध निदेशक, श्री एंड्रयू हार्डिंग और श्री भास्कर रंजन दास, विपणन प्रमुख, दक्षिण एशिया, सीआईएमए ने 27 मई, 2016 को आईसीएआई का दौरा किया।
 - श्री टॉम ओडलजैम्बो न्यागारे, मुख्य प्रबंधक, सदस्य सेवा, इंस्टिट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स आफ केन्या ने 1 से 12 अगस्त, 2016 के दौरान भारत का दौरा किया था। अपने दौरे के अनुक्रम के दौरान, उन्होंने आईसीएआई की प्रणाली और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया था ताकि उन्हें उनके संस्थान में दोहराया जा सके और साथ ही समझौता ज्ञापन के लिए बातचीत शुरू की थी।
 - जोखिम प्रबंध सोसायटी, न्यूयॉर्क से एक प्रतिनिधिमंडल ने 22 फरवरी, 2017 को आईसीएआई का दौरा किया था, जिसमें नोवेल आर. सीमेन, अध्यक्ष आरआईएमएस, मैरी रोथ, सीईओ आरआईएमएस ; कैरोल फॉक्स, उपाध्यक्ष, नीतिगत पहलें, आरआईएमएस ; रॉबर्ट कार्टराइट, उपाध्यक्ष आरआईएमएस ; सौभाग्य परिजा, एसवीपी और मुख्य जोखिम अधिकारी, न्यूयॉर्क

पावर अथारिटी ; जुगल किशोर मदान, अध्येता और सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय समिति, आरआईएमएस ; स्टीवन चाउ, वरिष्ठ निदेशक, ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट, आरआईएमएस और लौरा लैंगोन, ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट एंड इश्योरेंस, नेपाल सम्मिलित थे।

- श्री मोहम्मद जारिफ लुदिन, कार्यक्रम प्रबंधक, खजाना विभाग, वित्त मंत्रालय, अफगानिस्तान ने प्रस्तावित समझौता ज्ञापन पर चर्चा करने के लिए और आईसीएआई तथा वित्त मंत्रालय, अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के विषय को अग्रसर करने के लिए 8 मार्च, 2017 को आईसीएआई का दौरा किया था।
- अध्यक्ष, आईसीएआई, एक केंद्रीय परिषद सदस्य, इंस्टीट्यूट के अधिकारियों के साथ 9 मार्च, 2017 को आईसीएआई के कार्यालय, मुंबई में, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट (सीआईएमए) से आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी, जिसमें श्री लॉसन कारमाइकल, ईवीपी – रणनीति, पीपल एंड इनोवेशन फॉर द एसोसिएशन, सुथ्री आइरिन टेंग, एमडी- यूरोप, अफ्रीका और एशिया तथा श्री अजय लालवानी, देश प्रमुख – भारत - मैनेजमेंट अकाउंटेंटिंग एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स सम्मिलित थे।
- आईसीए नेपाल से एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें श्री महेश खनल, अध्यक्ष, आईसीएएन ; श्री प्रकाश जंग थापा, उपाध्यक्ष, आईसीएएन और श्री प्रकाश लमसाल, तुरंत पूर्व अध्यक्ष ने आईसीएआई कार्यालय, मुंबई में आईसीएआई के कृत्यकारियों के साथ दो संस्थानों के बीच अर्हता संबंधी परस्पर आदान-प्रदान की संभावना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी।

(iv) सम्मेलन / कार्यक्रम

22-24 अप्रैल, 2016 के दौरान मुंबई में साफा समितियों और साफा बोर्ड बैठकों तथा साफा-आईएफएसी प्रादेशिक पीएआईबी

मंच : आईसीएआई ने 22-24 अप्रैल, 2016 के दौरान मुंबई में साफा समितियों और साफा बोर्ड बैठकों तथा साफा-आईएफएसी प्रादेशिक पीएआईबी मंच की मेजबानी की थी, जिसका उद्देश्य कारबार में लगे वृत्तिक अकाउंटेंटों (पीएआईबी) को, विश्व भर में पीएआईबी को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक अवसर प्रदान करना था। साफा-आईएफएसी प्रादेशिक पीएआईबी मंच में, पीएआईबी के लिए सुसंगत कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि शासन में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण और प्रभावी कारबार रिपोर्टिंग और समान मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया था। साफा-आईएफएसी प्रादेशिक पीएआईबी मंच में भाग लेने वाले व्यक्तियों को आईएफएसी की पीएआईबी समिति के सदस्यों और सार्क क्षेत्र से अन्य विख्यात वक्ताओं के साथ आमने-सामने परस्पर क्रिया करने का अवसर उपलब्ध कराया गया था।

- **अफ्रीका-भारत भागीदारी : अफ्रीकी महाद्वीप के राष्ट्रों के दूतावासों/उच्च आयुक्तों के साथ आईसीएआई सभा तथा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग :** अर्थव्यवस्थाओं के बीच सेवाओं के बढ़ते आदान-प्रदान के मद्देनजर आज की परिस्थितियों में किसी भी राष्ट्र की प्रतिस्पर्धात्मकता और उसकी भावी संभावनाओं के लिए प्रशिक्षित और कौशल मानव पूंजी रखना सफलता का एक मुख्य कारक है। ऐसे क्रियाशील संदर्भ में अपनी भूमिका और योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए और विभिन्न उपयोक्ता समूहों के बीच एक अंतरापृष्ठ उपलब्ध कराने की पहल के रूप में तथा भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों के महत्व को ध्यान में रखते हुए आईसीएआई ने, 8 अगस्त, 2016 को नई दिल्ली में, भारत में स्थित अफ्रीकी दूतावासों/उच्चायोगों के राजदूतों/उच्चायुक्तों तथा अफ्रीका में विकासात्मक हित रखने वाले पणधारियों के साथ अफ्रीका-भारत भागीदारी : आईसीएआई सभा और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था।
- **क्रमशः 13-14 अक्टूबर, 2016 को आईसीएआई के प्रधान कार्यालय में आईसीएआई – आईएफआरएस फाउंडेशन न्यासी संयुक्त पणधारी आयोजन और बैठक :** आईसीएआई ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) फाउंडेशन के न्यासियों के साथ संयुक्त रूप से, भारत में इंड एस की कार्ययोजना और आईएफआरएस के साथ संबंधों के बारे में 13 अक्टूबर, 2016 को एक पणधारियों के समारोह का आयोजन किया था। आईएफआरएस फाउंडेशन, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) का एक पर्यावलोकन निकाय है और उसके अंतर्गत शासन तथा पर्यावलोकन आता है, जिसे न्यासियों द्वारा पूरा किया जाता है और जो उसके प्रचालनों का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त, जी-20 पहल के भागरूप में भारत सरकार ने आईएफआरएस फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी आईएफआरएस के साथ इंड एस को अभिसरित करने का वचन दिया था और उसने यह अभिसरण कार्य पूरा कर लिया है।
- **हैदराबाद में आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2016 और सीएपीए बोर्ड तथा समिति की बैठकें :** 22-23 अक्टूबर, 2016 के दौरान हैदराबाद में “ज्ञान यज्ञ : उत्कृष्टता की तलाश” विषय पर आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे भारत वर्ष और विश्व से भी 3500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का उदघाटन श्री एम. वैकेया नायडू, तत्कालीन माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया था। श्री अर्जुन राम

मेघवाल, संघ के माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लेखांकन मानक, जीएसटी, एसएमपी की प्रतिस्पर्धात्मकता, निगम कपट, अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे अनेक विषयों पर चर्चा की गई थी और वर्तमान संदर्भ में सुसंगत होने के कारण वृत्ति की सक्षमता निर्माण को उद्देश्य के रूप में स्थापित किया गया था।

- **9 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में “वैश्विक संपरीक्षा पर्यावलोकन : अनुभूति अंतर का सुमेलन” विषय पर आईसीएआई – पीआईओबी संयुक्त पणधारियों की सभा :** आईसीएआई ने लोक हित पर्यावलोकन बोर्ड (पीआईओबी), एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावलोकन निकाय, के सहयोग से 9 फरवरी, 2017 को होटल रायल प्लाजा, नई दिल्ली में “वैश्विक संपरीक्षा पर्यावलोकन : अनुभूति अंतर का सुमेलन” विषय पर आईसीएआई – पीआईओबी संयुक्त पणधारियों की सभा आयोजन किया था। इस संयुक्त आईसीएआई – पीआईओबी सभा का मुख्य उद्देश्य पीआईओबी की भूमिका के संबंध में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना और मानक निर्धारण माडल के संबंध में जानकारी प्राप्त करना तथा भारत में वृत्ति की चुनौतियों और अनुभवों के संबंध में एक खुली वार्ता का आयोजन करना था।
- **आईसीएआई द्वारा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह की बैठक की मेजबानी :** अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएसबी) ने ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी मुद्दों का, जो अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं, समाधान करने में सहायता करने हेतु एक ईईजी समूह का गठन किया है। राष्ट्रीय मानक निर्धारक, इस ईईजी के स्थायी सदस्य हैं, जिनके अभिहित व्यष्टि समूह के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। सुक्ष्म अस्तित्वों के लिए लेखांकन, उच्च मुद्रास्फीति तथा आईएफआरएस और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 8-9 मई, 2017 के दौरान भारत में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह की बैठक की गई थी।

(v) अविकसित देशों को तकनीकी सहयोग

- आईसीएआई को “लेखांकन और संपरीक्षा मानक बोर्ड, भूटान के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट पाठ्यचर्या को विकसित करने के लिए, आईसीएबी के लिए उपविधियों के प्रारूपण तथा लेखांकन और संपरीक्षा मानक बोर्ड, भूटान के लिए नियमों और विनियमों के प्रारूपण हेतु परामर्शी सेवाओं” की विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना प्रदान की गई है। इस कार्य के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :--
 - चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को विकसित करना।
 - आईसीएबी के लिए उप विधियों का प्रारूपण।
 - एएस अधिनियम के नियमों और विनियमों का प्रारूपण।

यह परियोजना, आईसीएआई द्वारा दिसंबर, 2015 में विश्व बैंक की निविदा के प्रति अपनी बोली प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसरण में दो परिषद् सदस्यों ने निदेशक, आईसीएआई के साथ मई, 2016 मास में भूटान का दौरा किया था। इसके अतिरिक्त, आईसीएआई और एएसबी भूटान के बीच विद्यमान समझौता ज्ञापन के कारण, आईसीएआई इस परियोजना के लिए विचार में लिए जाने के लिए एक अग्रता प्राप्त संस्थान था। परियोजना को हित के आधार पर बोली द्वारा प्रदान किया गया था।

- आईएफएसी ने, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में लेखांकन वृत्ति और पीएओ को सुदृढ़ करने संबंधी आईएफएसी की प्रतिबद्धता को अग्रसर करते हुए अफ्रीकी क्षेत्र में लेखांकन संबंधी अवसंरचना के विकास हेतु हित की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध जारी किया था। यह ईओआई, ऐसे हितबद्ध संगठनों की पहचान करने के लिए जारी किया गया था, जिनके पास समान प्रास्थिति की परियोजनाओं का निष्पादन करने के लिए अपेक्षित अर्हताएं और सुसंगत अनुभव है। आईसीएआई ने 1 दिसंबर, 2016 को पीएओ हेतु सक्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए अपने हित की अभिव्यक्ति को सम्यक् रूप से प्रस्तुत किया था। हमारी हित की अभिव्यक्ति के अनुसरण में आईएफएसी ने म्यांमार में एक आगामी परियोजना की सूचना भेजी है, जिसके संबंध में आईसीएआई को 21 जुलाई, 2017 तक प्रतिक्रिया जारी की जानी थी।

(vi) रचना खंडों के लिए कार्यकरण

- **आईसीएआई वैश्विक कैरियर ई किट, युगांडा का शुभारंभ :** आईसीएआई ने 16 मई, 2016 को युगांडा चैंप्टर के आयोजन के साथ ही सफलतापूर्वक आईसीएआई वैश्विक कैरियर ई किट, युगांडा का शुभारंभ किया था।
- **आईसीएआई वैश्विक कैरियर ई किट, अफ्रीका का शुभारंभ :** आईसीएआई ने 8 अगस्त, 2016 को अफ्रीकी महाद्वीप के राष्ट्रों के राजदूतों/उच्चायुक्तों के साथ आईसीएआई सभा और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग शिखर सम्मेलन के आयोजन के अवसर पर

तंजानिया के लिए संयुक्त रूप से वैश्विक कैरियर ई किट, अफ्रीका का शुभारंभ किया था।

- **आईसीएआई वैश्विक कैरियर ई किट, केन्या का शुभारंभ :** आईसीएआई ने 23 जनवरी, 2017 को तंजानिया चैप्टर के आयोजन के साथ ही सफलतापूर्वक आईसीएआई वैश्विक कैरियर ई किट, केन्या का शुभारंभ किया था। यह दोहा, कुवैत, मस्कट, तंजानिया, यूएई और केन्या के लिए पहले से जारी छह ई-किटों, जिनके द्वारा दुबई और आबु धाबी, दोनों को सम्मिलित किया गया था, की श्रृंखला में सातवीं ई-किट है तथा अन्य शेष बचे चैप्टरों के लिए भी ई-किटें जारी करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

इन किटों की अवधारणा इस प्रकार की गई है कि वे वृत्तिक अवसरों के लिए विदेशों में जाने का आशय रखने वाले सदस्यों को विहंगम आरंभिक जानकारी उपलब्ध कराती हैं। इन वैश्विक कैरियर ई-किटों में संबद्ध अधिकारिता से संबंधित साधारण जानकारी को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि जनसांख्यिकीय ब्यौरे, आर्थिक परिस्थितियां, उद्योग कारबार संबंधी जानकारी, बीजा संबंधी अपेक्षाएं आदि। इसके अतिरिक्त, स्थानीय चैप्टर के संपर्क ब्यौरे, एमओयू/एमआरए संबंधी जानकारी तथा विदेशों में स्थित सदस्यों के लिए एफएक्यू जैसी उपयोगी जानकारी को भी इन ई-किटों में सम्मिलित किया जाता है। इन ई-किटों से यह आशा की जाती है कि वे सदस्यों की, आने वाले समय में किसी अधिकारिता में सेवा प्रदान करने के लिए उस अधिकारिता में प्रारंभिक अंतरापृष्ठ स्थापित करने में सहायता करेंगी।

7. अन्य क्रियाकलाप

7.1 एचआर रूपांतरण समूह

वर्तमान परिषद् वर्ष से, इस समिति को एक समूह में परिवर्तित किया गया है, अर्थात् एचआर रूपांतरण समूह। उपरोक्त अवधि के दौरान, समिति द्वारा व्यवहार संबंधी पहलुओं और तकनीकी बुद्धिमता के क्षेत्र में 79 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिनके दौरान लगभग 8314 प्रशिक्षण कार्य घंटें प्रदान किए गए थे। समिति के एक उपखंड द्वारा एक संसाधन वितरण चार्ट तैयार किया गया था, जिसमें आईसीएआई के भीतर संसाधन उपयोग को उपदर्शित किया गया था।

समूह द्वारा किए गए क्रियाकलाप

- जीएमसीएस संकायों के साथ राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, अनुसचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- लंबित एचआर मुद्दों के संबंध में विचार करने के लिए एचआरटी अधिकारी समूह का गठन किया गया था।
- सभी पूर्ववर्ती रिपोर्टों की साध्य सिफारिशों को चरणबद्ध रीति में कार्यान्वित करने का कार्य एचआरटी अधिकारी समूह को सौंपा गया है क्योंकि इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के लिए अनुमोदन सैद्धांतिक रूप से बैठक में अधिकारियों के समूह को प्रदान किया गया था। सभी एचआर संबंधी विषयों को तीन चरणों में विभाजित किया गया था।

क्रम सं.	चरण	किए जाने वाले क्रियाकलाप
1	I	कार्य का वर्णन
2		केआरए और केपीआई
3		संसूचना संबंधी रणनीति
4		जनशक्ति का सुव्यवस्थीकरण
5	II	संगठन की पुनः संरचना
6		मूल्यांकन प्रबंध प्रणाली को पुनः तैयार करना
7		प्रशिक्षण की प्रभाविकता को मापना
		आयोजन प्रबंध विभाग का सृजन करना
8	III	मूल्यांकन प्रबंध प्रणाली का कार्यान्वयन
		उत्तरोत्तर योजना

- एचआरटी अधिकारी समूह ने समिति सचिवों और एचओडी के साथ, उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के संबंध में जनशक्ति के निर्धारण के लिए आमने-सामने परस्पर क्रिया बैठकें पूरी कर ली हैं और संगठन की पुनः संरचना के लिए संसूचना संबंधी रणनीति को दूसरे चरण में पूरा किया जाएगा। अधिकारी समूह, एचआरटी समूह की आगामी बैठक में चरण-1 के पूरा होने संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

- इसके अतिरिक्त, विभागों/समितियों में कर्मिकों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को उपदर्शित करने वाला संगठन ढांचा, सभी समितियों/विभागों के लिए तैयार किया गया था ताकि इन अंगों के भीतर सकल कार्य उत्तरदायित्वों का संकलन किया जा सके और उनके सुचारु कार्यकरण के लिए जनशक्ति के उपयोग को उचित ठहराया जा सके।
- भविष्य के लिए विभिन्न समितियों/विभागों के बीच प्रशासनिक और कार्यक्रम आयोजन प्रबंध को पूल किए जाने संबंधी संभावनाओं की भी खोज की जा रही है।

7.2 मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास एक प्रणालीगत और योजनाबद्ध अवधारणा है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों की दक्षता में सुधार किया जाता है। यह एक ऐसा ढांचा है, जिसके द्वारा कर्मचारियों की, उनके व्यक्तिगत और संगठनात्मक कौशल ज्ञान और सामर्थ्य का विकास करने में सहायता की जाती है। यह किसी विशिष्ट क्रियाकलाप के लिए आवश्यक कौशल सेट और विशेषज्ञता को उपयुक्त रूप से नियोजित किए जाने को भी सुनिश्चित करता है और इस प्रकार संगठन के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति होती है।

आईसीएआई का मानव संसाधन विकास विभाग, कर्मचारी के कैरियर के विकास, कार्यपालन प्रबंध और विकास, कोचिंग, परामर्श, उत्तरोत्तर योजना, मुख्य कर्मचारियों की पहचान और संगठन के विकास जैसे अवसरों को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ऐसे सर्वाधिक उच्चतर कार्यबल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे संगठन और व्यष्टिक कर्मचारी, अपने सदस्यों और छात्रों को सेवा उपलब्ध कराने के अपने कार्य संबंधी उद्देश्यों की सफलतापूर्वक पूर्ति कर सकें।

अपने वित्तीय, विधिक, तकनीकी, अवसंरचनात्मक और पीआर खंडों को प्रधान कार्यालय स्तर पर सुदृढ़ करने के विचार से एचआर विभाग ने वर्ष 2016-17 के दौरान भिन्न-भिन्न स्तरों पर विभिन्न भर्ती अभियान चलाए थे। सिविल इंजीनियर, आईटी परामर्शी, जन संपर्क एसोसिएट, विधिक सलाहकार और आईटी परामर्शी के पदों के लिए संविदाकारी आधार पर नियुक्तियां की गई हैं। सचिव, निदेशक (प्रचालन), निदेशक (वित्त), एचआर वृत्तिकों, संकायाध्यक्ष – एआरएफ के स्तर पर और दिल्ली तथा मुंबई अवस्थानों के लिए तकनीकी निदेशालय हेतु जनशक्ति की भर्ती हेतु प्रक्रिया की जा रही है।

आईसीएआई के दक्ष प्रशासन को बनाए रखने के लिए यह समीचीन है कि आईसीएआई के कर्मचारियों के लिए एक आचार-संहिता स्थापित की जाए। आईसीएआई के कर्मचारियों के लिए, उनके कर्तव्यों के निर्वहन के अनुक्रम में मार्गदर्शक की भूमिका निभाने के लिए वर्ष के दौरान, आईसीएआई द्वारा उसके कर्मचारियों के आचार से संबंधित विभिन्न सलाहों का अनुपालन करने के अलावा, एक आचार-संहिता जारी की गई है, जो आईसीएआई के सभी कर्मचारियों को लागू है।

आईसीएआई के विभिन्न खंडों के सुचारु और निर्बाध कार्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु एक दीर्घकालिक योजना तैयार करने के उद्देश्य से, आगामी दो वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले पदधारियों के संदर्भ में एक द्वितीय पंक्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक पहलें की गई हैं। साथ ही, आईसीएआई के विभिन्न विभागों और समितियों में संगततः समुचित रूप से कार्यपालन न करने वाले कर्मचारियों की पहचान करने के संबंध में भी विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे उनके कार्यपालन में सुधार करने हेतु संभव उपाय किए जा सकें।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल सेट को विकसित करने के विचार से तथा उन्हें आईसीएआई के भिन्न-भिन्न खंडों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों से सुपरिचित कराने हेतु, ऐसे कर्मचारियों के, जिन्होंने किसी एक विभाग में अपनी सेवा अवधि के दौरान दस वर्ष या अधिक समय के लिए कार्य किया है, चक्रानुक्रम का एक प्रयोग आरंभ किया गया है। ऐसे कर्मचारियों के चक्रानुक्रम संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

7.3 प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति

सदस्यों के लिए पहलें

- समिति व्यवसाय और उद्योग में लगे आईसीएआई के सदस्यों के लिए अपना प्रमुख पाठ्यक्रम कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (एमबीएफसीसी) का संचालन करती है। यह प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम एक वर्ष की अवधि का है, जिसमें 30 कक्षा पठन सत्र, जिनमें से प्रत्येक सत्र 5 घंटे की अवधि का है, 5 दिवस के 2 आज्ञापक आवासीय कार्यक्रम और परीक्षाएं सम्मिलित हैं।
 - समिति ने 9 अप्रैल, 2016 को मुंबई में कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दसवें बैच का संचालन किया था।
 - समिति ने 10 अप्रैल, 2016 को दिल्ली में कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दसवें बैच का

संचालन किया था।

- समिति ने 24 जून, 2017 को मुंबई में कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के ग्यारहवें बैच का संचालन किया था।
- समिति ने 24 जून, 2017 को दिल्ली में कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के ग्यारहवें बैच का संचालन किया था।
- समिति ने मई, अगस्त और नवंबर, 2016 के मासों के दौरान कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए तीन आवासीय कार्यक्रमों का संचालन किया था।
- समिति ने कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए जुलाई से सितंबर, 2016 और फरवरी-मार्च, 2017 के मासों के दौरान सभी तीन स्तरों पर परीक्षाओं का आयोजन किया था, जिनमें प्रत्येक स्तर हेतु दो प्रश्न पत्र अंतर्विष्ट थे।

उद्योग/निगम पहलें/कार्यक्रम

- समिति ने जुलाई, 2016 में आईसीएआई टावर, मुंबई में हैज निधियों और प्राइवेट साम्या संबंधी एक पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई थी। इस कार्यशाला की, उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अत्याधिक अनुशंसा की गई थी। इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या 104 थी।
- समिति ने 22 जनवरी, 2017 को आईसीएआई टावर, मुंबई में जीएसटी का प्रभाव – भू-संपदा क्षेत्र विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था। इस कार्यशाला की, उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अत्याधिक अनुशंसा की गई थी।

सदस्यों को शिक्षित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग

समिति ने भारत सरकार द्वारा विकास की दर में वृद्धि करने के लिए की गई प्रमुख पहलों – स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा बैंक के संबंध में – ऐसी प्रमुख पहलों से उदभूत होने वाले वृत्तिक अवसरों के बारे में 24 जून, 2016 को वेबकास्टों का और विमुद्रीकरण – कराधान, फेमा, लेखांकन संबंधी मुद्दों के संबंध में 24 नवंबर, 2016 को पैनल चर्चाओं का आयोजन किया था।

समिति की हाल ही की पहलें

कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की संगततः और उसे मिली प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, समिति ने उसे प्रबंध और कारबार वित्त में अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया था, जिसे पहले परिषद् द्वारा और उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 204 में संशोधन करने वाली अंतिम अधिसूचना 25 मई, 2017 को जारी की गई थी।

7.4 उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति

इस समिति का उद्देश्य, आईसीएआई और उद्यमों या लोक सेवा में लगे सदस्यों के बीच परस्पर फायदाप्रद लाईव संबंध स्थापित करना तथा ऐसे सदस्यों और साथ ही आईसीएआई के अन्य सदस्यों के परस्पर फायदों के पहलुओं का पता लगाने और उन्हें वास्तविक बनाने हेतु कार्य करना है। यह युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अतिरिक्त अवसरों का सृजन करने और उन्हें जागरूक बनाने में भी सहायता करेगी और इस प्रकार वृत्ति को अग्रसर करने के प्रति अपना सहयोग देगी। 1.4.2016 - 30.06.2017 के दौरान समिति ने निम्नलिखित क्रियाकलाप किए थे :

लोक सेवाओं में लगे आईसीएआई के सदस्यों के लिए आवासीय शिखर सम्मेलन

लोक सेवा में लगे सदस्यों से राष्ट्रीय महत्व के कतिपय ऐसे मामलों पर, जिनके संबंध में आईसीएआई अनुसंधान तथा आगे और अध्ययन कर सकता है, गहन विचार-विमर्श करने के लिए और साथ ही वृत्ति द्वारा प्रतिक्रिया के लिए अपेक्षित समकालीन महत्व के विभिन्न विषयों पर भी विचार-विमर्श करने के लिए समिति ने 16-18 दिसंबर, 2016 के दौरान कोच्ची में 'आर्थिक विकास के लिए लेखांकन वृत्ति' विषय पर लोक सेवाओं में लगे आईसीएआई के सदस्यों के लिए एक आवासीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। इस

कार्यशाला का उद्घाटन सीए सुरेश प्रभाकर प्रभु, संघ के माननीय रेल मंत्री ने एक वीडियो संदेश द्वारा किया था। सीए के. रहमान खान, माननीय संसद् सदस्य, राज्य सभा, सीए (डा.) किरीट सौमय्या, माननीय संसद् सदस्य, सीए सुभाष चंद्र बहेरिया, माननीय संसद् सदस्य और माननीय न्यायमूर्ति (सीए) अनिल आर दवे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय ने इस शिखर सम्मेलन में अपने प्रमुख व्याख्यान प्रस्तुत किए थे। सीए (डा.) किरीट सौमय्या, माननीय संसद् सदस्य ने लोक सेवा में लगे आईसीएआई के सदस्यों के आवासीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों हेतु एक प्रोफाइल पुस्तिका का भी अनावरण किया था।

इस शिखर सम्मेलन में 34 व्यक्तियों ने भाग लिया था, जो लोक सेवा में लगे वृत्तिकों में से वरिष्ठ सदस्य थे, जिनमें सांसद, राजनीति में वरिष्ठ सदस्य, न्यायाधीश, भारतीय प्रशासनिक और अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारी, अधिकरणों के सदस्य और पत्रकारिता में लगे सदस्य सम्मिलित थे।

लोक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों की क्षेत्रीय बैठकें

जैसा कि कोच्ची में आयोजित आवासीय शिखर सम्मेलन में विनिश्चय किया गया था, समिति ने विभिन्न क्षेत्रों में लोक सेवा में लगे आईसीएआई के सदस्यों की क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया था। पहली ऐसी बैठक का आयोजन 13 जनवरी, 2017 को मुंबई में और उसके पश्चात् 12 अप्रैल, 2017 को दिल्ली में और 22 जून, 2017 को कोलकाता में ऐसी बैठकों को आयोजित किया गया था।

मुंबई में हुई क्षेत्रीय बैठक में लोक सेवा में लगे आईसीएआई के 13 वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया था। दिल्ली में हुई बैठक में लोक सेवा में लगे वृत्तिकों के 16 वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें के. रहमान खान, माननीय संसद् सदस्य, राज्य सभा, सीए. सुभाष चंद्र बहेरिया, भीलवाड़ा से माननीय संसद् सदस्य, न्यायमूर्ति (सीए) अनिल आर. दवे, माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय सम्मिलित थे और कोलकाता में हुई बैठक में लोक सेवा में लगे वृत्तिकों के 9 वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया था।

इस दौरान आयोजित की गई विभिन्न परस्पर क्रियाओं के दौरान सदस्यों ने आईसीएआई की छवि में आगे और सुधार करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया था, जिसके अंतर्गत पीआर को सुदृढ़ करना, प्रोदभवन लेखांकन की पद्धति में स्थानांतरण के लिए सरकारी विभागों की सहायता करना, जीएसटी कार्यान्वयन और जागरूकता पहलें और अन्य समान विषय भी थे।

13 मई, 2017 को “युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए सिविल सेवाओं में अवसर” विषय पर लाइव वेबकास्ट

समिति ने, व्यवसायगत सदस्यों की सक्षमता निर्माण संबंधी समिति (सीसीवीएमपी), आईसीएआई के युवा सदस्य सशक्तिकरण समूह के साथ संयुक्त रूप से 13 मई, 2017 को “युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए सिविल सेवाओं में अवसर” विषय पर लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया था।

सीए. महावीर सिंघवी, आईएफएस, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय ने इस परिचर्चा का संचालन किया था। सीए. रविन्द्र, आईएएस मंत्री के निजी सचिव, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय तथा सीए. नमित मेहता, आईएएस, अपर आयुक्त वैट, जयपुर इस सत्र के दौरान पैनल वार्ताकार थे।

इस वेबकास्ट का उद्देश्य हमारे ऐसे युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों को प्रोत्साहित करना था, जो सिविल सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए इच्छुक हैं। इस वेबकास्ट को आईसीएआई के 550 से अधिक सदस्यों द्वारा देखा गया था।

7.5 सहकारिताओं और एनपीओ क्षेत्रों संबंधी समिति

समिति का प्रमुख उद्देश्य सहकारिताओं और एनपीओ के लिए एक समान लेखांकन ढांचे का संवर्धन करना है, ताकि इन क्षेत्रों में उत्तम वित्तीय प्रबंध को प्रोत्साहित किया जा सके तथा राज्यवार संपरीक्षकों को पैनलबद्ध करने के लिए दिशानिर्देशों को तैयार किया जा सके। इसके साथ ही सदस्यों को संगोष्ठियों, व्यवहारिक कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से सहकारिताओं और एनपीओ के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं की अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है।

क. प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन

- 24 अगस्त, 2016 को एक अभ्यावेदन, सहकारिता आयुक्त और सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य, पुणे को संपरीक्षा संबंधी नियुक्तियों की रीति और अन्य संपरीक्षा संबंधी मुद्दों के संबंध में प्रस्तुत किया गया। इस अभ्यावेदन में जिन मुद्दों को उठाया गया था, उनमें जिला उप रजिस्ट्रारों (डीडीआर), पैनलबद्ध करने संबंधी प्रक्रिया, सहकारी आवासन सोसाइटियों के लिए विहित संपरीक्षा फीस, बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद न्यायपीठ के आडिट फीस जीआर तारीख 29.10.2014 के संबंध में तारीख 02.05.2016 के अंतरिम आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने, विभाग की वेबसाइट पर

तथा अन्यत्र परिपत्रों के उपलब्ध न होने, लॉग इन में कठिनाईयों और वेबसाइट पर दस्तावेजों को अपलोड करने में कठिनाईयां आदि मुद्दे सम्मिलित थे।

- 4 अक्टूबर, 2016 को एक अभ्यावेदन संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, मध्य प्रदेश, भोपाल को, मध्यप्रदेश में स्थित सहकारी सोसाइटियों में संपरीक्षा कार्य करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। इस अभ्यावेदन में संपरीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटों की वृत्तिक सक्षमता का वर्णन किया गया था और चार्टर्ड एकाउंटेंटों की विशेषज्ञता के भिन्न-भिन्न और विशिष्ट क्षेत्रों को दर्शित किया गया था।
- 28 दिसंबर, 2016 को एक अभ्यावेदन माननीय मंत्री, सहकारिता, विपणन और टैक्सटाइल विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई को सहकारी पैनल संपरीक्षकों के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। इस अभ्यावेदन में चार्टर्ड एकाउंटेंटों की वित्तीय संपरीक्षा करने की वृत्तिक सक्षमता और चार्टर्ड एकाउंटेंटों की विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों को दर्शित किया गया था।

ख. कार्यक्रम/संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं/परस्पर क्रियाशील बैठकें/व्याख्यान बैठकें

- अप्रैल 2016 में मुंबई में, सहकारिता, एनपीओ और संबंधित क्षेत्रों में सीए के लिए मुद्दों और अवसरों संबंधी परस्पर क्रियाशील बैठक।
- अप्रैल, 2016 में मुंबई में, स्टाम्प शुल्क के संबंध में सभी बातें, जिनके अंतर्गत नए स्टाम्प शुल्क सुगम संदर्भ, 2016 को समझना भी था, विषय पर व्याख्यान बैठक।
- जून, 2016 में पटना में, सहकारी सोसाइटियों के लिए संपरीक्षा मानक और सेवाकर संबंधी संगोष्ठी।
- जून, 2016 में मुंबई में, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 और भवन निर्माताओं, विकास कर्ताओं, पणधारियों के लिए उसकी विवक्षाएं, पुनः विकास संबंधी परियोजनाओं पर उसकी विवक्षाएं और चार्टर्ड एकाउंटेंटों की बढ़ती भूमिका संबंधी व्याख्यान बैठक।
- जून 2016 में ठाणे में, सहकारी आवासन सोसाइटियों की संपरीक्षा और सेवाकर विवक्षाओं, ऑनलाइन फाइलिंग के क्षेत्र में हुई हाल ही की घटनाओं और भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के संबंध में संगोष्ठी।
- अगस्त, 2016 में विशाखापत्तनम में एनपीओ, सोसाइटियों और सहकारी सोसाइटियों संबंधी संगोष्ठी।
- नवंबर, 2016 में जलगांव में खानदेश सहकारी सभा – 2016।
- दिसंबर, 2016 में मुंबई में भू-संपदा क्षेत्र में हुई हाल ही की घटनाओं संबंधी कार्यशाला, जिसके अंतर्गत विमुद्रीकरण का प्रभाव, रेरा के अधीन मुद्दे और उनका समाधान, मूल्यांकन सहित जीएसटी और आईटीसी तथा पुनरीक्षित विकास और नए एफएसआई नियम भी हैं।

ग. वेबकास्ट

समिति ने अक्टूबर, 2016 में पुणे में महाराष्ट्र सहकारी क्षेत्र में प्रमुख नीति विषयक निर्णयों और विभिन्न पहलों के संबंध में एक वेबकास्ट का आयोजन किया था, जिसमें संपरीक्षा के लिए पैनलकरण प्रक्रिया और अन्य संपरीक्षा तथा प्रशासन संबंधी मुद्दे सम्मिलित थे और इस संबंध में नवीनतम घटनाओं के बारे में श्री चंद्रकांत दलवी, सहकारिता आयुक्त और सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र द्वारा संबोधन प्रस्तुत किया गया था।

7.6 विधिक सलाहकार खंड

इस अवधि के दौरान विधिक खंड द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्रियाकलाप किए गए थे :

विधिक रायों के रूप में प्रभावी विधिक सहायता अध्ययनों और रिपोर्टों को उपलब्ध कराना, जैसा कि समय-समय पर आईसीएआई की परिषद्/कार्यपालक समिति/ विभिन्न अस्थायी समितियों और विभागों द्वारा अपेक्षा की जाए।

आईसीएआई के हित को ठोस रूप से सुनिश्चित करने के लिए आईसीएआई के प्रशासनिक कार्यकरण से उद्भूत होने वाली विधि के सारवान और प्रक्रियात्मक प्रश्नों की विविध शृंखला पर उपयुक्त विधिक सलाह उपलब्ध कराना, जैसा कि प्रचालनात्मक विभागों द्वारा अपेक्षित किया जाए।

आईसीएआई के प्रचालन विभागों और विभिन्न समितियों द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार संविदाओं, निविदाओं, दस्तावेजों और अन्य विधिक दस्तावेजों के पुनर्विलोकन, उनके संबंध में बातचीत, उनके प्रारूपण और विधीक्षा संबंधी कार्य का अधीक्षण और पर्यावलोकन

करना।

नीतियों को तैयार करने के संबंध में विधिक सूक्ष्मताओं का ध्यान रखने के लिए यथाअपेक्षित रूप में विभिन्न स्थाई और अस्थायी समितियों, अध्ययन समूहों और कार्यबलों में सेवा प्रदान करना।

जब कभी आवश्यक हो, विधिक उपचारों का अवलंब लेने के विषयों में सलाह देना और प्राप्त हुई विधिक सूचनाओं का उत्तर तैयार करने में प्रचालन विभागों और समितियों की सहायता करना।

1.4.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के दौरान संबद्ध उच्च न्यायालयों द्वारा धारा 21(6) के अधीन निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 19 है। परिषद् द्वारा धारा 21(5) के अधीन अग्रेषित कुल 151 मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं।

7.7 अवसंरचना विकास संबंधी समिति

आईसीएआई द्वारा शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों/कार्यालयों की अवसंरचना के विकास के लिए एक नीति की विरचना की गई है, जिसमें अवसंरचना विकास के लिए दिशा-निर्देशों, अंतर्वर्तित लागत कारकों और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है। समिति का गठन वर्ष 2014 में, ऐसे भवन प्रस्तावों के संबंध में नीति के कार्यान्वयन के लिए किया गया था, जो आईसीएआई की विभिन्न शाखाओं/प्रादेशिक परिषदों से प्राप्त हों।

अवसंरचना नीति को तैयार करने के पश्चात् नई अवसंरचना का क्रय :

1. कन्नूर शाखा, एसआईआरसी - भूमि निजी पक्षकार से क्रय की
2. जालंधर शाखा, एनआईआरसी - सरकारी भूमि, जालंधर सुधार न्यास से
3. जबलपुर शाखा, सीआईआरसी - सरकारी भूमि जबलपुर विकास प्राधिकरण से
4. गोवा शाखा, डब्ल्यूआईआरसी - भूमि निजी पक्षकार से क्रय की
5. गुडगांव शाखा, एनआईआरसी - सरकारी भूमि एचएसआईआईडीसी से
6. मुरादाबाद शाखा, सीआईआरसी - सरकारी भूमि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से
7. पाली शाखा, सीआईआरसी - सरकारी भूमि नगर परिषद, पाली से
8. आगरा शाखा, सीआईआरसी - सरकारी भूमि उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद से
9. गोरखपुर शाखा, सीआईआरसी - सरकारी भूमि गोरखपुर विकास प्राधिकरण में
10. करनाल शाखा, एनआईआरसी - एचएसआईआईडीसी से सरकारी भूमि
11. किशनगढ़ शाखा, सीआईआरसी - नगर परिषद् किशनगढ़
12. लातूर शाखा, डब्ल्यूआईआरसी - भूमि निजी पक्षकार से क्रय की

समिति द्वारा अनुमोदित संनिर्माण के प्रस्ताव

1. अजमेर शाखा, सीआईआरसी
2. सूरत शाखा, डब्ल्यूआईआरसी
3. हुबली शाखा, एसआईआरसी
4. भटिंडा शाखा, एनआईआरसी
5. बरेली शाखा, सीआईआरसी
6. भोपाल शाखा, सीआईआरसी
7. जोधपुर शाखा, सीआईआरसी
8. रायपुर शाखा, सीआईआरसी
9. कन्नूर शाखा, एसआईआरसी
10. गुंटूर शाखा, एसआईआरसी (सिद्धांत रूप में स्वीकृत)

7.8 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम ने लोक प्राधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता तथा जवाबदेही का संवर्धन करने के लिए भारत के नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन जानकारी तक पहुंच बनाने के लिए सूचना के अधिकार को उपलब्ध कराया था। आईसीएआई, जो संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन गठित एक कानूनी निकाय है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) में परिकल्पित किए गए अनुसार एक लोक प्राधिकारी है। सूचना का अधिकार

अधिनियम, 2005 के उपबंधों और केन्द्रीय सूचना आयोग के निदेश के अनुपालन में इस लोक प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारियों को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी (एफएए) और पारदर्शिता अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अधीन प्रकटन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के निबंधनों के अनुसार संस्थान द्वारा आवश्यक प्रकटन किए गए हैं और उन्हें संस्थान की वेबसाइट www.icaai.org पर रखा गया है और उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की संख्या नीचे सारणी में प्रदान की गई है :

त्रैमास	ऐसे आवेदनों की कुल संख्या, जो त्रैमास में प्राप्त हुए थे और जिनका उत्तर दिया गया था
पहला त्रैमास	149
दूसरा त्रैमास	135
तीसरा त्रैमास	106
चौथा त्रैमास	177

7.9 एक्सबीआरएल

एक्सबीआरएल इंडिया का मुख्य उद्देश्य, भारत में इलेक्ट्रॉनिक कारबार रिपोर्टिंग और अन्य किस्म की कारबार रिपोर्टिंग के लिए मानक के रूप में 'एक्सटेन्सिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज' (एक्सबीआरएल) को अपनाए जाने का संवर्धन करना तथा उसके लिए प्रोत्साहन देना और साथ ही ज्ञान का प्रसार और संवर्धन करना, वर्गीकरणों के विकास के माध्यम से एक्सबीआरएल के विकास और संवर्धन के उद्देश्य का समर्थन करना, एक्सबीआरएल संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण को सुकर बनाना तथा नियंत्रण प्रणालियों और संबद्ध विधाओं में प्रबंधन सूचना को बढ़ावा देना है, जिसका समर्थन भारत सरकार और विभिन्न विनियामक निकायों, अर्थात् कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आदि द्वारा किया जा रहा है।

➤ इंड एस वर्गीकरण और कारबार नियम

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कतिपय प्रवर्ग की कंपनियों के लिए यह आज्ञापक बनाया है कि वे अपने वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस), जिन्हें वित्तीय वर्ष 2016-17 से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिसरित किया गया है, के अनुसार तैयार करें। ऐसी कंपनियों से वित्तीय विवरणों को वार्षिक रूप से फाइल किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए एक्सबीआरएल वर्गीकरण अपेक्षित होगा। तदनुसार, एक पृथक् वर्गीकरण को भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) के आधार पर तैयार किया गया है, जिसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। इस वर्गीकरण के आधार पर, कारबार नियमों के एक सेट को भी तैयार किया गया है, जिसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

➤ कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा एक्सबीआरएल फाइलिंग संबंधी अपेक्षाएं

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा, वर्ष 2010-11 से कंपनियों के एक चुने हुए वर्ग के वित्तीय विवरणों को वार्षिक रूप से फाइल किए जाने के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) वर्गीकरण का उपयोग किया जा रहा है। इस वर्गीकरण को, लेखांकन ढांचे में हुए परिवर्तनों पर विचार करते हुए प्रत्येक वर्ष अद्यतन बनाया जाता है। वर्ष 2016 में, सीएंडआई वर्गीकरण को कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 और कुछ अन्य परिवर्तनों के अधीन अधिकथित नई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पुनरीक्षित किया गया था। तत्समान कारबार नियमों को भी पुनरीक्षित किया गया था। पुनरीक्षित सी एंड आई वर्गीकरण और कारबार नियमों का उपयोग एमसीए द्वारा कंपनियों के वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय विवरणों को फाइल करने के लिए किया जाएगा। वर्ष 2017 में सीएंडआई वर्गीकरण को पुनः पुनरीक्षित किया गया था, जिससे कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 और वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू कुछ परिपत्रों द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों को उनमें सम्मिलित किया जा सके। पुनरीक्षित वर्गीकरण को, पुनरीक्षित कारबार नियमों के साथ कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।

➤ अंतरराष्ट्रीय क्रियाकलाप

- एक्सबीआरएल भारत ने सिंगापुर में 7-8 नवंबर, 2016 के दौरान आयोजित एक्सबीआरएल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और सदस्य सभा बैठक में और 11 नवंबर, 2016 को आयोजित एक्सबीआरएल एशिया गोलमेज (एक्सएआरटी) बैठक में प्रतिनिधित्व किया था।
- अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड के आईएफआरएस वर्गीकरण परामर्शी समूह (आईटीसीजी) की सदस्यता के लिए नामांकन भेजे गए थे।

7.10 आईसीएआई – एआरएफ

लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन एआरएफ को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 है) के अधीन जनवरी, 1999 में लेखांकन, संपरीक्षा, पूंजी बाजारों, राजकोषीय और धनीय नीतियों के क्षेत्रों में मूल अनुसंधान करने के लिए संस्थान में स्थापित किया गया था। अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा पूरी की गई परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :--

- **भारतीय रेल** – लेखांकन सुधार परियोजना के भागरूप में, उत्तर-पूर्वी रेल, जयपुर और रेल कोच कारखाना, कपूरथला में प्रोदभवन लेखांकन की पद्धति को आरंभ करने के संबंध में एक अग्रणी अध्ययन आरंभ किया गया था। इस अग्रणी अध्ययन के दौरान, वर्तमान नकद आधारित वित्तीय विवरणों के स्थान पर इन इकाईयों में प्रोदभवन आधारित वित्तीय विवरणों को तैयार किए जाने की समीक्षा की गई थी। इन अग्रणी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किए जाने पर अब अग्रणी अध्ययन में अनुसरित समान पद्धति और रणनीति के आधार पर पूरी भारतीय रेल में रेल के सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाईयों में प्रोदभवन आधारित लेखांकन को आरंभ किया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री ने 20 दिसंबर, 2016 को माननीय रेल मंत्री, अध्यक्ष, आईसीएआई, वित्तीय आयुक्त, भारतीय रेल और सीएजी, सीजीए, नीति आयोग, भारतीय रेल, डाक और टेलिग्राफ विभाग और अन्य सरकारी विभागों के अन्य वरिष्ठ सरकारी पदधारियों की उपस्थिति में प्रोदभवन लेखांकन कार्यान्वयन मैनुअल और लेखांकन नीतियों के साथ उत्तरी पश्चिमी जोनल रेल के लिए 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रोदभवन आधारित वित्तीय विवरण को जारी किया था।
- **पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) और उसके समनुषंगी** – पीएफसी की वित्तीय रिपोर्टिंग के विद्यमान अनुपालन तंत्र का अध्ययन करने संबंधी परियोजना, जिसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों, जिनमें सुधार किया जाना अपेक्षित था, पहचान करना और एक ऐसे अनुपालन ढांचे को, जो पीएफसी को इन अपेक्षाओं के संबंध में प्रभावी रूप से कार्यवाही करने में समर्थ बनाएगा और जो अनुपालन प्रबंध ढांचे को मजबूत करेगा।
- **कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता (विद्युत मंत्रालय)** – पूंजी व्यय उपापन प्रक्रिया और नीति अनुपालन ढांचे का पुनर्विलोकन।

8. अन्य मामले

8.1 आईसीएआई का वार्षिक समारोह

संस्थान के 67वें वार्षिक समारोह का आयोजन 8 फरवरी, 2017 को विज्ञान भवन के प्लेनरी हाल, नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें आईसीएआई ने अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाया था। इस अवसर पर न केवल वर्ष 2016-17 में आईसीएआई की उपलब्धियों की सफलताओं का स्मरण किया गया था, अपितु इसमें उसके भावी वृत्तिक प्रयासों की कार्ययोजना को भी उपदर्शित किया गया था। संघ के रेल मंत्री, सी.ए. सुरेश प्रभु ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लेखांकन वृत्ति, सरकार और अन्य पणधारियों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए थे। मुख्य अतिथि ने अपने संक्षिप्त किंतु अत्यधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण संबोधन द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित व्यक्तियों का दिल जीत लिया था। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में उनके वृत्तिक भ्रातृसंघ द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को अभिस्वीकृति प्रदान करते हुए उसकी सराहना की थी। उनका यह कथन कि हमें, चार्टर्ड अकाउंटेंटों के रूप में यह पता लगाना चाहिए कि हम सर्वोत्तम रूप से ऐसा क्या योगदान दे सकते हैं जो भारत को आज की तुलना में एक बेहतर राष्ट्र बनाएगा। इस अवसर पर योग्य सीए छात्रों और उत्कृष्ट प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं और विदेशी चैप्टरों को वर्ष के दौरान उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया गया था। इस अवसर पर आईसीएआई के विभिन्न प्रकाशनों का भी विमोचन किया गया था।

8.2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस समारोह – 1 जुलाई, 2017

आईसीएआई ने, 1 जुलाई 2017 को अपने 68 स्वर्णिम वर्षों के पूरा होने पर, अपने स्थापना दिवस को देश भर में की 5 प्रादेशिक परिषदों और 163 शाखाओं तथा 30 विदेशी चैप्टरों में धूमधाम से मनाया था। परंपरा के अनुसार, इंदिरा गांधी इनडोर सभागार, नई दिल्ली में

आईसीएआई के ध्वजारोहण संबंधी आयोजन के साथ ही सीए दिवस समारोह आरंभ हुआ था।

इंदिरा गांधी इनडोर सभागार, नई दिल्ली में 1 जुलाई 2017 को, आईसीएआई के 68 स्थापना दिवस को सीए दिवस के रूप में मनाने के लिए हुए एक बड़े समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी अद्वितीय शैली में, एक घंटा लंबा शक्तिशाली और विचारपूर्ण भाषण देते हुए यह कहा था कि “चार्टर्ड अकाउंटेंट भारतीय अर्थव्यवस्था के भारी भरकम स्तंभ हैं वे भारतीय आर्थिक जगत के ऋषि-मुनियों के समान हैं वे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के डाक्टरों के समान हैं सीए के नाम को अनुपालन और सटीकता के समरूप माना जाना चाहिए”। उन्होंने इस अवसर पर आईसीएआई की चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम की पुनरीक्षित शिक्षा और प्रशिक्षण स्कीम का भी अनावरण किया था।

प्रधानमंत्री ने इस आयोजन में बड़ी संख्या में उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित किया था जिनमें अनेक केबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नौकरशाह, आईसीएआई के सदस्य, छात्र और व्यापार जगत के प्रतिनिधि सम्मिलित थे और इसके अतिरिक्त कई लाख अन्य व्यक्तियों ने इसे आईसीएआई के प्रादेशिक कार्यालयों और राज्यों की राजधानियों में स्थित शाखाओं के माध्यम से देखा था, जिनमें अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री और संघ के मंत्री सम्मिलित थे। कुल मिलाकर राज्यों की 25 राजधानियों में 11 मुख्यमंत्रियों, 15 राज्यों के वित्त मंत्रियों/जीएसटी के प्रभारी मंत्रियों और संघ के 40 मंत्रियों ने इस आयोजन में भाग लिया था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सीए भ्रातृसंघ को “ईमानदारी के महोत्सव” का भाग बनने और उनकी सरकार के स्वच्छ अर्थव्यवस्था के संकल्प में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था और उनसे आग्रह किया था कि वे देश को अपने ग्राहक से पहले रखें और माल और सेवाकर (जीएसटी), जिसे उन्होंने “उत्तम और साधारण कर” के रूप में संबोधित किया था, की सफलता के लिए अथक कार्य करें।

राष्ट्रीय राजधानी में इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित व्यक्तियों में संघ के वित्त, रक्षा और कारपोरेट कार्य मंत्री, श्री अरुण जेटली, वित्त राज्य मंत्री, श्री संतोष गंगवार और श्री अर्जुन राम मेघवाल, संघ के विद्युत, कोयला, नई और नवीकरणीय ऊर्जा तथा खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री पीयूष गोयल, संघ के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री धर्मेन्द्र देवेन्द्र प्रधान और संघ के सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, एवीएसएम, राजस्व सचिव श्री हसमुख अधिया और सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, श्री तपन रे सम्मिलित थे।

श्री मोदी के संबोधन के पहले, उसी स्थान पर “अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव/ जीएसटी – वृत्तिक और कारबार परिप्रेक्ष्य” विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें संघ के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और राजस्व सचिव श्री हसमुख अधिया और उद्योग, व्यापार तथा मीडिया जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। लगभग तीन घंटों तक चले इस समारोह का सीधा प्रसारण राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम को आईसीएआई के प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं के माध्यम से पूरे भारत में प्रसारित किया गया था।

8.3 केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय

आईसीएआई का केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय उसके पणधारियों की सूचना संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसका उद्देश्य, आईसीएआई के वर्तमान और भावी सदस्यों, अनुसंधान अध्येताओं और पदधारियों को प्रारंभिक और द्वितीय मुद्रण और गैर-मुद्रण सामग्रियों का व्यापक और अद्यतन संग्रह उपलब्ध कराना है। पुस्तकालय ने समितियों, विभागों में जानकारी प्रदान करने और मूल्यवान सूचना का प्रसार करने के वृहत्तर उत्तरदायित्व को ग्रहण किया है, यह इस उत्तरदायित्व का निर्वहन पुस्तकों, ई-पुस्तकों, जर्नलों, मैगजीनों, ऑनलाइन डाटाबेसों, मुद्रित समाचारपत्रों और साथ ई-समाचारपत्रों के माध्यम से करता है। केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय विभिन्न समितियों के कार्य के लिए अपेक्षित जर्नलों और पुस्तकों को उपलब्ध कराने तथा उन्हें अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी है।

केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय पूर्णतया कंप्यूटरीकृत है और वह लिबर्टी-एक पुस्तकालय प्रबंधन साफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करता है। पुस्तकालय की सामग्रियों, जिनके अंतर्गत पुस्तकों, जर्नलों और लेखों का डाटा बेस भी है, के लिए विषय, लेखक, शीर्षक, टापिक, कुंजी शब्द और प्रकाशक के माध्यम से खोज की जा सकती है। ये अभिलेख पुस्तकालय में इंटरनेट ऑनलाइन सर्विस www.icaai.org पर “नो युअर इंस्टीट्यूट सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी” पुस्तकों, जर्नलों, लेखों आदि के लिए पुस्तकालय में ऑनलाइन सर्च ओपीएसी लिबर्टी के अधीन उपलब्ध है।

स्तंभ “एकाउंटेंट्स ब्राउजर” के अधीन लेखांकन वृत्ति से सुसंगत लेखों की अनुक्रमणिका को प्रत्येक मास “द चार्टर्ड अकाउंटेंट” जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि “एकाउंटेंट्स ब्राउजर” पूर्ववर्ती लेखों के अभिलेखागार के साथ महत्वपूर्ण/वृत्तिक लेखों की एक अनुक्रमणिका है। निर्देश सेवा विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और विद्वानों, संकाय और छात्रों को प्रदान की जाती है।

पुस्तकालय द्वारा अनेक ऑन लाईन डाटाबेस भी अर्जित किए गए हैं जो www.icaai.org –Central Council Library पर उपलब्ध हैं। पुस्तकालय ने इन डाटाबेसों को केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय परिसरों और विभिन्न विभागों तथा साथ ही आईसीएआई की प्रादेशिक

परिषदों के पुस्तकालयों में भी अपेक्षित सामग्री की सर्व को सुकर बनाने के लिए प्रतिष्ठापित किया है। पुस्तकालय में अनेक आनलाइन जर्नलों की ग्राहकी भी प्राप्त की गई है। केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय के क्रमशः प्रधान कार्यालय और नोएडा कार्यालय में स्थित पुस्तकालयों में अप्रैल, 2016 से 30 जून, 2017 की अवधि के दौरान जोड़े गए नए संसाधनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	शीर्षक	प्रधान कार्यालय	नोएडा सेक्टर-62
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	61	31
2.	ग्राहकी प्राप्त किए गए जर्नलों तक ई-पहुंच	13	01
3.	आनलाइन संसाधन	12	06
4.	अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकें	1049	207

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय नियमित रूप से अपने संसाधनों को अद्यतन बना रहा है ताकि वृत्तिक सदस्यों, छात्रों, संकायों आदि को नवीनतम और अद्यतन जानकारी और सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

8.4 संपादक बोर्ड

संपादक बोर्ड : वृत्तिक ज्ञान आधार को अक्षरशः समृद्ध बनाना

संपादक बोर्ड संस्थान की एक अस्थायी समिति है जिसका उद्देश्य सदस्यों को निरंतर रूप से समकालीन वृत्तिक ज्ञान, वृत्ति से हितबद्ध अन्य विषयों पर एक संरचित रीति में 'दि चार्टर्ड एकाउंटेंट' जर्नल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना है। जर्नल की पहुंच और प्रभाव का अनुमान इसके परिचालन से संबंधित आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो आज के दिन **2,80,000** है। यह आईसीएआई का ब्रांड अम्बेसेडर है और सदस्यों, छात्रों तथा बाह्य श्रोताओं के लिए संस्थान के प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज द चार्टर्ड एकाउंटेंट विश्व की ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं से टक्कर ले रहा है। विभिन्न विषयों और मुद्दों पर आईसीएआई के सदस्यों और द चार्टर्ड एकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों को अद्यतन बनाए रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए संपादक बोर्ड निरंतर प्रयास कर रहा है।

1 अप्रैल, 2016 से 30 जून, 2017 की अवधि के बीच संपादक बोर्ड द्वारा की गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

क्वालिटी और समकालीन अंतर्वस्तु :

- **विषयों की व्यापक रेंज को सम्मिलित किया जाना :** अप्रैल, 2016 से जून, 2017 तक के जर्नल के अंकों में विभिन्न नवीन विषय संबंधी मुद्दों के अधीन 350 से अधिक लेख/फीचर और विभिन्न विषयों पर रिपोर्टों का प्रकाशन किया गया था।
- **प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट के अवसर पर ई-फ्लैश :** संसद् में बजट के प्रस्तुतिकरण और बजट संबंधी मुद्दों के जर्नल में वास्तविक प्रकाशन के बीच समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए, सदस्यों को वास्तविक समय में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संसद् में बजट के वास्तविक प्रस्तुतिकरण के 48 घंटों के भीतर वित्त विधेयक में अंतर्विष्ट संशोधनों के एक ई-प्रकाशन (ई-फ्लैश) की अवधारणा तैयार की गई थी, इसे विकसित किया गया था और आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था और उसके लिंक को सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेज दिया गया था।
- **जर्नल के अद्यतन विधिक खंड का उन्नयन :** जर्नल के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले खंडों में से एक विधिक निर्णयों संबंधी खंड/फीचर को मूल्यवर्धित सेवा के रूप में आगे और समुन्नत किया गया था और तीन नए क्षेत्रों - दिवाला विधियों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान विधियों और आईसीएआई अनुशासन संबंधी मामलों - को जून, 2017 के अंक से जर्नल के इस खंड में जोड़ा गया है।

अंकीय पाठ को अद्यतन करना

- **ई-जर्नल :** द चार्टर्ड एकाउंटेंट जर्नल, जो कि इस जर्नल का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, आईसीएआई की वेबसाइट www.icaai.org पर आनलाइन रूप से एक उच्च प्रौद्योगिकी और उपयोक्ता मित्र ई-मैगजीन के रूप में उपलब्ध है, को और अधिक समुन्नत किया गया था तथा उसे नवीनतम एचटीएमएल 5 प्रौद्योगिकी पर आधारित एक नए ई-मैगजीन मंच वी 6 पर पूर्ण रूप से स्थानांतरित किया गया था। ई-जर्नल का नया पाठ, पूर्ववर्ती पाठ की तुलना में तीव्र तथा अधिक क्रियाशील है, जिससे एक बेहतर उपयोक्ता अनुभव प्राप्त होता है तथा यह और अधिक बेहतर मोबाइल अनुरूपता प्रस्थापित करता है, जो चार्टर्ड एकाउंटेंटों की नई पीढ़ी की अपेक्षाओं के अनुरूप है।
- **पीडीएफ प्ररूप में जर्नल :** तथापि, पाठकों के लिए और अधिक तथा वैकल्पिक सुविधाओं को आरंभ करने, विशिष्ट रूप से अंतर्वस्तुवार पृथक् डाउनलोड के लिए जर्नल को पीडीएफ प्ररूप में वेबसाइट पर रखा जाता है और साथ ही इसके लिए अनुक्रमणिका पद्धति को अपनाया जाता है। अंकीय जर्नल के जुलाई, 2002 के आगे से पिछले सार संग्रह आईसीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

- **मोबाइल पर जर्नल** : इसके अतिरिक्त, यह ई-जर्नल अब मोबाइल पर भी उपलब्ध है तथा यह आईओएस (आई पैड/आई फोन आदि) और एंड्रयॉड युक्तियों के समनुरूप है। इस जर्नल तक पहुंच को <http://www.icaai.org/> के अधीन 'ई-जर्नल' टैब पर सुकर बनाया जा सकता है। यह ई-जर्नल आईसीएआई मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।
- **जर्नल हार्डलाईट ईमेलर्स** : एक अतिरिक्त सेवा के रूप में जर्नल के प्रत्येक अंक की विशिष्टियों को संक्षिप्त रूप में तथा जर्नल में सम्मिलित अध्यक्ष के संदेश को सभी सदस्यों को ई-मेल किया जाता है।

'आई गो ग्रीन विद आईसीएआई' पहल

आईसीएआई के बहु आयामी हरित अभियान के भागरूप में, हरित क्रांति की सोच रखने वाले सदस्यों और द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों को हाल ही में एक विकल्प प्रदान किया गया था, जिसके अधीन वे वृक्षों को बचाने के लिए जर्नल की हार्ड प्रति को न लेकर जर्नल के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक पाठों का विकल्प ले सकते थे। इस संबंध में प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए एक माइक्रो वेबसाइट को भी स्थापित किया गया था। एक उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया के रूप में, लगभग 7,000 सदस्यों/पाठकों ने जर्नल की हार्ड कापी को न लेने का विकल्प चुना था। यह सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। इस हरित पहल का समर्थन करने वाले आईसीएआई के सदस्य, आईसीएआई के साथ स्वयं को रजिस्टर करने के लिए <http://www.icaai.org/newpost.html?postid=12763&cid=240> पृष्ठ पर जा सकते हैं।

- **आईसीएआई के हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में योगदान और अन्य उपलब्धियां** : संपादक बोर्ड ने सम्मेलन की प्रत्येक दिन की कार्यवाहियों के पूर्ण व्यौरों के साथ दैनिक क्रान्तिक (समाचार-पत्र) निकाला था, जिसे सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बीच परिचालित किया गया था।
- **जर्नल के कागज की क्वालिटी की निगरानी** : मुद्रक द्वारा जर्नल में प्रयुक्त किए जाने वाले कागज की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली सतत पूर्वावधानी/निगरानी प्रक्रिया के भाग रूप में, कार्यालय ने स्वैच्छिक रूप से, केंद्रीय पल्प और कागज अनुसंधान संस्थान (सीपीपीआरआई), जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, के माध्यम से मुद्रक द्वारा प्रयुक्त कागज की परीक्षा की थी।
- **सभी कानूनी अनुपालनों को सुनिश्चित करना** : जर्नल के पब्लिकेशन के संबंध में सभी कानूनी विधिक अनुपालनों को सुनिश्चित किया गया था। इसके अंतर्गत जर्नल के भारत में समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार (आरएनआई) के प्रमाणपत्र का नवीकरण तथा शासकीय रियायती दरों पर जर्नल के निर्बाध और समय पर मुद्रण तथा प्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्ररूप ख का पुनरीक्षण भी था।
- **साहित्य-चोरी रोधी नीति** : शिक्षाविदों, आईसीएआई के सदस्यों, छात्रों आदि सहित लेखकों द्वारा चोरी की गई साहित्य की अंतर्वस्तु को प्रस्तुत किए जाने के मामलों में हुई अत्यधिक वृद्धि का संज्ञान लेते हुए, जिसके कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल की विश्वसनीयता और विश्वस्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी, एक व्यापक साहित्य-चोरी रोधी नीति को स्थापित किया गया है। इस प्रक्रिया को, सुसंगत साहित्य-चोरी रोधी साफ्टवेयर के नवीकरण और उसे पुनः प्रचालन में लाकर सुदृढ़ बनाया गया था।
- **मुद्रित/प्रेषित की गई जर्नल की प्रतियों की कुल संख्या के सत्यापन की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जाना** : जैसा कि हाल ही में संपादक बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया गया है, मुद्रित/प्रेषित की गई जर्नल की प्रतियों की कुल संख्या के सत्यापन की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया गया है, इस प्रक्रिया के दौरान एक ऐसे तंत्र को स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा आईसीएआई के मुंबई स्थित कार्यालय (डब्ल्यूआईआरसी) के एक कार्मिक ने, यह अभिनिश्चित करने के लिए कि मुद्रण आदेश में उल्लिखित सभी जर्नलों को प्रेषित किया जा रहा है, (मई, 2017 के अंक से) मुंबई जीपीओ में जर्नल को डाक द्वारा प्रेषित किए जाने की तारीखों का मासिक निरीक्षण करना आरंभ किया है। यह तंत्र नवी मुंबई आधिकारिक संपरीक्षक द्वारा नियमित पृथक् सत्यापन के अतिरिक्त है।

8.5 भारत का लेखांकन संग्रहालय

भारत का लेखांकन संग्रहालय, भारत और विश्व में लेखांकन वृत्ति की कहानी सुनाता है और उसके प्रारंभ और विकास का इतिवृत्त प्रस्तुत करता है। अभी तक, संग्रहालय ने वृत्ति की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करने के लिए संस्थान की पांच प्रादेशिक परिषदों, 13 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और 107 शाखाओं के परिसरों में अपने प्रोटोटाइप को स्थापित किया है। इन परिसरों में, संग्रहालय दुर्लभ ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण शिल्प-उपकरणों, दस्तावेजों, छवियों और पांडुलिपियों आदि को प्रदर्शित करता है। यह पूर्व, मध्यकालीन तथा आधुनिक भारत में लेखांकन व्यवहारों और व्यवसायियों के संबंध में टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

पणधारियों का ध्यान आकृष्ट करना

वर्ष 2009 में इसकी स्थापना से ही, संस्थान के सदस्यों और छात्रों के नियमित दौरों के अलावा संग्रहालय निरंतर रूप से एनसीआर क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं से वाणिज्य और प्रबंध स्नातकों तथा स्नातकोत्तर छात्रों को निरंतर अपने परिसर की ओर आकृष्ट करता रहा है।

संग्रहालय में संस्थागत दौरे किए गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में से एक महाविद्यालय ने लगातार अपने वाणिज्य के स्नातकोत्तर छात्रों के तीसरे बैच को भेजा है।

संग्रहालय की वेबसाइट

संग्रहालय की वेबसाइट, अर्थात् <http://ami-icai.org/>, को कार्यरत बनाया गया है और इस कार्य के लिए संग्रहालय के परिसरों को व्यौरेवार रूप से फोटोग्राफ करना अपेक्षित था। संग्रहालय की वेबसाइट में संभावी आंगतुकों, दानकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं आदि और संग्रहालय के अन्य पणधारियों के लिए सभी सुसंगत सूचना उपलब्ध है।

विद्यमान डिजिटल पैन्लों और नई थीमों/शृंखलाओं संबंधी पैन्लों का पुनरीक्षण

कुछ अंकीय पैन्लों को सारवान रूप से पुनरीक्षित किए जाने के पश्चात् दो नई थीमों/शृंखलाओं, अर्थात् विश्व लेखांकन और भारतीय लेखांकन के पिता संबंधी कार्य (अर्थात् अंकीय पैन्लों के लिए पाठ), जिन्हें प्रतिष्ठापित किया जाना है, का कार्य अग्रिम प्रक्रम पर है।

8.6 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में संशोधन

अन्य बातों के साथ, परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए परिषद् चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में प्रारूप संशोधनों को केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया गया था। ये प्रारूप संशोधन, सरकार के सैद्धांतिक अनुमोदन के पश्चात् भारत के राजपत्र में अप्रैल, 2016 में साधारण जनता से टीका-टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे। प्राप्त हुई टीका-टिप्पणियों पर परिषद् अक्टूबर, 2016 में हुई उसकी बैठक में विचार किया गया था। प्राप्त टीका-टिप्पणियों के आधार पर परिषद् ने कतिपय प्रारूप संशोधनों को उपांतरित करने का विनिश्चय किया था और इस प्रकार उपांतरित प्रारूप संशोधनों को एक बार पुनः अंतिम अनुमोदन हेतु केंद्रीय सरकार को 2016 में अग्रेषित किया गया था। तथापि, अधीनस्थ विधान की अपेक्षा को पूरा करने के लिए ये प्रारूप संशोधन, एक बार पुनः भारत के राजपत्र में दिसंबर, 2016 में साधारण जनता की टीका-टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए अधिसूचित किए गए थे और सम्यक् प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् उन्हें अनुमोदन हेतु पुनः केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया गया था। केंद्रीय सरकार ने मई, 2017 में अपना अंतिम अनुमोदन प्रदान किया था। इन संशोधनों को अंतर्विष्ट करने वाली अंतिम अधिसूचना को 25 मई, 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और तदनुसार इन संशोधनों को उक्त तारीख से प्रवृत्त किया गया है।

9. सदस्य

9.1 सदस्यता

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईसीएआई द्वारा 16,970 नए सदस्यों को दर्ज किया गया था, जिससे 1 अप्रैल, 2017 को आईसीएआई की कुल सदस्यता संख्या 2,70,307 हो गई है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, पूर्व वर्ष में 2,744 की संख्या की तुलना में 6,712 सहयोजित सदस्य अध्येता के रूप में प्रविष्ट किए गए थे। 1.4.2017 को सदस्यों की कुल संख्या के व्यौरे निम्नानुसार हैं :

सदस्यों का प्रवर्ग	अध्येता (1)	सहयोजित (2)	स्तंभ (1) और (2) का योग
पूर्णकालिक व्यवसाय में	72263	48576	120839
अंशकालिक व्यवसाय में	2866	5417	8283
जो व्यवसाय में नहीं हैं	13593	127592	141185
योग	88722	181585	270307

9.2 दीक्षांत समारोह

आईसीएआई, नवम्बर, 2008 से अपने नए नामांकित सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है। "दीक्षांत समारोह 2016" का आयोजन जनवरी, 2017 में निम्नलिखित स्थानों पर किया गया था :

1. अहमदाबाद	6. कोलकाता
2. मुंबई	7. जयपुर
3. पुणे	8. कानपुर
4. चैन्नई	9. नई दिल्ली
5. हैदराबाद	

9.3 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कल्याण निधि

दिसम्बर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कल्याण निधि ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों, जो संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं और उनके आश्रितों को, उनके भरणपोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा आदि की अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। निधि की वित्तीय और अन्य विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

सदस्यता के व्यौरे

1.	31 मार्च, 2016 को कुल आजीवन सदस्य	128500
2.	31 मार्च, 2017 को कुल आजीवन सदस्य	132883
3.	नए आजीवन सदस्यों में कुल वृद्धि (31 मार्च, 2017 को यथाविद्यमान)	4383

वित्तीय विशिष्टियों के व्यौरे

	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (रुपए)	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (रुपए)
1. दी गई कुल वित्तीय सहायता	1,13,28,500	1,09,34,500
2. प्रशासनिक खर्चे	567	582
3. वर्ष के दौरान निधि में अधिशेष	69,93,000	71,96,531
4. निधि का अतिशेष	1,63,54,000	93,60,845
5. कोरपस का अतिशेष	18,49,63,000	17,21,68,397

वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय के व्यौरे निम्नानुसार हैं :

आजीवन सदस्यता के रूप में अभिदाय	1,27,95,000/- रुपए
वार्षिक सदस्यता के रूप में अभिदाय	19,57,000/- रुपए
स्वैच्छिक अभिदाय	25,29,000/- रुपए
योग	1,72,81,000/- रुपए

9.4 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, 1000 रुपए प्रतिमास के मूल्य की 100 छात्रवृत्तियां, आर्टिकलड प्रशिक्षण करने वाले छात्रों को दी जा रही हैं। निधि की आजीवन सदस्यता 31 मार्च, 2016 को 7370 के मुकाबले 31 मार्च, 2017 को बढ़कर 7682 हो गई थी। 31 मार्च, 2016 को निधि के पास जमा अतिशेष 39,91,584/- रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2017 को 49,60,000/- रुपए है।

9.5 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि (सीएसबीएफ)

आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य और उद्देश्यों से अगस्त, 2008 में इस निधि की स्थापना की गई थी। 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 513 ऐसे आर्टिकलड सहायकों, जो आईपीसीसी और आईआईपीसीसी के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं, को वित्तीय सहायता के रूप में 1500 रुपए प्रति मास की दर पर और 205 ऐसे आर्टिकलड सहायकों, जो फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं, को वित्तीय सहायता के रूप में 2000 रुपए प्रति मास की दर पर एक वर्ष के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। 31 मार्च, 2016 को 11,43,35,000/- रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2017 को साधारण निधि में 12,59,75,000/- रुपए का अतिशेष जमा था।

10. अध्ययन बोर्ड

अध्ययन बोर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यचर्या के प्रशासन और चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम करने वाले लगभग 2,50,656 छात्रों को सैद्धांतिक अनुदेश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष के दौरान बोर्ड की महत्वपूर्ण पहलों और उपलब्धियों को नीचे उल्लिखित किया गया है :

I. शैक्षिक अंतःनिवेश

शिक्षा और प्रशिक्षण का पुनर्विलोकन : चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम एक सक्रिय प्रकृति का पाठ्यक्रम है, जिसका आवधिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है ताकि समकालीन आर्थिक विकास की घटनाओं की तुलना में वृत्ति अपनी अग्रता बनाए रखे। आईसीएआई ने हाल ही में, तीन वर्ष से अधिक अवधि के परिश्रम के पश्चात् शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी अपनी विद्यमान स्कीम का पुनर्विलोकन किया था और ब्यौरेवार पद्धतियों का अनुपालन करने के पश्चात् उसने शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी पुनरीक्षित स्कीम का प्रारूपण किया था। पणधारियों के साथ ब्यौरेवार परिचर्चाओं की एक शृंखला और लोक उदभासन के पश्चात् पुनरीक्षित स्कीम को अंतिम रूप प्रदान किया गया था और उसे 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है।

अध्ययन सामग्रियों का पुनरीक्षण : छात्रों की जानकारी को अद्यतन करने की सतत प्रक्रिया के भागरूप में मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल स्तर पर विभिन्न अध्ययन सामग्रियों की अंतर्वस्तु को अद्यतन/पुनरीक्षित किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित सामग्रियों को भी जारी किया गया था और उन्हें निःशुल्क डाउनलोडिंग प्रसुविधा के साथ वेबसाइट पर भी रखा गया था :

- 1) चुने गए मामलों का सार संग्रह
- 2) अनुपूरक अध्ययन सामग्री :--
 - लेखांकन
 - कारबार विधि नैतिक और संसूचना
 - कराधान
 - निगम और संबद्ध विधियां
 - प्रत्यक्ष कर विधियां और अप्रत्यक्ष कर विधियां
- 3) पुनरीक्षण प्रश्न-पत्र और सुझाए गए उत्तर

इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ भूटान (आईसीएबी) की चार्टर्ड अकाउंटेंटों की पाठ्यचर्या का विकास : विश्व बैंक ने आईसीएआई को, “आईसीएबी की चार्टर्ड अकाउंटेंटों की पाठ्यचर्या के विकास, उप विधियों के प्रारूपण और एएएसबीबी के लिए नियमों और विनियमों के प्रारूपण के लिए परामर्शी सेवा” उपलब्ध कराने की परियोजना सौंपी है। बोर्ड ने निर्धारित तारीख से काफी समय पूर्व सभी स्तरों पर शिक्षा और प्रशिक्षण की स्कीम तथा सभी विषयों की पाठ्यचर्या और अध्ययन सामग्री को विकसित किया था।

II. आईटी संबंधी पहलें

आईसीएआई क्लाउड परिसर सीए पाठ्यक्रम के छात्रों की जानकारी, नामांकन, शैक्षणिक, प्रशासनिक, परीक्षा संबंधी तथा अन्य अपेक्षाओं के लिए एकल विंडो का कार्य करता है। ईट और गारे से बने परिसर की प्रणाली से आगे बढ़ते हुए, यह परिसर बटन के एक क्लिक के साथ ही छात्रों को उनके घर पर सीए पाठ्यक्रम के लिए दुरस्थ शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह निम्नलिखित दुरस्थ शिक्षा सुविधाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराता है :

- **वीडियो व्याख्यान :** लेखा, कराधान, वित्तीय प्रबंध, लागत लेखांकन आदि जैसे व्यावहारिक विषयों के लिए वीडियो आधारित प्रशिक्षण (वीबीटी) व्याख्यान आईसीएआई के क्लाउड परिसर पर उपलब्ध हैं, जिनका उद्देश्य ब्लैक बोर्ड पर कदम-दर-कदम व्यावहारिक समस्या की समाधान प्रक्रिया का अध्यापन करना है। अब बोर्ड ने सैद्धांतिक विषयों के लिए भी वीडियो व्याख्यानों को रिकार्ड और अपलोड करना आरंभ कर दिया है ताकि बेहतर अवधारणात्मक स्पष्टता को प्राप्त किया जा सके। इस समय, 20 जून, 2017 तक, 428 घंटों के 495 व्याख्यानों को क्लाउड परिसर पर रख दिया गया है।
- **वेबकास्ट :** मार्च-अप्रैल, 2017 मासों के दौरान फाइनल और मध्यवर्ती (आईपीसी) के लिए मई, 2017 में होने वाली परीक्षा के लिए प्रत्येक विषय को उत्तीर्ण करने के लिए पद्धति के संबंध में लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया गया था। प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं की सहायता से जीएसटी, समवर्ती संपरीक्षा आदि जैसे विषयों पर विशेषीकृत वेबकास्टों और उनके पश्चात् एक दिवसीय संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है। इन वेबकास्टों की रिकार्डिंग बाद में देखने के लिए आईसीएआई के क्लाउड परिसर पर उपलब्ध है।
- **छात्र एलएमएस पर ई पठन :** यह 20 जून, 2017 को यथाविद्यमान 797 घंटों के ई-व्याख्यान उपलब्ध कराता है। लगभग सभी अध्यायों के लिए स्वनिर्धारण प्रश्नोत्तर भी उपलब्ध हैं।
- **बीओएस ज्ञान पोर्टल :** बीओएस ज्ञान पोर्टल सीए पाठ्यक्रम के लिए सभी शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराता है।
- **आर्टिकल नियोजन पोर्टल :** आर्टिकल नियोजन पोर्टल लिंक छात्रों को, उनके अधिमानी अवस्थान पर व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए सीए फर्मों के साथ ऑनलाइन रूप से रजिस्टर करने और चुने जाने के लिए समर्थ बनाता है।

- **जीएमसीएस/ओसी/आईटीटी पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन रजिस्ट्रीकरण पोर्टल :** यह आनलाइन रजिस्ट्रीकरण पोर्टल छात्रों को जीएमसीएस/ओसी /आईटीटी पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन रजिस्ट्रीकरण, अधिमानी अवस्थानों पर सुविधापूर्ण बैचों का चयन करने, बैच अंतरित करने, संकाय के आबंटन, पाठ्यक्रम संबंधी अनुसूची, प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करने और प्रमाणपत्र का सृजन करने में समर्थ बनाता है।

III. अन्य पहलें

पठन कक्ष : 146 पुस्तकालय-सह-पठन कक्षों तथा 41 अतिरिक्त पठन कक्षों को प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा चलाया जा रहा है।

मौखिक कोचिंग कक्षा

(i) **प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के द्वारा :** सीए पाठ्यक्रम के छात्रों को कक्षा अध्यापन उपलब्ध कराने के लिए प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं द्वारा मौखिक कोचिंग कक्षाओं का आयोजन किया गया है। वर्तमान में, छात्रों के लिए 62 केंद्र कोचिंग कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं, जिनमें से 26 केंद्र सीपीटी के लिए, 24 केंद्र आईपीसीसी के लिए और 12 केंद्र फाइनल परीक्षा के छात्रों के लिए इन कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं।

(ii) **प्रत्यायित संस्थाएं :** प्रत्यायित संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली मौखिक कोचिंग कक्षाएं, युक्तियुक्त लागत पर क्वालिटी कक्षा कोचिंग उपलब्ध कराके आईसीआई के प्रयासों को अनुपूरित करती हैं। वर्तमान में, 53 संस्थाएं सीपीटी पाठ्यक्रम कक्षाओं, 11 संस्थाएं आईपीसी पाठ्यक्रम कक्षाओं और दो संस्थाएं फाइनल पाठ्यक्रम कक्षाओं को उपलब्ध करा रही हैं।

मौक परीक्षा : प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के माध्यम से मई/नवम्बर और जून/दिसम्बर की मुख्य परीक्षाओं के लिए छात्रों को, परीक्षाओं हेतु उनकी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करने के विचार से मध्यवर्ती (आईपीसी)/फाइनल और सीपीटी स्तर की मौक परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। मई, 2016 के लिए मध्यवर्ती और फाइनल स्तर शृंखला 1 और 2 में 20,129 छात्र और जून, 2016 के लिए सीपीटी स्तर पर 17,561 छात्र उपस्थित हुए थे।

नवंबर, 2016 के लिए मध्यवर्ती और फाइनल स्तर शृंखला 1 और 2 में 20,578 छात्र और दिसंबर, 2016 के लिए सीपीटी स्तर पर 7,500 छात्र उपस्थित हुए थे।

मई, 2017 के लिए मध्यवर्ती और फाइनल स्तर शृंखला 1 और 2 में 14,135 छात्र और जून, 2017 के लिए सीपीटी स्तर पर 909 छात्र उपस्थित हुए थे।

आईसीआई स्वर्ण पदक/वृत्तिदान निधि : तेजपुर विश्वविद्यालय, नापाम, असम के साथ स्वर्ण पदक का पुरस्कार देने के लिए नई वृत्तिदान निधि का सृजन किया गया है।

सीए छात्रों के लिए निःशुल्क टेलीफोन सेवा : अध्ययन बोर्ड ने 11 मई, 2017 से, देश भर के सीए छात्रों के प्रश्नों और समस्याओं का उत्तर देने के लिए एक निःशुल्क टेलीफोन सेवा आरंभ की है। 18001211330, टेलीफोन नंबर प्रातः 10 बजे से सायं 5.30 तक सोमवार से शुक्रवार तक कार्य करता है। इस सेवा पहल का प्रयोजन छात्रों को उनकी अपेक्षा के अनुसार जैनरिक और विषय विनिर्दिष्ट, दोनों प्रकृति की सूचना समय पर उपलब्ध कराना है। बीओएस स्थित विषय-वस्तु का संकाय, सायं 3 बजे से 4 बजे तक के समय के अनुसार विषय-वस्तु विनिर्दिष्ट प्रश्नों का उत्तर देंगे। यह सुविधा पूरे राष्ट्र में अवस्थित छात्रों के लिए संपर्क के एकल बिन्दु के रूप में कार्य करेगी। यह नंबर आईसीआई की संपूर्ण छात्र संख्या के लिए जैनरिक और साथ ही विषय विनिर्दिष्ट सहायता टेलीफोन लाइन के रूप में कार्य करेगा।

वाद-विवाद प्रतियोगिता : प्रादेशिक परिषदों सहित 51 शाखाओं द्वारा शाखा स्तर पर वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिनमें 1160 छात्रों ने भाग लिया था और डब्ल्यूआईआरसी, एसआईआरसी, ईआईआरसी और सीआईआरसी द्वारा प्रादेशिक स्तर पर वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिनमें 30 छात्रों ने भाग लिया था।

सीए छात्र समारोह : वर्ष के दौरान, 3 प्रादेशिक परिषदों सहित 44 शाखाओं द्वारा 44 सीए छात्र समारोह का आयोजन किया गया था, जिनमें 14,756 छात्रों ने भाग लिया था।

खेल प्रतियोगिताएं : वर्ष के दौरान, 3 प्रादेशिक परिषदों सहित 62 शाखाओं द्वारा 73 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिनमें 9,983 छात्रों ने भाग लिया था।

IV. विकास कार्यक्रम**आईटीटी केंद्र और अग्रिम आईटीटी :**

अभी तक 156 पीओयू देश भर में क्रमशः आईटीटी और अग्रिम आईटीटी पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान (1 अप्रैल, 2016 – 30 जून, 2017) संचालित किए गए बैचों और छात्रों के व्यौरे निम्नानुसार हैं :

पाठ्यक्रम का नाम	बैचों की संख्या	छात्रों की संख्या
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रशिक्षण	1974	57,288
अग्रिम आईटीटी	314	7,855

विकास कार्यक्रम : 06-08 अप्रैल, 2016 के दौरान कोलकाता में अग्रिम आईटीटी पाठ्यक्रम के लिए एक भौतिक एफडीपी का आयोजन किया गया है, जिसमें 34 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया था।

अभ्यास मैनुअल : आईटीटी पाठ्यक्रम के भाग रूप में बेहतर व्यवहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए उक्त पाठ्यक्रम हेतु सीडी सहित एक अभ्यास मैनुअल को उपलब्ध कराया गया है।

अध्ययन सामग्रियों का पुनरीक्षण : शिक्षा और प्रशिक्षण की पुनरीक्षित स्कीम के अधीन परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अनुसार आईसीआईटीएसएस (आईटी) और एआईसीआईटीएसएस (अग्रिम आईटी) के पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु को विकसित किए जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

आनलाइन संदाय : आईसीआईटी ऐसे छात्रों के लिए, जो आनलाइन रजिस्ट्रीकरण पोर्टल के माध्यम से साफ्ट कौशल पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रीकरण कर रहे हैं, आनलाइन संदाय सुविधा को आरंभ किया है। इस सुविधा का उपयोग करते हुए छात्र पूरे देश भर से क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके आनलाइन रूप से पाठ्यक्रम फीस का संदाय करने में समर्थ होंगे। यह बैचों से मांगदेय ड्राफ्ट तैयार कराने में लगने वाले छात्रों के समय और प्रयासों को बचाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री के डिजीटल भारत अभियान का भी समर्थन करेगी।

छात्रों के लिए वृत्तिक कौशल विकास संबंधी चार सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम : वर्ष के दौरान उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में 11 बैचों का संचालन किया गया था और 505 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया था।

अंग्रेजी बोलने, लेखन कौशलों और कारबार परस्पर संपर्क संबंधी अल्पकालिक पाठ्यक्रम/कार्यशाला : दो प्रादेशिक परिषद् सहित 12 शाखाओं ने अंग्रेजी बोलने, लेखन कौशलों और कारबार संबंधी परस्पर संपर्क से संबंधित 15 अल्पकालिक पाठ्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन किया था, जिनमें 704 छात्रों ने भाग लिया था।

विशेष परामर्शी कार्यक्रम (सीए परीक्षाओं की चुनौती का सामना कैसे करें ?) :

वर्ष के दौरान 42 शाखाओं ने, जिनके अंतर्गत 3 प्रादेशिक परिषदें भी थी, 73 विशेष परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिनमें 5,615 छात्रों ने भाग लिया था।

एकदिवसीय संगोष्ठियां : वर्ष के दौरान, प्रादेशिक 4 परिषदों सहित 61 शाखाओं द्वारा 217 एकदिवसीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था, जिनमें 20,559 छात्रों ने भाग लिया था।

वक्तृता प्रतियोगिता : 5 प्रादेशिक परिषदों सहित 90 शाखाओं द्वारा शाखा स्तरीय वक्तृता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिनमें 1256 छात्रों ने भाग लिया था। इसके अलावा 5 प्रादेशिक स्तरीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय वक्तृता प्रतियोगिता का आयोजन 27 नवंबर, 2016 को कोच्चि, एर्नाकुलम में किया गया था, जिनमें 14 छात्रों ने भाग लिया था।

क्विज प्रतियोगिताएं : 5 प्रादेशिक परिषदों सहित 92 शाखाओं द्वारा शाखा स्तरीय क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिनमें 1814 छात्रों ने भाग लिया था। इसके अलावा 5 प्रादेशिक स्तरीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 27 नवंबर, 2016 को कोच्चि, एर्नाकुलम में किया गया था जिनमें 10 छात्रों ने भाग लिया था।

V. एमओ/यू/एमआरए/मान्यता/अन्य ठहराव

सीए पाठ्यक्रम को पीएच.डी कार्यक्रम के लिए मान्यता : विभिन्न विश्वविद्यालयों से निरंतर संपर्क करने के पश्चात् अध्ययन बोर्ड पीएचडी/फैलो कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए 101 विश्वविद्यालयों, 6 भारतीय प्रबंध संस्थानों और 2 आईआईटी, बंबई और मद्रास (कुल 109) से सीए पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल रहा है।

VI. सम्मेलन/सभाएं/संगोष्ठियां और अन्य क्रियाकलाप

- **राष्ट्रीय सभा, अखिल प्रादेशिक छात्र सम्मेलन, अखिल भारतीय सम्मेलन और सीए छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन :** इस अवधि के दौरान, अहमदाबाद में अखिल प्रादेशिक छात्र सम्मेलन, एनकुलम में अखिल भारतीय सम्मेलन और हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अलावा देश के विभिन्न भागों में 27 राष्ट्रीय सभाओं का आयोजन किया गया था और लगभग 30,400 छात्रों ने इन छात्र सम्मेलनों में भाग लिया था।
- **सीए छात्रों के लिए प्रादेशिक/उप प्रादेशिक/राष्ट्रीय सभा/सीए छात्र सम्मेलन :** इस अवधि के दौरान, एक प्रादेशिक सम्मेलन और छह उप प्रादेशिक सम्मेलनों के अलावा देश के विभिन्न स्थानों पर 13 राष्ट्रीय सभाओं और तीन सीए छात्र सम्मेलनों का आयोजन किया गया था और लगभग 11,700 छात्रों ने इन छात्र सम्मेलनों में भाग लिया था।

विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त संगोष्ठियां : देश भर में फैले 4 विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अनावरण समारोह : अध्ययन बोर्ड ने 3 जून, 2016 को मुंबई में, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संबंधी अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस समारोह का उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री श्री श्रीपाद यशो नाईक ने मुख्य अतिथि के रूप में किया था, उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने भी सम्मानित अतिथि के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाई थी और 1000 से अधिक उपस्थित सदस्यों और छात्रों के समक्ष जीवन प्रक्रिया के भाग रूप में योग के फायदों के प्रति अपने बोध को साझा किया था। इस समारोह में श्री अनिल कुमार गनेरीवाला, संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय, अध्यक्ष, बीओएस, उपाध्यक्ष, बीओएस और कुछ केंद्रीय परिषद सदस्य उपस्थित हुए थे। डॉ. शाहिद ए. मर्चेट, संस्थापक सदस्य, लीलावती अस्पताल ने "स्वस्थ, दीर्घ और खुशहाल जीवन का मेरा रहस्य" विषय पर भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित किया, जबकि श्रीमती हंसा जे. योगेंद्र योग संस्थान की निदेशक ने "जीवन शैली प्रबंध जहां योग जीवन का तरीका है" विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की आयुष मंत्रालय और साथ ही अन्य प्रतिभागियों द्वारा भलीभांति सराहना की गई थी।

5 सितंबर, 2016 को शिक्षक दिवस : अध्ययन बोर्ड ने 5 सितंबर, 2016 को अपनी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के माध्यम से देश भर में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया था, ताकि सीए और सीए छात्रों के बीच एक सुदृढ़ अध्यापक और छात्र संबंधों को स्थापित किया जा सके। छात्रों के बीच उनके शिक्षकों के प्रति आदर और आभार की भावना का सृजन करने के लिए बोर्ड ने कुछ ई-कार्डों और एसएमएस कोड्स को छात्रों को उपलब्ध कराया था। इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों संबंधी क्रियाकलाप, अर्थात् वक्तृता प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता और शतरंज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। अध्यक्ष, आईसीएआई ने केंद्रीय परिषद् सदस्यों के साथ उस दिवस को उत्कृष्टता दिवस केंद्र में, अध्ययन बोर्ड द्वारा 5 सितंबर, 2016 को सीओई, हैदराबाद के माध्यम से आयोजित लाइव वेबकास्ट के माध्यम से साधारण रूप से सदस्य और छात्र भ्रातृसंघ को संबोधित किया था। शिक्षक दिवस – मन की बात के संबंध में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रिकार्ड किए गए संबोधन को भी वेबकास्ट के माध्यम से सदस्यों और छात्रों को सुनाया गया था।

VII. छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियां

अध्ययन बोर्ड विभिन्न प्रवर्गों, अर्थात् मेरिट, मेरिट-सह-आवश्यकता, आवश्यकता आधारित और कमजोर वर्गों को, वृत्तिदान के अधीन वर्ष में दो बार छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान अध्ययन बोर्ड ने उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन चुने गए छात्रों को 575 छात्रवृत्तियां प्रदान की थी।

VIII. कैरियर परामर्श संबंधी समूह

तत्कालीन कैरियर परामर्श संबंधी समिति को माध्यमिक, वरिष्ठ/उच्चतर माध्यमिक, स्नातक/ स्नातकोत्तर छात्रों और साथ ही अन्य पणधारियों के बीच विशेष सीए पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान के साथ वाणिज्य शिक्षा का संवर्धन करने के उद्देश्य से फरवरी, 2015 में सृजित किया गया था, अध्ययन बोर्ड के अधीन परिषद् वर्ष 2017-18 में कैरियर परामर्श संबंधी समूह के नाम से सृजित किया गया था।

क्रियाकलाप एक दृष्टि में**वाणिज्य विशेषज्ञ – 2016 : कक्षा 9, 10, 11 और 12 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए योग्यता खोज परीक्षा**

आईसीएआई वाणिज्य विशेषज्ञ – 2016 के नाम से ज्ञात वाणिज्य योग्यता खोज परीक्षा, एक ऐसी विश्लेषणात्मक परीक्षा है, जो कक्षा 9, 10, 11 और 12 में पढ़ने वाले छात्रों की किसी अवधारणा को समझने के सामर्थ्य का मापमान करती है।

आईसीएआई वाणिज्य विशेषज्ञ – 2016 के पुरस्कार समारोह का आयोजन समिति द्वारा किया गया था। अध्यक्ष, आईसीएआई, उपाध्यक्ष, आईसीएआई और अन्य परिषद् सदस्यों के अलावा श्री विजय गोयल, संघ के माननीय युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री ने इस आयोजन की शोभा बढ़ाई थी। सचिव, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मणिपुर ने भी इस पुरस्कार समारोह में भाग लिया था। इस पुरस्कार समारोह के पश्चात् सीए. गिरिश आहूजा द्वारा बजट संबंधी एक वार्ता प्रस्तुत की गई थी।

10 नवंबर, 2016 को राष्ट्रीय/विश्व वाणिज्य शिक्षा दिवस

समिति ने 10 नवंबर, 2016 को राष्ट्रीय/विश्व वाणिज्य शिक्षा दिवस के रूप में मनाया था, जिसकी थीम “वाणिज्य शिक्षा के आयामों का विस्तार करना” था। इस वर्ष राष्ट्रीय/विश्व वाणिज्य शिक्षा दिवस को भारत के एक प्रमुख वाणिज्य समारोह के रूप में मनाया गया था, जिसके दौरान विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया था और साथ ही इसके दौरान कैरियर परामर्श संबंधी समूह द्वारा पूरे भारत वर्ष में और साथ ही विदेशों में भी कैरियर परामर्श संबंधी कार्यक्रमों की मेजबानी की गई थी।

सोशल मीडिया मंच पर सीसीसी की अनन्य वेबसाइट

माध्यमिक, वरिष्ठ/उच्चतर माध्यमिक, स्नातक/ स्नातकोत्तर छात्रों और साथ ही अन्य पणधारियों के बीच सीए पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान के साथ वाणिज्य शिक्षा का संवर्धन करने के लिए समूह ने एक अनन्य वेबसाइट, अर्थात् ccc.ical.in को स्थापित किया है। पूर्वोक्त वेबसाइट छात्रों को लेखांकन वृत्ति के गौरवपूर्ण जगत के संबंध में शिक्षित करेगी। यह वेबसाइट विशिष्ट रूप से लेखांकन शिक्षा के साथ वाणिज्य शिक्षा के विशेष प्रतिनिर्देश सहित एक उत्कृष्ट कैरियर चुनने में छात्रों के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगी और उन्हें लेखांकन शिक्षा के संबंध में उपलब्ध सही कैरियर का चुनाव करने के संबंध में विनिश्चय करने में सहायता करेगी।

समूह ने माध्यमिक, वरिष्ठ/उच्चतर माध्यमिक, स्नातक/ स्नातकोत्तर छात्रों और साथ ही अन्य पणधारियों के बीच सीए पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान के साथ वाणिज्य शिक्षा का संवर्धन करने के लिए सोशल मीडिया मंच पर अपनी अंतर्वस्तु निकाली थी। सीए पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान के साथ वाणिज्य शिक्षा का संवर्धन करने के लिए पूर्वोक्त विभिन्न सोशल मीडिया मंच जैसे कि फेसबुक, ट्वीटर, गुगल+, यू ट्यूब और लिंकेडिन आदि पर बज के सृजन, अद्यतन जानकारी को पोस्ट करने, परिचर्चाओं को आरंभ करने, लिंकों को साझा करने, संवर्धनात्मक अभियानों को आरंभ करने, ब्लॉग/फीड्स का संवर्धन करने, फोटो और दस्तावेजों को पोस्ट करने, टवीटर हैंडलों का सृजन करने, उसके लिए संपर्क प्ररूप/रजिस्ट्रीकरण प्ररूप को तैयार करने आदि जैसे कार्यों को सुकर बनाया गया है।

“चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम : अपार अवसरों के साथ एक उत्कृष्ट कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने” संबंधी डीवीडी

समिति ने “चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम : अपार अवसरों के साथ एक उत्कृष्ट कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने” संबंधी एक डीवीडी निकाली थी, जिसमें सीए पाठ्यक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण व्यौरे अंतर्विष्ट हैं। यह डीवीडी सीए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले नए अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी और साथ ही वह उनका मार्गदर्शन करने के लिए सुगम संदर्भ उपलब्ध कराएगी तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की वांछा करने वाले छात्रों के लिए एक ज्ञान के भंडार का प्रयोजन भी सिद्ध करेगी। यह डीवीडी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के प्रति आकर्षित होने वाले छात्रों के लिए संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराएगी, जो उनके आगे के चुनौतीपूर्ण कैरियर में स्वतंत्रता, संपूर्णता, सम्मान, नाम और शोहरत का आगाज करेगी।

11. प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं

संस्थान की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं, अर्थात् पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तर भारत प्रादेशिक परिषद् जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं। इस समय इसके पास पूरे भारत में 163 शाखाएं, 30 विदेशी चैप्टर और 15 प्रादेशिक पुस्तकालय हैं।

11.1 सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद्, प्रादेशिक परिषद् की सर्वोत्तम शाखा, सर्वोत्तम छात्र संघ और छात्र संघ की सर्वोत्तम शाखा के लिए पुरस्कार :

ये पुरस्कार आईसीएआई द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सकल कार्यपालन और स्थापित संनियमों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2016 के लिए ये शील्डें 8 फरवरी, 2017 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी।

1. प्रादेशिक परिषदों की सर्वश्रेष्ठ शाखा :-

1. बृहत्त श्रेणी

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरएसी की अहमदाबाद शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरएसी की पुणे शाखा

2. बड़ी शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरएसी की नासिक शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की एर्नाकुलम शाखा

3. मध्यम शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरएसी की औरंगाबाद शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की ईआईआरसी की सिलीगुडी शाखा

4. लघु शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की सीआईआरसी की भिलाई शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की सलेम शाखा

5. सुक्ष्म शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की तुतीकोरिन शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी के पालघाट शाखा

2. सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ

प्रथम पुरस्कार: पूर्वी भारत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघ

दूसरा पुरस्कार: दक्षिणी भारत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघ

3. छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा

1. बड़ी शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की सीआईआरसी की सीआईसीएसए की इंदौर शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी के डब्ल्यूआईसीएसए की सूरत शाखा

2. मध्यम शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएसए की जलगांव शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की ईआईआरसी की ईआईसीएसए की गुवाहाटी शाखा

3. लघु शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की सीआईआरसी की सीआईसीएसए की भिलाई शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की एसआईसीएसए की तुतीकोरिन शाखा

11.2 विकेन्द्रीकृत कार्यालय

आईसीएआई की परिषद् ने, त्वरित और व्यक्तिगत सेवा के मूल्य को मान्यता प्रदान करते हुए, जिन्हें विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, निम्नानुसार रूप से 18 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों की स्थापना की है :

मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	कानपुर	नई दिल्ली	अहमदाबाद
बैंगलोर	हैदराबाद	पुणे	जयपुर	नागपुर	सूरत
वडोदरा	ठाणे	एनकुलम	कोयंबतूर	इंदौर	चंडीगढ़

12. वित्त और लेखा

31 मार्च, 2017 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा, जो परिषद् द्वारा अनुमोदित है, संलग्न हैं।

13. अनुशंसा

परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 2006 के अधीन गठित संस्थान के बोर्डों/समितियों में सहयोजित सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए थे और उस रूप में कार्य किया था और वह उनके प्रति आभार व्यक्त करती है, जो व्यवसाय के सदस्य नहीं हैं लेकिन जिन्होंने परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परीक्षाओं के संचालन में वर्ष 2016-2017 के दौरान परिषद् की सहायता की और वह प्रादेशिक परिषदों, उनकी शाखाओं और उनके सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2016-2017 के दौरान केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए।

परिषद्, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, संघ के वित्त, रक्षा और कारपोरेट कार्य मंत्री श्री अरुण जेटली, वित्त राज्य मंत्री श्री संतोष गंगवार और श्री अर्जुन राम मेघवाल, स्वतंत्र प्रभार के साथ संघ के विद्युत, कोयला, नई और नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री, श्री पीयूष गोयल, संघ के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र देवेन्द्र प्रधान, संघ के सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, एवीएसएम, संघ के माननीय रेल मंत्री, सीए. सुरेश पी. प्रभु, राजस्व सचिव श्री हसमुख अधिया और सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय श्री तपन रे और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का, जिन्होंने आईसीएआई द्वारा आयोजित

विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, दिल से आभार व्यक्त करती है।

परिषद् संघ के माननीय मंत्रियों, श्री एम. वैकेया नायडु, श्री बंडारु दत्तात्रेय, श्री एम.जे. अकबर, श्री कलराज मिश्रा, सुश्री अनुप्रिया पटेल, श्री राधा मोहन सिंह, श्री अशोक गजपति राजू, श्री श्रीपाद यासो, जर्नल वी.के. सिंह, सुश्री उमा भारती, श्रीमती मेनका गांधी, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री वाई.एस. चौधरी, श्री विजय सांपला, श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री थावर चंद गहलौत, डा. जीतेन्द्र सिंह, श्री जयंत सिन्हा, श्री सुदर्शन भगत, श्री मनसुख लाख मंडाविया, सीए सुरेश सी. प्रभु, श्री प्रकाश जावडेकर, श्री अनंत कुमार, श्री सदानंद गौडा, डा. हर्षवर्धन, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री नितिन गडकरी, डा. सुभाष भामरे, श्री जुएल ओरम, श्री पी.पी. चौधरी, श्री विजय गोयल, श्री बाबुल सुप्रियो, श्री राजेन गोहिन और राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल, श्री विजय रुपाणी, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री केशव प्रसाद मौर्या, श्री पेमा खांडु, श्री मनोहर पर्रिकर, श्री मनोहर लाल खट्टर, श्री रमण सिंह, श्री देवेन्द्र फडनवीस, श्रीमती वसुंधरा राजे, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री नोगथोमवाम बिरेन सिंह और साथ ही राज्य मंत्रियों श्री ऐटेला राजेन्द्र, श्री राजेश अग्रवाल, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, श्री ओम प्रकाश राजभर, श्री बृजेश पाठक, श्री स्वतंत्र देव सिंह, श्रीमती स्वाति सिंह, श्री मोहसिन रजा, श्री संदीप सिंह, श्री बलदेव ओलख और श्री सुरेश पासी, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, कैप्टन अभिमन्यु, श्री डी. जयल कुमार, श्री अमर अग्रवाल, श्री अमर कुमार बौरी, श्री जयंत माल्या, श्री सुधीर मुगन्तीवार, श्री शशि भूषण बेहेरा, श्री प्रकाश पंत, अधिवक्ता मैथ्यू टी. थामस, प्रोफेसर वासुदेव देवनानी, डा. नीलकंठ तिवारी का, जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में सीए दिवस समारोह की शोभा बढ़ाई थी, दिल से आभार व्यक्त करती है।

परिषद् राज्य स्तर पर विभिन्न कृत्यकारियों की भी, जिन्होंने आईसीएआई के विभिन्न अंगों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, सराहना करती है।

परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक गतिविधियों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रुचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है।

परिषद्, आईसीएआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2016-2017 के दौरान और उसके पश्चात् उनके द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण और समर्पित प्रयासों के लिए उनकी अनुशंसा करती है।

सांख्यिकी एक दृष्टि में
सदस्य रजिस्ट्रीकरण
(1 अप्रैल, 2007 से)

सारणी 1

वर्ष (को यथाविद्यमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1 अप्रैल, 2007	सहयुक्त अध्येता योग	31159	18237	7829	9642	14182	81049
		16896	13646	6488	8882	12880	58792
		48055	31883	14317	18524	27062	139841
1 अप्रैल, 2008	सहयुक्त अध्येता योग	32364	19203	7939	10045	14642	84193
		17646	14034	6738	9472	13398	61288
		50010	33237	14677	19517	28040	145481
1 अप्रैल, 2009	सहयुक्त अध्येता योग	34294	20666	8193	10578	15951	89682
		18442	14516	7002	10007	13951	63918
		52736	35182	15195	20585	29902	153600
1 अप्रैल, 2010	सहयुक्त अध्येता योग	36390	21733	8512	11252	17104	94991
		19181	15076	7192	10615	14461	66525
		55571	36809	15704	21867	31565	161516
1 अप्रैल, 2011	सहयुक्त अध्येता योग	38608	22998	9154	12329	18547	101636
		19831	15612	7406	11182	14943	68974
		58439	38610	16560	23511	33490	170610
1 अप्रैल, 2012	सहयुक्त अध्येता योग	45273	25505	11069	15963	23332	121142
		20510	16132	7578	11720	15431	71371
		65783	41637	18647	27683	38763	192513
1 अप्रैल, 2013	सहयुक्त अध्येता योग	52846	28020	13258	20606	27743	142473
		21522	16918	7815	12327	16051	74633
		74368	44938	21073	32933	43794	217106

1 अप्रैल, 2014	सहयुक्त अध्येता योग	56595 22313 78908	29401 17460 46861	14035 8007 22042	22978 12915 35893	29467 16508 45975	152476 77203 229679
1 अप्रैल, 2015	सहयुक्त अध्येता योग	60229 22838 83067	30126 17864 47990	14514 8137 22651	24702 13441 38143	31137 16986 48123	160708 79266 239974
1 अप्रैल, 2016	सहयुक्त अध्येता योग	64235 23700 87935	31919 18495 50414	15046 8223 23269	27353 14071 41424	32774 17521 50295	171327 82010 253337
1 अप्रैल, 2017	सहयुक्त अध्येता योग	67746 25742 93488	33591 19711 53302	15580 8718 24298	30036 15618 45654	34632 18933 53565	181585 88722 270307

सदस्य

(1 अप्रैल, 1950 से)

सारणी 2

	सहयुक्त	अध्येता	योग
1 अप्रैल, 1950 को	1,120	569	1,689
1 अप्रैल, 1951 को	1,285	672	1,957
1 अप्रैल, 1961 को	4,059	1,590	5,649
1 अप्रैल, 1971 को	7,901	3,326	11,227
1 अप्रैल, 1981 को	16,796	8,642	25,438
1 अप्रैल, 1991 को	36,862	22,136	58,998
1 अप्रैल, 2001 को	51,603	44,789	96,392
1 अप्रैल, 2002 को	54,666	47,064	1,01,730
1 अप्रैल, 2003 को	60,619	49,637	1,10,256
1 अप्रैल, 2004 को	63,384	52,707	1,16,091
1 अप्रैल, 2005 को	68,052	55,494	1,23,546
1 अप्रैल, 2006 को	73,778	57,168	1,30,946
1 अप्रैल, 2007 को	81,049	58,792	1,39,841
1 अप्रैल, 2008 को	84,193	61,288	1,45,481
1 अप्रैल, 2009 को	89,682	63,918	1,53,600
1 अप्रैल, 2010 को	94,991	66,525	1,61,516
1 अप्रैल, 2011 को	1,01,636	68,974	1,70,610
1 अप्रैल, 2012 को	1,21,142	71,371	1,92,513
1 अप्रैल, 2013 को	1,42,473	74,633	2,17,106
1 अप्रैल, 2014 को	1,52,476	77,203	2,29,679
1 अप्रैल, 2015 को	1,60,708	79,266	2,39,974
1 अप्रैल, 2016 को	1,71,327	82,010	2,53,337
1 अप्रैल, 2017 को	1,81,585	88,722	2,70,307

रजिस्ट्रीकृत छात्र
(31 मार्च, 2010 से)

वर्ष के दौरान	फाइनल	सीपीटी	पीसीसी	आईपीसीसी एवं आईआईपी सीसी	एटीसी	योग
2009-10	24,172	1,67,073	1,860	80,745	3,376	2,77,226
2010-11	57,175	1,55,217	329	67,984	1,906	2,82,611
2011-12	47,515	1,61,712	-	85,053	2,099	2,96,379
2012-13	45,102	1,61,084	-	1,02,406	2,615	3,11,207
2013-14	39,348	1,54,742	-	96,285	3,209	2,93,584
2014-15	36,950	1,41,241	-	66,570	881	2,45,642
2015-16	31,669	1,25,140	-	77,962	1,249	2,36,020
2016-17	27,611	1,07,392	-	81,886	1,430	2,18,319

परिषद् की संरचना

परिषद् (2017-18)

परिषद् के सदस्य (2017-18)	
अध्यक्ष	निर्वाचित सदस्य
सी.ए. नीलेश एस. विक्रमसे	सी.ए. अग्रवाल रंजीत कुमार कोलकाता
	सी.ए. अग्रवाल संजय नई दिल्ली
	सी.ए. अग्रवाल श्याम लाल जयपुर
उपाध्यक्ष	सी.ए. अग्रवाल मनु कानपुर
सी.ए. नवीन एन.डी. गुप्ता	सी.ए. बाबु अब्राहम कल्लीवयालिल कोच्ची
	सी.ए. भंडारी अनिल सत्यनारायण मुंबई
	सी.ए. चौधरी संजीव कुमार नई दिल्ली
	सी.ए. छेयरा जय सूरत
	सी.ए. छाजेड प्रफुल प्रेमसुख मुंबई
अवधि	सी.ए. देवराजा रेड्डी एम. हैदराबाद
12 फरवरी, 2017 से आगे	सी.ए. धिया तरुण जमनादास मुंबई
	सी.ए. गोयल सुशील कुमार कोलकाता
	सी.ए. गुप्ता अतुल कुमार दिल्ली
	सी.ए. गुप्ता नवीन एन.डी. नई दिल्ली
परिषद् के सचिव	सी.ए. गुप्ता विजय कुमार फरीदाबाद
श्री वी. सागर	सी.ए. हेगड़े नंदकिशोर चिदम्बर मुंबई
	सी.ए. जम्बुसरिया निहार निरंजन मुंबई
	सी.ए. खंडेलवाल धीरज कुमार मुंबई
	सी.ए. किनारे मंगेश पांडुरंग ठाणे
	सी.ए. कुमार श्रीप्रिया चेन्नई
	सी.ए. कुशवाहा मुकेश सिंह गाजियाबाद
	सी.ए. मधुकर नारायण हीरेगंगे बंगलुरु
	सी.ए. (डा.) मित्रा देवाशीष गुवाहाटी
	सी.ए. सेकर जी. चेन्नई

सीए. शाह धीनल अश्विनभाई	अहमदाबाद
सीए. शर्मा प्रकाश	जयपुर
सीए. शर्मा राजेश	दिल्ली
सीए. सोनी केमिशा	इंदौर
सीए. वासुदेवा संजय	नई दिल्ली
सीए. विजय कुमार एम.पी.	चेन्नई
सीए. विकमसे निलेश शिवजी	मुम्बई
सीए. जावरे शिवाजी भीकाजी	पुणे
नामनिर्दिष्ट सदस्य	
श्री मनोज कुमार (मार्च, 2017 तक)	नई दिल्ली
श्री के.वी.आर. मूर्ति (अप्रैल, 2017 से)	नई दिल्ली
श्री विठयाथिल कुरियन	नई दिल्ली
डा. गुरुप्रसाद मोहपात्रा (मार्च, 2017 तक)	नई दिल्ली
डा. सुधांशु पांडे (अप्रैल, 2017 से)	नई दिल्ली
श्री चन्द्र वाधवा	नई दिल्ली
डा. पी.सी. जैन	दिल्ली
श्री सुनील कनोरिया	नई दिल्ली
श्रीमती इंदु मल्होत्रा (मार्च, 2017 तक)	नई दिल्ली
डा. रवि गुप्ता (अप्रैल, 2017 से)	नई दिल्ली
श्री विजय कुमार झलानी	नई दिल्ली

31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा

हिंदोराणी एम. एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

खन्ना एंड आन्नदनम
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

परिषद्, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान") के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2017 को यथा विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य स्पष्टीकारक जानकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "वित्तीय विवरण" कहा गया है) सम्मिलित हैं, की संपरीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधमंडल का उत्तरदायित्व

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अनुसार, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व संस्थान के प्रबंधमंडल का है, जो भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिनके अंतर्गत भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक भी हैं, के अनुसार संस्थान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यपालन और नकद प्रवाह के संबंध में सत्य और उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व के अंतर्गत संस्थान की आस्तियों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखना तथा कपटों और अन्य अनियमितताओं का निवारण करना और उनका पता लगाना, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करना, जो युक्तियुक्त और विवेकपूर्ण हों तथा डिजाइन कार्यान्वयन और ऐसे पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों को बनाए रखना भी है, जो ऐसे वित्तीय विवरणों, जो सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं और सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे कपट के कारण हों या त्रुटिवश हों, से मुक्त हैं, को तैयार करने और उनके प्रस्तुतिकरण से सुसंगत लेखांकन अभिलेखों की सत्यता और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यकरण कर रहे थे।

संपरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी संपरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी संपरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी संपरीक्षा की है। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा इस बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए संपरीक्षा की योजना बनाएं और उसके अनुसार संपरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

किसी संपरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में रकमों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले संपरीक्षा संबंधी साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना सम्मिलित है। चुनी गई प्रक्रियाएं संपरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणों में सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे कपट के कारण हों अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों का निर्धारण करना भी है। ऐसे जोखिम निर्धारणों में, संपरीक्षक, संपरीक्षा संबंधी ऐसी प्रक्रियाओं को, जो दी गई परिस्थितियों में उपयुक्त हों, तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतीकरण हेतु संस्थान के सुसंगत आंतरिक नियंत्रणों को भी विचार में लेते हैं, किंतु ऐसा इस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता कि इस संबंध में राय व्यक्त की जाए कि क्या संस्थान ने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं और क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी हैं। संपरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंध मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण लेखांकन आकलनों तथा संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।

हमारा यह विश्वास है कि हमारे द्वारा ऐसे संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य अभिप्राप्त किए गए हैं जो हमारी संपरीक्षा संबंधी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पूर्वोक्त वित्तीय विवरण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अनुसार सभी तात्विक अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, तैयार किए गए हैं और वे भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2017 को संस्थान के मामलों की स्थिति और उसके अधिशेष और नकद प्रवाह के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं।

अन्य विषय

हमने संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं (जो एकीकृत रूप में शाखाओं के नाम से ज्ञात हैं) के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण कुल 41,131 लाख रुपए की आस्तियां, 19,725 लाख रुपए का कुल राजस्व और 136 लाख रुपए की रकम का शुद्ध नकद प्रवाह/(बहिर्गामी) उपदर्शित करते हैं और जिन्हें वित्तीय विवरणों में विचारार्थ लिया गया है। इन वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा अन्य संपरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें प्रबंधमंडल द्वारा हमें प्रस्तुत की गई थीं। इन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, जहां तक उसका संबंध इन शाखाओं के संबंध में सम्मिलित की गई रकमों और प्रकटनों से है, पूर्णतया उन अन्य संपरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि :

- क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;
- ख) हमारी राय में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थान द्वारा समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं से समुचित और पर्याप्त विवरणियां प्राप्त हुई हैं ;
- ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुसार हैं।

कृते हिंदोरानी एम. एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 006772एन

खन्ना एंड आन्तदनम
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 001297एन

ह/
सी.ए. संजय कुमार नारंग
भागीदार

सदस्यता सं. 090943

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 14 सितंबर, 2017

ह/
सी.ए. बी.जे. सिंह
भागीदार

सदस्यता सं. 07884

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002
31 मार्च, 2017 को यथाविद्यमान तुलन पत्र

		31 मार्च, को यथा विद्यमान	
विशिष्टियां	टिप्पण सं.	2017	2016
I निधियों के स्रोत :		(लाख रुपए में)	
i. अधिशेष और उद्दिष्ट निधियां			
क. आरिश्चितियां और अधिशेष	3	113,941	112,493
ख. उद्दिष्ट निधियां	4	34,329	29,199
ii. गैर चालू दायित्व			
क. अन्य दीर्घकालिक दायित्व	5	731	801
ख. दीर्घकालिक प्रावधान	6	16,338	9,691
iii. चालू दायित्व			
क. व्यापार संबंधी देय	7	3,191	3,971
ख. अन्य चालू दायित्व	8	19,345	18,787
ग. अल्पकालिक प्रावधान	6	937	328
योग		188,812	175,270
निधियों का उपयोग			
II गैर चालू आस्तियां			
क. नियत आस्तियां			
i) मूर्त आस्तियां	9	51,615	51,939
ii) अमूर्त आस्तियां	10	19	23
iii) चालू पूंजी संकर्म	11	13,875	13,202
ख. गैर-चालू निवेश	12	24,631	-
ग. उद्दिष्ट और अन्यो के लिए धारित आस्तियां	13	3,630	11,816
घ. दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	14	2,987	3,721
ङ. अन्य गैर चालू आस्तियां	15	1,684	1,755
ii. चालू आस्तियां			
क. चालू निवेश	12	8,091	-
ख. उद्दिष्ट और अन्यो के लिए धारित आस्तियां	13	70,388	80,636
ग. वस्तु-सूचियां	16	1,001	1,243
घ. नकद और बैंक अतिशेष	17	5,035	5,085
ङ. अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	14	2,252	3,970
च. अन्य चालू आस्तियां	15	3,604	1,880
योग		188,812	1,75,270

संलग्न टिप्पण 1 से 26 देखें, जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।
परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-
सी.ए. सुदीप श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

ह./-
वी. सागर
सचिव

ह./-
सी.ए. नवीन एन. डी. गुप्ता
उपाध्यक्ष

ह./-
सी.ए. नीलेश शिवजी विक्रमसे
अध्यक्ष

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते हिंमोरानी एम. एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 006772एन
ह/
सी.ए. संजय कुमार नारंग
भागीदार
सदस्यता सं. 090943
स्थान : नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2017

खन्ना एंड आनन्दनम
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 001297एन
ह/
सी.ए. बी.जे. सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 07884

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002
31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

		31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए		
	विशिष्टियां	टिप्पण सं.	2017	2016
		(रुपए लाख में)		
I	आय			
	क) फीस	18	48,585	49,088
	ख) संगोष्ठियां		5,529	5,943
	ग) अन्य आय		10,989	11,393
		19		
	कुल आय		65,103	66,424
II	व्यय			
	क) संगोष्ठियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम		6,108	6,745
	ख) कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय	20	17,190	13,569
	ग) मुद्रण और लेखन सामग्री		6,704	6,967
	घ) परीक्षकों और परामर्शियों को संदत्त वृत्तिक फीस	9-10	6,812	8,171
	ड) अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय	21	2,334	2,463
	च) अन्य व्यय		19,639	21,689
	कुल व्यय		58,787	59,604
III	शुद्ध अधिशेष (I-II)		6,316	6,820
IV	निधियों/आरक्षितियों को विनियोग:			
	क) शिक्षा निधि [टिप्पण 2.6(iii) देखें]		3,158	3,410
	ख) कर्मचारी कल्याण निधि [टिप्पण 2.6(iv) देखें]		43	41
	ग) उद्दिष्ट निधि (व्ययों का शुद्ध योग)		2,281	2,171
	घ) साधारण आरक्षिती		834	1,198
	योग		6,316	6,820

संलग्न टिप्पण 1 से 26 देखें, जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-
सी.ए. सुदीप श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

ह./-
वी. सागर
सचिव

ह./-
सी.ए. नवीन एन. डी. गुप्ता
उपाध्यक्ष

ह./-
सी.ए. नीलेश शिवजी विक्रमसे
अध्यक्ष

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते हिंशोराती एम. एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 006772एन

खन्ना एंड आनन्दनम
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 001297एन

ह/
सी.ए. संजय कुमार नारंग
भागीदार
सदस्यता सं. 090943
स्थान : नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2017

ह/
सी.ए. बी.जे. सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 07884

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002
31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	
	2017	2016
	(लाख रुपए में)	
I. विशिष्टियां		
प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात् शुद्ध अधिशेष	6,316	6,820
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
अवधायन और परिशोधन संबंधी व्यय	2,334	2,463
ऐसे प्रावधान, जो अब अपेक्षित नहीं हैं, अपलिखित	(114)	(172)
व्याज संबंधी आय	(7,686)	(7,734)
सदस्यों से प्रवेश फीस, जिसे सीधे आरक्षिती को आबंटित किया गया है	242	202
कार्यकरण पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन अधिशेष	1,092	1,579
कार्यकरण पूंजी में परिवर्तन :		
प्रचालन संबंधी आस्तियों में वृद्धि/कमी के लिए समायोजन :		
वस्तु सूचियां	242	457
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	416	210
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	1,718	(129)
प्रचालन संबंधी आस्तियों में वृद्धि/कमी के लिए समायोजन		
अन्य दीर्घकालिक दायित्व	(70)	(160)
दीर्घकालिक प्रावधान	6,647	4,333
व्यापार संबंधी देय	(666)	(1,682)
अन्य चालू दायित्व	634	612
अल्पकालिक प्रावधान	609	78
	10,622	5,298
स्रोत पर कटौती किया गया कर (वसूलनीय)	318	(207)
प्रचालन क्रियाकलापों से हुई आय (अ)	10,940	5,091
II. निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
गैर-चालू निवेशों का क्रय	(24,631)	-
चालू निवेशों का क्रय	(8,091)	-
नियत आस्तियों पर पूंजी व्यय	(2,858)	(7,459)
नियत आस्तियों के विक्रय से आगम	103	94
उद्दिष्ट और अन्य निधियों में कमी	18,434	(6,058)
प्राप्त व्याज आय	6,033	7,180
निवेश संबंधी क्रियाकलापों में (प्रयुक्त) नकद (आ)	(11,010)	(6,243)
III. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
भवन के लिए प्राप्त संदान	18	1
प्राप्त अभिदाय	3	173
पर्याप्त/(प्रयुक्त) अन्य निधि	(1)	36
वित्तीय क्रियाकलापों से नकद (इ)	20	210
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध कमी (अ+आ+इ)	(50)	(942)
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	5,085	6,027
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	5,035	5,085

संलग्न टिप्पण 1 से 26 देखें, जो परिषद् के लिए और उसकी ओर से वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

टिप्पण :

- (1) नकद और नकद समतुल्य, हाथ में नकदी और बैंकों में जमा धन को बताते हैं (टिप्पण 17 देखें)।
- (2) कोष्ठकों में दी गई रकमें बहिर्गम्य धन को बताती हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-
सी.ए. सुदीप श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

ह./-
वी. सागर
सचिव

ह./-
सी.ए. नवीन एन. डी. गुप्ता
उपाध्यक्ष

ह./-
सी.ए. नीलेश शिवजी विक्रमसे
अध्यक्ष

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते हिंमोराणी एम. एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 006772एन
ह/
सी.ए. संजय कुमार नारंग
भागीदार
सदस्यता सं. 090943
स्थान : नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2017

खन्ना एंड आनन्दनम
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 001297एन
ह/
सी.ए. वी.जे. सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 07884

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां

1. साधारण जानकारी

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान या आईसीएआई") जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, को 1 जुलाई, 1949 को संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की वृत्ति का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया था। उक्त अधिनियम के निबंधनों के अनुसार संस्थान की परिषद् को, संस्थान के कार्यों के प्रबंध का कार्य सौंपा गया है। इस प्रयोजन के लिए, परिषद् ने अभी तक मुंबई, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और नई दिल्ली प्रत्येक में एक और कुल 5 प्रादेशिक परिषदों, 18 प्रादेशिक कार्यालयों और विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और 163 शाखाओं और 1 विदेशी कार्यालय का भी गठन किया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण

2.1 लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को, जिनमें तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण, टिप्पणों के साथ सम्मिलित है, संस्थान द्वारा जारी और लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों को, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, गोईंग कन्सर्न संबंधी ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन सतत आधार पर तथा प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, पूर्व वर्ष में अपनाई गई नीतियों से संगत हैं।

2.2 प्राक्कलनों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति प्रबंधमंडल से यह अपेक्षा करती है कि वे ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान करें, जो वर्ष के दौरान आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्टित रकमों (जिसके अंतर्गत आकस्मिक दायित्व भी हैं) और आय और व्यय की रिपोर्टित रकमों हेतु विचार में लिए जाते हैं। प्रबंधमंडल यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों तथा प्राक्कलनों के बीच अंतर को ऐसी अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है, जिनमें परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी/ वे कार्यान्वित किए गए थे।

2.3 वस्तु-सूचियां

वस्तु-सूचियों में प्रकाशनों, अध्ययन सामग्रियों, लेखन सामग्रियों और अन्य भंडारों की वस्तु-सूचियां सम्मिलित होती हैं, जिनका मूल्यांकन प्रथम आगम, प्रथम जावक ("एफआईएफओ") पद्धति के आधार पर, जिसके दौरान जहां आवश्यक समझा जाए, अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए उपबंध करने के पश्चात् संगणित निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य के आधार पर किया जाता है।

लागत में माल को विक्रय के बिन्दु पर लाने संबंधी सभी प्रभार सम्मिलित होते हैं, जिसके अंतर्गत चुंगी, अन्य उदग्रहण, प्रवहन बीमा और प्राप्ति प्रभार भी हैं।

2.4 नकद और नकद समतुल्य (नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए)

नकद में, हाथ में नकदी और बैंकों में मानदेय निक्षेप अंतर्विष्ट हैं। नकद समतुल्य ऐसे अल्पकालिक अतिशेष हैं (जिनकी मूल परिपक्वता, उनके अर्जन की तारीख से तीन मास या उससे कम की अवधि है), जो अत्यधिक रूप से चल निवेश हैं, जिन्हें सुगम रूप से नकद की ज्ञात रकमों में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

2.5 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाहों को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें गैर-नकद प्रकृति के संब्यवहारों के प्रभावों और पूर्ववर्ती या भावी नकद प्राप्तियों या संदायों में किसी आस्थगन या प्रोदभवनों के लिए शुद्ध अधिशेष को समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों से होने वाले नकद प्रवाहों को उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक् किया जाता है।

2.6 आरक्षितियों में विनियोग और उद्दिष्ट निधियों को आबंटन

- (i) संस्थान के अध्येता के रूप में प्रवेश हेतु सदस्यों से प्राप्त फीस को अवसंरचना संबंधी आरक्षित खाते में जमा किया जाता है।
- (ii) भवनों और अनुसंधान के लिए प्राप्त संदानों को सीधे संबंधित आरक्षित खाते में जमा किया जाता है।

- (iii) दूरस्थ शिक्षा फीस के 25 प्रतिशत, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, शिक्षा निधि को अंतरित किया जाता है।
- (iv) वर्ष के दौरान प्राप्त सदस्यता फीस (वार्षिक और व्यवसाय प्रमाणपत्र संबंधी फीस) के 0.75 प्रतिशत को कर्मचारी कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है।
- (v) उद्दिष्ट निधियों से शिक्षा आरक्षित खाते को निम्नलिखित अंतरण किए जाते हैं :
- | | |
|-------------------------------------|--|
| (क) अनुसंधान भवन निधि
लेखांकन से | लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से भवन से संबंधित
अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का
100 प्रतिशत |
| (ख) शिक्षा निधि से | अन्य नियत आस्तियों से संबंधित अभिवृद्धियों की लागत
(कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 50 प्रतिशत |
- (vi) उद्दिष्ट निधियों के निवेश से होने वाली आय को उद्दिष्ट निधियों में जोड़ा जाता है। इस आय को, संबद्ध उद्दिष्ट निधियों के प्रारंभिक अधिशेष के आधार पर, भारत औसत का आधार बनाते हुए आबंटित किया जाता है।

2.7 अवक्षयण और परिशोधन

आस्तियों के लिए अवक्षयण संबंधी रकम, आस्ति की लागत या लागत के लिए प्रतिस्थापित कोई अन्य रकम है, जिसमें से उसके प्राक्कलित शेष मूल्य को घटा दिया गया हो।

मूर्त नियत आस्तियों के संबंध में अवक्षयण को संस्थान की परिषद् द्वारा अनुमोदित उपयोगी जीवन के अनुसार अपलिखित मूल्य पद्धति पर उपलब्ध कराया जाता है।

आस्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण, तकनीकी सलाह के आधार पर आस्ति की प्रकृति, आस्ति के प्राक्कलित उपयोग, आस्ति के प्रचालन की परिस्थितियों, प्रतिस्थापन के पूर्व ईतिवृत्त, अनुमानिक प्रौद्योगिकी संबंधी परिवर्तनों, विनिर्माताओं की वारंटियों और अनुरक्षण समर्थन आदि को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार किया जाता है। नियत आस्तियों के परिशोधन के लिए प्रयुक्त परिशोधन दरें निम्नानुसार हैं :

आस्तियों का वर्ग	अवक्षयण की दर
(i) भवन	5%
(ii) लिफ्ट, इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग	10%
(iii) कंप्यूटर	60%
(iv) फर्नीचर और फिक्सचर	10%
(v) वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	15%
(vi) वाहन	20%
(vii) पुस्तकालय की पुस्तकें	100%

पट्टाधृत भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि के पश्चात् किया जाता है।

अमूर्त आस्तियों का परिशोधन उनकी प्राक्कलित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी कटौती पद्धति के अनुसार निम्नलिखित रूप में किया जाता है : कंप्यूटर साफ्टवेयर : 3 वर्ष

अमूर्त आस्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवन और परिशोधन अवधि का पुनर्विलोकन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत पर किया जाता है और परिवर्तित पैटर्न, यदि कोई हो, उपदर्शित करने के लिए हानिकरण की अवधि का पुनरीक्षण किया जाता है।

2.8 राजस्व मान्यता

संस्थान राजस्व को निम्नानुसार मान्यता प्रदान करता है :

- दूरस्थ शिक्षा फीस को संबद्ध पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर अनुपाततः मान्यता प्रदान की जाती है।
- कक्षा प्रशिक्षण फीस में साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल कार्यक्रम ("जीएमसीएस") सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण ("आईटीटी") और अनुकूलन कार्यक्रम ("ओपी") के लिए प्राप्त फीस सम्मिलित होती है, इस आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, जब सेवाओं को प्रदान किया जाता है और संबद्ध लागतों को उपगत किया जाता है।
- परीक्षा फीस को संबंधित परीक्षाओं के आयोजन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

- iv) संगोष्ठी फीस को संबद्ध क्रियाकलाप के आयोजन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।
- v) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाण-पत्र और उसे पुनः स्थापित करने की फीस भी सम्मिलित है) और प्रवेश फीस से मिलकर बनने वाली सदस्यता फीस को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :
- क) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए फीस भी है) को उस समय आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब वह वर्ष के दौरान शोध्य हो जाती है। नाम को पुनः प्रविष्ट करने संबंधी फीस की आय को, उसके प्राप्त होने पर मान्यता प्रदान की जाती है।
- ख) प्रवेश फीस :
- एसोसिएट सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिए जाने के समय एकत्रित प्रवेश फीस के एक-तिहाई भाग को उस वर्ष की प्रवेश संबंधी आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है और शेष भाग को अवसंरचना आरक्षिती में मान्यता प्रदान की जाती है।
 - अध्येता सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिए जाने के समय एकत्रित प्रवेश फीस को अवसंरचना आरक्षिती में मान्यता प्रदान की जाती है।
- vi) छात्र रजिस्ट्रीकरण फीस को संबद्ध पाठ्यक्रमों की अवधि के अनुसार अनुपाततः मान्यता दी जाती है।
- vii) छात्र संगमों संबंधी आय को उस समय मान्यता दी जाती है जब छात्रों को पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रदान किया जाता है।
- viii) अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के राजस्वों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें सेवाएं दी जाती हैं।

2.9 अन्य आय

- क) प्रकाशन के विक्रय से होने वाली आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब जोखिम और पुरस्कारों को क्रेता को अंतरित किया जाता है, जो सामान्यतः माल के परिदान के समय होता है। इस आय में, प्राप्त हुआ यह प्राप्य प्रतिफल, बट्टों का शुद्ध और अन्य विक्रय संबंधी कर (यदि कोई हों) सम्मिलित हैं।
- ख) छात्र न्यूज लैटर और जर्नल के अभिदाय से होने वाली आय को अभिदाय के समय के अनुसार अनुपाततः मान्यता प्रदान की जाती है।
- ग) कैम्पस साक्षात्कार और विशेषज्ञ सलाहकार फीस से होने वाली आय को उस समय मान्यता दी जाती है, जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और संबद्ध लागतों को उपगत किया जाता है।
- घ) व्याज संबंधी आय में बैंकों में साधारण रूप से जमा निक्षेपों और उद्दिष्ट निधियों पर प्राप्त व्याज सम्मिलित होता है। व्याज संबंधी आय का लेखांकन प्रोदभवन आधार पर किया जाता है।
- ङ) कर्मचारियों को दिए गए ऋणों का लेखांकन प्रोदभवन आधार पर किया जाता है।

2.10 नियत आस्तियां

क) मूर्त आस्तियां

मूर्त आस्तियों का कथन, एकत्रित अवक्षयण और हानिकरण हानियों (यदि कोई हों) को घटाकर लागत पर किया जाता है। किसी नियत आस्ति की लागत में सामग्रियों की क्रय लागत, किन्हीं व्यापार संबंधी बट्टों और छूटों के शुद्ध को गणना में लेते हुए, सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क और अन्य कर (उनसे भिन्न, जो पश्चातवर्ती रूप से कर अधिकारियों से वसूलनीय होते हैं), किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत, अन्य अनुषंगी व्यय और आशयित उपयोग के लिए आस्ति के तैयार होने की तारीख तक अर्हित नियत आस्तियों के अर्जन के मद्दे लिए गए उधारों पर व्याज भी है। मूर्त आस्तियों के क्रय/उनके पूर्ण होने के पश्चात् उनसे संबंधित पश्चातवर्ती व्यय को केवल उस दशा में पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्ययों के परिणामस्वरूप उसके पूर्व में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से परे ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी फायदों में वृद्धि होती है।

ख) अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्तियों का कथन, एकत्रित परिशोधन और एकत्रित हानिकरण (यदि कोई हों) को घटाकर लागत पर किया जाता है। किसी अमूर्त आस्ति की लागत में, उसकी क्रय लागत (छूट और बट्टों का शुद्ध) सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क और अन्य कर (उनसे भिन्न, जो पश्चातवर्ती रूप से कर अधिकारियों से वसूलनीय होते हैं), किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत भी है। किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत, अन्य अनुषंगी व्यय और आशयित उपयोग के लिए आस्ति के तैयार होने की तारीख तक अर्हित नियत आस्तियों के अर्जन के मद्दे लिए गए उधारों पर व्याज भी है। अमूर्त आस्तियों के क्रय/उनके पूर्ण होने के पश्चात् उनसे संबंधित पश्चातवर्ती व्यय को केवल उस दशा में पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्ययों के परिणामस्वरूप उसके पूर्व में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से परे ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी फायदों में वृद्धि होती है।

ग) चालू पूंजी संकर्म

ऐसी आस्तियों के, जो उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, संनिर्माण पर उपगत व्यय को, चालू पूंजी संकर्म के अधीन हानिकरण (यदि कोई हों) को घटाकर लागत पर संगणित किया जाता है। इस लागत में, सामग्रियों की क्रय लागत सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लागतों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े आयात-शुल्क और गैर-प्रतिदेय कर भी हैं।

2.11 निवेश

- क) आईसीएआई भारत सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों ("एसडीएल"), सावधि निक्षेपों, पीएसयू बैंक बंधपत्रों और पीएसयू बंधपत्रों में निवेश कर रहा है।
- ख) सावधि निक्षेपों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।
- ग) सरकारी प्रतिभूतियों और बैंक बंधपत्रों में निवेशों को अर्जन लागत के आधार पर संगणित किया जाता है। क्रय के समय पर संदत्त प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि के अनुसार परिशोधित किया जाता है। प्रीमियम के परिशोधन को "निवेशों पर व्याज" शीर्ष के अधीन आय के प्रति समायोजित किया जाता है।
- घ) क्रय के समय संदत्त प्रोदभूत व्याज का मुजरा आय की प्रथम प्राप्ति के प्रति किया जाता है।
- ङ) व्यष्टिक रूप से प्रत्येक निवेश के लिए अस्थायी से भिन्न ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है।

2.12 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को, संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दरों पर या उन दरों पर, जो संव्यवहार की तारीख को विद्यमान दर के आसपास थी, लेखांकित किया जाता है।

संस्थान की विदेशी मुद्रा धनीय मदों (संविदाओं के व्युत्पन्नों से भिन्न) जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया हैं, वर्ष अंत की दरों पर पुनः प्रारंभ किया जाता है। संस्थान की गैर-धनीय मदों का लेखांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

संस्थान की विदेशी मुद्रा धनीय आस्तियों और दायित्वों के समाधान/पुनर्कथन पर उदभूत होने वाले विनिमय संबंधी अंतरों को आय और व्यय के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.13 कर्मचारी फायदे

कर्मचारी फायदों में भविष्य निधि, उपदान निधि, प्रतिपूरित अनुपस्थिति, दीर्घ सेवा पुरस्कार, पेंशन स्कीम और सेवा-पश्च चिकित्सीय फायदें सम्मिलित हैं

i) परिभाषित अभिदाय योजनाएं

परिभाषित अभिदाय योजनाएं, ऐसी योजनाएं हैं, जहां भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के भविष्य निधि न्यास ("न्यास") को अभिदाय के रूप में भविष्य निधि स्कीम में किए गए संस्थान के अभिदाय को, परिभाषित अभिदाय योजनाओं के रूप में विचार में लिया जाता है और उसे अभिदाय की रकम पर आधारित ऐसे व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है, जिसे उपगत किया जाना अपेक्षित था और जब यह कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले किया जाता है। न्यास का प्रबंध भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा निर्वाचित शासी निकाय द्वारा किया जाता है।

ii) परिभाषित फायदा योजनाएं

उपदान और सेवानिवृत्ति पेंशन के रूप में परिभाषित फायदा योजनाओं के लिए, फायदे उपलब्ध कराने की लागत का अवधारण प्रक्षेपित यूनिट प्रत्यय पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है, जिसके दौरान प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक अभिलाभों और हानियों को उस अवधि के आय और व्यय विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वे उद्भूत होते हैं। पूर्व सेवा संबंधी लागत को, फायदों के पहले से ही निहित किए जाने की सीमा तक तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें अन्यथा फायदों के निहित हो जाने तक की औसत अवधि के अनुसार सीधी कटौती पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है। तुलन-पत्र में मान्य ठहराई गई सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी बाध्यता, गैर-मान्यताप्राप्त पूर्व सेवा लागत के लिए यथा समायोजित परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य को उपदर्शित करती है, जिसमें से स्कीम संबंधी अस्तियों के उचित मूल्य को घटा दिया गया हो। इस परिगणना के पारिणामिक कोई आस्ति, पूर्व सेवा लागत धन उपलब्ध प्रतिदायों और स्कीमों में भावी अभिदायों में कमी के वर्तमान मूल्य तक सीमित है।

उपदान संबंधी दायित्व को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इन परिभाषित फायदा बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को लेखांकन मानक (एएस) – 15, कर्मचारी फायदे के अनुसार एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा अभिनिश्चित किया जाता है।

iii) अल्पकालिक कर्मचारी फायदे

अल्पकालिक कर्मचारी फायदों (जैसे कि वेतन, भत्ते, अनुग्रह आदि) की बढ़ा रहित रकम को, कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले संदत्त किए जाने की आशा की जाती है, जिसे वर्ष के दौरान उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। अल्पकालिक कर्मचारी फायदे संभावी रूप से उस अवधि के अंत के 12 मास के पश्चात् उत्पन्न होते हैं, जिसमें कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक प्रतिपूरित अनुपस्थिति की लागत को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है :

क) एकत्रित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो उनकी भावी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की हकदारी में वृद्धि करती हैं ; और

ख) गैर-एकत्रित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब अनुपस्थितियां दर्ज की जाती हैं।

iv) दीर्घकालिक कर्मचारी फायदे

ऐसी प्रतिपूरित अनुपस्थितियां, जिनकी उस अवधि के अंत के पश्चात् 12 मास के भीतर उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, जिसमें कर्मचारी द्वारा दी गई संबद्ध सेवाओं को तुलन-पत्र की तारीख को परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य पर एक ऐसे दायित्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें से योजना आस्तियों के उचित मूल्य को घटा दिया गया हो और जिसमें से बाध्यताओं के समाधान होने की आशा की जाती है।

v) अन्य फायदे

क) पेंशन फायदे

संस्थान पेंशन के रूप में अपने कर्मचारियों को फायदे की प्रस्थापना करता है। तुलन-पत्र की तारीख को इस बाध्यता के वर्तमान मूल्य को बीमांकक से बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

ख) सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को सेवानिवृत्ति-पश्च चिकित्सीय स्कीम संबंधी फायदे

संस्थान एक चिकित्सा स्कीमों के रूप में अपने कर्मचारियों को फायदे की प्रस्थापना करता है। तुलन-पत्र की तारीख को इस बाध्यता के वर्तमान मूल्य को बीमांकक से बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

2.14 पट्टे

ऐसे पट्टा संबंधी ठहरावों में, जहां किसी आस्ति के स्वामित्व से अनुषंगी जोखिम और पुरस्कार सारवान रूप से पट्टाकर्ता में निहित होते हैं, वहां उन्हें चालू पट्टों के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। चालू पट्टों के अधीन पट्टा संबंधी किरायों को पट्टे की अवधि के अनुसार सीधे कटौती पद्धति के आधार पर आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.15 मूर्त और अमूर्त आस्तियों का हानिकरण

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों के अग्रेषण मूल्य को हानिकरण हेतु पुनर्विलोकित किया जाता है। यदि हानिकरण का कोई संकेत विद्यमान होता है तो ऐसी आस्तियों की वसूलनीय रकम को प्राक्कलित किया जाता है और हानिकरण को उस

समय मान्यता प्रदान की जाती है, यदि इन आस्तियों की अग्रणीत रकम उनकी वसूलनीय रकम से अधिक हो जाती है। वसूलनीय रकम, वह शुद्ध विक्रय कीमत और उनके उपयोग मूल्य दोनों में से उच्चतर है। उपयोग मूल्य की गणना, भावी नकद प्रवाहों को एक समुचित बढ़ा कारक के आधार पर बढ़ा देते हुए उनके वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है। जब इस बात का कोई संकेत प्राप्त होता है कि किसी आस्ति के लिए पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों के दौरान मान्यता प्रदान किया गया हानिकरण अब विद्यमान नहीं है या उसमें कोई कमी आई है तो ऐसे हानिकरण की वापसी को आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.16 आय पर कर

संस्थान को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) और 11 के अधीन आय-कर से छूट प्रदान की गई है।

2.17 उद्दिष्ट और अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां

उद्दिष्ट निधियों और बैंकों में निक्षेपों के रूप में धारित ऐसे अन्य निक्षेपों के रूप में अन्य निधियों को, जो तुलन-पत्र की तारीख से 12 मास की अवधि के पश्चात् परिपक्व हो रहे हैं, गैर-चालू और अन्य निधियों को चालू निधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये निधियां संस्थान की परिषद् के विवेकानुसार उपयोग के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध हैं, सिवाय उद्दिष्ट और कर्मचारी फायदा निधियों की कुल योग की सीमा तक।

2.18 प्रावधान और आकस्मिकताएं

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप संस्थान की कोई बाध्यता विद्यमान है और इस बात की संभावना है कि ऐसी बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

आकस्मिक दायित्व ऐसी संभाव्य बाध्यता है, जो किन्हीं पूर्व घटनाओं से उद्भूत होती है और जिसकी विद्यमानता की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित ऐसी भावी घटनाओं के घटित या घटित न होने पर निर्भर हो सकती है, जो पूर्णतया संस्थान के नियंत्रणाधीन नहीं है या जो कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता है, जो किसी पूर्व घटना से उद्भूत हुई है, किंतु जिसे या तो इस कारण से कि यह संभाव्य नहीं है कि उस बाध्यता को पूरा करने के लिए आर्थिक फायदों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित होगा या इस कारण से कि बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, मान्यता प्रदान नहीं की गई है। आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन किया जाता है और उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जाती है।

आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

टिप्पण # 3. आरक्षितियां और अधिशेष

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	साधारण		शिक्षा		अवसंरचना		अन्य*		कुल	
	31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	71,810	71,133	34,874	32,150	5,068	4,726	741	652	112,49	108,661
जोड़ें आय और व्यय के विवरण से विनियोग	834	1,198	-	-	-	-	-	834	1,198	3
साधारण आरक्षिती, अवसंरचना आरक्षिती और अन्य आरक्षिती से/(को) अंतरण	-	(59)	-	-	-	20	-	39	-	-
उद्दिष्ट निधियों से/(को) अंतरण	(848)	(272)	980	2,724	(24)	(1)	247	(56)	355	2,395
दाखिला फीसों और आबंटित प्रवेश फीसों	-	-	-	-	242	202	-	-	242	202

भवनों के लिए प्राप्त संदान	-	-	-	18	1	-	-	18	1
(उपयोग)/परिवृद्धियां	-	(190)	-	-	120	(1)	106	(1)	36
वर्ष के अंत में अतिशेष	71,796	71,810	35,854	34,874	5,304	5,068	987	741	113,941
									112,493

* अन्य आरक्षितियों में, पुस्तकालय आरक्षितियों और कक्षा प्रशिक्षण आरक्षितियों जैसी आरक्षितियां सम्मिलित हैं।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

टिप्पण : # 4. उद्दिष्ट निधियां

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	अनुसंधान निधियां		लेखांकन भवन अनुसंधान निधि		शिक्षा निधि		पदक और पुरस्कार निधि		छात्रों की छात्रवृत्ति निधियां		कर्मचारी कल्याण निधि		अन्य निधियां		योग	
	31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	2,094	1,920	727	667	21,107	18,726	222	184	120	112	572	487	4,357	3,703	29,199	25,799
जोड़े : छात्र संघों की उद्दिष्ट निधियों का आरंभिक अतिशेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आय और व्यय के विवरण से विनियोग आरक्षितियों और अतिशेष से/(को) अंतरण	-	-	-	-	3,158	3,410	-	-	-	-	43	41	-	-	3,201	3,451
वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/परिवृद्धियां	-	-	-	-	(980)	(2,724)	-	-	-	-	-	-	625	329	(355)	(2,395)
वर्ष के दौरान आय और व्यय के विवरण के माध्यम से विनियोग की गई व्याज आय	-	-	-	-	-	-	(5)	(14)	(4)	(22)	(6)	-	(48)	(52)	(63)	(88)
वर्ष के अंत में अतिशेष	2,282	2,094	793	727	25,204	21,107	236	222	127	120	661	572	5,026	4,357	34,329	29,199

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

टिप्पण # 5 : अन्य दीर्घकालिक दायित्व		31 मार्च को यथा विद्यमान	
		2017	2016
		(लाख रुपए में)	
क) अग्रिम में प्राप्त फीस			
i) शिक्षा फीस		723	793
ii) जर्नल का अभिदाय		8	8
योग		731	801
टिप्पण #6 : प्रावधान		31 मार्च को यथा विद्यमान	
		2017	2016
		(लाख रुपए में)	
		दीर्घकालिक	अल्पकालिक
कर्मचारी फायदों के लिए प्रावधान			
क) नियोजन पथ पर परिभाषित फायदे			

i) उपदान	-	-	186	66
ii) पेंशन	10,710	5,074	406	12
ख) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	3,528	3,217	345	250
ग) अन्य प्रावधान	2,100	1,400	-	-
योग	16,338	9,691	937	328
टिप्पण #7 : व्यापार संबंधी देय			31 मार्च को यथा विद्यमान	
			2017	2016
			(लाख रुपए में)	
व्यापार संबंधी देय			3,191	3,971
योग			3,191	3,971

टिप्पण #8 : अन्य चालू दायित्व		31 मार्च को यथा विद्यमान	
		2017	2016
		(लाख रुपए में)	
क)	अग्रिम में प्राप्त फीस		
i)	परीक्षा फीस	7,106	5,601
ii)	जर्नल अभिदाय	16	17
iii)	सदस्यता फीस	1,886	1,575
iv)	शिक्षा फीस	7,327	8,267
v)	अर्हता पश्च पाठ्यक्रम फीस	110	67
vi)	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम फीस	40	73
vii).	संगोष्ठी फीस और अन्य संग्रहण	929	789
योग (क)		17,414	16,389
ख)	व्यय और अन्य देय		
ग)	अन्य दायित्व		
i)	नियत आस्तियों के क्रय के लिए देनदार	4	80
ii)	कर्मचारियों से वसूलियां और कर्मचारियों के अभिदाय (भविष्य निधि, ईएसआईसी को अभिदाय, वृत्तिक कर आदि)	166	191
iii)	कानूनी देय (प्रतिधारण संबंधी कर)	258	328
iv)	प्रतिभूति और बनाया संबंधी निक्षेप	787	612
v)	अन्य	716	1,187
कुल योग (ख)		1,931	2,398
योग (क+ख)		19,345	18,787

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

टिप्पण 9. # मूर्त आस्तियां

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि		पट्टाधृत भूमि		घवन		लिफ्ट तथा इलेक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग्स		कंप्यूटर		फर्नीचर और फिक्सचर		वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर		वाहन		पुस्तकालय की पुस्तकें		योग	
	31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
वर्ष के प्रारंभ में लागत	18,817	15,690	5,683	5,399	27,789	26,932	1,806	1,757	4,868	4,463	4,072	3,765	4,585	4,236	135	134	966	907	68,721	63,283
परिवृद्धियां	397	3,148	197	284	680	857	63	64	301	416	151	388	259	378	1	1	41	59	2,090	5,595
विलोपन	-	(21)	-	-	(28)	-	(6)	(15)	(39)	(11)	(29)	(81)	(44)	(29)	(1)	-	-	-	(147)	(157)
वर्ष के अंत में	19,214	18,817	5,880	5,683	28,441	27,789	1,863	1,806	5,130	4,868	4,194	4,072	4,800	4,585	135	135	1,007	966	70,664	68,721

लागत																				
वर्ष के प्रारंभ में संचयी अवक्षयण	-	-	583	499	5,492	4,325	973	873	4,384	3,958	1,758	1,535	2,534	2,219	92	82	966	907	16,782	12,179
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	86	84	1,127	1,167	92	105	399	436	237	258	320	328	9	10	41	59	2,311	2,447
विलोपन	-	-	-	-	(19)	-	(2)	(5)	(15)	(10)	(3)	(35)	(5)	(13)	-	-	-	-	(44)	(63)
वर्ष के अंत में संचयी अवक्षयण	-	-	669	583	6,600	5,492	1,063	973	4,768	4,384	1,992	1,758	2,849	2,534	101	92	1,007	966	19,049	16,782
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	19,214	18,817	5,211	5,100	21,841	22,297	800	833	362	484	2,202	2,314	1,951	2,051	34	43	-	-	51,615	51,939

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

टिप्पण 10.# अमूर्त आस्तियां कंप्यूटर साफ्टवेयर	31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2017	2016
	(लाख रुपए में)	
वर्ष के प्रारंभ में लागत	646	637
परिवृद्धियां	19	9
विलोपन	(2)	-
वर्ष के अंत में लागत	663	646
वर्ष के प्रारंभ में परिशोधन	623	607
वर्ष के लिए प्रभार	23	16
विलोपन	(2)	-
वर्ष के अंत में परिशोधन	644	623
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	19	23
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य	23	30

टिप्पण 11. #: चालू पूंजी संकर्म	31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2017	2016
	(लाख रुपए में)	
प्रारंभिक अतिशेष	13,202	11,387
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	673	1,815
घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत/ समायोजित रकम	-	-
अंतिम अतिशेष	13,875	13,202

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

टिप्पण # 12: निवेश (लागत पर)	31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2017	2016	2017	2016
	(लाख रुपए में)		(लाख रुपए में)	
	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
क. केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां				
i. 8.27% भारत सरकार 2020	2,628	-	-	-
ii. 7.46% भारत सरकार 2017	-	-	1,651	-
iii. 7.49% भारत सरकार 2017	-	-	861	-
iv. 7.80% भारत सरकार 2021	2,618	-	-	-
बही मूल्य	5,246	-	2,512	-
बाजार मूल्य	5,214	-	2,514	-
ख. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां				
i. 8.47% तमिलनाडु एसडीएल 2017	-	-	3,042	-
ii. 8.21% राजस्थान यूडीएवाई एसडीएल 2018	-	-	2,537	-
iii. 7.75% राजस्थान यूडीएवाई एसडीएल 2018	2,532	-	-	-
बही मूल्य	2,532	-	5,579	-
बाजार मूल्य	2,527	-	5,574	-
ग. शाश्वत बेसल-3 बंधपत्रों के अधीन पब्लिक सेक्टर				
i. 10.75% आईडीबीआई बैंक लि.	3,018	-	-	-
ii. 10.95% ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1,021	-	-	-
iii. 10.95% ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1,532	-	-	-
iv. 9.00% भारतीय स्टेट बैंक	511	-	-	-
v. 9.00% भारतीय स्टेट बैंक	4,576	-	-	-
vi. 11.00% बैंक आफ इंडिया	1,047	-	-	-
vii. 11.00% बैंक आफ इंडिया	1,047	-	-	-
viii. 10.99% आंध्र बैंक	3,101	-	-	-
बही मूल्य	15,853	-	-	-
बाजार मूल्य	15,878	-	-	-
घ. समनुषंगी के साम्या निवेशों में निवेश (पूर्ण समादत्त)				
- आईसीएआई का दीवाला वृत्तिक संस्थान	1,000	-	-	-
100 रुपए प्रत्येक के 10,00,000 साधारण शेयर				
योग (क+ख+ग+घ)	24,631	-	8,091	-

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

टिप्पण # 13: उद्दिष्ट और अन्यो के लिए धारित आस्तियां	31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2017	2016	2017	2016
	(लाख रुपए में)		(लाख रुपए में)	
	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
टिप्पण : बैंकों में सावधि निक्षेप (नीचे टिप्पण देखें)	3,630	11,816	70,388	80,636
योग	3,630	11,816	70,388	80,636
टिप्पण : धारित आस्तियों में निम्नलिखित हैं :				
- उद्दिष्ट निधियां (टिप्पण # 4)	3,630	11,816	30,699	17,383
- कर्मचारी फायदे (टिप्पण # 6)	-	-	17,275	10,019
- अन्य	-	-	22,414	53,234
योग	3,630	11,816	70,388	80,636

टिप्पण # 14: ऋण और अग्रिम (सुरक्षित, उत्तम समझे गए)	गैर चालू	गैर चालू	चालू	चालू
क) प्रतिभूति निक्षेप	254	282	145	141
ख) स्रोत पर कर कटौती	1,854	2,172	-	-
ग) अन्य ऋण और अग्रिम				
i) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	634	746	561	538
ii) अन्य प्राप्य	245	521	1,878	3,291
घटाएं : संवेदास्पद उधारों और अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	(332)	-
योग	2,987	3,721	2,252	3,970

टिप्पण # 15 : अन्य आस्तियां	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
क) प्रोदभूत ब्याज				
i. बैंक के साथ सावधि जमा पर	452	1,636	3,449	1,870
ii. निवेश पर	1,111	-	123	-
iii. कर्मचारियों के ऋणों पर	121	119	32	10
योग	1,684	1,755	3,604	1,880

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

टिप्पण # 16 : वस्तु-सूचियां (निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर)	31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2017	2016
	(लाख रुपए में)	
क) प्रकाशन और अध्ययन सामग्रियां	949	1,112
ख) लेखन सामग्रियां और भंडार	52	131
योग	1,001	1,243

टिप्पण # 17 : नकद और नकद समतुल्य		
क) हाथ में नकदी	36	58
ख) बैंकों में अतिशेष	4,999	5,027
योग	5,035	5,085

टिप्पण # 18 : फीसें		
क) दूरस्थ शिक्षा	18,971	19,570
ख) कक्षा प्रशिक्षण आय	7,609	8,414
ग) परीक्षा	13,099	12,680
घ) सदस्यता	5,869	5,636
ङ) छात्र रजिस्ट्रीकरण	515	459
च) प्रवेश	74	71
छ) छात्र संघ	386	344
ज) अर्हतापश्च पाठ्यक्रम	797	560
झ) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	1,265	1,354
योग	48,585	49,088

टिप्पण # 19 : अन्य आय		
क) व्याज आय		
i. साधारण निधियों में धारित बैंक निक्षेप पर	4,098	5,405
ii. निवेशों से	1,172	-
iii. उद्दिष्ट निधियों के लिए धारित बैंक निक्षेप पर	2,344	2,259
iv. कर्मचारियों के ऋणों पर	72	70
ख) प्रकाशनों का विक्रय	1,540	1,634
ग) न्यूजलेटर	149	185
घ) जर्नल अभिदाय	52	70
ङ) कैम्पस साक्षात्कार	759	567
च) विशेषज्ञ सलाहकार फीस	25	12
छ) अनापेक्षित प्रावधानों का अपलेखन	114	172
ज) प्रकीर्ण आय	664	1,019
योग	10,989	11,393

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

टिप्पण # 20 : कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय	31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2017	2016
	(लाख रुपए में)	
क) वेतन, पेंशन और अन्य भत्ते	16,151	12,690
ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों को अभिदाय	847	707
ग) कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय	192	172
योग	17,190	13,569

टिप्पण # 21. अन्य व्यय			
क)	डाक और टेलीफोन	2,639	2,861
ख)	किराया, दरें और कर	3,868	4,026
ग)	यात्रा और वाहन-घरेलू	1,418	2,105
घ)	विदेशों से संबद्ध		
	i) विदेश यात्रा	256	297
	ii) विदेशी वृत्तिक निकायों की सदस्यता फीस	342	326
	iii) अन्य	52	23
ङ)	मरम्मत और अनुरक्षण	1,775	1,895
च)	प्रकाशन	1,101	1,136
छ)	कक्षा प्रशिक्षण व्यय	4,833	4,685
ज)	विज्ञापन और प्रचार	398	413
झ)	बैठक व्यय	595	564
॥É)	योग्यता छात्रवृत्ति	124	131
ट)	संपरीक्षा फीस : प्रधान कार्यालय	11	11
	अन्य कार्यालय	33	32
ठ)	उद्दिष्ट निधियों से संदाय	63	88
ड)	पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध) (टिप्पण 22)	227	340
ढ)	संदेहास्पद उधारों और अग्रिमों के लिए प्रावधान	332	-
ण)	प्रकीर्ण व्यय	1,572	2,756
	योग	19,639	21,689

टिप्पण # 22 : पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध)		
i) आय	(173)	(70)
ii) व्यय	400	410
योग	227	340

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

23. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी

23.1 आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं :

(लाख रुपए में)

2017 **2016**

क. आकस्मिक दायित्व

i) संस्थान के विरुद्ध ऐसे दावे, जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है	1,216	1,358
iii) आयकर की मांग – धारा 143(1) के अधीन संसूचना (टिप्पण #23.2 देखें)	4,142	4,142

पूर्वोक्त मामलों के संबंध में भावी नकद प्रवाह का अवधारण केवल विभिन्न मंचों में लंबित निर्णय/विषय की प्राप्ति पर ही किया जाएगा।

ख. प्रतिबद्धताएं :

(लाख रुपए में)

i) पूंजी प्रतिबद्धताएं (अग्रिमों का शुद्ध)	4252	4744
--	-------------	------

23.2 निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आयकर विभाग से एक संसूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कुल 4142 लाख रुपए के आयकर की मांग रखी गई है और जिसमें संस्थान द्वारा किए गए कानूनी दावों को स्वीकार नहीं किया गया है। उसके विरुद्ध प्रथम अपील अधिकरण में एक अपील फाइल की गई है जो अभी लंबित है। संस्थान को यह सलाह दी गई है कि उसका मामला मजबूत है और यह संभावना है कि यह मांग समाप्त हो जाएगी।

23.3 टिप्पण # 11 दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के अधीन अन्य प्राप्यों में, नागपुर में भू-संपत्ति के अर्जन के लिए मूल और अनुपूरक करारों के रद्द हो जाने के कारण, स्टाम्प शुल्क के लिए 243.75 लाख रुपए के प्रतिदेय प्राप्य सम्मिलित हैं, जिसे संयुक्त जिला रजिस्ट्रार (जेडीआर), नागपुर द्वारा नामंजूर कर दिया गया है। संस्थान ने, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, पुणे के समक्ष महाराष्ट्र स्टाम्प शुल्क अधिनियम की धारा 53 के अधीन, जेडीआर, नागपुर द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए दो अपील फाइल की हैं, जो अंतिम अधिनिर्णयन के लिए लंबित हैं। संस्थान को यह सलाह दी गई है कि स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए उनके पास उत्तम विधिक मामला है।

23.4 संगोष्ठियों संबंधी क्रियाकलापों के मद्दे प्रत्यक्ष रूप से होने वाले व्ययों को संगोष्ठी संबंधी व्ययों के अधीन प्रभारित किया गया है और इससे संबंधित अप्रत्यक्ष व्ययों को व्यय के कार्यकरण शीर्षों के अधीन प्रभारित किया गया है।

23.5 छात्रों से, छात्र संघ फीस के मद्दे प्राप्त फीस में से, 1 अप्रैल, 2009 के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक छात्र के लिए 250 रुपए प्रति छात्र की एक राशि को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि में जमा किया जा रहा है।

23.6 पट्टाधृत भूमि के मूल्य में 6.17 लाख रुपए सम्मिलित हैं, जो भूमि और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली से इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में विद्यमान (प्रधान कार्यालय के प्लॉट के साथ लगी) भूमि से संबंधित हैं, जिसके लिए करार और पट्टाभिलेख के ज्ञापन के निष्पादन संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

23.7 संस्थान ने, सभी स्तरों पर संस्थान की संपूर्ण गतिविधियों, जिनके अंतर्गत सदस्य, छात्र और अन्य वृत्तिक गतिविधियां भी हैं, के अंकीकरण के उद्देश्य से एक प्रक्रिया संबंधी पहल की है, जिसे "परिवर्तन परियोजना" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, संस्थान ने एक वैश्विक रूप से ख्यातिप्राप्त परियोजना प्रबंध परामर्शी के द्वारा पर्यवेक्षित एक वैश्विक एकीकृत सेवा प्रदाता (विक्रेता) को नियुक्त किया था, जिसकी कुल लागत 3,981 लाख रुपए है। 31 मार्च, 2015 तक 867 लाख रुपए की राशि उपगत की गई है।

चूंकि एकीकृत सेवा प्रदाता ने, उसे विस्तारित समय सीमाएं प्रदान करने के पश्चात् भी अपेक्षा के अनुसार विकास कार्य नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान ने इस संबंध में विवाद उठाते हुए संविदा को रद्द कर दिया था। अंतिम समाधान के लंबित रहते हुए, संस्थान ने जून, 2015 को 295 लाख रुपए की बैंक प्रत्याभूति का प्रत्याहान और नकदीकरण किया था और 572 लाख रुपए के लिए 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया था।

गत वर्ष, सेवा प्रदाता ने प्रदाय किए हार्डवेयर के मद्दे शोध शेष रकम और संस्थान द्वारा नकदीकरण की गई बैंक प्रत्याभूति के प्रतिदाय के संबंध में समाधान करने के लिए एक मांग सूचना भेजी है। तथापि, संस्थान ने यह मत लिया है कि अपेक्षित साफ्टवेयर की अनुपस्थिति में प्रदाय किए गए हार्डवेयर की कोई उपयोगिता नहीं है, अतः शेष संदाय के बारे में विचार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, बैंक प्रत्याभूति का नकदीकरण, संविदा के रद्द हो जाने के कारण उपगत हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए किया गया था। संस्थान अब एक प्रतिदावा फाइल करने के लिए प्रक्रिया कर रहा है। वर्ष के दौरान, मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विक्रेता के अनुरोध पर उसके पदधारियों के साथ अनेक बैठकें की गई थी। तारीख 26 जुलाई, 2016 के पत्र द्वारा विक्रेता ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें संस्थान द्वारा वापस ली गई बैंक प्रत्याभूतियों की रकम के अतिरिक्त संस्थान से 605 लाख रुपए का संदाय करने की अपेक्षा की गई थी। संस्थान द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है और साथ ही सेवा प्रदाता के साथ मास्टर कारबार करारों को संस्थान द्वारा उसके तारीख 8 फरवरी, 2017 के पत्र द्वारा समाप्त कर दिया गया है और तब से इस संबंध में विक्रेता से कोई और संसूचना प्राप्त नहीं हुई है।

23.8 आईसीएआई भवन, फरीदाबाद से 225 वर्ग मीटर के मापमान वाली भूमि को जनवरी, 2013 में डीएमआरसी द्वारा अधिगृहीत किया गया था, जिसके लिए फरीदाबाद शाखा ने डीएमआरसी द्वारा किए गए अधिग्रहण के विरुद्ध प्रतिकर के रूप में शाखा के आसपास और अधिक भूमि के लिए अनुरोध किया था। इस मामले पर वर्तमान में हुडा (हरियाणा) द्वारा विचार किया जा रहा है।

23.9 चंडीगढ़ शाखा में स्टॉक /प्राप्तियों की कमी को लेखांकित न करने की कतिपय घटनाएं सूचना में आई हैं, जिसके लिए प्रधान कार्यालय के प्रबंध द्वारा इस संबंध में आवश्यक समझे गए उपायों को किया गया है।

23.10 अन्य व्यय में 278 लाख रुपए भी सम्मिलित हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28-क के अधीन गठित क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा उपगत लागतों की प्रतिपूर्ति है। अन्य व्ययों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन गठित अपील प्राधिकरण को दिया गया 25 लाख रुपए का अभिदाय भी सम्मिलित है। क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड और अपील प्राधिकरण के व्ययों का वहन संस्थान द्वारा किया जाना है। अन्य व्ययों के अंतर्गत आईसीएआई लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान (आईसीएआई-एआरएफ) को दिया गया 70 लाख का अनुदान भी है।

23.11 पूर्व वर्षों में सृजित विभिन्न आरक्षित निधियों और उद्दिष्ट निधियों का और उद्दिष्ट निवेशों का ब्यौरेवार पुनर्विलोकन आरंभ किया गया है ताकि संस्थान की वर्तमान अपेक्षाओं और कार्यकरण के अनुसार इन निधियों को पुनः संरचित किया जा सके।

23.12 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित पेंशन दायित्व को भी बीमांकिक रूप से अवधारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 4,207 लाख रुपए सहित 4,920 लाख का अतिरिक्त प्रावधान 31 मार्च, 2016 तक उदभूत हुआ था।

23.13 वर्ष के दौरान संस्थान ने 15,500 लाख रुपए का निवेश गैर-परिवर्तनीय शाश्वत, अधीनस्थ, असुरक्षित बीएसईएल-3 अनुपालक अतिरिक्त टियर 1 बंधपत्रों में किया था, जो पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों की प्रकृति के थे और 15,869 लाख रुपए का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया था। ये बंधपत्र विमोचनीय नहीं हैं, किंतु जारीकर्ता बैंक द्वारा एक कॉल विकल्प उपलब्ध कराया गया है, जिसका कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग किया जा सकता है। 779 लाख रुपए की रकम के संदत्त प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि के अनुसार परिशोधित किया जा रहा है।

23.14 कतिपय निवेश, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18(2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सीमाओं से अधिक हैं। इस मामले को नियमित करने हेतु उपाय किए जा रहे हैं।

23.15 यद्यपि, संस्थान की आय को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) के अधीन पूर्णतया छूट प्राप्त है, फिर भी कुछ अस्तित्वों में संस्थान ने किए जाने वाले संदायों पर स्रोत पर कर की कटौती की है। वर्ष 2014-15 के निर्धारण वर्ष के लिए 452 लाख रुपए सहित कुल 1,855 लाख रुपए का स्रोत पर कटौती किए गए कर का प्रतिदाय, आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित अपील में अंतिम निर्णय पर प्राप्त होने की संभावना है।

23.16 वर्ष के दौरान, संस्थान ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान लिमिटेड की शेयर पूंजी के मद्दे 10 करोड़ रुपए के 10,00,000 साम्या शेयरों का अभिदाय किया है। आईसीएआई, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक कंपनी है। इस निवेश को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसका मूल्यांकन लागत पर किया गया है।

23.17 वर्ष के दौरान, संस्थान ने आनलाइन केंद्रीयकृत लेखांकन साफ्टवेयर के प्रति अंतरण किया था और शाखाओं तथा अन्य कार्यालयों के साथ उसके संव्यवहारों के पुनः समाधान को लगभग पूरा कर लिया गया है, इस संबंध में प्रबंधमंडल की राय यह है कि लंबित समाधानों का प्रभाव वित्तीय विवरणों को सारवान रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

23.18 वर्ष के अंत के पश्चात् अधिकांश शाखाओं की नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और भौतिक अतिशेषों को बही अतिशेषों के साथ तुलना करके समाधान किए जाने पर, रिपोर्टों का समुचित समायोजनों, यदि कोई हों, के पश्चात् विश्लेषण किया जा रहा है। तथापि, प्रबंधमंडल की राय यह है कि इसका प्रभाव वित्तीय विवरणों को सारवान रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटन

24. कर्मचारी फायदे

परिभाषित अभिदाय योजनाएं

संस्थान ने भविष्य निधि में अभिदाय के मद्दे 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 432.54 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 432.46 लाख रुपए) की राशि को मान्यता प्रदान की है।

परिभाषित फायदा योजनाएं

संस्थान ने अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित परिभाषित फायदा योजनाएं प्रदान की हैं

उपदान	वित्तपोषित
सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन	गैर-वित्तपोषित
क्षतिपूरित अनुपस्थिति	गैर-वित्तपोषित

24.1 उपदान योजना से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं

लाख रुपए में

	वर्णन	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1.	बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान				
	क. वर्ष के आरंभ में बाध्यता	2,358	2,213	2,057	1,957
	ख. चालू सेवा लागत	202	184	167	147
	ग. ब्याज लागत	166	169	154	171
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	44	(53)	32	(63)
	ङ. संदत्त फायदे	(260)	(155)	(197)	(155)
	च. वर्ष के अंत में बाध्यता	2,510	2,358	2,213	2,057
2.	योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन				
	क. वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,292	2,232	2,103	1,950

	ख. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	183	191	184	174
	ग. बीमांकिक अभिलाभ/ (हानि)	2	6	3	10
	घ. संस्थान द्वारा किया गया अभिदाय	132	78	239	91
	ङ. संदत्त फायदे	(285)	(215)	(297)	(122)
	च. वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,324	2,292	2,232	2,103
3.	योजना, आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान				
	क. बाध्यताओं का विद्यमान मूल्य	2,510	2,358	2,213	2,057
	ख. योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,324	2,292	2,232	2,103
4.	ग. तुलन पत्र आस्ति/(दायित्व) में मान्यता प्रदान की गई रकम	(186)	(66)	19	46
	वर्ष के दौरान माने गए व्यय				
	क. चालू सेवा लागत	202	184	167	147
	ख. व्याज लागत	166	169	154	171
	ग. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	(183)	(191)	(184)	(174)
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	42	(59)	29	(73)
	ङ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	227	103	166	71
5.	निवेशों के ब्यौरे	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत
	क. अन्य – भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधियां	100.00	100.00	100.00	100.00
	उपदान योजना के ब्यौरे (जारी....)				
6.	वर्णन पूर्वानुमान	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	7.45%	7.92%	7.85%	9.00%
	ख. योजना आस्तियों से आय की प्राक्कलित दर (प्रतिवर्ष)	8.25%	8.85%	8.85%	9.00%
	ग. वेतन में वृद्धि की दर	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%
	घ. संनिघर्षण दर	5%	5%	5%	5%
	ङ नश्वरता सूची	आईएएल 2006-08	आईएएल 2006-08	आईएएल 2006-08	आईएएल 2006-08
		अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा

24.2 सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन योजनाओं के ब्यौरे					
वर्णन	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
1.	बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	5,086	2,684	1,406	1,489
	ख. व्याज लागत	358	211	110	134
	ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	6,063	2,210	1,169	(215)
	घ. संदत्त फायदे	(391)	(19)	(1)	(2)
	ङ वर्ष के अंत में बाध्यताएं	11,116	5,086	2,684	1,406
2.	योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान				
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	11,116	5,086	2,684	1,406
	ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकमे	(11,116)	(5,086)	(2,684)	(1,406)
3.	वर्ष के दौरान माने गए व्यय				
	क. व्याज लागत	358	211	110	134
	ख. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	6,063	2,210	1,169	(215)
	ग. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	6,421	2,421	1,279	(81)
4.	पूर्वानुमान				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	7.30	7.90%	7.90%	7.80%
	ख. वेतन में वृद्धि की दर	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%
	ग. संनिघर्षण दर	5%	5%	5%	5%
	घ. नश्वरता सूची	आईएएल 1996-98	आईएएल 1996-98	आईएएल 1996-98	आईएएल 1996-98
	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा

24.3 कर्मचारी फायदे (जारी....)**छुट्टी नकदीकरण के ब्यौरे**

(लाख रुपए में)

	वर्णन	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1.	बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	3,217	2,857	2,359	2,239
	ख. चालू सेवा लागत	305	280	338	104
	ग. ब्याज लागत	227	216	175	199
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	127	115	259	(83)
	ङ. संदत्त फायदे	(348)	(251)	(274)	(100)
	च. वर्ष के अंत में बाध्यताएं	3,528	3,217	2,857	2,359
2.	योजना अस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान				
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	3,528	3,217	2,857	2,359
	ख. तुलन-पत्र अस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकमे	(3,528)	(3,217)	(2,857)	(2,359)
3.	वर्ष के दौरान माने गए व्यय				
	क. चालू सेवा लागत	305	280	338	104
	ख. ब्याज लागत	227	216	175	199
	ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	127	115	259	(83)
	घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	659	611	772	220
4.	पूर्वानुमान				
	क. बढ़ा दर (प्रतिवर्ष)	7.45%	7.92%	7.85%	9.10%
	ख. वेतन में वृद्धि की दर	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%
	ग. संनिघर्षण दर	5%	5%	5%	5%
	घ. नश्वरता सूची	आईएएल 2006-08 अंततोगत्वा	आईएएल 2006-08 अंततोगत्वा	आईएएल 2006-08 अंततोगत्वा	आईएएल 2006-08 अंततोगत्वा

25. खंड रिपोर्टिंग

संस्थान के प्रचालन "चार्टर्ड एकाउंटेंसी की वृत्ति को अग्रसर करना" तक सीमित है और यह मुख्यतः भारत में प्रचालन करता है। अतः, इसके सभी प्रचालन, लेखांकन मानक (एएस-17) खंड रिपोर्टिंग के अर्थातगत एकल खंड के अंतर्गत आते हैं।

26. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के तत्समान बनाने के लिए, जहां कहीं आवश्यक है, पुनः समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	वी. सागर	सीए. नवीन एन. डी. गुप्ता	सीए. नीलेश शिवजी विक्रमसे
संयुक्त सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते हिंगोरानी एम. एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 006772एन

खन्ना एंड आन्नदनम
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 001297एन

ह/
सीए. संजय कुमार नारंग
भागीदार
सदस्यता सं. 090943

ह/
सीए. बी.जे. सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 07884

स्थान : नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2017

वी. सागर, सचिव

[विज्ञाप-III/4/असाधारण/246/17]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2017

No. 1-CA(5)/68/2017. – In pursuance of sub-section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Audited Accounts and Report of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India for the year ended 31st March, 2017 is hereby published for general information.

68th Annual Report

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has immense pleasure in presenting its 68th Annual Report for the year ended 31st March, 2017. Since the inception of the Institute on 1st July, 1949 by an Act of Parliament, the accountancy profession has grown tremendously. Founded with about 1,700 members, the Institute has today more than 2,70,000 members and 8,05,000 students as on 1st July, 2017. The Report highlights the important activities of the Council and its various Committees during the year 2016-2017, besides the accounts of the Institute for the year ended on 31st March, 2017. The Council also takes this opportunity to submit in this Report major initiatives, important events, statistical data relating to members, students, details of seminars, conference, workshop, training programmes organised during the period upto early July, 2017. The Council commends its members and students for the respect which the chartered accountancy profession commands today in the Society. This has been achieved through excellence, independence and integrity displayed by the members and students all along.

1. THE COUNCIL

The twenty-third Council was constituted on 12th February, 2016 for a period of three years. The Council comprise 32 elected members and 8 members nominated by the Central Government. The composition of the twenty-third Council is shown separately.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council, in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949, constituted, on 12th February, 2017, Standing Committees and other Non-Standing Committees/Boards to deal with matters concerning the profession. During the year ended 31st March, 2017, 261 meetings were held of various Committees of the Council.

3. AUDITORS

M/s. Hingorani M. & Co., and M/s. Khanna & Annadhanam were the joint auditors of the ICAI for the financial year 2016-17.

4. STANDING COMMITTEE**4.1 Executive Committee**

The Executive Committee is one of the Standing Committees of the Council of the ICAI. The functions of the Committee have been prescribed in Regulation 175 of the Chartered Accountants Regulations, 1988. Some of these functions are relating to articulated and audit assistants and enrolment, removal, restoration of members from the Register, cancellation of certificate of practice, permission to engage in any other business or occupation other than profession of accountancy. The Committee is also the custodian of the property, assets and funds of the Institute beside maintenance of the office of the ICAI.

4.2 Finance Committee

The Finance Committee introduced vide Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006, controls, implements and supervises the activities related with and incidental, inter alia, to maintenance of true and correct accounts, formulation of annual budget, investment of the funds, and disbursements from the funds for expenditure – both revenue and capital.

4.3 Examination Committee

The Examination Committee performs all the functions of the Council relating to examinations. The Committee smoothly conducted the Chartered Accountants Intermediate (IPC) Examinations and the Final Examinations all over the country and abroad in 461 and 359 centres respectively from 2nd May to 22nd May, 2016. The total number of candidates, who appeared in the said Intermediate (IPC) and Final Examinations and passed were as follows:

May, 2016					
Sr.No.	Category	Intermediate (IPC)		Final	
		Appeared	Passed	Appeared	Passed
I	Appeared in Group I only	65672	6028	37194	5382
II	Appeared in Group II only	56742	4004	36906	7864
III	Appeared in Both Groups				
(a)	Passed either in Group I or Group II only	47979	8325	40180	6190
(b)	Passed in Both Groups		2295		4565
	Total		20652		24001

The Chartered Accountants Intermediate (IPC) Examinations and the Final Examinations were also conducted all over the country and abroad in 438 and 347 centres respectively from 1st to 16th November, 2016. The total number of candidates, who appeared in the said intermediate (IPC) and Final Examinations and passed, were as follows:

November, 2016					
Sr.No.	Category	Intermediate (IPC)		Final	
		Appeared	Passed	Appeared	Passed
I	Appeared in Group I only	69653	13424	37200	2655
II	Appeared in Group II only	62123	18701	36896	4545
III	Appeared in Both Groups				
(a)	Passed either in Group I or Group II only	47766	12434	36768	2976
(b)	Passed in Both Groups		3109		1280
	Total		47668		11456

Besides, the Common Proficiency Test [CPT] was held successfully on 19th June, 2016 and on 18th December, 2016 across the country and abroad at 416 and 326 examination centres respectively. The total number of candidates who appeared and passed in the CPT are as under:

CPT held on	Appeared	Passed
19 th June, 2016	107058	41727
18 th December, 2016	70321	32658

The examinations of Post Qualification Course in Management Accountancy Course (MAC) (Part-1), Corporate Management Course (CMC) (Part-1), Tax Management Course (TMC) (Part-1), Insurance and Risk Management (IRM) and International Trade Laws and World Trade Organization (ITL & WTO), were also conducted in November, 2016.

During the year, Post Qualification Course - Information Systems Audit – Assessment Test was held successfully on 25th June, 2016 all over the country in 55 Examination centres. Another Information Systems Audit – Assessment Test was held successfully on 24th December, 2016 all over the country in 56 examination centres. The total number of candidates, who appeared in these examinations and passed were as follows:

ISA Assessment Test held on	Appeared	Passed
25 th June, 2016	1464 (Old)	111 (Old)
	1636 (New)	717 (New)
24 th December, 2016	1256 (Old)	90 (Old)
	2158 (New)	439 (New)

Introduction of International Taxation-Assessment Test (INTT-AT):- ICAI introduced a new Post Qualification Diploma course in International Taxation-Assessment Test (INTT-AT) for members and the first examination of the said course was held in November, 2016. Out of 103 members who appeared for the test, 56 members passed the same.

ICAI has continuously been improving its Examination Processes right from the question paper setting up to declaration of results so that the integrity and sanctity of the examination system which is well known for over six decades, are maintained and further strengthened and developed.

ICAI's examinations test the conceptual understanding as well as practical application of each of the topics covered in the CA curriculum to enable the students to meet the stakeholders' expectations. By focusing on analytical abilities of the students and by avoiding predictability of questions, ICAI's examinations continue to ensure that those qualifying are well groomed professionals.

Special Examination: Arising out of the Mutual Recognition Agreement / Memorandum of Understanding entered with the following foreign professional accounting bodies, the Special Examination for their members desirous of membership of ICAI were successfully conducted on 21st & 22nd June, 2016 in New Delhi:

1. The Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW)
2. The Institute of Chartered Accountants of Australia (ICA Australia)
3. The Institute of Certified Public Accountants in Australia (CPA Australia)
4. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (CPA Ireland)
5. Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA)

Beside this the ICAI has entered into Memorandum of Understanding (MoU) with the New Zealand Institute of Chartered Accountants (NZICA).

The above Special Examination is open to the members of the above international accounting bodies.

Web-Interface on Students Exam Life Cycle Management:-

ICAI embarked on an integrated web-interface called Student Exam Life Cycle Management Project, where CA students using a single user ID and password, can access various examination related services, including application for duplicate marksheets/pass certificates/transcripts, change of centre/medium/group, downloading admit cards, checking results, and applying for verification/seeking certified copies of answer books post result etc.

New Examination Centres:- With a view to facilitate students to appear in the examination centres as nearer to their place of residence as possible, new examination Centres were opened as follows:

For CA Intermediate and Final examinations :

- a) With effect from May 2016 examination onwards: Shimoga and Malappuram.
- b) With effect from May, 2017 examination onwards: Haridwar and Nizamabad.

For CPT Examination:

- a) With effect from June 2016: Shimoga, Malappuram and Satna
- b) With effect from June, 2017: Badlapur, Banswara, Bhiwandi, Burhanpur, Chandrapur, Chhindwara, Gondia, Haldwani, Haridwar, Ichalkaranji, Jalna, Junagadh, Mandsaur, Muzaffarpur, Nizamabad, Palghar, Parbhani, Ratnagiri, Rewa & Yavatmal.

4.4 Disciplinary Committee

As part of ICAI's continuous drive to uphold the credibility, integrity and image of the accountancy profession in India, the regulatory framework of ICAI has put in place a strong and vibrant disciplinary mechanism wherein proceedings are initiated and conducted through a well-defined procedure which consistently strives to ensure the principles of natural justice ensuring that the guilty are punished .

In terms of the amendments made in the Chartered Accountants Act, 1949 in the year 2006, the disciplinary mechanism of ICAI underwent certain important and path breaking changes in the provisions of procedures for conduct of disciplinary cases. Accordingly, as on date, the disciplinary mechanism functions through its two quasi-judicial arms constituted as per the provisions of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 viz.;

- (i) Board of Discipline (under Section 21A); and
- (ii) Disciplinary Committee (under Section 21B).

In 2016-17 for the first time, two Benches of the Disciplinary Committee viz. Bench-1 and Bench-2 were constituted with a view to sustain the process of expeditious disposal of cases pending for enquiry. In this regard, Bench-1, headed

by the President, ICAI, was looking into cases pertaining to Western/Northern Regions apart from public interest matters. Similarly, Bench-2, headed by Vice President, ICAI was looking into cases relating to Southern/Eastern/Central Regions.

In respect of the cases pending prior to the amendments made in 2006, the transitional provisions under Section 21D are applicable whereby the Disciplinary Committee under Section 21D looks into such residual cases pending in terms of the earlier provisions in the Act and Regulations framed there under. The brief write-up of the activities of Board of Discipline (under Section 21A)/Disciplinary Committees (under Section 21B) and Disciplinary Committee (under Section 21D) are provided below.

Board of Discipline under Section 21A.

The Board of Discipline has been constituted by the Council of ICAI under Section 21A of the Chartered Accountants Act, 1949 so as to look into matters of professional and other misconduct by members which fall within the purview of First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 and/or cases wherein the members are held prima facie NOT guilty of any misconduct by Director (Discipline).

Though the Board was constituted on 12th February, 2016 it actually started functioning from May, 2016 as the Government nominee was appointed in April, 2016. During the year under report, the Board held 11 meetings at various places across the country. In these meetings, the Board concluded its enquiry in 30 cases, including cases which had been referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Board of Discipline during this period 1st April, 2016 to 31st March, 2017 is given below:

Sl. No.	Particulars	No. of cases*
a)	No. of meetings held	11(11)
b)	Number of Complaint/Information cases considered wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed.	162 (198)
c)	Out of the above, number of Complaint/Information cases referred for further enquiry	37 (44)
d)	Number of cases (Complaint/Information cases) in which enquiry was completed (including those cases, which were referred during the earlier years).	30 (18)
e)	Number of cases (Complaint/Information) in which punishment has been awarded (including those cases, which were referred during the earlier years).	8 (7)

* Figures in brackets refers to the corresponding figure of previous year

During the year, the Board, in terms of the decision taken by it at its meeting held in July, 2016, decided to constitute a separate Group to look into the intricacies involved in the disciplinary mechanism of the ICAI. Accordingly, a Group was constituted by the President under the Convenership of CA. Sanjay Kumar Agarwal, Central Council Member to examine the intricacies involved in areas wherein changes need to be made pertinent to the disciplinary mechanism as provided under the Chartered Accountants Act, 1949 and the Rules framed thereunder and thereafter suggest amendments to the Chartered Accountants Act, 1949 and the Rules framed thereunder.

For accomplishing the task assigned to it, the Group held three meetings and submitted its Report to the Council at its meeting held in May, 2017. The Council accepted the recommendations made by the Group. The Report of the Group along with recommendations accepted by the Council has also been shared with the High Level Committee constituted by the Ministry of Corporate Affairs to look into the issues related to the Disciplinary Mechanism of the three professional Institutes.

Disciplinary Committee under Section 21B

The Disciplinary Committee has been constituted by the Council of the ICAI under Section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 so as to look into matters of professional misconduct by members which fall within the purview of Second Schedule and both First and Second Schedules to the Chartered Accountants Act, 1949. Though the Committee was constituted on 12th February, 2016 it actually started functioning from May, 2016 as the Government nominees were appointed in April, 2016. During the year under report, this Committee held 18 meetings (Bench 1 : 8 meetings & Bench 2 : 10 Meetings) at different places across the country. During the course of the aforesaid meetings, the Committee concluded its enquiry in 48 cases, which included cases, referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Disciplinary Committee during the period 1st April, 2016 to 31st March, 2017 is given below:

Sl. No.	Particulars	No. of cases
a)	No. of meetings held	18 (28)
b)	Number of Complaint/Information cases considered wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed.	53 (70)
c)	Out of the above, number of Complaint/Information cases referred for enquiry	55* (64)
d)	Number of cases (Complaint/Information cases) in which enquiry was completed (including those cases, which were referred to the during the earlier years).	48 (94)
e)	Number of cases (Complaint/Information) in which punishment has been awarded (including those cases, which were referred during the earlier years).	23 (28)

*Including cases referred by Board of Discipline to Disciplinary Committee. Figures in brackets refers to the corresponding figure of previous year

Keeping in view the changing times in terms of advancement of technology enabling faster communication and the Council of the ICAI having given its in-principle approval for introduction of e-hearings, the Committee is presently in the process of amending the Rules so as to enact the modalities in this regard for approval by the Ministry of Corporate Affairs. The amendments in Rules, when put in place, shall go a long way in conducting hearings on fast track mode resulting in disposal of disciplinary cases across the country in expeditious manner and reducing the overall costs and time.

Disciplinary Committee under Section (21D)

The Disciplinary Committee functioning under the provisions of Section 21D of the Chartered Accountants Act, 1949 conducts enquiry and submits its report to the Council in respect of residual cases pending prior to the amendments made in the aforesaid Act in 2006. In discharging its avowed responsibility of conducting disciplinary enquiries against members whose cases have been referred to it by the Council upon forming prima facie opinion, during the year under review, this Committee held 03 meetings and engaged in the process of expediting and concluding the hearings in the four residual cases pending before it.

Cases dealt with under the Old Disciplinary Mechanism [Section 21(D)]

Statistics of cases placed before the Council and the Disciplinary Committee during the period from 1st April, 2016 to 31st March, 2017:

Sl. No.	Particulars	No. of cases*
1.	(i) Number of cases concluded during the above period (out of 04 total pending cases with the Committee for enquiry) (ii) Meetings held during the aforesaid period	01 (-) 03 (02)
2.	Number of reports of Disciplinary Committee considered by the Council (including reports of those cases, which were heard during the earlier years).	04 (09)
3.	Out of the above a) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule for affording an opportunity of hearing before the Council before passing an order under Section 21(4) of the Chartered Accountants Act, 1949.	01 (01)
	b) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the Second Schedule and/or other misconduct to be referred to High Courts under Section 21(5) of the Chartered Accountants Act, 1949.	01 (-)
	c) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule and the Second Schedule/other misconduct	NIL (-)
	d) Number of cases referred back to the Disciplinary Committee for further enquiry.	NIL (-)
	e) Number of cases in which Respondents have been found not guilty of any misconduct.	02 (08)
4.	Number of cases in which Orders passed under Section 21(4) in respect of the Respondents who were found guilty under the First Schedule.	NIL (01)
5.	Number of cases disposed of by the High Court under Section 21(6)	19 (10)

*Figures in brackets refers to the corresponding figure of previous year

5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

5.1 Accounting Standards Board (ASB)

The followings are the major activities initiated/completed by the Accounting Standards Board during the year under Report:

I. Upgrading financial reporting standards:

- (a) ICAI has issued the following amended Accounting Standards for non-corporate entities corresponding to amendments notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for companies vide notification dated March 30, 2016.

- AS 2, *Valuation of Inventories*
- AS 4, *Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date*
- AS 6, *Depreciation* withdrawn.
- AS 10, *Property, Plant and Equipment*
- AS 13, *Accounting for Investments*
- AS 14, *Accounting for Amalgamations*
- AS 21, *Consolidated Financial Statements*
- AS 29, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*

These amendments issued by the ICAI are effective in respect of accounting periods commencing on or after April 1, 2017.

- (b) Updation of Indian Accounting Standards in line with amendments to IFRS

- Amendments to Ind AS 7, *Statements of Cash Flows*, corresponding to *amendments to IAS 7 Statement of Cash Flows* and Amendments in Ind AS 102, *Share Based Payments* were submitted to the MCA after following the due process. These amendments have been notified as Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2017, vide notification dated 17th March, 2017.
- Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses- Amendments in Ind AS 12, *Income taxes*, approved by NACAS
- Amendments cleared by the Council, ICAI
 - Amendments of Clarifications to Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers
 - Amendments regarding Transfers of Investment Property, Ind AS 40, Investment Property
 - Formulation of Appendix B of Ind AS 21, Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
 - Annual Improvements to Ind AS - Amendments in Ind AS 112 and 28 (corresponding to Annual Improvements to IFRS Standards 2014-2016 cycle issued by the IASB)

- (c) Continued its efforts to upgrade the existing Accounting Standards to bring them nearer to Ind ASs and in this regard following developments took place:

- Upgraded AS 7, *Statements of Cash Flows* and AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors* approved by the NACAS.
- Formulation of various upgraded Accounting Standards is in progress e.g. Accounting Standard on financial instrument.
- Ind AS-Compliant Schedule III (Division II) to the Companies Act, 2013, for preparation and presentation of Ind AS-compliant Financial Statements, was submitted to MCA, which has been notified on April 06, 2016.
- Ind AS compliant Schedule III to Companies Act, 2013, for Non-Banking Finance Companies (NBFCs) has been formulated which has been considered and approved by the National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS).

II. Implementation Support

Following Guidance Note/ FAQs/Announcement issued:

- Guidance Note on Combined and Carve-out Financial Statements
- Guidance Note on Accounting for Real Estate Transactions (for entities to whom Ind AS is applicable)

- Announcement regarding withdrawal of existing Accounting Standards, AS 30 *Financial instruments: Recognition and Measurement*, AS 31, *Financial Instruments: Presentation*, and AS 32, *Financial Instruments: Disclosures*
- FAQ regarding treatment of Dividend Distribution Tax
- FAQ on Elaboration of terms ‘infrequent number of sales’ or ‘insignificant in value’ used in Ind AS 109
- FAQ regarding requirements to prepare Consolidated Financial Statements
- FAQ on deemed cost of Property, Plant and Equipment under Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*

III. International initiatives: Forging long lasting partnership

(a) The ICAI representatives participated at various forums such as:

- Hosted the 13th meeting of IASB’s Economic Emerging Group (EEG) on 8-9 May, 2017 at ICAI Bhawan, Mumbai, which was attended by representatives of IASB and emerging economies viz. Brazil, China, Indonesia, Malaysia, Russia, South Africa, Turkey and India. A paper was presented on ‘Issue of Micro Entities - Financial Reporting Challenges’.
- Meeting of International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) held at Toronto, Canada, on April 4-5, 2016 whereat IASB Workplan and Foundation Developments, Professional Judgement and “Terms of Likelihood” under IFRS, IFRS Implementation Issues (IASB) and various other issues were discussed.
- Meeting of World Standard-Setters Conference held on 26-27 September, 2016 at London and meeting of Emerging Economies Group (EEG) held in Johannesburg, South Africa on November 3-4, 2016.
- Meeting of International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) held at Taiwan, on March 2-3, 2017 whereat India presented a paper on Treatment of Income Tax on Distribution of Dividends. Besides, topics like High Inflation, consistent application on IFRS, Implementing “big” standards and various other issues were discussed.
- At the 33rd Session of ISAR, UNCTAD held from 3rd to 6th October, 2016 at Geneva, ICAI made a presentation of IFRS 15 – Revenue Recognition from Contracts with Customers’ representing India’s position on implementation issues and practical considerations to converge with IFRS 15 Standard in India.

(b) Comments on the following Exposure Drafts/Discussion Papers issued by the International Accounting Standards Board (IASB) were submitted to the IASB.

- Exposure draft on Annual Improvements to IFRS Standards 2015–2017 Cycle
- Exposure draft on Definition of a Business and Accounting for Previously Held Interests (Amendments to IFRS 3 and IFRS 11)
- Request for Views : 2015 Agenda Consultation
- Prepayment Features with Negative Compensation (Proposed amendments to IFRS 9)

(c) **Interaction with International Bodies:**

- IFRS Foundation Trustees Joint Stakeholders Event was held on October 13, 2016 at New Delhi whereat dignitaries from International Accounting Standards Board and IFRS Foundation were present.
- On October 14, 2016, ICAI leadership also met the dignitaries from IASB and IFRS Foundation to discuss various issues such as necessity and removal of Carve-outs, strengthening ICAI and IFRS Foundation relationship, etc. Certain technical issues were also deliberated at a meeting with Mr. Henry Rees, Director, IASB.

IV. Building robust relationship with Regulatory Bodies:

- Submitted comments on FAQs formulated by the RBI on issues involved in Implementation of Ind AS by Banks.

- Recommendations of the Group, lead by the ICAI representative, for the 'Continuous Disclosures' with respect to financial statements to be made by REITs and InvITs submitted to the 'Committee for Accounting Norms' constituted by SEBI.
- Submitted views regarding repatriation of accumulated profits from overseas branches of banks in context of provisions of AS 11.
- Views submitted on Draft Composite Tariff and Accounting Regulations 2015, to Delhi Electricity Regulatory Commission.
- Comments submitted with Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) on accounting policy and method of accounting for investments in equity & related investments.

V. Other Initiatives

- Organized the ICAI-EEG Joint Stakeholders Seminar on 9th May 2017 for half day on the theme 'Emerging IFRS (Ind AS) Challenges' dealing with 'Service Concession Arrangements' and 'Expected Credit Loss Model' under Ind AS 109 which was well attended by about 80 ICAI members, EEG representatives and other stakeholders.
- On the occasion of completion of 40 years of the ASB on April 21, 2017, hosted an event on 12th June, 2017 whereat past Chairmen of ASB, NACAS, ICAI's Central Council Members were invited for an interactive session and a booklet was released titled '*Accounting Standards Board – Leading the Way in Accounting Reforms 1977 to 2017*' which chronicles history and the achievements of the ASB since its inception.

5.2 Committee on Accounting Standards for Local Bodies

The Committee on Accounting Standards for Local Bodies (CASLB) has been formulating Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs) since March 2005, which lay down the sound accounting policies for Local Bodies that will improve the quality of their financial reporting and bring consistency and comparability.

Important activities:

ASLB issued:

- ASLB 18, 'Segment Reporting' - Preliminary exposure draft ASLB issued for comments
- ASLB 20, 'Related Party Disclosures'
- The formulation of 'The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Local Bodies'
- The ASLB also submitted Comments on:
 - Government Accounting Standard Advisory Board (GASAB)'s documents:
 - ✓ IGAS 4, 'General Purpose Financial Statements of Government'
 - ✓ Draft of Assets advisory.
- Four days training programme on 'Accrual Accounting and Accounting Standards' jointly with the Accounting Standards Board for the officials of Rajasthan Government on May 28 & 29, 2016 and June 4 & 5, 2016 at Jaipur with the support of Jaipur branch of ICAI.
- Training programmes on 'Improvement of Accounting and Implementation of Double Entry Accrual System of Accounting in Urban Local Bodies (ULBs)' to build the capacity of officials of ULBs of the following States:
 - Punjab: jointly with the Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration on August 18 - 19, 2016 at Chandigarh
 - North Delhi Municipal Corporation (NDMC): jointly with NDMC on September 23 - 24, 2016 at New Delhi
 - Himachal Pradesh: jointly with the Directorate of Urban Development, Shimla on October 21 - 22, 2016 at Shimla
 - Jharkhand: jointly with the Directorate of Municipal Administration, Department of Urban Development & Housing, Govt. of Jharkhand on October 26 - 27, 2016 at Ranchi.

These programmes were highly appreciated by the participants.

- One day training programme on 'Audit in Local Bodies' in collaboration with Department in Local Fund Audit on February 21, 2017 at Chennai for the auditors of Local Fund Department, Tamil Nadu.

5.3 Auditing & Assurance Standards Board (AASB)

- During the period under report, the Board submitted the following inputs /representations/suggestions to the Ministries and Regulators:
 - To the Ministry of Corporate Affairs (MCA), comments on the Draft Companies (Auditor's Report) Order, 2016 (CARO 2016) issued by MCA for public comments.
 - To the Reserve Bank of India:
 - (i) the illustrative formats of auditor's report of Urban Co-operative Banks.
 - (ii) views on Allocation of Audit Duties of Statutory Central Auditors of Banks.
 - (iii) views on Accounting of Sick Leaves as per Accounting Standard (AS) 15, 'Employee Benefits'.

The Board brought out the following important publications:

- Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes (Revised 2016).
- Guidance Note on Audit of Consolidated Financial Statements (Revised 2016).
- Guidance Note on Reports in Company Prospectuses (Revised 2016).
- Guidance Note on Audit of Banks (Revised 2017).
- Implementation Guide on Auditor's Reports under Indian Accounting Standards for Transition Phase.
- Implementation Guide on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting with Specific Reference to Smaller, Less Complex Companies.
- Implementation Guide on Auditor's Report under Rule 11(d) of Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2017 and Amendment to Schedule III to Companies Act, 2013.
- Technical Guide on Audit of Non-Banking Financial Companies (Revised 2016).
- On the suggestion received from the Quality Review Board, the Board has developed the Technical Guide on Conducting Quality Reviews.
- The Board developed the Implementation Guide on Application of Standards on Auditing and Review Engagements while issuing Reports under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Board organised number of awareness programmes across the country on CARO 2016, reporting under the Companies Act, 2013, auditing standards and other auditing aspects for awareness and professional enhancement of the members. Programmes were held at Indore, Rajkot, Hyderabad, Coimbatore, Jaipur, Kolkata, Raipur, Udaipur, Tuticorin, Beawar, Surat, Chennai, Visakhapatnam, Allahabad, Bhopal, Siliguri, Jamshedpur, Mumbai, Alwar, Gandhidham, Madurai, Bilaspur, Dhanbad, Agra, Bhuj, Bareilly, Mathura, Pali, Sambalpur, Meerut and Gwalior.

- The Board organized the Two Days National Conference on "Auditing and Beyond" at Jaipur in December 2016. The Conference was attended by more than 2000 participants.
- The Board constituted an online Bank Audit Expert Panel to address the queries of the members related to bank branch audits for the financial year 2016-17.
- The Board provided replies/clarifications to the various queries on auditing aspects received from the members from time to time.
- The Board issued the following announcements/clarifications for guidance of the members:
 - Important Clarification on Amendment to Paragraph 17 of Revised Guidance Note on Audit of Consolidated Financial Statements.
 - Important Announcement on Revised Effective Date of SA 701 and Revised SAs 700, 705, 706.
 - Clarification on the transitional time gap in the requirements relating to the engagement partner's rotation under SQC 1 and the auditor's rotation under the Companies Act, 2013.
- The Board issued the exposure drafts of the following Standards on Auditing for public comments:
 - Revised SA 299, 'Joint Audits'.
 - Revised SA 720, 'The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information'.
- The Chairman, AASB represented ICAI at the annual meeting of the International Auditing and Assurance Standards Board with the National Standards Setters (the IAASB-NSS meeting) held in June 2017 at New York.
- The Chairman and the Vice Chairman, AASB also represented ICAI at the meetings of the –
 - International Auditing and Assurance Standards Board held in September 2016 at Hong Kong.
 - International Auditing and Assurance Standards Board held in December 2016 at New York.

- The International Auditing and Assurance Standards Board held in March 2017 at Lima, Peru.
- The International Auditing and Assurance Standards Board held in June 2017 at New York.

5.4 Banking, Financial Services and Insurance Committee

- The Committee sent a representation to Ministry of Finance (Department of Financial Services) to consider the experience of practicing members at par with members in industry while receiving the applications for the Post of Whole Time Member (Finance) in Pension Fund Regulatory and Development Authority.
- The Chairman & Vice Chairman of the Committee, met Shri Nitin Gadkari, Hon'ble Ministry of Road Transport Highways & Shipping on 12th June 2017.
- A representation was sent to Pension Fund Regulatory and Development Authority for spreading awareness of various pension schemes launched by Govt. of India/PFRDA amongst public at large.
- The Chairman of the Committee met the Senior Financial Control Officer of Asian Development Bank on 7th June 2016 and offered the services of the ICAI and its members for various endeavours of ADB.
- The Committee sent a representation to Department of Financial Services (Ministry of Finance, Government of India) to consider including a representative of ICAI as a member of the Banks Board Bureau.
- The Chairman of the Committee met Chairman and Member (Economics) of Pension Fund Regulatory and Development Authority to discuss the matter of mutual interest.
- The Chairman and Vice Chairman of the Committee addressed the delegates of 8th Banking & Finance Conference organized by Indian Merchants' Chamber on 18th April 2016 at Mumbai.
- ICAI through the Committee was the "Knowledge Partner" for "Indian Banking Reforms Conclave 2016" organized by the Governance Now (SAB TV Group) on 24th August 2016 at Mumbai.
- The Committee had organized A Half Day programme on Capital Market in association with NSDL on 21st April 2017 at Mumbai.
- The Committee organized a Workshop on "Project Appraisal, Financing and Control" on 14th May 2016 at New Delhi.
- The Committee organised the Webcasts on Due Diligence for Project Cost Estimation and National Pension System on 26th July, 2016 and 13th December, 2016 respectively.
- Three batches of the Certificate Course on Forex and Treasury Management were organized at Mumbai, Chennai and Noida from 29th April to 21st May 2017 (on weekends only).
- An Orientation Programme for the DIRM Technical Examination passed members of ICAI was conducted at Mumbai during 24th – 28th May 2017. As on 26th July 2017, there were 4994 registrations to the DIRM Course.
- The Committee is actively supporting the society and nation by organizing Investor Awareness Programmes (IAP) under the aegis of Investor Education and Protection Fund (IEPF) of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India through its various Programme Organizing units POU's. In total 764 programmes were conducted during the period 1st April, 2016 to 11th February, 2017.
- Shri Suresh Prabhakar Prabhu – then Hon'ble Union Minister for Railways, Government of India inaugurated the Investor Awareness Programme organised on 16th June, 2016 by Committee and hosted by Ernakulum Branch of SIRC of ICAI. Hon'ble Minister for Agriculture, Food Processing, Ministry for State Shri Sanjeev Kumar Balyan was also present.
- The Committee has been organizing IAP in association with 'Bombay Stock Exchange – Investor Protection Fund (BSE-IPF)' through its various Programme Organizing units POU's. Total 5 Investor Awareness Programmes were conducted during the period by the POU's with the support of Investor Protection Fund of Bombay Stock Exchange.
- The Committee conducted 9 batches of Certificate Course on Forex and Treasury Management during the period from 1st April, 2016 to 11th February, 2017.
- The Committee has conducted 2 Webcasts during the period.

5.5 Committee for Capacity Building of Members in Practice

The Committee for Capacity Building of Members in Practice (CCBMP) was formed in February, 2010. The ultimate objective of the Committee is to strengthen CA firms as well as Small & Medium Practitioners. The prime function of the Committee is to create awareness amongst CA firms on capacity building through consolidation by networking, merger & setting up management consultancy services firm and popularizing the concept of union through arranging workshops, symposia and summit on the benefits of consolidation and endurance to better accounting, auditing and ethical standards.

In tune to vision of ICAI which is 'The Indian Chartered Accountancy Profession' will be the valued trustees of world class financial competencies, good governance and competitors, the Committee has its motto for Capacity Building of Indian CA firms through consolidation and empowering small & medium practitioners by developing and upgradation of their professional competence. Accordingly, the Committee has following issues to deal with;

- Preparation of code for consolidation of CA firms.

- Identifying means and ways for empowering SMPs.
- Upgrading and updating the knowledge and skills set on standard practice.
- Developing practice areas for SMPs.
- Identifying Role of SMPs in emerging areas.
- Developing technical material to facilitate practice in new areas of profession.
- Facilitation on IT savvy office management and audit tools for CA firms & SMPs.
- Re-engineering of profession and establishment of CA Firms with sound infrastructure and finance.
- Arrangement of social security & insurance protection for Practitioners & CA Firms

Activities Undertaken:

- **Arrangement of the ‘Quick Heal Total Security for PC at special price for the Members & Students of ICAI**

The Committee in order to enable members to have access to antivirus software, has tied up with Quick Heal technologies Pvt. Ltd. Pune for providing access to Quick Heal Total Security at a special discounted price Rs. 1200/- plus applicable taxes from January 1, 2016 to December 31, 2017 for single user for a period of 3 years for the Members & students of ICAI the details are available at http://www.icai.org/post.html?post_id=11505

- **Office Protection Shield Insurance**

The CCBMP has Office Protection Shield Insurance for members of ICAI. The scheme has become effective from 18th September, 2013 for the Members in practice/ Firms of the ICAI. Details is available at http://www.icai.org/post.html?post_id=10097

- **Motor Vehicle Insurance**

The Motor Vehicle Insurance arranged through New India Assurance Company Ltd with specialized terms. The Motor Vehicle Insurance is basically designed for the members but also has been extended to the students and employees of ICAI. Detail available at http://www.icai.org/post.html?post_id=12760

- **ICAI Connect – A self-service portal for members of ICAI**

The Committee launched the ICAI Connect, a self-service portal for the members of ICAI. The features of the aforesaid single window self-service portal includes viewing personal Profile and firms constitution, Announcements of ICAI, details of payments of fees and regulatory charges to ICAI, My Articles details, tracking regulatory forms and application status, e-Services, My Firms, My Software(s), Letters & Certificates, CPE Hours credited, Guidelines of Networking, Merger & Demerger etc.

- **e-Samadhan portal for resolving the professional queries raised by members of ICAI**

The e-Samadhan portal for resolving the professional queries of the members of ICAI launched. The empaneled professionals will answer the queries raised by the members in various areas of the profession. Members need to log in to SSP and click on ‘e-samadhan’ to register their query.

- **Committee’s exclusive website www.icai.org.in**

The CCBMP has developed a Website namely www.icai.org.in, where the Firms and Practitioners may create their portals as per the norms laid down by the Council. The website provides a platform for the CA Firms to upload their firms’ details and gives them an opportunity to reach out to the members and CA firms practicing worldwide.

The website also acts as a forum for consolidation of the members and CA Firms by providing for consolidation measures like Networking, Merger and Corporate Form of Practice. The members may visit portals of other members and firms and like-minded persons may join hands to grow big to compete in the international front.

- **Portal for Senior Members of ICAI www.seniormembers.icai.org**

The Committee has developed a website namely seniormembers.icai.org. The website provides a platform for senior members of ICAI for getting flexi working hours assignment as well as fulltime assignment after their retirement. At the same time it will also help industry to tap experienced talent pool which might not be accessible otherwise in normal course. The said portal would be useful & handy to all the senior members of ICAI.

- **Networking & Merger - Revised Guidelines**

The CCBMP has considered practical difficulties in consolidation of CA Firms through medium of Networking. The CCBMP has appropriately finalized the revised Guidelines of Networking facilitating members and firms for its easy adoption. The details of the Revised Guidelines of Networking is available at http://www.icai.org/post.html?post_id=7710. The details of the Rules on Merger is uploaded at www.icai.org.in

- **Brochure on Revised Minimum Recommended Scale of the fees for the Professional Assignments done by the Chartered Accountants for Class 'A' & Class 'B' cities**

The Committee has prepared a Brochure on Revised Minimum Recommended Scale of the fees for the Professional Assignments done by the Chartered Accountants for Class 'A' & Class 'B' cities. The aforesaid Brochure is available at http://www.icai.org/post.html?post_id=7252

- **The Certificate Course on Wealth Management and Financial Planning**

The Committee is conducting the Certificate Course on Wealth Management and Financial Planning enhancing new career opportunities for the members. The objective of this Course is to equip the members with the principles of Management of Wealth as well as devising effective Investment Strategy and the practical procedural aspects and to build the competency level to position them as financial consultants and advisor. The details of the Course are available are at http://www.icai.org/new_post.html?post_id=11179&c_id=240

Live Webcast

- The Committee organized live Webcast on
 - Wealth Management & Investment Strategies
 - Insolvency Act
 - "Capacity Building Measures of Practitioners with special reference to Bank Audit"
 - "Capacity Building Measures of Practitioners with special reference to Fair Value Measurement Under Ind AS"
 - "Capacity Building Measures of Practitioners with special reference to Ind AS: Practical Application & Emerging Trends"
 - Capacity Building Measures of Practitioners with special reference to FCRA and GST
 - Capacity Building Measures of Practitioners with special reference to Trust & Taxation under IT Act

Programmes of the Committee

The Committee organized various programmes throughout the year at various parts of the country which included Workshops, Seminars, Residential programmes, Conferences and training programmes.

Women Members Empowerment Group

- a) In order to encourage empowerment of women Chartered Accountants, Women Members Empowerment Group has been working with the main objective to formulate and implement plans, policies and programmes for development of women members. The Sub-Group is committed towards its objective of empowering women members by conducting various workshops/ seminars/ conferences for the benefit of CA Women fraternity at large.

A dedicated Portal, 'Portal for Women Members' is also being maintained by the Sub-Group, which provides women members a medium through which they can post their requirements and can explore flexi working options available for them. It also aims to provide a common platform to women members to update their knowledge and share their views and concerns.

- b) The Sub-Group organized "Seminar for Women Chartered Accountants" which was hosted by Bangalore Branch of SIRC in Bangalore on 11th March, 2017. Sessions on Insolvency & Bankruptcy Code – An Overview, Swalpa Adjust Madi – for your own peace of mind, An overview of GST – the most radical reform in the area of - Indirect Taxes - Sought for topic of the day and Fitness, Image Branding and self-grooming were there. The conference was inaugurated by Smt. Shobha Karandlaje, Member of Parliament, & Former Minister for Rural Development & Panchayat Raj, Government of Karnataka. Around 200 women members participated in the conference.

Young Members Empowerment Group

Young Members Empowerment Group (YMEG) of Committee for Capacity Building for Members in Practice of ICAI

undertakes the initiatives to young CAs in meeting the evolving expectations of the society as far as the technical and professional skills are concerned and to enable capacity building amongst them.

I. Seminars/Workshops/Conferences/Residential Refresher Courses/ webcasts:

Group has organized 23 Seminars/ Workshops/ Conferences throughout the country on various contemporary topics which are beneficial for Chartered Accountants viz. Start Up and Entrepreneurship, Insolvency & Bankruptcy Code 2016, GST, Income Disclosure Scheme-2016, Forensic Audit, Income Tax, E-Commerce & Cloud Computing, ICDS & Preparation of Appeals etc. 2 Residential Refresher Course on contemporary topics were also organized besides 7 webcasts on various subjects.

II. YMEG portal- YMEG Portal provides the Young CAs a platform from where they can connect with YMEC Activities with their active involvement and participation (www.ymec.in). The portal contains various features such as Events, Mentoring, Articles, Technical and Motivational Videos, Knowledge Centre, Useful Links, Programmes Archives etc. YMEG has uploaded five Videos of Motivational messages by successful Entrepreneurs and one video to motivate Young Members to become as Civil Servants.

III. E-booklet-Useful Professional Information for the Young Chartered Accountants - YMEG has launched e-version of useful information as E-booklet, which is beneficial for Young Chartered Accountants whether in practice or in service. This E-booklet covers topics such as- Professional Opportunities for members, Various Guidelines viz., Corporate Form of Practice, Network firm, Advertisement, Website, Technical topics like Standards on Auditing, Ind-As, Generic Internal Audit Guide etc. e-booklet is available at YMEG Portal (www.ymec.in).

IV. E-newsletter- YMEG has published 2nd Volume of 1st Quarter (April, 2016 to June, 2016) E-News letter. It contains all the details of YMEC Committee Activities/ Programmes/ Workshops/ Webcasts organized and details of forthcoming activities.

5.6 Continuing Professional Education Committee (CPE)

The Committee has all along endeavoured to keep its members aware of and abreast with the professional and technological changes that are taking place, around the globe, in this ever- changing economic environment, through the process of continuous skill honing, by way of classroom teaching, e-Learning mode, In-house Executive Development Programmes, Webcasts, Awareness programmes, Seminars, Conferences etc.

The main objective of the Committee is to adopt, execute and implement such measures using latest technology in order to provide sufficient opportunity to Members to keep abreast with current knowledge.

To keep pace with the global requirements, CPE requirements are mandatory for all the members of the ICAI, whether he/she be in practice or in service and such system is measured, monitored and managed scientifically.

1. Robust Members' Learning and Professional Development Mechanism:-

➤ **Revision of CPE Statement :-**

With a view to enable its members to maintain the requisite professional competence and thus ensure high quality and standards in the professional services that they render, all the members of the ICAI, be in practice or in service, are mandatorily required to meet the CPE credit hours requirements from time to time, as specified by the Council of ICAI.

Contemporary with Global requirements & Practices, the CPE Credit Hours requirements were revised for various categories of members and are applicable from the current block of 3 years (1-1-2017 to 31-12-2019). The CPE credit hours requirements have been revised for various categories of members as under:-

Category	Existing (CPE Hrs) Upto 31.12.2016	Revised (CPE Hrs) (Effective from 01.01.2017)
A. All the members (below the age of 60 yrs) holding COP(except those residing abroad)	90 (Structured – 60 Hrs& Unstructured 30 Hrs)	120 (Structured – 60 Hrs& Unstructured 60 Hrs)

B. All the members (below the age of 60 yrs) not holding COP and members residing abroad (whether holding COP or not)	45 Structured or Unstructured (as per member's choice) [10+10+10]+15 at any time in the block of 3 yrs	60 Structured or Unstructured (as per member's choice) [15+15+15]+15 at any time in the block of 3 yrs
C. All the members (aged 60 yrs & above) holding COP	70 Structured or Unstructured (as per member's choice) [10+20+20]+20 at any time in the block of 3 yrs	90 Structured or Unstructured (as per member's choice) [20+20+20]+30 at any time in the block of 3 yrs

Exemptions to Members:

- a) A member is exempted only for the particular calendar year in which he gets his membership for the first time.
- b) **The following class of members are exempted from CPE credit hours requirement:**
- All the members (aged 60 years and above) who are not holding Certificate of Practice.
 - Judges of Supreme Court, High Court, District Courts and Tribunal
 - Members of Parliament/MLAs/MLCs
 - Governors of States
 - Centre and State Civil Services
 - Entrepreneurs (owners of Business (manufacturing) organizations other than professional services)
 - Judicial officers
 - Members in Military Service
- c) **Temporary Exemptions:**
- Female members for one Calendar year on the ground of pregnancy.
 - Physically disabled members on case to case basis having permanent disability of not less than 40% and above (Supported with medical certificates from any doctor registered with Indian Medical Council with relevant specialisation as evidenced by Post Qualifications (M.D., M.S. etc.).
 - Members suffering from prolonged critical diseases/illnesses or other disability as may be specified or approved by the CPEC. (Supported with medical certificates from any doctor registered with Indian Medical Council with relevant specialisation as evidenced by Post Qualifications (M.D., M.S. etc.).
- d) A member or class of members to whom the Committee may in its absolute discretion grant full/partial exemption specifically or generally on account of facts and circumstances of the case which in their opinion prevent such person(s) from compliance with the requirements of CPE as specified in the Statement.

➤ Revamping of CPE Portal and Integration of CPE Activities also through ICAI Mobile App:-

The CPE Committee revamped its CPE Portal (www.cpeicai.org) to facilitate members with more robust, user friendly and mobile compatible functionalities with regard to CPE activities. The CPE activities are also linked with "ICAI Mobile App" by providing a segment/tab called "CPE Programs". Now members can utilize the above services from anywhere anytime as per their convenience. The main features are:

<ul style="list-style-type: none"> • Know details of upcoming programs 	<ul style="list-style-type: none"> • Search event facility through keywords City-Wise, POU-Wise Subject-Wise
<ul style="list-style-type: none"> • Set alert facility for receiving alerts of CPE Programs through SMS/Email 	<ul style="list-style-type: none"> • Submit details online for claiming CPE Hours under Unstructured Learning Activities
<ul style="list-style-type: none"> • Know your CPE Hours Credit 	<ul style="list-style-type: none"> • CPE E-Newsletter
<ul style="list-style-type: none"> • View Webcasts 	<ul style="list-style-type: none"> • View Background material

➤ Revision of CPE Guidelines for effective monitoring and organizing quality CPE Programmes:-

For effective monitoring and organizing quality CPE Programmes, the Norms, Guidelines and Directions for CPE Programme Organising Units were revised and are available at the CPE Portal.

➤ CPE Calendar

The CPE Calendar for the 2017-18 was finalised consisting of more than 750 topics on various areas of professional interest.

➤ **Spreading Wings Globally:**

14 CPE International Study Tours / Seminars were organised internationally by the CPE Programme Organising Units (POUs) at Tashkent and St. Petersburg (Russia), Prague (Central Europe), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia), Thimpu (Bhutan), Pattaya & Bangkok (Thailand) and Bali (Indonesia).

2. Brand and Capacity Building:

ICAI on its part has always been proactive towards the fulfilment of the emerging professional needs of its members enabling them to acquire contemporary knowledge and skills to face the challenges effectively. The Committee has been taking various initiatives to provide sufficient opportunity to members to keep themselves updated about the latest developments in their core areas of competence and familiarize with new and emerging areas related to professional development and National Interests. Few of the milestones are as follows:

➤ **CPE National Live Webcasts**

Three National Live Webcasts were organized by CPE Committee on emerging topics of professional and national interest namely Demonetization of Currency; Overview, Application and Implications of ICDS and Proposed Amendment Bill for Undisclosed Income under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna, 2016.

➤ **National Level Programmes and other Important Events**

- 21 CPE Programmes were organised at National level etc. and hosted by Regional Councils/Branches of ICAI in different parts of the Country since April, 2016.
- 9,973 CPE Programmes with 46,806 CPE Hours were organised for the Members across the country and abroad, by the CPE Programme Organising Units of ICAI on various topics of professional interests. 9,38,513 members participated in the above programmes and they were granted 49,92,963 CPE hours.
- 209 Programmes on Certificate Courses of ICAI on GST, Anti Money laundering Laws, Wealth Management and Financial Planning, Concurrent Audit of Banks, Forensic Accounting and Fraud Detection etc. were organised for Members through Central Committees of ICAI.
- 114 Post Qualification Courses on Information Systems Audit (ISA), Diploma in Insurance and Risk Management (DIRM) and International Taxation etc. were organised through Central Committees of ICAI.

➤ **Opening of New CPE Programme Organising Units (POUs)**

34 more CPE POUs were opened by CPEC for helping the members in mofussil/remote areas to undergo CPE activities in their nearby places, reaching to strong network base of 588 CPE POUs in India and Abroad.

3. Training Programmes for Public Sector Undertakings:-

The Committee Organized a In-house Executive Development Programme (IHEDPs) for the officials of Power Finance Corporation Ltd. on the topic “Ind-AS” at PFC Premises on 28th-29th September & 1st October, 2016.

4. Supporting Society – Commitment to Nation:

ICAI organises following other programmes supporting the initiatives of the Government for effective implementation of the same in various parts of Country through its strong Network Base of CPE Program Organising Units.

- 367 Programmes on Demonetization, Black Money, Benami Transactions and Undisclosed Income.
- 3001 Programmes on GST in various parts of the Country.
- 184 programmes on RERA (Real Estate Regulatory Act)
- 369 programmes on ICDS (Income Computation and Disclosure Standards)
- 113 programmes on Insolvency and Bankruptcy Code
- 197 programmes on Companies Act
- 14 Programmes on Corporate Social Responsibility (CSR)
- 22 CPE Programmes on Stress Management, Lifestyle Management where Yoga is way of life, Work Life Balance etc on 21st June celebrated as International Yoga Day.
- A Mega event was also organised at Mumbai on 3rd June, 2016 jointly with Ministry of Ayush,

Government of India, a Curtain-Raiser Programme on the International Yoga Day.

5. Other Initiatives:-

- Quarterly e-newsletter “CPE Bulletin” is being brought out to share recent initiatives that have been taken by the Committee and was hosted at the ICAI Website as well as at the CPE Portal for information of members, POUs and others.
- Revised CPE Manual was brought out containing Guidelines, Norms, Directions etc. issued from time to time by the Council and CPE Committee for Programme Organising Units (POUs) which is available at CPE portal - www.cpeicai.org.
- National Database (subject wise) of CPE Resource Persons engaged by CPE POUs has been updated with their contact details for the use of CPE POUs and is available at CPE Portal.

5.7 Corporate Laws & Corporate Governance Committee

The Corporate Laws & Corporate Governance Committee acts as an instrument towards empowerment of the profession and aims to facilitate a fair corporate regime with the best global practices. The Committee regularly formulates and issue Guidance Note, Background Material, Reports, Commentaries, References in relation to Corporate Laws and the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The Committee examines Corporate Laws including the Insolvency and Bankruptcy Laws, Rules, Regulations, Guidelines, Notifications, Schemes, Schedules issued thereunder vis-à-vis best global practices and make appropriate representation/suggestions to the concerned Ministries of Government and to participate as well as to facilitate the Law making process.

Significant Achievements and Initiatives

1. Representation to Ministry of Corporate Affairs and Insolvency & Bankruptcy Board of India

a. Companies Act, 2013

The Committee regularly interacts with the Ministry of Corporate Affairs for smooth implementation of the Companies Act 2013. The Committee submitted about 33 representations to the Ministry of Corporate Affairs on various matters. Some of the important representations made were on the following matters:-

- i. Waiving off the additional fees, if levied for delay in filing the documents due to technical glitch in MCA-21 online E-filing portal
- ii. Introducing an Easy Exit Scheme/ LLP Settlement Scheme for the limited liability partnership firms registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008.
- iii. Exempting unlisted and private companies from Reporting on Internal Financial Control by the auditors (Section 143 (3) (i)) and from applicability for preparation of Consolidated Financial Statements (Section 129 (3)) of the Companies Act 2013.
- iv. Draft Rules of Chapter XVII- Registered Valuers of the Companies Act 2013 relating to applicability of the Valuation Standards while undertaking Valuation of any asset- Valuation Standards that would be formulated by ICAI may be considered for prescribing Valuation Standards as per Rule 17.6 (iv) to Chapter XVII of the Companies Act 2013.
- v. Draft Rules under the following Chapters of the Companies Act 2013 dated 4th May, 2016:
 - National Company Law Tribunal (NCLT)
 - Prevention of Oppression and Management and
 - Compromises, Amalgamation and Arrangements
- vi. Draft amendments to Secretarial Standard-1 (Meetings of the Board of Directors) and Secretarial Standard-2 (General Meetings) dated 10th May, 2016.
- vii. Difficulty in MCA-21 online e-filing portal and difficulty in creation of a company.

- viii. Differential qualification experience for legal professionals and Chartered Accountants to be empanelled as mediator and conciliator as per Section 442 of the Companies Act 2013.
- ix. Draft Notification regarding giving further exemptions to private companies under some of the provisions of the Companies Act 2013.
- x. Issues with regard to Implementation of Ind AS submitted to the Ministry of Corporate Affairs.

b. Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

During the year 2016-2017, The Committee submitted 7 representations before the Insolvency & Bankruptcy Board of India and Ministry of Corporate Affairs on matters pertaining to -

- Complying with the provisions of the Companies Act, 2013 while acting as an Insolvency Professional as per the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
- Draft Regulation on Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 on 28th October, 2016.
- Formation of Insolvency Professional Agency by ICAI as per the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
- Relaxation of the Net worth Criteria of Rs. 10 crores to register for an Insolvency Professional Agency.
- Suggestions with regard to Capital contribution and composition of the Governing Board of Insolvency Professional Agency in November, 2016.
- Clarification regarding eligibility criteria to become insolvency professional in the limited period registration.
- Representation regarding having the similar name and URL of the website of Insolvency Professional Agency (IPA) formed by the Institute of Cost Accountants of India- It has been requested that ICWAI may be asked to change the name of their Agency as well as URL of their website to avoid confusion.

2. Frequently Asked Questions:

The Committee released in February, 2017 Frequently Asked Questions on the Companies Act, 2013 and Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

3. Presentation & oral hearing before the Hon'ble Parliamentary Standing Committee on Finance on the Examination of Companies (Amendment) Bill 2016.

- The Hon'ble Parliamentary Standing Committee on Finance had requested ICAI to give suggestions on the Companies (Amendment) Bill 2016. ICAI suggestions on the Issues and Concerns in the Companies Act, 2013 and Rules thereon were submitted to the Hon'ble Parliamentary Standing Committee on Finance. The Hon'ble Standing Committee had decided to hear ICAI expert views in connection with the examination of the Bill on 3rd June, 2016.
- A second meeting with the Committee was held on 30th August, 2016 where ICAI representatives made a presentation before the Committee.

4. Operationalisation of Insolvency and Bankruptcy Code 2016.

The Committee has been working closely with the Government for Operationalisation of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and its Regulations.

5. Formation of Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI.

- The Committee on behalf of ICAI formed Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIPI) as an Insolvency Professional Agency to enroll Insolvency Professionals who can undertake the process of liquidation and bankruptcy. ICAI IPA has been awarded with the certificate as the First Insolvency Professional Agency of India by Hon'ble Union Finance Minister Shri Arun Jaitley on 28th November 2016 at Delhi.
- The first set of Insolvency Professional who had enrolled with IIP of ICAI as on 29th & 30th November, 2016 have been awarded with the Certificate of Registration as Insolvency Professionals by Secretary, MCA on 30th November 2016.
- Learning Management System for the preparation of the Limited Insolvency Examination to be an Insolvency Professional as per the Insolvency and Bankruptcy Board of India has been launched, where the PPTs were prepared on the basis of various Acts like Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, The Companies Act, 2013, The Limited Liability Partnership Act, 2008, The Partnership Act, 1932, The Indian Contract Act, 1872, The Sales of Goods Act, 1930, The Transfer of Property Act, 1882, The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interests Act, 2002; and Corporate Debt Restructuring Scheme and Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A) (of RBI). Further the Multiple Choice Questions were prepared for each of the Acts in the form of Practice Test as well as Mock Test.

6. Training Programme on the implementation of the Companies Act 2013 and Rules thereon, and the

Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

The Committee has taken an initiative to keep the members of ICAI, equipped and abreast with the latest developments/ changes/ amendments in the provisions of the Companies Act 2013 and in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, by conducting various programme across the country, in the form of Interactive meetings, training Programmes, webcasts, Seminars and Conferences on an Update on Companies Act, 2013, etc.

7. ICAEW to become Knowledge Partner for ICAI Insolvency Professional Agency.

The Institute of Chartered Accountants of England and Wales has agreed to become Knowledge Partner for ICAI Insolvency Professional Agency.

8. Certificate Course on Valuation.

Since the start of the Course 8 years ago, the Committee has so far conducted 67 batches of the Certificate Course on Valuation. Till date more than 3400 members have registered for the Course.

5.8 Direct Taxes Committee.

The Direct Taxes Committee played an important role in assisting the Government in the matter of post-demonetisation and Income Declaration Scheme, 2016. The important activities undertaken by the Committee during the period under report are as under:-

A. Programmes organized.

- ICAI organized various Citizens & Members Awareness Programs on the Income Declaration Scheme, 2016. Some of such programmes are as under:-
 - On 2nd July, 2016 at more than 125 places across the country which were attended by more than 15000 citizens The Hon'ble Finance Minister Shri Arun Jaitley along with the top brass of CBDT headed by then Chairman Shri Atulesh Jindal along with Ms. Rani Singh Nair then Member (L&T) addressed the viewers during the program. Ms. Pragya Sahay Saksena JS (TPL) – I, Shri V Anandaraman JS (TPL) – II, CA. Rajesh Kumar Bhoot CIT(A), CA. Anand Kumar Kedia CIT also graced the occasion and answered the queries raised by the viewers.
 - Shri Hasmukh Adhia, Revenue Secretary and CA. Nilesh Shivji Vikamsey, the then Vice President, ICAI addressed the members on 2nd July, 2016 at Pune wherein more than 300 members and citizens participated.
 - On 10th July, 2016 at Ahmedabad. Shri Arun Jaitley, Hon'ble Union Finance Minister and Dr. Hasmukh Adhia, Secretary (Revenue), Department of Revenue along with Chief Minister and Finance Minister of Gujarat graced the occasion, around 2500 citizens including Chartered Accountants, Advocates, Members from Trade and Industry attended the programs.
 - On 23rd July, 2016 at Bengaluru wherein Shri Arun Jaitley, Hon'ble Union Finance Minister and Dr. Hasmukh Adhia, Secretary (Revenue), Department of Revenue graced the occasion. Around 1500 citizens including Chartered Accountants, Company Secretaries, Advocates, Members from Trade and Industry attended the programs.
- An Interactive Session on IDS & Gold Monetization Scheme was organized by ICAI jointly with FICCI on 1st September, 2016 at Mumbai. The session was addressed by the Hon'ble Union Finance Minister, Shri Arun Jaitley and Ms. Rani Singh Nair, the then chairperson, CBDT.

B. Representations to Central Board of Direct Taxes (CBDT).

The Committee has been submitting various representations to the CBDT from time to time. Some of the matters represented to CBDT were in the matter of -

- Hardship faced by tax deductors on account of provisions of section 276B of the Income-tax Act, 1961 attracting prosecution proceedings for delay in remittance of tax to the credit of the Central Government.

- Amendments in Form No. 3CD.
- Not rejecting the Appeals by the CIT (Appeals) which were not filed electronically between the period 01.03.2016 to 15.05.2016 but which had been filed manually within the time period prescribed under section 249 of the Income-tax Act, 1961.
- Submitting the preliminary views/ issues/ suggestions of the ICAI relating to ICDS & other measures relating to simplification of Income Tax Act before the Justice Eashwar Committee.
- In order to provide paper free digital experience, allowing acceptance of Form No. 60 digitally which may preferably be AADHAAR based e-authorization.
- Amendment in section 143(2) and consequent issue of Notification No 105/2016, dated 16.11.16 and put in place appropriate checks before giving effect to such amendment.
- Issuance of FAQs to clarify the genuine issues faced by assesseees on account of email/sms received Post-Demonetisation for confirmation of cash deposit online and extension of time for submission of response.
- Issuance of clarifications regarding applicability of provisions of section 269ST. Although the notification regarding withdrawal of cash from a bank, cooperative bank or a post office savings bank exceeding Rs. 2 lakhs was issued by the CBDT, there were still certain other concerns, as stated below, being faced by the assesseees, which were represented vide the said representation:
 - Clarification in respect of the phrase “transactions relating to one event or occasion.”
 - Exceptions on the lines of Rule 6DD be provided to avoid genuine hardship being faced by the assesseees.
 - Payment made through banking channels, including debit cards, credit cards and e-wallets be permitted by way of issue of a clarification.
- Requesting withdrawal of proposed penalty under section 271J. Meetings were also held with the Chairman, CBDT, Revenue Secretary and Hon’ble Finance Minister wherein the probable hardships were discussed at length. Since provisions of section 271J have been enacted, ICAI has requested that administrative instructions, guidelines may be issued for curbing genuine hardships faced by the Chartered Accountants due to inserted section 271J.
- Considering the teething problems arising due to first time compliance of submission of SFT and also the lack of guidance/ clarity on certain issues, a representation was made for extending the due date for submission of Statement of Financial Transaction (SFT) in Form No. 61A from 31st May, 2017 to 31st July, 2017. The CBDT extended the due date of filing SFT from 31st May, 2017 to 30th June, 2017.
- Providing the inputs on draft rules relating to valuation of unquoted equity share for the purposes of section 56 and section 50CA of the Income-tax Act, 1961, arising out of insertion of Section 56(2)(x) and 50CA through the Finance Act, 2017.
- Inputs on the draft ICDS on Real Estate transactions were also submitted to the Chairman, CBDT vide representation dated 13th June, 2017.

C. Meetings with the Ministry/CBDT.

- A meeting was held with the then Hon’ble Minister of State for Commerce and Industry, Ms. Nirmala Sitharaman on 07.06.2016 at New Delhi in the matter of support sought by the Government for creating awareness about the Income Declaration scheme (IDS), 2016 all over India through the various branches of the

Institute.

- Meeting with the Standing Committee on TDS was held on 20.09.2016 for discussing the issues relating to TDS/TCS. Vice-Chairman, Direct Taxes Committee attended the said meeting.
- Pre-Budget meeting on 7th November, 2016 to outline the gist of recommendations made by the ICAI with regard to Budget 2017. Pre-Budget meeting was chaired by Chairman CBDT, and was attended by Chairman, Direct Taxes Committee along with other ICAI representatives. Pre- Budget Memoranda 2017 was submitted to the Ministry of Finance during the said meeting. A power point presentation on the preliminary suggestions was also made.
- A meeting of the Vice-President, ICAI, Chairman, Direct Taxes Committee and Chairman, Committee on International Taxation of ICAI was held with Chairman, CBDT on 3.05.2017. In the said meeting, the following matters were discussed:
 - Draft guidelines for levy of penalty under section 271J for furnishing incorrect information in reports or certificates that may be issued by the CBDT for proper administration of section 271J.
 - Representation requesting to grant exemption under section 139AA(3) to the resident assesseees of Assam and Meghalaya.
 - Letter requesting to provide list of 17500 Chartered Accountants engaged in fraudulent practices as reported in the news published in the Hindi edition of the newspaper 'Hindustan', who have brought disrespect to the profession by resorting to fraudulent practices so that action may be taken against these members by the ICAI. Despite follow ups the list has not yet been received either from the Newspaper or CBDT.

D. Activities Relating to Union Budget.

- a) The Committee organised a 'LIVE Webcast' on tax proposals of Union Budget 2017 jointly with Indirect Taxes Committee and Committee on International Taxation on 1st February, 2017 wherein the experts discussed the budget proposals at length. Approx. 2500 members viewed the webcast.
- b) **ICAI Conclave on Union Budget 2017 on 2nd February 2017**
ICAI Conclave on Union Budget 2017 related to discussion on various Direct and Indirect tax proposals of the Union Budget 2017 was organized on 2nd February, 2017 at New Delhi. During the Special Technical Session Shri Santosh Kumar Gangwar, Hon'ble Minister of State for Finance as Chief Guest, Shri Hasmukh Adhia, Hon'ble Revenue Secretary, Shri Sushil Chandra, Chairman, Central Board of Direct Taxes (CBDT) and Shri Ram Tirath, Member (Budget & GST) Central Board of Excise & Customs (CBEC) graced the occasion. Shri Santosh Kumar Gangwar, Hon'ble Minister of State for Finance and Shri Hasmukh Adhia, Hon'ble Revenue Secretary, appreciated the efforts made by ICAI for making the IDS Scheme successful and its continued support in administration and collection of direct and indirect taxes. During the Budget Talk Session CA. Ved Jain, Past President, ICAI, CA. (Dr) Girish Ahuja, CA. Ashok Batra and CA. J K Mittal addressed the members. The programme was also Webcast Live. Around 1,000 members physically and more than 5,000 members through Webcast participated/ viewed the program across the globe.
- c) **Submission of Post-Budget Memorandum, 2017**

Pursuant to the presentation of the Union Budget, 2017-18 in the Parliament by the Finance Minister on 1st February, 2017, steps were taken to assimilate suggestions on the issues arising out of direct tax proposals of Budget 2017. After due consideration of the suggestions received for inclusion in the Post Budget memoranda, the Post Budget Memoranda, 2017 was submitted to the Ministry of Finance under the signatures of President, ICAI on 27.2.2017.

E. Other initiatives:

- ❖ **'LIVE Webcast' on "E-filing- Tax Audit reports and returns on 1st September, 2016**
The Committee organised a 'LIVE Webcast' on "E-filing- Tax Audit reports and returns on 1st September, 2016. The Chairman, Direct Taxes Committee, ICAI moderated the webcast as the representative from ICAI. In addition to providing inputs to the members on E-filing- tax audit reports and returns, Shri Ramesh

Krishnamurthi, Addl. DGIT (System) also updated the members on the following E-initiatives taken by the Income tax department:

- E-filing Vault and Electronic Verification Code (EVC) - Recent initiatives for strengthening taxpayer services
- E-Assessment - for e-communication between the taxpayers and the Income Tax department
- E-nivaran – special e-grievance redressal system launched by the Income Tax department
- E-Sahyog - online mechanism to resolve mismatches in Income Tax return without requiring taxpayers to attend the Income Tax Office
- E-TDS – online filing of TDS statements

❖ **E-Newsletter of Direct Taxes Committee**

The Committee came out with its first edition of the E-newsletter. The E-newsletter covered the latest Notifications and Press Releases issued by the CBDT along with the Circulars on the Income Declaration Scheme, 2016 containing the FAQs, Announcement having deferment of the ICDSs etc. The E-newsletter is hosted on the website at <http://resource.cdn.icai.org/42951dtc32707main.pdf>.

❖ **Inputs submitted on comparative review of Fiscal & Tariff Laws in SAFA countries:**

The Committee had received a request from SAFA to review and update the information in respect of India in relation to the comparative review of Fiscal and Tariff laws in SAFA countries. Accordingly, the updates were provided to SAFA within the desired timeline.

❖ **Ease of Doing Business - Paying Taxes Questionnaire - World Bank Report – Survey:**

A meeting of Vice-President, ICAI and Chairman, Direct Taxes Committee was held on 24.03.2017 with the Addl DGIT (Systems) at Vaishali, Ghaziabad. It was informed that the World Bank was conducting a survey on “doing Business”. The “Doing business” Report is one of the flagship publications of the World Bank Group and is read worldwide by Governments with great interest. Accordingly, the department requested that the members may participate in the survey by filling up the questionnaire provided by the World Bank.

F. Seminars/Conferences/Tax Awareness Programmes/workshops

The Committee organized 22 Seminars/Conference/Webcasts/Lecture Meeting etc. across the country on topics related to Direct Taxes during the period.

5.9 Committee on Economic, Commercial Laws & WTO & Economic Advisory

India-African Partnership: ICAI Conclave with Ambassadors/ High Commissioners of African Continent Nations and International Networking Summit: As an initiative to provide an interface between various user groups, and given the significance of India and African Nations, the Committee on Economic, Commercial Laws & WTO jointly with International Affairs Committee organised this Summit on 8th August, 2016 in New Delhi with Ambassadors/ High Commissioners of African Embassies in India and stakeholders having developmental interest in Africa. The programme inter-alia dwelt on to foster at either end bilateral co-operation between the trade and industry of the two nations, doing Business, at either end, Knowledge and Resource sharing for Capacity Building in Accounting, Auditing, Corporate Finance and allied areas, Eminent personalities from the Ministry of External Affairs, Ministry of Commerce & Industry, Accounting Profession and Corporate World graced the occasion.

Representations to various Government Authorities/ Regulators: The Committee made various representations to concerned authorities on Recognition of the Certificate Course on Arbitration, Mediation & Conciliation and empanelment of the panel of Arbitrators maintained by ICAI on the Panel of Mediators or Conciliators maintained by the Government of India; allowing the Chartered Accountants under Rule 150 of the Trade Marks Rules 2002; popularizing the preliminary study conducted “Augmenting the Revenue of the Urban Local Bodies”; inputs in the Mid-term Review of the Foreign Trade Policy 2015-20; inputs in preparation of Indian wish list of the services negotiations in Trade Agreement in Goods, Services & Investments in the Inter-Ministerial stakeholder consultation in the on-going India- Peru and India-Sri Lanka; representations on the Circular No 2/2017 dated 31-05-2017 issued by Maharashtra Real Estate Regulatory Authority recognizing the heads of Finance department of government controlled development authorities, autonomous bodies, etc., as deemed Chartered Accountants.

Study Groups: Various Study groups were constituted on FEMA including FDI & Allied Laws and RERDA for revising the existing publications; for exploring the possibility/ feasibility of conducting certificate course/ beginners workshop/ webcast/ academic initiatives/ publications in the respective fields.

Workshops/ Seminars/ Conferences/ webcasts: Awareness on contemporary subjects like FEMA, IPR Laws, RERA, unconventional areas of practice, etc was created among members by way of conducting 04 Webcasts, 03 Conferences and 02 Workshops.

Revised Background Material: The revised BGM for the Certificate Course on Arbitration, Mediation & Conciliation was launched so as to keep the members up-to-date.

Certificate Course on Anti Money Laundering Laws

Keeping in view the efforts and initiatives of the Government to curb the generation of the black money in various sectors and to closely work with the Government as a partner in the nation building and help the Government to achieve its objectives in Prevention of Money Laundering, the Committee launched a Certificate Course on Anti Money Laundering Laws (Anti- Money Laundering Specialist) with the objective to equip the members of the ICAI in this field and in line conducted the 2nd batch of the Certificate Course on Anti Money Laundering Laws. 42 members appeared and qualified the evaluation test.

Certificate Course on Arbitration, Mediation and Conciliation

The Background Material on the Certificate Course on Arbitration, Mediation & Conciliation as revised & updated on the recommendations of group constituted on arbitration related matters, approved by the Committee. Apart from the comprehensive theoretical aspects, this background material contains the practical and procedural aspects with multiple case studies. Separate chapters on Mediation & Conciliation in view of the changes in the Companies Act, 2013 and rules notified under section 442 of the Companies Act, 2013 in September, 2016. Statutory Provisions and Procedures for Arbitration with provisions, discussions and case laws relating to Arbitration & Conciliation Act, 1996 (Amended by the Arbitration & Conciliation Act, 2015 and on International Commercial Arbitration, list of leading Arbitration Institutions- Domestic & International, Glossary of Legal Latin has been included.

Restructuring of the Post Qualification Course on ITL & WTO

The Committee with the approval of Council has revised the scheme by dispensing with the Part-II and providing Course Completion certificate at the completion of Part-I only.

5.10 Ethical Standards Board

For formulation of ethical standards for members and issuing guidance, the Council of ICAI constituted Ethical Standard Committee (Now Ethical Standards Board) in December, 1975.

The mission of the Board is to work towards evolving a dynamic and contemporary Code of Ethics and ethical behaviour for members while retaining the long cherished ideals of 'excellence, independence, integrity' as also to protect the dignity and interests of the members.

Besides updating the Code of Ethics, other publications of the Board are : 'FAQs on Ethical Issues' and 'Guidance Note on Independence of Auditors'. The Board promotes public awareness and confidence in the fundamental principles viz. integrity, objectivity, competence and professionalism for members. It advises members of the profession on the professional dilemmas faced by them in day to day situations. For any guidance and clarifications, members can reach Ethics Help Desk, E-Sahayataa and ESB portal i.e. esb.icai.org

Activities/ Initiatives

1. The Board has recommended to the Council - Revision of Code of Ethics in the light of the provisions of the latest edition of the IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) Code of Ethics, 2016, Companies Act, 2013 and other developments. These are under consideration of the Council.
2. The Board has also issued Code of conduct for elected, co-opted and nominated representatives of ICAI, which is effective w.e.f 1.1.2017
3. "Know Your Client" (KYC) Norms for members which are mandatory for all attest functions, and applicable w.e.f 1.1.2017. Earlier, the norms were recommendatory in nature. The mandatory and revised norms are a big step towards preventing money laundering.
4. Issued an announcement on 18.5.2017 on prohibition of advertisement of coaching/ teaching activities by chartered accountants in practice.

5.11 Expert Advisory Committee

Accounting is the language of business to communicate financial affairs to various stakeholders including its shareholders, potential investors, consumers and government regulators. While preparing and presenting financial reports, the accountancy professionals are often posed with a situation where difficulties arise in applying and implementing the accounting principles to particular situation/ transactions. In order to assist the members of the ICAI in the application and implementation of accounting and/or auditing principles under specific situations, the Council of the ICAI had constituted the Expert Advisory Committee in the year 1975 to reply to such queries received from its

members in accordance with Advisory Service Rules framed for this purpose. These Rules are available on the web-site of the ICAI, at its hyperlink, [http://www.icai.org/new_category.html?c_id=142].

The opinions issued by the Expert Advisory Committee are based on the given facts and circumstances of the query, the relevant legal position and the accounting/ auditing principles, guidance notes, and other pronouncements of the ICAI prevailing on the date the Committee finalises the particular opinion. The date of finalisation of the opinion is indicated with each opinion.

The Committee is providing its continuous services to the members by giving independent and objective opinions on various accounting/ auditing issues to the members in industry, practice and also to the Regulatory and Government authorities, such as, Comptroller and Auditor General of India, Ministry of Corporate Affairs, etc. During the period from 01.04.2016 to 30.06.2017, the Committee finalised 28 opinions received from the members of the ICAI and 5 opinions on different accounting issues received from the Regulators/ Government authorities. During this period, the Committee also organised its 200th meeting on December 20, 2016. This being a milestone event for the Committee, the President and Vice-President, ICAI addressed the Members. A Brochure containing significant achievements of the Committee since its inception was also released.

The opinions issued by the Committee are also published in the Compendium of Opinions. Till now, thirty-five volumes of the Compendium have been released for sale. A CD containing around 1400 opinions contained in all the thirty-five volumes of Compendium of Opinions with advanced and user friendly search facilities to locate the opinions on desired subject(s) and/or the opinions issued during a particular period has also been released, which is available with Volume XXXV of the Compendium of Opinions.

Some of the opinions of wider professional interest, finalised by the Committee are published in every issue of the ICAI's Journal 'The Chartered Accountant'. Recent opinions of the Committee are also hosted on the knowledge sharing page of the Committee on the website of the ICAI.

5.12 Financial Reporting Review Board

The Financial Reporting Review Board (FRRB) reviews the General Purpose Financial Statements of various enterprises and the auditors' report thereon in its endeavor to improve financial reporting practices in the country. The Board aims to maintain an environment of sound financial reporting and also to improve transparency in financial reporting and good governance, which is important to promote investor confidence in audited financial statements. The Board also supports various regulators viz Qualified Audit Report Review Committee (QARC) of Securities and Exchange Board of India (SEBI) in review of significant audit qualifications of the listed enterprises, Election Commission of India in review of annual audited accounts of political parties and undertakes review of other cases as referred by the regulators time to time.

Board reviews the financial statements of various enterprises selected on suo moto basis or referred by the regulators or cases where serious accounting irregularities have been reported in the media. Considering it as an effective mechanism, the Board has been empowered by the Council for seeking information from the auditor(s) of the enterprises in reference to which media and /or regulator has highlighted/ referred any information involving serious accounting and/or auditing irregularities.

Reviews Undertaken

During the period under report, the Board has completed the review of 95 cases selected on suo motto basis or as special case as against the previous year figure of 65 cases. It includes the review of financial statements of large corporates where financial irregularities were reported in the media.

Contribution to Society – Commitment to Nation

The Board is playing a paramount role in improving the financial reporting practices prevailing in India. The regulators are approaching it to perform various assignments for it. The significant assignments that were performed by the Board towards partner in nation building are as follows:

- On the request of Election Commission of India, the Board has reviewed the Annual Audited Accounts of various political parties. This year also, the - Commission requested the Board to undertake review of the annual audited accounts of at least six National political parties and recognized parties with income/ expenditure exceeding Rs. 10 Crore. Accordingly, the Board has undertaken the review of 33 annual audited accounts of political parties and considered all these cases.
- SEBI has requested ICAI to undertake a study for identifying early warning signals to detect entities running unauthorised collective investment scheme which would help MCA to take preventive action. The Board had a dialogue with SEBI, based on that the Board undertook preliminary review of information relating to 50 cases received from SEBI. The Board is in the process of collecting further information from SEBI for the said study.

Awareness Programmes on Financial Reporting Practices

To enhance the knowledge of members on review skill, as well as to update them with the changes made in financial reporting framework, Board organized 3 awareness programmes on Financial Reporting Practices in various Branches of the ICAI that were attended by 197 members.

5.13 Indirect Taxes Committee

The Indirect Taxes Committee has played a stellar role in felicitating the implementation of GST. The activities undertaken are as under:-

1. The Committee has submitted following inputs/ suggestions to the Government:

- (i) Suggestions on Model GST Law, Revised Model GST Law, GST Acts & on draft GST Rules
- (ii) Presentation on “Transitional Issues and IGST” before the Empowered Committee of State Finance Minister
- (iii) Presentation on “policy issues of GST, including making Matching Principal workable” before the CBEC & Empowered Committee of State Finance Minister
- (iv) Mechanism for resolving administrative issue of GST- ICAI suggested PAN based mechanism for administering GST by the Centre & State Governments
- (v) Submission of report on impact of GST Regime on Finances & Economy in Delhi to Delhi Government.
- (vi) Preliminary Study Report on Impact of Ind AS on Indirect Taxes
- (vii) Preliminary draft format of annual return cum reconciliation Statement between Excise Return and Financial Statement *viz. a viz.* Service Tax
- (viii) Pre & Post Budget Memorandum, 2017 relating to Indirect Taxes
- (ix) Based on the request from GSTN, following supports have been provided to Goods and Services Tax Network (GSTN):
 - a. List of IT Firm collected from the members of ICAI and provided to GSTN for providing training so that IT Firm may make necessary changes compatible with GST.
 - b. Sharing web based data of ICAI’s members for online validation by GSTN.
 - c. Nominating members for providing feedback on the software module of GST developed by GSTN.

2. Representation to the Government:

- (i) For allowing Audit of Financial Record under GST to be carried out exclusively by Chartered Accountants
- (ii) For revising audit fees of Service Tax Audit U/s 72A of Finance Act, 1994
- (iii) For extending due date of filing online Service Tax Return from 25th April, 2017
- (iv) To Commissioner of Commercial Taxes, Delhi for removing the condition of being a member of Sales Tax Bar Association for empanelment as Auditors for conducting special audit u/s 58-A.

3. Publication – A research Initiatives: The Committee brought out/revised following publications on GST/Service Tax/Excise:

- (i) Background Material on Model GST Law
- (ii) Background Material on Revised Model GST Law
- (iii) BGM on GST Act and Draft Rules, 2017
- (iv) Bare Law on Revised Model GST Law
- (v) Bare Law on GST Act(s) and Draft Rule(s)
- (vi) Simplified GST Guide for Manufacturer
- (vii) Study Paper on Taxation of E-Commerce under GST
- (viii) FAQ and MCQ on Revised Model GST Law
- (ix) FAQ and MCQ on GST
- (x) Study Paper on Unjust Enrichment
- (xi) Background Material for Course on Litigation Management
- (xii) Background Material for Course on Customs and FTP
- (xiii) Background Material for Certificate Course on Service Tax
- (xiv) Technical Guide to CENVAT Credit
- (xv) Background Material for Programme on Enabling Service Tax Practice
- (xvi) Background Material on Training Programme for CBEC Officials
- (xvii) A Handbook on Professional Opportunities for Members in Indirect Taxes

4. E-initiatives

- (i) **Video lectures on GST:** The Committee developed video lecture(s) on all topics of Model GST Law and hosted on its website and ICAI TV. The Committee has also launched its You Tube channel <https://www.youtube.com/indirecttaxcommittee> which contains aforesaid video recordings at a click of mouse and can be downloaded for offline viewing.

- (ii) **E-learning on GST:** The Committee has launched E-learning on GST through recorded video sessions covering almost the entire topics of GST.
 - (iii) **Webcasts on Indirect Taxes:** The Committee organised twenty-nine (29) webcasts on indirect taxes majority of which was on GST.
 - (iv) **Short video lectures on process of migration into GST and its benefits:** The Committee recorded a short video lectures on process of migration into GST and its benefits for benefits of the all the stakeholders.
5. **ICAI E-Newsletter on GST:** ICAI has been issuing its newsletter on GST from April, 2017. 6 issues of the same have been released till now. 7th issue will be released shortly.
 6. **Standardised PPT on GST:** The Committee has developed Standardised PPT on GST with a view to provide guidance to the faculty members and bring uniformity in the session of GST in the programme and session organised by the ICAI.
 7. **Training Programme for the Government:** With a view to help the Government in capacity building and partner them in Nation Building, the Committee organised approx. 20 training programmes at various Commissionerates across the Country.
 8. **Interactive Programme on GST for trade associations:** The Committee has organised 19 interactive programme on GST for trade association as part of its initiatives for partner in nation building.
 9. **Outreach Programme on GST in association with Service Tax Commissionerate:** The Committee has organised 4 outreach programmes on GST as knowledge partner in association with Kolkata, Delhi and Ahmedabad Commissionerate.
 10. **Awareness programme for members through Course, programme, workshop, conferences etc.**
 - a) **Certificate Course on GST**
ICAI has launched its first batch of “Certificate Course on Goods and Services Tax (GST)” on 28th April, 2017 with a view to provide specialized and updated knowledge of GST in a systematic manner. Within a small span of time more than 40 batches of the Course have been organised across the Country which have been attended by approx. 2500 members.
 - b) **Certificate Course on GST – through virtual classes**
ICAI has organised Certificate Course on GST through virtual classes from 9th June, 2017 to 30th June, 2017 which were concurrently hosted at 63 locations wherein 1800 members were trained.
 - c) **Programmes, Seminars and Conferences:** During the period, 152 programmes, seminars, conferences and workshops etc. have been organised by the Committee. These programmes were attended by more than 35000 members and others.
 11. **Identification and Training of new speakers on GST:** 500 new speakers have been identified and trained on GST Law making the expert pool of over 800 faculties across India.
 12. **Formation of Study Group for helping State Governments in smooth implementation of GST:** The Committee has already formed twenty (20) State level Study Group on GST for extending its support to the State Governments in smooth implementation of GST.
 13. **Indirect Taxes, including GST Update-** With a view to update the members, summary of significant notifications, circulars and other important development in the area of Indirect Taxes, including GST are regularly been circulated among the IDT NET registered members on the website of the Committee www.idtc.icai.org.

5.14 Committee on Information Technology

The Committee has been constituted by the Council of the ICAI as a non-standing Committee in the year 2000 to identify Information Technology challenges facing the profession and convert them into gainful professional opportunities for members by conducting Post-Qualification and Certificate Courses, Conferences, Seminars, and Practical Workshops, Training programmes, ERP/ IT courses apart from Practice Guides, Training Aids, Software's and Publications on Information Technology for the benefit of members.

During the period under report, the details of the course/programmes organized by the Committee are given below in brief:

A. Forensic Lab (Data Analytics lab of ICAI)

The first Forensic Lab – (Data Analytics lab) was launched on 30th January, 2017 at ICAI Bhawan Sector 62 Noida, where Hands on Training is being given to the members on CAAT Tools. The Committee is also in the process of equipping the present IT Lab and launching 5 more such labs at – COE Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Kanpur & Chennai.

B. Release of New Publication on Sample Information Systems Audit and Forensic Audit Reports

The Committee released a new publication on “Sample Information Systems Audit and Forensic Audit Reports” which can be used by the members during their professional assignments. These reports will be used as background material for the participants during the certificate course. Further these reports will also be uploaded on web site to be used by every member for value addition and standardization of reporting.

C. Publication on “Early signals of fraud in Banking Sector”

The Committee is working to bring a publication on "Early signals of fraud in Banking Sector". This publication will be useful for the members while doing the bank audits and for forensic assignments.

D. IT Awareness Programmes, Workshops, Seminars, and Conferences:

The Committee organizes many IT related Workshops, Seminars and Conferences which are of flexible duration and help the members in keeping abreast with latest developments in IT related fields. During the period under report the Committee organized 19 awareness programmes which were attended by 1299 members.

E. DISA-Eligibility Test & FAFD- Assessment Test

- The Committee successfully conducted the ISA Eligibility Test for the Post Qualification Course on Information Systems Audit on 13th May, 2017 at 39 cities PAN India where in 2386 members filled the form and 2110 members appeared for the exam at different Centres.
- The Committee successfully conducted the Second FAFD Assessment Test on 25th March, 2017 at 24 cities PAN India.

F. Workshops/ Seminars

The Committee organized various workshops/seminars on Experience Training on Forensic Analytics using CAAT Tools, Advanced Excell & Data Dashboard, Big Data Analytics and Artificial Intelligence in Assurance Services, etc. at Kolkata, Mumbai, Ahmedabad, etc.

5.15 Internal Audit Standards Board

The Internal Audit Standards Board has undertaken number of activities during the year to help internal auditors recognise and understand the skills and techniques necessary to thrive in a rapidly changing risk environment.

Proposal to Make Standards on Internal Audit Mandatory

Standards on Internal Audit as issued by the Board provide a framework for internal audit activities, establish the basis for evaluation of internal audit performance, and foster improved organizational processes and operations. The Board has initiated the process of strengthening the framework of Internal Audit practice in view of the changes in the law and needs of the various stakeholders. The Board has prepared a "Concept Paper on Proposal to Make Standards on Internal Audit Mandatory" after taking views/ suggestions of members at Conclaves held at Mumbai and Delhi for approval of the Council.

Revision of Definition of “Internal Audit”

The Board has taken up the project of revision of definition of “Internal Audit” as issued by it in July, 2007. The objective is to make definition contemporary highlighting the ever increasing role of internal auditors in governance, risk and compliance framework of organisations. The exposure draft of revised draft definition is being issued by the Board and thereafter the same will be placed before the Council for its approval.

Review and Revise Standards on Internal Audit

The Board has till date brought out eighteen Standards on Internal Audit. Standards on Internal Audit (SIAs) represent a codification of the best practices for internal auditors. These Standards play a vital role in strengthening and building up the performance benchmarks in internal audit. The Board has undertaken project to review and revise SIA and constituted study groups for this purpose.

Technical Literature

The Board is putting immense efforts to enlighten the members working as internal auditors in various industries by bringing out high quality technical literature in the form of Standards on Internal Audit and Technical Guides/ Manuals/ Knowledge Booklets. During the year 2016-17, the Board has issued the following publications and knowledge booklet:

- Manual on Concurrent Audit of Banks (2016 edition)
- Technical Guide on Internal Audit of Automobile Industry
- Internal Audit Checklist
- Knowledge Booklet IV- Quality Internal Audit Reports
- Note on Review of Demonetisation Activity by Chartered Accountants in Banks

Certificate Courses

- The Board conducts *Certificate Course on Concurrent Audit of Banks* with the purpose of providing an opportunity to the members to understand the intricacies of concurrent audit of banks. During the period, the Board has conducted around 75 batches of the Certificate Course at various places in the country and more than 3,650 members have successfully qualified this Certificate Course.
- *Certificate Course on Enterprise Risk Management* and *Certificate Course on Internal Audit* The Board has finalised revised Course Structure for these certificates course with new topics and a heavy dose of information technology.

Programmes, Seminars, Conferences for Awareness on Internal Audit

With a view to provide platform for dissemination of knowledge among members, the Board has organized 10 workshops, seminars, training programmes, interactive meets at various places for the benefits of the members.

5.16 Committee on International Taxation

A. Representation/interactions with Government

During the year under Report, the Committee made representation on -

- Issues faced in respect of new utility of Form No. 15CA/15CB
- Issues faced in respect of Notification No.93/2015 dated 16th December, 2015
- Draft rules for granting relief or deduction of income tax under Section 90/ 90A / 91 of the Income-tax Act 1961 and Committee on Taxation of e-commerce formed by CBDT
- Guidelines on Place of Effective Management (POEM)

Besides, representation, the Committee also gave its inputs to Expert Review Committee and also submitted Pre-Budget and Post Budget Suggestions on International tax.

B. Conferences/Seminars/Workshops/Webcasts on International Taxation

The Committee organized various conferences, seminars, workshops and webcasts and various issues pertains to International Taxation at different locations in the country. These includes 9 Webcast viewed by 3209 members and others and 4 CPE programmes attended by 806 members.

C. Post Qualification Diploma in International Taxation - The Committee conducted the 9 batches of Diploma Course in International Taxation during the period under Report at Mumbai, Delhi, Bangalore, Ahmedabad, Gurgaon, Pune, Hyderabad and Chennai. Total number of participants in these batches were 558.

D. Other initiatives

- The Committee had released three editions of e-Newsletter on International taxation during the abovementioned period.
- Revision of the publication "Guidance Note on Report under Section 92E of the Income Tax Act, 1961 (Transfer Pricing)" (revised 2016)
- Revision of the publication "Aspects of International Taxation –A Study"
- Arrangement with C-MTOS technologies Pvt. Ltd. In respect of Capital Line TP Corporate database for members.
- Contribution of articles on International taxation in CA Journal.
- Regular updates to the members on the subject of International taxation.

5.17 Committee for Professional Accountants in Business & Industry

The Committee for Professional Accountants in Business & Industry (CPABI) of ICAI serves as a platform for facilitating synchronization between the individual goals with organizational goals creating an interface between ICAI and industry and to recognize /project CAs beyond traditional fields as knowledgeable persons on all aspects in the functioning of the company, business and commerce. The Committee seeks to encourage and enhance close links between the CAs in Industry and business and the ICAI. The Committee also seeks to project the CAs amongst the Industry and other stakeholders for their in-depth and versatile knowledge, expertise and skills. To support this

endeavor, the CPABI has been organizing various knowledge enriching Conferences, Industry Meets, Outreach Programmes for the benefit of the members. Other important activities of CPABI include providing placement opportunities to the young and experienced chartered Accountants through Campus Placement programmes and ICAI job portal, organizing the prestigious ICAI awards to recognize exemplary achievements of Chartered Accountants in Business and Industry, releasing general publications on matters of professional interest, formation of CPE study circles, E-newsletter etc, all aiming to benefit the members. The major activities that took place during the period are as under::

Campus Placement Programme:

August-September 2016 - It was held at 21 centres, where 7322 candidates were shortlisted for being interviewed. 100 organisations had participated and 1279 job offers were made. The highest salary (cost to company) offered was Rs. 24.00 Lakh per annum for domestic posting and Rs. 76.32 Lakh per annum for International Posting.

In February-March 2017 - It was held at 21 centres, where 4081 candidates were shortlisted for being interviewed. 118 organisations had participated and 1273 job offers were made. The highest salary (cost to company) offered was Rs. 21.00 Lakh per annum for domestic posting and Rs. 43.00 Lakh per annum for International Posting.

Jury Meet for ICAI Awards 2016

The Committee had conducted a Jury Meet on 9th January, 2017 at New Delhi for finalising the awardees for the ICAI Awards 2016. Shri K. V. Chowdary, Central Vigilance Commissioner was the Chairman of Jury Meet.

10th ICAI-CPABI Corporate Forum and ICAI Awards 2016

The CPABI had organized Annual (10th) Corporate Forum on 19th & 20th January, 2017 at Chennai which comprised of the following sub- events:

- a. **Corporate Conclave** (19th & 20th January, 2017) – A two day National Convention on contemporary topics to enrich the knowledge and to enhance the skill sets of the members in industry.
- b. **Financial Services Expo** (19th & 20th January, 2017) - A platform where Chartered Accountants and Corporates from all over India mark their presence.
- c. **ICAI Awards 2016** (20th January, 2017) - honoured the exemplary work of Chartered Accountants in Industry by recognizing those who have demonstrated excellence in their professional life, personal life and are the role models for others in industry. Thiru K. Pandiarajan, Hon'ble Minister of School Education, Archaeology, Youth Welfare, Sports Development Department of the Government of Tamilnadu was the Chief Guest for the ICAI Awards 2016.

5.18 Peer Review Board

The Peer Review process is based on the principle of systematic monitoring of the procedures adopted and records maintained while carrying out audit & assurance services in the course of one's professional responsibility to ensure and sustain quality. The Peer Review mechanism of ICAI is directed towards maintenance as well as enhancement of quality of assurance services and to provide guidance to members to improve their performance and quality of professional work as adhere to various statutory & other regulatory requirements. The main objective of Peer Review is to ensure that in carrying out the assurance service assignment, the members of the ICAI (a) comply with Technical, Professional and Ethical Standards as applicable including other regulatory requirements thereto and (b) have in place proper systems including documentation thereof, to amply demonstrate the quality of the assurance services.

The effort of the Board coupled with effective performance of the Peer Reviewers not only inspired the practice Units to continually improve the quality of service that they render to the society at large, but also received recognition from various regulatory authorities as mentioned below:-

- The Securities & Exchange Board of India (SEBI), has made it mandatory with effect from April 1, 2010 for the listed entities, that limited review / statutory audit reports submitted to the concerned stock exchanges shall be given only by those auditors who have subjected themselves to peer review process and who hold a valid certificate issued by the 'Peer Review Board' of the ICAI.
- The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) has recognised Peer Review Board's work; now it seeks additional details from the Chartered Accountants firms about their Peer Review Status in the application form for allotment of audit for Public Sector Undertakings. Furthermore, from last few years the C&AG annually seeks details from ICAI of those firms which have been issued certificate by the Board.

To ensure that there is consistency and uniformity in carrying out reviews by the Reviewers, the Board imparts training

to the Reviewers before assigning them the practice units for review. A total of 5715 reviewers have been trained so far. The training programme is aimed to understand the nuances and intricacies of the peer review process i.e. how to carry out peer review of a Practice Unit. Further the Board since its inception has organised 163 Peer Review Training Programmes across the country. During the period under Report 7 such programmes were organized.

Coverage of more firms under Peer Review process

Peer Review Board as a regulator for review of assurance services of CA firm in India, has increased its scope of assurance services by coverage of more firms for peer review on the basis of specified new criteria. Peer review has been started for newly established firms. Cases of non-compliances observed in the Financial Statements by the Financial Reporting Review Board which may not affect the True and Fair view but indicates negligence on the part of the auditor and forwarded to the Peer Review Board are reviewed by Technical Reviewer so that the quality control framework applied by the member may be ascertained. Such efforts will make the regulatory mechanism of the ICAI more effective.

Recent Developments

Continuous efforts are being made to enhance the scope of peer review making it more effective and also to have more practicing units peer reviewed. Towards this, the Statement on Peer Review has been revised by the Peer Review Board and Questionnaire on Peer Review sent to the Practice Units has also been revised in accordance with Standards on Quality Control. Annexure II to the Questionnaire has been made mandatory to be filled by Reviewer incase of Level 1 and Level 2 firms from March 17, 2017 onwards, for strengthening the Quality of Review. Peer Review Manual is also under revision by the Board. The Peer Review Board has also revised the fees for the Peer Reviewers which is borne by the Practice Unit.

5.19 Professional Development Committee

The Professional Development Committee determines the professional development needs and identifies issues and other areas, which can impact the profession. In order to achieve this, Committee has been striving to generate more professional opportunities for the members by exploring/pursuing new/existing areas where the professional skills of the members could be utilized. The Committee has also made considerable efforts to ensure that equitable opportunities are available to all members of the profession. Apart from exploring uncharted territories in the professional development, the Committee strives to strengthen the communication process with multitude of users across the different sections of the society and educate them about the role of Chartered Accountants.

Managerial Autonomy given to Banks for Appointment of Statutory Auditors.

Pursuant to representations regarding the appointment of Banks Branch Auditors through use of Software and meetings held, a letter dated 13th April, 2017 has been sent by RBI to all Public Sector Banks, wherein it is mentioned that PSBs may formulate a fair and transparent policy and procedure in the matter of selection and appointment of Statutory Branch Auditors which may also be hosted on their website. As part of this revised procedure, selection and appointment of SBAs may be made centrally at the Corporate Office of respective Bank. RBI advised the banks that ICAI has developed a software for parameter based allocation of such audit amongst the eligible firms and further advised that banks may consider appointing SBAs centrally at Corporate Office with the help of such or other suitable software, customized or otherwise, to select audit firms in terms of the appointment policy formulated/approved by the Banks Board/ACB. For the purpose, a software has been prepared by the Committee which is in testing phase.

Mechanism to monitor tendering process.

With a view to enhance the quality of services rendered by the members and to monitor the tendering system for attest functions a notification dated 7th April, 2016 has been issued by the Council of the ICAI. The Committee has subsequently prepared the FAQs for general guidance of the members. Letters were sent to various authorities from time to time to draw their attention to the decision of Council regarding responding to tenders thereby requesting them to take ICAI panel to avail services of our members.

Multipurpose Empanelment Form and provision of Panels to various Authorities:

The Committee has been striving to generate more professional opportunities for the members of the ICAI by exploring/pursuing new/ existing areas where the professional skills of the members could be utilized in a productive and fruitful manner. As per the practice, the Committee this year also hosted Multipurpose Empanelment Form online at www.meficai.org. Every effort was made to make MEF more comprehensive to collect maximum information and disseminate through a centralized database. For the first time facility of Digital Signatures for submission of declaration was provided. The Committee also submitted Panel to various Government Departments and other agencies.

State Level Co-ordination Committee (SLCC) Meeting on the working of Non-Banking Financial Companies & Unincorporated Bodies

Various SLCC meetings were held throughout the year for the states of Goa, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh,

Karnataka, Maharashtra, NCT of Delhi, Chhattisgarh, Odisha, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Haryana, Tamil Nadu, Arunachal Pradesh, Rajasthan, Kerala, Gujarat, Tripura, Nagaland, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Pondicherry, Raipur, Chandigarh. Various Sub-State Level Co-ordination Committee (SLCC) Meeting on the working of Non-Banking Financial Companies & Unincorporated Bodies have been held for states of Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Haryana.

Start Up India

Start up India is a flagship initiative of the Government of India, intended to build a strong eco-system for nurturing innovation and Start-Ups in the country that will drive sustainable economic growth and generate large scale employment opportunities. The campaign is based on an action plan aimed at promoting bank financing for start-ups ventures to boost entrepreneurship and encourage start ups with job creation. One of the key concerns of the young entrepreneurs trying to make efforts to make themselves and consequently nation financially strong, is the financial difficulty faced by them for getting the valuation of business done. Ministry of Commerce & Industry, Government of India has requested the ICAI support for the same. As a Partner in Nation Building, the Committee is preparing a panel of Chartered Accountants willing to render this service on minimum reasonable fee.

5.20 Committee on Public Finance & Government Accounting

The Committee on Public Finance & Government Accounting organised following Training Programmes/Workshop during the period under report:

- Workshop on Financial Management for “Top Level Finance Executives of SLPEs” jointly with Finance Department, Government of Tamil Nadu
- Training Programme on “Role in Audit-Internals/ Statutory/ C&AG and Audit Committee” for the Assistant Audit/ Accounts Officers and Auditors, Finance Department, Government of Tripura
- Training Programme on “Budgeting and taking Financial Decisions” for the Dy Commissioner/ Chief Executive Officer/ Executive Officer of Urban Local Bodies, Managing Director/ Accounts Officers of different State PSUs, Government of Tripura
- Workshops on “Recent Changes in Companies Act 2013 –IFRS” for the executives of CPSEs and SLPEs of Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India
- Three days Residential Training Programme on “Finance for Non Finance Professional” jointly with Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India
- Training Programme on “Internal Financial Control and its Benefits” for the senior management personnel, including CEOs/ CFOs/ Functional as well as Independent Directors from the member CPSEs jointly with Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE)
- One Day Workshop on “Ind AS” for the Executives of CPSEs and SLPEs of Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India
- Training Programme on “Ind AS” for the Executives of CPSEs and SLPEs of Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India

The Committee also organised a three days Residential Refresher Course and Webcasts on various topics.

E-newsletter- Prudence:

The Committee regularly comes out with a quarterly E-Communique of the Committee named “Prudence” which highlights the major initiatives of the Committee and gives an insight on the recent regulations and changes in the field of Public Finance and Government Accounting.

5.21 Public Relations and CSR Activities

During the year 2016-17, the Committee in pursuance of its mission and goals continued its endeavor to develop, strengthen and enhance the image of the ICAI as a premier accounting body and the sole regulatory authority. The Committee expanded its area of activities in addition to the regular tasks being undertaken. For the year 2017-18, the Committee has been reconstituted as Public Relations & CSR Committee. Some of the important activities undertaken by the Committee during the aforesaid period include the following:

ICAI International Conference on ‘Jnana Yajna: The Quest for Excellence’

ICAI organized two days International Conference ‘Jnana Yajna: The Quest for Excellence’ from October 22-23, 2016 in Hyderabad. The goodwill messages were invited by PR Committee and published in the Souvenir brought out to mark the occasion. The event was attended by many delegates from overseas and by various stakeholders and members

of ICAI. The Conference was also publicized through print and electronic media.

Union Budget 2017

Every year, PR Committee follows up with various electronic channels, newspapers, magazines to include the reaction from ICAI on the Union Budget. The President, ICAI attended the panel discussion organised by Zee Business on budget day.

Year Book -2016-17

A comprehensive document of the significant achievements & initiatives taken by the ICAI/ Committee's/ branches/ regional offices is brought out as a publication "Year Book". The inputs received from all Committees/ branches/ regional offices was edited and compiled by the Committee for the Year Book: 2016-17.

3rd International Day of Yoga

The ICAI has always been a torch bearer for promoting healthy living by undertaking various initiatives including marathon run, yoga sessions for stress management, creating awareness about the environment, Go Green initiatives etc. ICAI through its widespread CA members & student community is committed to take forward this initiative of Hon'ble Prime Minister of India.

The 5 Regional Councils & 110 Branches of ICAI had actively undertaken celebrations on International Day of Yoga by undertaking specified activities which were attended by over 10,000 participants. In order to make the members & students aware about the health benefits of Yoga, dedicated Yoga sessions were organized on June 21st which were attended by members, students and their families. The participants were encouraged through lectures given by experts to inculcate Yoga in their daily lives. A video message of President, ICAI motivating the CA fraternity was shared with all Regional Councils & Branches encouraging them to inculcate Yoga as part of their daily routine.

Media interactions:

The Media interactions increased through one on one interviews/ Press Release/ Press Conferences by way of which the media was constantly apprised of the latest developments regarding the various activities undertaken, issues concerning the fraternity, stakeholders, trade and industry by the President by way of one on one interactions and telephonic interviews.

5.22 Research Committee

Research Committee is one of the oldest non-standing committees of ICAI established in the year 1955. The primary objective of Research Committee is to undertake research in the field of accounting and other affiliated areas with a view to enhance the value of services rendered by the profession. It formulates Guidance Notes on accounting aspects which are issued under the authority of the Council. It also brings out Technical Guides, Studies, Monographs, etc., on generally accepted accounting and/or auditing principles. The Committee, through its sub-committee, the Shield Panel, also conducts an annual competition, 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' with a view to improve the presentation of financial statements.

ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting for financial year 2015-16

These awards are being presented annually since 1958. Selection of awardees in specified categories is made through a robust three tier process: first review by Technical Reviewers followed by review of short listed annual reports by Shield Panel and final review by External Jury.

Jury Meeting for the competition year 2015-16 was held on January 9, 2017, at New Delhi and was chaired by Shri C.B. Bhawe, Trustee, IFRS Foundation & Former Chairman, (SEBI). Other members of the Jury, who participated in the meeting to select the awardees, were: Shri H.R. Khan, Former Deputy Governor, (RBI), Shri R. Bandyopadhyay, Former Secretary, Ministry of Corporate Affairs (MCA), CA. Amarjit Chopra, Chairman, NACAS & Past President ICAI, CA. Kamlesh Shivji Vikamsey, Past President, ICAI, Dr. Asish K. Bhattacharyya, Former Professor – IIM, Kolkata, CA. Uday Phadke, Former President Finance & Legal and Financial Services Sector and member of the Group Executive Board, Mahindra & Mahindra Limited., CA. Nilesh Shah, Managing Director & CEO, Kotak Mahindra Asset Management Company Limited. As per the scheme of awards, one Gold Shield and one Silver Shield are awarded for the best entry and the next best entry, respectively. Apart from the above-mentioned awards, Plaques are awarded for commendable entries. Hall of Fame award is bestowed on an entity which wins five consecutive Gold Shields in a particular category.

A function to honour the awardees of 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' was held on January 24, 2017 New Delhi. Shri Vinod Rai, Chairman of Banks Board Bureau & Former Comptroller and Auditor General of

India was the Chief Guest at the occasion. A total of 13 awards – three Gold Shield, three Silver Shields and seven Plaques were given away.

5.23 Ind AS Implementation Committee

The Ind AS Implementation Committee since its inception in the year 2011 has been making relentless efforts to create knowledge and awareness about Ind AS in the country. Pursuant to the notification by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) with regard to the mandatory applicability of Ind AS from financial year 2016-17 onwards for certain class of companies and from financial year 2018-19 onwards for scheduled commercial banks and NBFCs, there was an urgent need to provide guidance to members and other stakeholders on Indian accounting Standards (Ind AS). The Committee has been taking every possible effort to make the transition to Ind AS smooth through its various initiatives.

In order to ensure implementation of Ind AS in the same spirit in which these have been formulated and to provide appropriate guidance to the members and other stakeholders, the Ind AS Implementation Committee of ICAI issues Educational Materials on Ind AS, which contains summary of the respective Ind AS and the Frequently Asked Questions (FAQ) covering the issues, which are expected to be encountered frequently while implementing the Standard. The Committee is working to bring out Educational Materials on all the Ind AS.

The Committee revised its publication titled “Indian Accounting Standards (Ind AS): An Overview (Revised 2016)”, which contains an overview of all Ind AS in brief and major differences between existing Accounting Standards vis-a-vis Ind AS and Ind AS vis-a-vis IFRS.

In order to provide timely clarification on various issues that are being raised by the members, preparers and other stakeholders with regard to applicability/ implementation of Ind AS, an Ind AS Transition Facilitation Group (ITFG) was constituted. The Group issues clarification bulletins addressing implementation issues from time to time.

The Committee has also launched “Support-desk for Implementation of Ind AS” in order to address the difficulties being faced by the members wherein the members can submit their queries, questions, suggestions online by clicking on a link.

The Committee is also taking adequate steps to enhance the knowledge of the members and other stakeholders for proper implementation of Ind AS by conducting workshops, seminars and Certificate Course.

The Committee organises 12-days Certificate Course on Ind AS throughout the country and abroad to impart knowledge about Ind AS. Comprehensive session plan of the course has been designed with a view to make members competent in field of Ind AS. During the period, 32 batches of Ind AS Certificate course have been conducted wherein around 1200 members have been trained. So far, around 8000 members have been successfully trained in the Certificate Course on Ind AS across various locations throughout the country and abroad. It has also developed E-learning modules on various Indian Accounting Standards (Ind AS).

The Committee also organises one/two day awareness programme on Ind AS at various locations across the country. In these awareness programmes, training on the basic Standards which form the premise for preparation and presentation of financial statements under Ind AS, difference between Ind AS and existing AS are also specifically covered in order to educate the members and stakeholders about how accounting under Ind AS would be different from existing AS. During the period, 10 awareness programmes have been organised at various locations across the country.

The Committee also organises in-house training programmes on Ind AS for various regulators, organisations and corporate houses. During the period, various training programmes on Ind AS have been organised for Comptroller & Auditor General of India (C&AG). It also conducting series of webcasts on Ind AS to create awareness on Ind AS. The Committee is making every possible effort to create knowledge and awareness about Ind AS and to make this transition smooth.

5.24 Audit Committee

The Audit Committee reviews the reporting process and disclosure of financial information of the ICAI to ensure that the financial statements are true and fair. It is also responsible for appointment of Auditors for various units of the ICAI. The Audit Committee also has five Regional Audit Committees located at each of its Regional Councils.

5.25 Digital Transformation & Process Re-engineering Group

- Digital Transformation and Process Reengineering Group has launched online regulatory forms for ICAI students and members. Student’s dashboard for registration in Foundation Course, Intermediate Course through Foundation/CPT/Direct Entry/Final Course is available online. Development of other regulatory forms is in process

and same would be launched in phases.

- ICAI Mobile App ICAI Now and ICAI Social Media Platforms have been instrumental in Popularization of various ICAI's events and Key Achievements and Initiatives on no cost basis amongst students, members and other stakeholders of ICAI. The ICAI Twitter Account <https://twitter.com/theicai> has been verified by Twitter as Official Twitter Account and has been granted with the blue tick symbol as a mark of verification by Twitter. ICAI is also present on other Social Media Networking platform Facebook, LinkedIn, Google Plus and YouTube, Students and Members are connected via Social Media.
- Digital Transformation and Process Reengineering Group has enabled Paytm Payment gateway services on ICAI Website for Members and Students where all the online transaction charges are free of cost for one year for Net banking and Paytm wallet. ICAI Engagement with Paytm would facilitate efficient and secure payment option to students and Members.
- Digital Transformation & Process Reengineering Group (DTPRG) helped in the implementation of the Go Green Campaign of the ICAI Journal "Chartered Accountant". ICAI has also planned digital transformation of other departments i.e examination via Digitalizing its Documents and Documents Management System.

5.26 Quality Review Board

As reported in the last Report, the Quality Review Board was constituted on 28th June, 2007 by the Central Government pursuant to the powers vested in it under Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 for perform the following functions:-

1. To make recommendations to the Council with regard to the quality of services provided by the members of ICAI.
2. To review the quality of services provided by the members of ICAI including audit services; and
3. To guide the members of ICAI to improve the quality of services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements.

One of the functions of the Council under clause (o) of sub-section (2) of Section 15 of the Chartered Accountants Act, 1949 is to consider the recommendations of the Quality Review Board made by it with regard to the quality of services provided by the members of ICAI. The aforesaid clause (o) also provides that the details of action taken on such recommendations shall be published in its Annual Report. In accordance with the aforesaid provisions, during the period under Report, the Council received 3 references under Section 28B(a) of the Chartered Accountants Act, 1949 from the Quality Review Board with regard to the quality of services provided by the members. Out of these, 2 references were considered by the Council at its meeting held during the financial year April, 2016 to March 2017. The following is the details of action taken:-

1. Number of references referred to the Director (Discipline) for making further investigation under the disciplinary mechanism of ICAI - 1
2. Number of references where comments of the Technical Reviewer were decided to be issued as an Advisory to the members/firms - 1
3. Number of references which were decided to be closed - Nil
4. Number of references pending for consideration of the Council - 1.

5.27 Management Committee

The Management Committee was constituted in the year 2015 as a non-standing Committee of the Council . The functions of the Committee among others are to consider matters pertaining to formation of branches, setting up of Chapters abroad, MOUs/MRAs with national/international bodies, appointment of central auditors of ICAI, annual accounts of the Institute, matters referred by the Central Government and other regulatory bodies, proposals for amendments in the Chartered Accountants Act, 1949, Rules and Regulations framed thereunder, Regional Councils and Branches matters, Members/ CA Firms/ LLPs/ mergers/ demergers/ networking related matters and proposals received from other Committees/Departments of the Institute having administrative and policy implications and making its recommendations to the Council wherever required. The following are some of the important recommendations made by the Committee to the Council and decisions taken by it:-

A. Recommendations made to the Council an important matters of -

- Issuance of Fit and Proper Certificate sought by CA Firms similar to Good Standing Certificate being issued to the members.
- Setting up of a new Chapters of ICAI at San Fransico Bay Area in California, USA and at Netherlands (Amsterdam).
- Cooling period of one year for faculty for the various courses organized by the ICAI before they become eligible to

contest the elections to the Council, Regional Councils and Branches.

B. Important decisions taken

- Approved the recommendation of Board of Studies for reimbursement of registration fee in two 6 equal monthly installments to the first two rank holders in all the 3 streams, i.e., Commerce, Science and Art, in the Final Examination of 12th Class of Senior Secondary Boards for Foundation course and awarding some recognition to such candidates by way of granting certificate / medal in Career Wizard organized by the Career Counselling Group of the Board of Studies without payment of any TA/DA and stay cost.
- Sharing of the profit of the firm by the non-CA wife of deceased partner by way of partnership deed or any other agreement but cannot be taken as a partner in the firm.
- Approved the proposal of Committee on Information Technology for establishment of first Data Analytics Lab at ICAI Bhawan, Noida-62 initially and then at other locations for organizing hands on Training sessions on Forensic Accounting and Fraud Detection and other training programmes.
- Changing the date of birth of members in ICAI's records on the basis of date of Birth given in Passport or Aadhaar Card or 10th class mark sheet/pass certificate or 10th class leaving certificate and on submission of an affidavit in case of mismatch in date of birth of members as per ICAI records and in Pan Card for e-filing of Income Tax Returns as per PAN Card.
- Advising the Regional Councils and branches to adopt cashless system of transacting business mandatorily w.e.f 1st January, 2017 by way of installing POS machine/e-wallet in their sale counters by getting in touch with their bankers and become completely cashless in days to come.

6. International Affairs Committee (IAC)

Initiatives of IAC for recognition of professional opportunities abroad

- (i) **CBFS Oman MoUs signed on December 14, 2016:** During its meeting on December 14, 2016, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi gave "ex-post facto approval" for the MoUs signed in 2008 and 2011 as well as for renewal of MoU between ICAI and CBFS.
- (ii) **Globalizing ICAI's Brand Equity:** As an extended arm of the ICAI, the foreign chapters of the ICAI have a pivotal role to play in furthering the Mission of the Indian Chartered Accountancy profession which position itself as the Valued Trustees of World Class Financial Competencies, Good Governance and Competitiveness. During the year under report, the (29th) USA (San Francisco) Chapter of the ICAI was inaugurated on March 04, 2017 and the (30th) Netherlands (Amsterdam) Chapter of ICAI was inaugurated on June 01, 2017.
- (iii) **Delegation visiting ICAI**
 - Delegation from International Federation of Accountants (IFAC) comprising President Ms. Olivia Kirtley and Mr. Russell Guthrie, Chief Financial Officer, IFAC visited India on 23rd & 24th June, 2016. The delegation had fruitful interactions with the Indian Regulators namely, Securities Exchange Board of India (SEBI), Reserve Bank of India (RBI), Deputy Comptroller and Auditor General of India, Ministry of Corporate Affairs and the Controller General of Accounts (CGA). The objective of meeting with the Government dignitaries was to have a closer and more in depth interaction with accounting fraternity in India in association with ICAI to lay the foundation for a long way in emphasizing the fusion of global, Indian and the regulatory perspective.
 - Mr. Mark Chau, Regional Manager, CPA Australia and Michelle Chan, Senior Business Development Manager, CPA Australia visited ICAI on July 04, 2016 to discuss on the matters of mutual interest and to strengthen the already existing ties between the two Institutes. CPA Australia had organized an outreach program at Mumbai on June 30, 2016 and on July 02, 2016 at Delhi wherein CPA Australia provided information on the opportunities Indian CAs have in Australia and how they could benefit from the MRA signed between ICAI & CPA Australia.
 - Mr. Tony Manwaring, Executive Director of External Affairs, CIMA visited ICAI on March 11, 2016 and Mr. Andrew Harding, managing Director, CIMA & Mr. Bhaskar Ranjan Das, Head of Markets, South Asia, CIMA visited ICAI on May 27, 2016 to discuss on issues of mutual interest.
 - Mr. Tom Odlziambo Nyagare, Chief Manager, Member Services, at the Institute of Certified Public Accountants of Kenya (ICPAK), visited India from 1st to 12th August 2016. During the course of his visit, he went through the system and procedures at ICAI for replicating in their Institute and also initiated dialogue for a Memorandum of Understanding.
 - A delegation from the Risk Management Society, New York visited ICAI on February 22, 2017 comprising of Nowell R. Seaman, President RIMS; Mary Roth, CEO RIMS; Carol Fox, Vice President Strategic Initiatives RIMS; Robert Cartwright, Vice President RIMS; Soubhagya Parija, SVP and Chief Risk Officer, New York

Power Authority; Jugal Kishore Madaan, Fellow & Member, International Committee, RIMS; Steven Chou, Senior Director, Global Business Development, RIMS and Laura Langone, Global Risk Management and Insurance, PayPal.

- Mr. Muhammad Zarif Ludin, Program Manager, Treasury Department, Ministry of Finance, Afghanistan had visited ICAI on March 08, 2017 to discuss the proposed MoU and to take the matter of bilateral dialogue between ICAI & Ministry of Finance, Afghanistan forward.
- The President, ICAI along with a Central Council Member and officers of the Institute met the delegation from Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) comprising of Mr. Lawson Carmichael, EVP – Strategy, People & Innovation for the Association, Ms. Irene Teng, MD- Europe, Africa & Asia and Mr. Ajay Lalwani, Country Head - India - Management Accounting Association of International Certified Professional Accountants on 9th March 2017 at ICAI office, Mumbai
- A delegation from ICA Nepal comprising of Mr. Mahesh Khanal, President, ICAN; Mr. Prakash Jung Thapa, Vice President, ICAN and Mr. Prakash Lamsal, Immediate Past President met the ICAI functionaries at ICAI, Mumbai on to discuss on the possibility of qualification reciprocity between the two Institutes.

(iv) Conferences/Programs

SAFA Committees & SAFA Board Meetings and SAFA - IFAC Regional PAIB Forum from 22nd to 24th April 2016 at Mumbai, India: ICAI hosted the CEO Forum of SAFA member bodies, SAFA Committees & SAFA Board Meetings and SAFA - IFAC Regional PAIB Forum from 22nd to 24th April 2016 at Mumbai, India, with the aim of giving Professional Accountants in Business (PAIBs), an opportunity to know about the significant developments impacting the PAIBs worldwide. The SAFA-IFAC Regional PAIB Forum dwelled upon some of the important issues relevant for PAIBs such as improving governance, international control and effective Business Reporting Processes and alike. The SAFA IFAC Regional PAIB Forum provided an opportunity to the participants to have a first-hand interaction with the members of PAIB Committee of IFAC and other renowned speakers from SAARC Region.

- **Africa-India Partnership: ICAI Conclave with Ambassadors/ High Commissioners of African Continent Nations and International Networking Summit:** With increasing share of services across economies having trained and skilled human capital is the key success ingredient to any Nation's Competitiveness and its future prospects. Recognizing its role and contribution in such a dynamic context, as an initiative to provide an interface between various user groups, and given the significance of India and Africa, the ICAI organized the Africa- India Partnership: ICAI Conclave with Ambassadors/ High Commissioners of African Continent Nations and International Networking Summit on 8th August, 2016 at New Delhi in the evening with Ambassadors/ High Commissioners of African Embassies/ High Commissions in India and stakeholders having developmental interest in Africa.
- **ICAI-IFRS Foundation Trustees Joint Stakeholders Event and Meeting at ICAI Head Office on 13th and 14th October 2016 respectively:** The ICAI jointly with the Trustees of the International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation organized the Stakeholders Event on 13th October 2016 to address the roadmap of Ind AS and IFRS relationship in India. The IFRS Foundation is the oversight body of the International Accounting Standards Board (IASB) and includes governance and oversight, undertaken by the Trustees, and support operations thereof. Further, as a part of G-20 initiative, the Government of India had committed and has converged with IFRS issued by the International Accounting Standards board (IASB) of IFRS Foundation.
- **ICAI International Conference 2016 and CAPA Board and Committee Meetings at Hyderabad:** The ICAI International Conference "Jnana Yajna – The Quest for Excellence" was successfully held in Hyderabad from 22–23 October, 2016 wherein more than 3500 delegates from all across the India and World participated. The Conference was inaugurated by Shri M Venkaiah Naidu, then Hon'ble Minister of Urban Development, Government of India. Shri Arjun Ram Meghwal, Hon'ble Minister of State for Finance, Government of India addressed the Conference. The International Conference delved on many topics like Accounting Standards, GST, Competitiveness of SMPs, Corporate Fraud, International Taxation and was targeted for capacity building of profession for being relevant in the current context.
- **ICAI-PIOB Joint Stakeholders' Conclave on "Global Audit Oversight: Reconciling Perception Gap" on 9th February 2017 at New Delhi:** The ICAI in collaboration with Public Interest Oversight Board (PIOB), the global independent oversight body organized the Joint ICAI-PIOB Stakeholders Conclave on the theme "Global Audit Oversight: Reconciling Perception Gap" on 9th February 2017 at Hotel Royal Plaza, New Delhi. The objective of the joint ICAI-PIOB Conclave was to have an insight into the role of the PIOB and the

standard setting model, and to have an open dialogue on the challenges of the profession and the experience in India.

- **Emerging Economies Group Meeting hosted by ICAI:** International Accounting Standards Board (IASB) has constituted an EEG Group to help in addressing the financial reporting issues that are of special significance to the economies. The National Standard Setters are the permanent members of the EEG with designated individuals as representatives on the Group. The meeting of the Emerging Economies Group was held in India on 8th-9th May 2017 to discuss accounting for micro entities, high inflation and IFRS and the issues relating to the implementation.

(v) Technical Co-operation to least developed countries

- ICAI had been awarded the World Bank funded project of "Consultancy Service for Development of Chartered Accountancy Curriculum of Institute of Chartered Accountants of Bhutan, Drafting of By-laws for ICAB and Rules and Regulation for Accounting and Auditing Standards Board of Bhutan". The main objective of the assignment was to:-
 - Develop curriculum, syllabus and study material for chartered accountancy course.
 - Drafting By-laws for ICAB
 - Drafting Rules and regulations of AAS Act.

The project was an outcome of the bid submitted by ICAI against the World Bank tender in December 2015, pursuant to which two Council Members had undertaken a visit to Bhutan in the month of May 2016 alongwith Director, ICAI. Further, on account of the existing MoU of ICAI with AASB Bhutan, ICAI was on advantageous position to be considered for this project. The project had been bid on pro-bono basis.

- IFAC had issued call for Expression of Interest, for development of accountancy infrastructure in Africa region in furtherance of IFAC's commitment to strengthen the accountancy profession and PAOs in emerging economies. The EOI is to identify from interested organizations who are having the required qualifications and relevant experience to execute projects of similar status. ICAI had duly submitted its Expression of Interest for Capacity Building Program for PAOs on December 01, 2016. Following our expression of interest, IFAC has sent the notice of an upcoming project in Myanmar which has to be responded to by ICAI by July 21, 2017.

(vi) Working for building blocks

- **Launch of Global Career E-Kit of Uganda:** The ICAI has successfully launched the Global Career E-Kit of Uganda coinciding with the event of Uganda Chapter on 16th May 2016.
- **Launch of Global Career E-Kit for Africa:** The ICAI on the occasion of ICAI Conclave with Ambassadors/ High Commissioners of African Continent Nations and International Networking Summit on August 08, 2016 launched the combined Global career E-kit for Africa and Tanzania.
- **Launch of Global Career E-Kit of Kenya:** The ICAI has successfully launched the Global Career E-Kit of Kenya coinciding with the event of Tanzania Chapter on January 23, 2017. This is the seventh E-Kit in the series of 6 already launched E-Kits for Doha, Kuwait, Muscat, Tanzania, UAE and Kenya covering both Dubai & Abu Dhabi and efforts are on for launch of E kits for other remaining Chapters as well.

These E-Kits provide panoramic view of the primary information to our members intending to go abroad for professional forays. These Global Career E-Kits covers general information of related jurisdiction such as demographic details, economic environment, useful business information, visa requirements etc. In addition, useful information such as contact details of local chapter, information on MoU/MRA and FAQs for members abroad is also included in these E-Kits. These E-Kits are likely to assist members to establish a preliminary interface with the jurisdiction to serve in times to come.

7. OTHER ACTIVITIES

7.1 HR Transformation Group

Effective from the current Council Year, this Committee has been converted into Group, i.e., HR Transformation Group. 79 training programmes imparting approx. 8314 training man hours were organized by the Committee during the above period in the areas of behavioral aspect and technical acumen. A resource distribution chart was prepared by the sub-organ of the Committee to depict the resource utilization within the ICAI.

Activities undertaken by the Group

- Trainings programmes organized in association with National Productivity Council, Institute of Secretarial Training and Management (ISTM) along with the GMCS Faculties.

- HRT Officers Group was constituted to look into the pending HR issues.
- The HRT Officers Group is assigned the task to implement the recommendations of the previous reports. All the HR matters were bifurcated into three phases:

Phase	Activities to be undertaken
I	Job description
	KRAs and KPIs
	Communication strategy
	Manpower rationalization
II	Organization restructuring
	Redesigning Appraisal management system
	Measuring Training effectiveness
	Creating Event Management department
III	Implementing appraisal management system
	Succession planning

- The HRT Officers Group has completed one to one interaction meeting with the Committee Secretaries and HOD for manpower assessment with regard to their roles and responsibilities and the communication strategy for the organization restructuring to be undertaken in the second phase. The officer Group will submit its report on completion of Phase I at the next meeting of the HRT Group.
- Further, organogram depicting the roles and responsibilities of the personnel in the departments/committees were prepared for all the committees/department in order to compile the total job responsibilities within these organs and to justify the manpower utilization for their smooth functioning.
- Pooling of administrative and Event management resources amongst various Committee/Departments is also being explored for future.

7.2 Human Resource Development

The Human Resource Development is a systematic and planned approach through which the efficiency of employees is improved. It is a framework for helping employees to develop their personal and organizational skills, knowledge, and abilities. It also ensures appropriate deployment of necessary skill set and expertise for a particular activity and thus, achieving the common goal of an organisation.

The Human Resource Development Department of the ICAI plays an important role in providing such opportunities as employee career development, performance management and development, coaching, mentoring, succession planning, key employee identification and organization development. It focuses on developing the most superior workforce so that the organization and individual employees can accomplish their work goals in service to its members and students.

With a view to strengthen its financial, legal, technical, infrastructural and PR Wings at the Head Office level, the HR Department during the year 2016-17 has executed various recruitment drives at diverse levels. Appointments have been made on contractual basis for the posts of Civil Engineer, IT Consultant, Public Relations Associate, Legal Advisor and IT Consultants. Recruitments at the level of Secretary, Director (Operations), Director (Finance), HR Professionals, Dean-ARF and manpower for Technical Directorate for Delhi and Mumbai locations are underway.

For maintaining efficient administration of the ICAI, it is expedient to have a Code of Conduct for employees of the ICAI. In order to serve as a guide for the employees of the ICAI in the course of their duties, a Code of Conduct has been issued during the year which is applicable to all employees of the ICAI, apart from complying with various advisories issued by the ICAI relating to conduct of its employees.

With an objective to have a long-term planning for smooth and unobstructed functioning of various wings of the ICAI, necessary initiatives have been taken to develop a second line of the officials due for retirement during the next two

years. Also, an analysis is being done with regard to identification of consistent non-performers in various departments and committees of the ICAI with a view to take possible measures to improve their performance.

Further, with a view to develop the knowledge and skill sets of the employees and make them well-versed with various tasks being handled by different wings of the ICAI, an exercise has been carried out to rotate the employees who have already served a department for ten years or more of his/her service period. The rotation of such employees is underway.

7.3 Committee on Management Accounting

Initiatives for members

- The Committee conducts its flagship course Master in Business Finance Certificate Course (MBFCC) for the Members of ICAI in practice and Industry. The Certificate Course is spread over to one year period covering 30 class room sessions of five hours' duration per session, two mandatory Residential Programmes of 5 days' each and examinations.
 - ❖ The Committee organized the 10th batch of Certificate Course on Master in Business Finance at Mumbai commenced on 9th April, 2016.
 - ❖ The Committee organized the 10th batch of Certificate Course on Master in Business Finance at Delhi commenced on 10th April, 2016.
 - ❖ The Committee organized the 11th batch of Certificate Course on Master in Business Finance at Mumbai commenced on 24th June, 2017.
 - ❖ The Committee organized the 11th batch of Certificate Course on Master in Business Finance at Delhi commenced on 24th June, 2017.
- The Committee conducted three residential programmes for the participants of Certificate Course on Master in Business Finance during the months of May, August and November 2016.
- The Committee conducted the examinations for the participants of Certificate Course on Master in Business Finance of all three levels where each level contained two papers, during the months of July - September 2016 and February - March, 2017.

Industry/Corporate Initiatives/Programmes

- The Committee organized a five days' Workshop on Hedge Funds and Private Equity in July, 2016 at ICAI Tower, Mumbai which was hosted by WIRC of ICAI. The workshop received an overwhelming response from the participants. Total number of 104 participants registered for this workshop.
- The Committee organized a Workshop on Impact of GST – Real Estate Sector on 22nd January, 2017 at ICAI Tower, Mumbai. The workshop received an overwhelming response from the participants.

Harnessing technology to educate members

The Committee organised Webcast on Key Initiatives by GOI to bolster growth – Startup India, Standup India, Make in India and Mudra bank - Professional opportunities emanating out of such key initiatives on 24th June, 2016 and on Demonetisation - Taxation, FEMA, Accounting issues - Panel discussion on 24th November, 2016.

Recent initiatives of the Committee

Seeing the relevance and response to the Certificate Course on Master in Business Finance, the Committee made proposal for conversion of the same into a Post Qualification Course in Management and Business Finance which was approved by the Council and thereafter by the Central Government. The Final Notification making amendments in Regulation 204 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 was issued on 25th May, 2017.

7.4 Committee for Members in Entrepreneurship & Public Services

The objective of the Committee is to have a mutually advantageous live connect between ICAI and the members in Entrepreneurship or Public Services and to work on the aspects realizing mutual benefit of such members as well as the other members of the ICAI. This would help to create and enlighten additional opportunity areas for young Chartered Accountants and thus contribute to furthering the profession. The following activities were undertaken by the Committee from 1.4.2016-30.6.2017:

Residential Summit of ICAI Members in Public Service

With a view to elicit views of members in Public Service on matters of national importance which ICAI can take up for research and further study and also to brainstorm on various matters of current significance for response by the profession, the Committee organized a Residential Summit of ICAI Members in Public Service on the theme 'Accountancy Profession for Economic Development' from December 16-18, 2016 at Kochi. The Workshop was inaugurated by CA. Suresh Prabhakar Prabhu, Hon'ble Union Minister of Railways via video message. CA. K. Rahman Khan, Hon'ble Member of Parliament, Rajya Sabha, CA. (Dr.) Kirit Somaiya, Hon'ble Member of Parliament, CA. Subhash Chandra Baheria, Hon'ble Member of Parliament and Hon'ble Justice (CA.) Anil R. Dave, Retired Judge, Supreme Court of India presented their key note address at the Summit. CA. (Dr.) Kirit Somaiya, Hon'ble Member of Parliament unveiled the profile booklet of the participants of the Residential Summit of ICAI Members in Public Service.

The Summit was attended by 34 participants who were senior members of the profession in Public service which included Parliamentarians, senior members in politics, Judges, Officers of Indian Administrative and other Civil services, Members of the Tribunal and Member in Journalism.

Regional Meets of ICAI Members in Public Service

As decided in the Kochi Residential Summit, the Committee organised regional meets of ICAI members in Public Service in different regions. First such meet was organised in Mumbai on January 13, 2017 followed by Regional meet in Delhi on April 12, 2017 and in Kolkata on June 22, 2017.

The Regional meet in Mumbai was attended by 13 senior ICAI members in Public Service. The meet in Delhi was attended by 16 senior members of the profession in Public service including CA. K. Rahman Khan, Hon'ble Member of Parliament, Rajya Sabha, CA. Subhash Chandra Baheria, Hon'ble Member of Parliament from Bhilwara, Justice (CA.) Anil R. Dave, Hon'ble Retired Judge, Supreme Court of India and meet in Kolkata was attended by 9 senior members of the profession in Public service.

The members during various interactions shared their views on various important matters for furthering the image of ICAI which includes strengthening PR, assisting Government department in shifting to accrual accounting; GST implementation and awareness initiatives and alike.

Live Webcast on "Opportunities for Young Chartered Accountants in Civil Services" on 13th May, 2017

The Committee jointly with the Young Members Empowerment Group of the Committee for Capacity Building of Members in Practice (CCBMP), ICAI had organised a Live Webcast on "Opportunities for Young Chartered Accountants in Civil Services" on 13th May, 2017.

CA. Mahaveer Singhvi, IFS, Joint Secretary, Ministry of External Affairs moderated the discussion. CA. Ravinder, IAS, Private Secretary to Minister, Ministry of Tourism & Culture & CA. Namit Mehta, IAS, Additional Commissioner VAT, Jaipur were the panelist for the session.

The objective of the Webcast was to motivate and guide our young Chartered Accountants aspiring to join Civil Services. The webcast was viewed by over 550 ICAI members.

7.5 Committee for Co-operatives & NPO

The major aim of the Committee is to promote uniform accounting framework for Cooperatives and NPOs, to encourage prudent financial management in the sectors and to formulate guidelines for state-wise auditors' empanelment. Also the members are kept updated about the latest developments in Cooperatives and NPOs through seminars, practical workshops, training programmes etc.

A. Representations made:

- A Representation dated 24th August, 2016 submitted to Commissioner for Cooperation and Registrar of Cooperative Societies, State of Maharashtra, Pune regarding manner of audit appointments and other audit related issues. The issues that were brought out in the representation were audit allotment by District Deputy Registrars (DDRs), Empanelment Process, Audit fees prescribed for Co-operative housing societies, seeking clarification on the Interim Order of Bombay HC Aurangabad bench dated 02.05.2016 on Audit fee GR dated 29.10.2014, non availability of the Circulars on Department website and elsewhere, difficulties in login and in uploading of documents on the website etc.
- A Representation dated 4th October, 2016 submitted to the Joint Commissioner, Cooperatives, Madhya Pradesh, Bhopal regarding carrying out the Audit work in Cooperative Societies in Madhya Pradesh. The representation

brought out the Professional competence of Chartered Accountants to perform audit and different and distinct areas of expertise of Chartered Accountants.

- A Representation dated 28th December, 2016 submitted to Hon'ble Minister, Cooperation, Marketing and Textiles, Maharashtra, Mantralaya, Mumbai regarding Cooperative Panel Auditors. The representation highlighted the professional competence of Chartered Accountants to perform financial audit and the distinct areas of expertise of Chartered Accountants.

B. Programmes/ Seminars/ Conferences/ Workshop/ Interactive Meet/ Lecture Meeting

- Interactive Meet on Issues & Opportunities for CAs in Co-operatives, NPOs and related fields in April, 2016 at Mumbai.
- Lecture Meeting on All about Stamp Duties including understanding of New Stamp Duty Ready Reckoner 2016 in April, 2016 at Mumbai.
- Seminar on Auditing Standards and Service Tax for Co-operative Societies in June, 2016 at Patna.
- Lecture Meeting on Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 and its implications for builders, developers, stakeholders, implications on redevelopment projects and enhanced role of Chartered Accountants in June, 2016 at Mumbai.
- Seminar on recent developments in audit of Co-operative Housing Societies and Service tax implications, Online filings and on Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 in June, 2016 at Thane.
- Seminar on NPOs, Societies and Cooperative Societies in August, 2016 at Visakhapatnam.
- Khandesh Co-operative Conclave -2016 in November, 2016 at Jalgaon.
- Workshop on Recent developments in Real Estate Sector including the Impact of Demonetisation, Issues and Way Forward under RERA, GST including Valuation and ITC and Revised Development Plan and New FSI Rules in December, 2016 at Mumbai.

C. Webcast

The Committee organized a Webcast on Key Policy decisions and various initiatives in Maharashtra Cooperative Sector including empanelment process for audit and other audit and administration related issues and on latest developments addressed by Shri Chandrakant Dalvi, Commissioner for Cooperation and Registrar of Cooperative Societies, Maharashtra in October, 2016 at Pune.

7.6 Legal Advisory Wing

The following important activities were undertaken by the Legal Wing during the period:

Rendering effective legal assistance in the form of legal opinions, studies and reports, as required from time to time by the Council /Executive Committees / various Non Standing Committees and departments of the ICAI.

Providing of appropriate legal advice on a diverse range of substantive and procedural questions of law arising in administrative functioning of the ICAI, to firmly secure the interest of ICAI, as required by the operational departments.

Supervising and overseeing the review, negotiations, drafting and vetting of contracts, tender documents and other legal documents, as required by the operational departments and various committees of ICAI.

Serving on various Standing and non-standing Committees, Study groups and task force, as required, to take care of legal niceties in framing of policies.

Advising in the matters of taking recourse to legal remedies whenever necessary and assisting the operational departments and committees in preparing of reply to legal notices received.

Total number of cases disposed of by the High Courts concerned under Section 21(6) during the period from 1.4.2016 to 31.3.2017 are 19. A total of 151 cases forwarded by the Council under Section 21(5) to various High Courts are pending.

7.7 Infrastructure Development Committee

A policy has been framed by ICAI for development of Infrastructure of Branches and Regional Councils/office specifying the guidelines of Infrastructure Development, cost factors involved and the procedures to be adopted. The Committee was constituted in the year 2014 for implementation of the policy with regards to building proposal that will be received from various Branches/Regional Councils of ICAI.

Purchase of New Infrastructure after formulation of Infrastructure Policy

1. Kannur Branch, SIRC- Land purchased from private party
2. Jalandhar Branch, NIRC-Govt. Land from Jalandhar Improvement Trust
3. Jabalpur Branch, CIRC-Govt. Land from Jabalpur Development Authority
4. Goa Branch, WIRC-Land purchased from private party
5. Gurgaon Branch, NIRC - Govt land from HSIIDC
6. Moradabad Branch, CIRC-Govt. Land from Moradabad Development Authority
7. Pali Branch, CIRC-Govt. Land from Municipal Council, Pali
8. Agra Branch, CIRC-Govt. Land from UP Awaas and Vikas Parishad
9. Gorakhpur Branch, CIRC-Govt. Land from Gorakhpur Development Authority.
10. Karnal Branch, NIRC - Govt land from HSIIDC
11. Kishangarh Branch, CIRC – Nagar Parisad Kishangarh.
12. Latur Branch, WIRC – Land purchased from private party

Construction Proposal approved By the Committee

1. Ajmer Branch, CIRC
2. Surat Branch, WIRC
3. Hubli Branch, SIRC
4. Bathinda Branch, NIRC
5. Bareilly Branch, CIRC
6. Bhopal Branch, CIRC
7. Jodhpur Branch, CIRC
8. Raipur Branch, CIRC
9. Kannur Branch, SIRC
10. Guntur Branch, SIRC (In-principle approval)

7.8 Right to Information Act, 2005

The Right to Information Act provided the right to information for citizens of India to access the information under the control of Public Authorities in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. The ICAI a statutory body set up by an Act of Parliament i.e. The Chartered Accountants Act, 1949 is a public authority as envisaged under section 2(h) of the RTI Act, 2005. In compliance of the provisions of the RTI Act, 2005 and direction of the Central Information Commission, officers of the ICAI have been designated as Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information officer, First Appellate Authority (FAA) and Transparency Officer.

Disclosure under Section 4(1)(b) of the RTI Act, 2005.

In terms of the Section 4(1)(b) of the Right to Information Act, 2005, necessary disclosures have been made by the ICAI by hosting them on the website of the ICAI www.icai.org and the same are updated from time to time. The number of RTI application received during the year 2016-17 is given in the table below:-

Quarter	Number of applications received and replied
1 st Quarter	149
2 nd Quarter	135
3 rd Quarter	106
4 th Quarter	177

7.9 XBRL

The main objective of XBRL India is Promoting and encouraging the adoption of 'Extensible Business Reporting Language' (XBRL) in India as the Standard for electronic business reporting in India and other kind of business reporting, spreading and promoting knowledge, support the objective of development and promotion of XBRL through development of taxonomies, facilitation of education and training on XBRL, management information and control systems and allied disciplines, etc. in India supported by the Government of India and various Regulatory bodies i.e. Ministry of Corporate Affairs (MCA), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Reserve Bank of India (RBI) etc.

- **Ind AS Taxonomy and Business Rules**

Ministry of Corporate Affairs (MCA) has mandated certain classes of companies to prepare their financial statements as per Indian Accounting Standards (Ind AS) which are converged with International Financial Reporting Standards (IFRS) w.e.f F.Y. 2016-17. In order to have the annual filings of the financial statements from such companies, XBRL taxonomy would be required. Accordingly, a separate taxonomy has been developed on

the basis of Indian Accounting Standards (Ind AS) which has been submitted to the Ministry of Corporate Affairs. On the basis of the taxonomy, set of business rules have also been prepared and submitted to the Ministry of Corporate Affairs.

- **XBRL filing requirements by the Ministry of Corporate Affairs (MCA)**

The Commercial & Industrial (C&I) taxonomy is being used by the Ministry of Corporate Affairs for having annual filings of the financial statements of a select class of companies from the year 2010-11. The taxonomy is updated every year considering the changes in accounting framework. In the year 2016, the C&I taxonomy was revised to meet the new requirements of Companies (Auditors Report) Order, 2016 and few other changes. The corresponding business rules were also revised. The revised C&I taxonomy and business rules were used by the Ministry of Corporate Affairs for having the filings of the financial statements for the year 2015-16 from the companies. In the year 2017, the C&I taxonomy was revised again to incorporate the changes coming from Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 and a few circulars applicable from the Financial Year 2016-17. The revised taxonomy alongwith the revised business rules were submitted to the Ministry of Corporate Affairs.

- **International Activities**

- ✓ XBRL India represented at the XBRL International Conference and Member Assembly meeting held on 7-8th November, 2016 in Singapore and XBRL Asia Roundtable (XART) held on 11th November, 2016 in Singapore.
- ✓ Nominations were sent for the membership of IFRS Taxonomy Consultative Group (ITCG) of the International Accounting Standards Board.

7.10 ICAI-ARF

The Accounting Research Foundation (ARF) was established in January, 1999 as a Section 25 Company (now Section 8 Company under the Companies Act, 2013) of the Institute for doing core research in the areas of accounting, auditing, capital markets, fiscal and monetary policies. The following is the details of the projected completed by this Research Foundation:-

- **Indian Railways** - As a part of the Accounting Reforms project, a pilot study on introduction of accrual accounting was undertaken at North Western Railway, Jaipur and Rail Coach Factory, Kapurthala. The pilot study saw the preparation of accrual based financial statements of these units in addition to the present cash based financial statements. On successful completion of pilot projects, now accrual accounting is being rolled out across all the Zonal Railways and Production Units across Indian Railways on the basis of same methodology and strategy as followed in the pilot study. Hon'ble Finance Minister on 20th December, 2016 released the Accrual Based Financial Statement for the year ended 31st March, 2015 for North Western Zonal Railway along with Accrual Accounting Implementation Manual and Accounting policies in the presence of Hon'ble Minister of Railway, President ICAI, Financial Commissioner, Indian Railways and other senior government officials of CAG, CGA, Niti Aayog, Indian Railways, Department of Posts & Telegraph and other government departments.
- **Power Finance Corporation (PFC) and its subsidiaries** - Project to study the existing compliance environment of PFC's Financial Reporting, to identify the improvement areas and propose a roadmap to establish a Compliance Framework that will enable PFC to effectively deal with these requirements and Strengthen Compliance Management Framework
- **Coal India Limited, Kolkata (Ministry of Power)** - Review of the Capital Expenditure Procurement Process and Policy Compliances Framework

8. OTHER MATTERS

8.1 Annual Function of the ICAI

ICAI celebrated a year of noteworthy achievements at its 67th Annual Function organized on 8th February, 2017 in the Plenary Hall of Vigyan Bhawan, New Delhi. The occasion not only recalled the success that ICAI achieved in the year 2016-17 but also set the tone for its future professional endeavours. Railway Minister CA. Suresh Prabhu graced the occasion as the Chief Guest in the presence of a large gathering including a host of dignitaries from the accountancy profession, Government and other stakeholders. The Chief Guest in his brief but very effective and meaningful presence veritably won the heart and mind of the mammoth gathering, going all out in acknowledging and commending the proactive role being played by his professional fraternity as a partner in nation building. He said that we, as chartered accountants, must find out what best we can contribute to make India far better place than what it is today. At the event, Meritorious CA students, and outstanding Regional Councils, Branches and overseas chapters were also honoured for their accomplishments during the year. The function also witnessed release of various ICAI publications.

8.2 Celebrations of Chartered Accountants Day – 1st July, 2017

ICAI celebrated its Foundation Day on 1st July, 2017 on completing of 68 glorious years at its 5 Regional Councils, 163 Branches and 30 overseas chapters. As per the tradition, the celebrations started with the ICAI flag hoisting event followed by the CA Day function in Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi.

“Chartered Accountants are big pillars of Indian Economy... they are like saints and sages of Indian economic world... they are like doctors of the domain of economy... the name of a CA must be equated with Compliance and Accuracy...,” heralded Prime Minister Shri Narendra Modi in his inimitable style as he delivered a power-packed and thoughtful hour-long address to mark the CA Day, the 68th Foundation Day of the ICAI at a grand function on July 1 at Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. He also launched the ICAI’s Revised Scheme of Education and Training of Chartered Accountancy course on the occasion.

The Prime Minister spoke to a massive gathering consisting of number of Cabinet Ministers, senior bureaucrats, members, students and trade representatives at the event besides lakhs of others watching through ICAI Regional Offices and branches at State Capitals led by Chief Ministers & Finance Ministers of many states and Union ministers. In all, 11 Chief Ministers, 15 state Finance Ministers/Ministers in-charge of GST and 40 Union Ministers participated in the event in 25 State Capitals and in Delhi. In his address, the Prime Minister invited the CA fraternity to be part of the “festival of honesty,” join his government’s resolve of clean economy and urged them to put country before client and work all out for the success of Goods and Services Tax (GST), which he called as “Good and Simple Tax”.

Those who were present on this momentous occasion in National Capital included Union Finance, Defence and Corporate Affairs Minister Shri Arun Jaitley, Ministers of State for Finance Shri Santosh Gangwar and Shri Arjun Ram Meghwal, Union Minister of State with Independent Charge for Power, Coal, New and Renewable Energy and Mines Shri Piyush Goyal, Union Minister of State (Independent Charge) for Petroleum and Natural Gas Shri Dharmendra Debendra Pradhan and Union Minister of State for Information & Broadcasting Col. Rajyavardhan Singh Rathore, AVSM, Revenue Secretary Shri Hasmukh Adhia and Secretary, Ministry of Corporate Affairs Shri Tapan Ray.

Hon’ble Prime Minister’s address was preceded by a Panel discussion on “Impact of GST on Economy/GST – Professional and Business Perspective” at the same venue which was participated by Union Finance Minister Shri Arun Jaitley and Revenue Secretary Shri Hasmukh Adhia and representatives of industry, trade and media. The nearly three-hour long function was telecast live by the national broadcaster Doordarshan. The programme was relayed all over India, through our ICAI Regional Offices and Branches.

8.3 Central Council Library

The Central Council Library of the ICAI caters to the information requirements of its stakeholders. Its aim is to provide comprehensive and up to date collection of primary and secondary print and non-print material to the present and anticipated members, research scholars and officials of ICAI. Library has assumed greater responsibilities of serving committees, departments in imparting knowledge and valuable information through books, e-books, journals, magazines, on-line databases, print newspapers as well as e-newspapers. Central council library is responsible for updating and providing journals and books required for the various committees work.

The Central Council Library is fully computerized and working through Liberty- library management software. Library material including database of Books, Journals & Articles can be searched through Subject, Author, Title, Topic, Keyword, & Publisher wise. These records are available on Internet Online Services www.icaai.org under “know your Institute – Central Council Library”-online search OPAC-Liberty for the books, Journals, articles etc. in the library.

Under the Column “Accountants Browser”, an index of articles relevant to accounting profession are published every month in the journal “The Chartered Accountant”. The “Accountants Browser” is an index of important/Professional Articles with archives of past articles. Reference service from library is also provided to the Researchers & Scholars, faculties, students and members.

A number of online databases have been acquired by the Library, details of which are available on www.icaai.org – Central Council Library. These On-line knowledge databases have been installed in the Central Council Library premises as well as at various Departments and also installed in Regional Council Libraries of ICAI, to facilitate the search for required material by the students, Members, Faculties and the Research Scholars. Several online journals have also been subscribed in the Library. Details of the new resources added in the Central Council libraries at Head office and Noida office library respectively for the period April 2016 to 30th June, 2017, are as follows:

S.No.	Title	Head Office	Noida-Sector 62
1.	Journals (Print)- national & International	61	31

2.	E-Access to Journals subscribed	13	01
3.	Online Resources	12	06
4.	No. of Books added during the period	1049	207

Central Council Library is regularly updating its resources to provide the professional Members, students, faculties, etc. with the latest & up to date knowledge and information.

8.4 Editorial Board

Editorial Board: Enriching Professional Knowledge Base in ‘Letter’ and Spirit

The Editorial Board is a non-standing committee of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) with a MISSION to convey regularly to the members the contemporary professional knowledge and other matters of interest of profession through the journal ‘*The Chartered Accountant*’. The reach and impact of the Journal can be gauged by its circulation figure which stands at more than 280,000 today.

A ‘Brand Ambassador’ of ICAI and the most visible indicator of the Institute’s profile for the members, students and external audiences, *The Chartered Accountant* today matches the global standards of professional Journals. The Editorial Board is continuously surging ahead with its mission to keep the ICAI members and other readers of journal up-to-date on various topics and issues.

Following are the most significant headways made by the Editorial Board between 1st April, 2016 and 30th June, 2017:

Quality and Contemporary Contents:

- ♦ **Wide Range of Topics Covered:** From April 2016 to June 2017 issues of the journal, more than 350 articles/features and reports on various topics were published under various contemporary theme issues.
- ♦ **e-flash on Annual Budgets every year:** In view of the time gap between presentation of Budget in Parliament and actual publication of Budget issue of the Journal, an e-publication of Finance Bill amendments (f-Flash) was conceptualised, developed and hosted on ICAI website and its link mass-mailed to members within 48 hours of actual presentation of Budget in Parliament for real-time update of the members.
- ♦ **The Legal Update Section of the Journal Upgraded:** In further upgrading of one of the most read Legal Decisions section/feature of the Journal as a value-added service, the legal decisions of three new areas – Insolvency Laws and International Taxation Laws and ICAI Cases— have been added in this section of the journal w.e.f June 2017 issue.

Upgradation of Digital Versions of Journal

- **eJournal:** The electronic version of The Chartered Accountant journal, which is available online on ICAI website www.icai.org hi-tech user-friendly e-magazine, was further upgraded and migrated to a completely new eMagazine platform V6 based on the latest HTML5 technology. The new version of e-Journal is faster and more responsive, carrying better user experience and offering better mobile compatibility, which is in line with the expectations of our new generation of chartered accountant.
- **Journal in PDF format:** However, for the added and alternative convenience of readers, particularly for separate content-wise downloads, the journal continues to be hosted in the PDF format and also in Indexed mode. The archives of digital journal are available on ICAI website from July 2002 onwards.
- **Journal on Mobile:** Further, this eJournal is now also available on mobile, compatible on iOS (IPad/IPhone etc.) and Android devices. It can be accessed at <http://www.icai.org/> under ‘e-journal’ tab. The eJournal is also available on ICAI Mobile App.
- **Journal Highlight emailers:** As an add-on service, the highlights of every issue of journal in capsule form and the President Message in the journal are now mass-emailed to all the members.

Encouraging Response to ‘I GO GREEN WITH ICAI’ Initiative

As part of a multifarious Green Drive of the ICAI, a noble initiative ‘*I Go Green with ICAI*’ has been launched by the Editorial Board. In this regard, a micro-website has been made live wherein the green-thinking members and other readers of The Chartered Accountant journal can take the option to opt for various electronic versions of the journal while discontinuing receiving the hard copy, to save trees. In an encouraging response, about 7000 members/readers have logged on to the website and opted to discontinue the hard copy of the journal. The positive response is growing by the day. The ICAI members supportive of this green initiative may go to the link http://www.icai.org/new_post.html?post_id=12763&c_id=240 to register themselves with the ICAI.

8.5 Accountancy Museum of India

Accountancy Museum of India narrates the story and traces the origin and growth of accountancy profession of India and the world. So far, the Museum has established its prototype in the premises of 5 Regional Councils, 13 decentralised offices and 107 Branches of the Institute, to promote the rich cultural heritage of the profession. The Museum showcases rare historical and important artefacts, documents, images and manuscripts, etc. in the premises. It endeavours to comment on the accounting practices and practitioners in early, medieval and modern India.

Attracting Attention of Stakeholders

Since its establishment in 2009, apart from regular visits of members and students of the Institute, the Museum has been constantly attracting commerce and management graduates and postgraduates from various institutions of NCR region to its premises. Institutionalised visits have been made to the Museum. One of the colleges of Delhi University has sent its third batch of commerce postgraduate students in a row.

Website of the Museum

Website of the Museum, i.e. <http://ami-icai.org/>, has been made functional and the work required a detailed photography of the Museum's premises. The Museum's website houses all relevant information meant for the prospective visitors, donors, researchers, etc., and other stakeholders of the Museum.

Revision of Existing Digital Panels and Those on New Themes/ Series

With some of the digital panels thoroughly revised, work (i.e. text for digital panels) on two new themes/ series, viz. world accountancy and fathers of Indian accountancy, which are to be installed, are at an advanced stage.

8.6 Amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988

The draft amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988 inter-alia to facilitate the implementation of the new Scheme of Education of Training as approved by the Council were submitted to the Central Government. These draft amendments after in-principle approval of the Government were published in the Gazette of India in April, 2016 inviting public comments. The Comments received were considered by the Council at its meeting held in October, 2016. Based on the comments received the Council decided to modify certain draft amendments and so modified draft amendments were once again forwarded to the Central Government for its final approval in 2016. However, to meet the requirement of sub-ordinate legislation, these draft amendments were once again notified in the Gazette of India inviting public comments in December, 2016 and after complying with the due process were once again submitted to the Central Government for approval. The Central Government accorded its final approval in May, 2017. The final notification containing these amendments was published in the Gazette of India on 25th May, 2017 and accordingly these amendments have been brought into force from the said date.

9. MEMBERS

9.1 Membership

During the year ended 31st March, 2017, 16,970 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 2,70,307 as on 1st April, 2017.

During the year ended 31st March 2017, 6,712 associates were admitted as fellows, in comparison to the figure of 2,744 in the previous year. The details of total numbers of members as on 1.4.2017 is as under:

Category of Members	Fellow (1)	Associate (2)	Total of Columns (1) and (2)
In Full Time Practice	72263	48576	120839
In Part-time Practice	2866	5417	8283
Not in Practice	13593	127592	141185
Total	88722	181585	270307

9.2 Convocation

Since November 2008, the ICAI has been organizing Convocation to confer membership certificates to newly enrolled members. The "Convocation 2016" was organized in January, 2017 at the following places:

1. Ahmedabad
2. Mumbai
3. Pune

- | | | |
|------------|--------------|--------------|
| 4. Chennai | 5. Hyderabad | 6. Kolkata |
| 7. Jaipur | 8. Kanpur | 9. New Delhi |

9.3 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund provides financial assistance to needy persons who are or have been members of the ICAI as well as their dependents, for maintenance, their emergent educational and medical needs etc. The financial and other particulars of the Fund are as follows:

Details of Membership

1.	Total Life Members as on 31 st March, 2016	128500
2.	Total Life Members as on 31 st March, 2017	132883
3.	Total Additions of New Life Members (as on 31 st March, 2017)	4383

Details of Financial Particulars

	During the year ended 31 st March, 2017 (Rs.)	During the year ended 31 st March, 2016 (Rs.)
1. Total Assistance provided	1,13,28,500	1,09,34,500
2. Administrative Expenses	567	582
3. Surplus of the Fund during the year	69,93,000	71,96,531
4. Balance of the Fund	1,63,54,000	93,60,845
5. Balance of Corpus	18,49,63,000	17,21,68,397

The details of contribution received during the year is as under:-

Contribution as life Membership	Rs.1,27,95,000/-
Contribution as Annual Membership	Rs. 19,57,000/-
Voluntary contribution	Rs. 25,29,000/-
Total	Rs.1,72,81,000/-

9.4 S. Vaidyanath Alyar Momorial Fund

During the year ended 31st March, 2017, 100 scholarships of the value of Rs.1000/- each per month are to be given to the students undergoing the articulated training. The number of life membership of the Fund increased from 7370 as on 31st March, 2016 to 7682 as on 31st March, 2017. The balance in the credit of the Fund was Rs. 49,60,000/- as on 31st March, 2017 as against Rs. 39,91,584/- as on 31st March, 2016.

9.5 Chartered Accountants Student's Benevolent Fund (CABF)

The Fund was established in August, 2008 with the aim and objective to provide financial assistance to the students registered with ICAI. During the year ended 31st March, 2017, 513 articulated assistants who are registered for IPCC and IIPCC have been granted assistance @ Rs. 1500 p.m. and 205 articulated assistants who are registered for final course granted financial assistance @ Rs. 2000/- p.m. for a period of one year. The balance in the credit of the general fund was Rs. 12,59,75,000/- as on 31st March, 2017 as against Rs. 11,43,35,000/- as on 31st March, 2016.

10. Board of Studies:

The Board of Studies is responsible for the administration of the Chartered Accountancy curriculum and imparting theoretical instruction to approx. 2,50,656 students undergoing Chartered Accountancy Course. The significant initiatives and achievements of the Board during the period are mentioned below:-

I. Educational Inputs

Review of Education and Training: The Chartered Accountancy Course being dynamic in nature is reviewed periodically so as to maintain the edge of the profession vis-à-vis contemporary economic developments. The ICAI recently reviewed its existing Scheme of Education and Training and after following a detailed methodology ranging over a period of three years, it drafted a Revised Scheme of Education and Training. After a series of detailed discussion with the stakeholders and public exposure, the Revised Scheme was finalized and has been made applicable from 1st July, 2017.

Revision of Study Materials: As a part of continuous process of updating the knowledge of students, the contents of

study materials at Intermediate (IPC) and Final levels have been updated/ revised. In addition to above, following material were also brought out and hosted on website with free downloading facility:

- 1) Digest of Select Cases
- 2) Supplementary Study Materials:
 - Accounting
 - Business Laws Ethics and Communication
 - Taxation
 - Corporate and Allied Laws
 - Direct Tax Laws and Indirect Tax Laws
- 3) Revision Test Papers and Suggested Answers

Development of Chartered Accountants Curriculum of Institute of Chartered Accountants of Bhutan (ICAB):

The World Bank awarded ICAI the project of providing “Consultancy service for development of Chartered Accountants Curriculum of ICAB, drafting Bylaws for ICAB and Rules and Regulations for AASBB”. The Board developed the Scheme of Education and Training, Curriculum and Study Material of all subjects at all levels well before the target date.

II. IT Initiatives

ICAI Cloud Campus provides One-Stop-Window for information, enrolment, educational, administrative, examination, and other requirements of Students for the CA Course. Moving ahead from the brick-n-mortar campus system, it provides distance education for the CA Course at the doorsteps of Students at the click of a button. It provides the following distance education facilities FREE of cost:

- **Video Lectures:** Video Based Training (VBT) Lectures for practical subjects like Accounts, Taxation, Financial Management, Cost Accounting etc. are available on the ICAI Cloud Campus, which aim to teach step-by-step practical problem solving process on the blackboard. Now, the Board has started to record and upload video lectures for theoretical subjects also for better conceptual clarity. Currently, 495 lectures covering 428 hours have been hosted on the Cloud Campus, as on June 20, 2017.
- **Webcasts:** LIVE webcasts had been organized on the methodology to crack each subject for the Final and Intermediate (IPC) May, 2017 examination, in the months of March-April, 2017. Specialized webcasts followed by One-Day Seminars are also being organized with the help of Regional Councils and Branches, on topics such as GST, Concurrent Audit etc. Recordings of these webcasts are available on the ICAI Cloud Campus for later viewing.
- **e-Learning on Students LMS:** E-Lectures of 797 hours are available as on June 20, 2017. Self-Assessment Quiz are also available for almost all the chapters.
- **BoS Knowledge Portal:** The BoS Knowledge Portal provides all educational content for CA Course.
- **Articles Placement Portal:** The Articles Placement Portal link enables students to register online and get selected for practical training in CA Firms in their preferred location.
- **Online Registration Portal for GMCS/ OC/ ITT Courses:** The Online Registration Portal enables students to register online for GMCS/ OC/ ITT Courses, select convenient batches at preferred location, batch transfer, faculty allocation, course scheduling, feedback submission and certificate generation.

III. Other Initiatives

Reading Rooms: 146 Libraries-cum-Reading Rooms and 41 Additional Reading Rooms are being operated by Regional Councils and Branches.

Oral Coaching Class

(i) By Regional Councils and Branches: Oral Coaching Classes have been organized by the Regional Councils and Branches to provide class room teaching to the students of CA Course. At present, 62 centres are organizing Coaching Classes for the students, out of which 26 centres are organizing for CPT, 24 are organizing IPCC and 12 centres are organizing for Final students.

(ii) Accredited Institutions: Oral coaching classes organized by the Accredited Institutions supplements the efforts of ICAI by providing quality classroom coaching at a reasonable cost. At present, 53 Institutions are providing CPT Course classes, 11 Institutions are providing IPC Course classes and 2 Institutions are providing Final Course Classes to our students.

Mock Tests: With a view to encourage the students to evaluate their preparation for the examinations, Mock Tests for Intermediate (IPC) / Final and CPT Level were organised through Regional Councils and Branches for May / November and June / December main examinations- 20,129 students appeared at Intermediate and Final Level Series-I & II for May, 2016 and 17,561 students appeared at CPT Level for June, 2016.

20,578 students appeared at Intermediate and Final Level Series-I & II for November, 2016 and 7,500 students appeared at CPT Level for December, 2016.

14,135 students appeared at Intermediate and Final Level Series-I for May, 2017 and 909 students appeared at CPT Level for June, 2017.

ICAI Gold Medal/Endowment Fund: New endowment was created for the award of Gold Medal with Tejpur University, Napaam, Assam.

Toll-Free Helpline for CA Students: The Board of studies has initiated toll-free help line service from May 11, 2017 to answer queries and grievances of CA students from across the country. Number – 18001211330 works from 10 AM to 5:30 PM Monday to Friday. The purpose of this service initiative is to provide timely information both generic and subject specific in nature to students as per their requirement. The subject faculties at BOS will answer subject specific queries as per the time slot of 3 PM to 4 PM. The facility will serve as a single point of contact for students located nationwide. The number will serve as a generic as well as subject specific help line for the entire student population of ICAI.

Debate Competitions: The Debate Competitions at Branch Level were organised by 51 Branches including Regional Councils wherein 1,160 students participated at these programmes and at Regional Level the Debate Competitions were organized by WIRC, SIRC, EIRC and CIRC wherein 30 students appeared.

CA Students' Festivals: During the year, 44 Branches including 3 Regional Councils, organized 44 CA Students' Festivals wherein 14,756 students attended these programmes.

Sports Competitions: During the year, 62 Branches including 3 Regional Councils, organized 73 Sports Competitions wherein 9,983 students participated.

IV. Development Programmes

ITT and Advanced ITT Course: As of now, 156, POUs are organizing ITT and Adv. ITT Course respectively across the country. During the period (1st April, 2016-30th June, 2017), the details of batches and students are asunder:

Course Name	No of Batches	No of Students
Information Technology Training	1974	57,288
Advanced ITT	314	7,855

Development Programmes: A physical FDP has been organized for Advanced ITT course from April 06-08, 2016 at Kolkata wherein 34 Faculty were trained.

Practice Manual: A Practice Manual with CD has been introduced for ITT Course to provide greater practical hands-on training as a part the course.

Revision of Study Materials: Development of course contents of ICITSS (IT) and AICITSS (Adv. IT) is in progress as per the approved syllabus by the Council under the revised Scheme of Education and Training.

Online Payment: The ICAI has started Online Payment facility for the students who are registering in soft skill courses through Online Registration Portal. Using this facility, students would be able to pay course fees online using Credit/Debit card from all across the Country. This would save lot of time and efforts of the students for generating Demand Drafts from the Banks. This initiative will also support the Prime Minister's Digital India campaign.

Four Weeks' Residential Programme on Professional Skills Development for students: 11 batches at Centre of Excellence, Hyderabad were held during the year and 505 students were trained.

Short Term Course/ Workshop on English Speaking, Writing Skills and Business Communication: 12 branches including two Regional Councils organized 15 Short Term Course/ Workshop on English Speaking, Writing Skills and Business Communication wherein 704 students attended the workshops.

Special Counselling Programmes (How to Face CA exam?): During the year 73 Special Counselling Programmes

were organized by 42 branches, including 3 Regional Councils wherein 5,615 students attended these programmes.

One-Day Seminars: During the year, 217 One-day Seminars were organized by 61 Branches including 4 Regional Councils wherein 20,559 students attended these Seminars.

Elocution Contests: Branch Level Elocution Contests were organized by 90 Branches, including 5 Regional Councils. Apart from this, 5 Regional Level Contests were organized wherein 1,256 students participated. All India Elocution Contest was held at Kochi, Ernakulam on 27th November, 2016 wherein 14 students participated.

Quiz Contests: Branch Level Quiz Contests were organized by 92 Branches, including 5 Regional Councils. Apart from this, 5 Regional Level Contests were organized wherein 1,814 students participated. All India Quiz Contest was held at Kochi, Ernakulam on 27th November, 2016 wherein 10 students participated.

V. MoUs/ MRAs/ Recognitions/ Other Arrangements

Recognition of CA Course for Ph.D Programme: With the constant follow up with various Universities, the Board of Studies has been successful in obtaining recognition for CA Course from 101 Universities, 6 IIMs and 2 IIT Bombay & Madras (Total 109) for the purpose of pursuit of Ph.D./Fellow Programme.

VI. Conferences/ Conventions/ Seminars and other activities: Conferences/ Conventions/ Seminars and other activities:

- National Convention, All Regional student Conference, All India Conference and International Conference for CA students: During the period, 27 National Conventions were organized at various places in the country in addition to All Regional Student Conference at Ahmedabad, All India Conference at Ernakulam and International Conference at Hyderabad and around 30,400 students participated in these students conferences.
- Regional/ Sub-Regional/ National Conclave/ CA Students Conference for CA Students: During the period, 13 National Conclaves, 3 CA Students Conference were organized at various places in the country, besides 1 Regional Conferences and 6 Sub-Regional Conferences and around 11,700 students participated in these students conferences.

Joint Seminars with Universities: Joint Seminars were organized with Four Universities spread across the country.

Curtain Raiser function for International Yoga Day: The Board of Studies had organized the Curtain Raiser Programme for International Yoga Day under the aegis of Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Government of India on 3rd June, 2016 at Mumbai. The event was inaugurated by Hon'ble Minister of State Shri Shripad Yesso Naik as Chief Guest and Vice-President, ICAI also graced the occasion as Guest of Honour and shared their words of wisdom with more than 1000 members and students on the benefits of Yoga as a part of life process. The event was also graced by Shri Anil Kumar Ganeriwala, Joint Secretary, Ministry of AYUSH, Chairman, BOS, Vice-Chairman, BOS and few Central Council Members. Dr. Shahid A. Merchant, Founder Member, Lilavati Hospital addressed the participants on the topic "My Secret of Healthier Longer and Happier Life" whereas Smt. Hansa J. Yogendra, Director of the Yoga Institute addressed the participants on the topic "Lifestyle Management where Yoga is way of Life". The programme was well appreciated by the Ministry of AYUSH as well as all participants.

Teachers' Day on 5th September, 2016: The Board of Studies celebrated Teachers' Day across the country through Regional Councils and Branches on 5th September, 2016 so as to have a strong Teacher and Student relationship amongst the CAs and the CA Students. To create a feel of reverence and gratitude in students for their mentor the Board facilitated the students with few e-cards and SMS quotes. During the programme students' activities viz. Elocution Contest, Debate Competition and Chess Competition were also conducted by them. President, ICAI along with Central Council Members at Centre of Excellence on that day addressed Members at large and Students fraternity through live Webcast organized by Board of Studies on 5th September, 2016 from CoE, Hyderabad. The recorded address of Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister of India on Teachers Day - Mann Ki Baat was also shared with Members and Students through Webcast.

VII. Scholarships granted to students

The Board of Studies awards Scholarships twice a year under various categories, namely Merit, Merit cum need, Need Based and Weaker Sections, Endowment. Accordingly, during the year, the Board of studies awarded 575 Scholarships to selected students under above categories.

VIII. Career Counselling Group

The erstwhile Career Counselling Committee which was formed in the month of February, 2015 with an objective to promote the Commerce Education with special focus on CA course among Secondary, Senior/ Higher Secondary, Graduate/ Post Graduate students as well as other stakeholders was converted into Career Counselling Sub-Group under

Board of Studies in the Council year 2017-18.

Activities at a Glance

Commerce Wizard-2016: A Talent Search Test for the Students of Class IX,X,XI & XII

The Commerce Talent Search Test called as ICAI Commerce Wizard -2016 is a diagnostic test that measures the concept understanding ability of a student of Class IX & X and XI & XII.

The award function of ICAI Commerce Wizard-2016 conducted by the Committee was graced by Shri Vijay Goel, Hon'ble Union Minister of State for Youth Affairs & Sports, besides the President, ICAI, Vice President, ICAI & other council members. The Secretary, Council of Higher Secondary Education, Manipur also attended the award function. The Award function was preceded by a talk on budget by CA. Girish Ahuja.

National/ World Commerce Education Day on 10th November, 2016

The Committee celebrated National/ World Commerce Education Day on 10th November, 2016 with the theme "Expanding Horizons of Commerce Education". National/ World Commerce Education Day celebrated as one of the main Commerce festivals in India this year during which students of the schools and colleges showcase their talent as well as hosting the career counseling programmes across India as well as abroad organized by the Career Counseling Group.

Exclusive website of CCC in Social Media Platform

In an exclusive website of the Group i.e. ccc.icai.in, is in place to promote the Commerce Education with special focus on CA course amongst Secondary, Senior/ Higher Secondary, Graduate/ Post Graduate students as well as other stakeholders. The aforesaid website educate students about the glorified world of Accountancy Profession. This website also provided a platform for choosing an excellent career with special reference to Commerce education particularly Accountancy education and help them in deciding the right career choice in accountancy education available to them.

The Group brought out its contents in social media platform, to promote the Commerce Education with special focus on CA course amongst Secondary, Senior/ Higher Secondary, Graduate/ Post Graduate students as well as other stakeholders. The aforesaid various social media platform like Facebook, Twitter, Google+, Youtube & LinkedIn, facilitate in creating buzz, post updates, starting discussions, sharing links, promotional campaigns, promote blogs/ feeds, posting of photos & documents, creating twitter handler, customised for Contact form/ Registration form for the same etc. to promote the Commerce Education with special focus on CA course.

DVD on "Chartered Accountancy Course: An excellent Career in Focus with endless opportunities"

The Committee brought out a DVD on "Chartered Accountancy Course: An excellent Career in Focus with Endless opportunities" containing significant details about the CA Course. This DVD will be very useful to the new aspirants for CA course but also handy reference to guide them and serve as repository for students aspiring to become Chartered Accountants. This DVD will also be reference material for students to look forward for Chartered Accountancy course which bring Independence, fulfillment, respect, name & fame and a challenging Career ahead.

11. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

The ICAI has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively. Currently it has 163 Branches, 30 Chapters outside India and 15 Regional Libraries all over India.

11.1 Award for Best Regional Council, Best Branch of Regional Council, Best Students' Association and Best Branch of Students' Association.

These awards are given by the ICAI every year. The awards are given on the basis of overall performance and established norms. For the year 2016 these Shields were awarded at the Annual Function held on 8th February, 2017 to the following winners:-

1. Best Branch of Regional Councils

- | | | |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. Mega Category - | First Prize | : Ahmedabad Branch of WIRC of ICAI |
| | Second Prize | : Pune Branch of WIRC of ICAI |
| 2. Large Category - | First Prize | : Nashik Branch of WIRC of ICAI |
| | Second Prize | : Ernakulam Branch of SIRC of ICAI |
| 3. Medium Category- | First Prize | : Aurangabad Branch of WIRC of ICAI |
| | Second Prize | : Siliguri Branch of EIRC of ICAI |
| 4. Small Category - | First Prize | : Bhilai Branch of CIRC of ICAI |

- ## 11.2 Decentralised Offices

Mumbai	Chennai	Kolkata	Kanpur	New Delhi	Ahmedabad
Bangalore	Hyderabad	Pune	Jaipur	Nagpur	Surat
Vadodara	Thane	Ernakulam	Coimbatore	Indore	Chandigarh

The Council wishes to place on record its heartfelt gratitude to Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Union Finance, Defence and Corporate Affairs Minister Shri Arun Jaitley, Ministers of State for Finance Shri Santosh Gangwar and Shri Arjun Ram Meghwal, Union Minister of State with Independent Charge for Power, Coal, New and Renewable Energy and Mines Shri Piyush Goyal, Union Minister of State (Independent Charge) for Petroleum and Natural Gas Shri Dharmendra Debendra Pradhan, Union Minister of State for Information & Broadcasting Col. Rajyavardhan Singh Rathore, AVSM, Hon'ble Union Minister of Railways, CA. Suresh P. Prabhu, Revenue Secretary Shri Hasamukh Adhia and Secretary, Ministry of Corporate Affairs Shri Tapan and Ray other dignitaries who were kind enough to grace the various programmes of the ICAI.

The Council also places on record its heartfelt gratitude to Hon'ble Union Ministers Shri M. Venkaiah Naidu, Shri Bandaru Dattatreya, Shri M.J. Akbar, Shri Kalraj Mishra, Ms. Anupriya Patel, Shri Radha Mohan Singh, Shri Ashok Gajapathi Raju, Shri Shripad Yasso, Gen. V.K. Singh, Ms. Uma Bharti, Mrs. Maneka Gandhi, Shri Birender Singh, Shri Y.S. Chowdary, Shri Vijay Sampla, Mrs. Nirmala Sitharaman, Shri Thawar Chand Gahlot, Dr. Jitendra Singh, Shri Jayant Sinha, Shri Sudarshan Bhagat, Shri Mansukh Lal Mandavia, CA. Suresh P. Prabhu, Shri Prakash Javadekar, Shri Ananth Kumar, Shri Sadananda Gowda, Dr. Harsh Vardhan, Shri Narendra Singh Tomar, Shri Nitin Gadkari, Dr. Subhash Bhamre, Shri Jual Oram, Shri P.P. Chaudhary, Shri Vijay Goel, Shri Babul Supriyo, Shri Rajen Gohain and Hon'ble Chief Ministers of States Shri Sarbananda Sonowal, Shri Vijay Rupani, Shri Yogi Adityanath, Shri Keshav Prasad Maurya, Shri Pema Khandu, Shri Manohar Parrikar, Shri Manohar Lal Khattar, Shri Raman Singh, Shri Devendra Fadnavis, Smt. Vasundhara Raje, Shri Trivendra Singh Rawat, Shri Nongthombam Biren Singh and also State Ministers Shri Etela Rajender, Shri Rajesh Agarwal, Shri Surya Pratap Shahi, Smt. Rita Bahuguna Joshi, Shri Om Prakash Rajbhar, Shri Brijesh Pathak, Shri Swatantra Dev Singh, Smt. Swati Singh, Shri Mohsin Raza, Shri Sandeep Singh, Shri Baldev Aulakh and Shri Suresh Pasi. Shri Vijendra Prasad Yadav, Capt. Abhimanyu, Shri D Jayalkumar, Shri Amar Agarwal Shri Amar Kumar Bauri, Shri Jayant Mallayya, Shri Sudhir Mungantiwar, Shri Sashi Bhusan Behera, Shri Prakash Pant, Adv. Mathew T Thomas, Prof. Vasudev Devnani, Dr Neelkanth Tiwari who had graced our CA Day Celebrations at various parts of the country.

The Council also desires to place on record its sincere appreciation to the various functionaries at State level who graced programmes organised by the organs of the ICAI.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/ being initiated by them, pursuant to such initiatives.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2016-17 and thereafter by all officers and employees of the ICAI.

STATISTICS AT A GLANCE MEMBERS REGISTERED

(From 1st April, 2007)

TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1 st April, 2007	Associate Fellow Total	31159 16896 48055	18237 13646 31883	7829 6488 14317	9642 8882 18524	14182 12880 27062	81049 58792 139841
1 st April, 2008	Associate Fellow Total	32364 17646 50010	19203 14034 33237	7939 6738 14677	10045 9472 19517	14642 13398 28040	84193 61288 145481
1 st April, 2009	Associate Fellow Total	34294 18442 52736	20666 14516 35182	8193 7002 15195	10578 10007 20585	15951 13951 29902	89682 63918 153600
1 st April, 2010	Associate Fellow Total	36390 19181 55571	21733 15076 36809	8512 7192 15704	11252 10615 21867	17104 14461 31565	94991 66525 161516
1 st April, 2011	Associate Fellow Total	38608 19831 58439	22998 15612 38610	9154 7406 16560	12329 11182 23511	18547 14943 33490	101636 68974 170610
1 st April, 2012	Associate Fellow Total	45273 20510 65783	25505 16132 41637	11069 7578 18647	15963 11720 27683	23332 15431 38763	121142 71371 192513
1 st April, 2013	Associate Fellow Total	52846 21522 74368	28020 16918 44938	13258 7815 21073	20606 12327 32933	27743 16051 43794	142473 74633 217106
1 st April, 2014	Associate Fellow Total	56595 22313 78908	29401 17460 46861	14035 8007 22042	22978 12915 35893	29467 16508 45975	152476 77203 229679
1 st April, 2015	Associate Fellow Total	60229 22838 83067	30126 17864 47990	14514 8137 22651	24702 13441 38143	31137 16986 48123	160708 79266 239974
1 st April, 2016	Associate Fellow	64235 23700	31919 18495	15046 8223	27353 14071	32774 17521	171327 82010

	Total	87935	50414	23269	41424	50295	253337
1 st April, 2017	Associate	67746	33591	15580	30036	34632	181585
	Fellow	25742	19711	8718	15618	18933	88722
	Total	93488	53302	24298	45654	53565	270307

MEMBERS*(From 1st April, 1950)***TABLE II**

	Associate	Fellow	Total
As on 1 st April, 1950	1,120	569	1,689
As on 1 st April, 1951	1,285	672	1,957
As on 1 st April, 1961	4,059	1,590	5,649
As on 1 st April, 1971	7,901	3,326	11,227
As on 1 st April, 1981	16,796	8,642	25,438
As on 1 st April, 1991	36,862	22,136	58,998
As on 1 st April, 2001	51,603	44,789	96,392
As on 1 st April, 2002	54,666	47,064	1,01,730
As on 1 st April, 2003	60,619	49,637	1,10,256
As on 1 st April, 2004	63,384	52,707	1,16,091
As on 1 st April, 2005	68,052	55,494	1,23,546
As on 1 st April, 2006	73,778	57,168	1,30,946
As on 1 st April, 2007	81,049	58,792	1,39,841
As on 1 st April, 2008	84,193	61,288	1,45,481
As on 1 st April, 2009	89,682	63,918	1,53,600
As on 1 st April, 2010	94,991	66,525	1,61,516
As on 1 st April, 2011	1,01,636	68,974	1,70,610
As on 1 st April, 2012	1,21,142	71,371	1,92,513
As on 1 st April, 2013	1,42,473	74,633	2,17,106
As on 1 st April, 2014	1,52,476	77,203	2,29,679
As on 1 st April, 2015	1,60,708	79,266	2,39,974
As on 1 st April, 2016	1,71,327	82,010	2,53,337
As on 1 st April, 2017	1,81,585	88,722	2,70,307

STUDENTS REGISTERED*(From 31st March, 2010)*

During the year	Final	CPT	PCC	IPCC & IIPCC	ATC	Total
2009-10	24,172	1,67,073	1,860	80,745	3,376	2,77,226
2010-11	57,175	1,55,217	329	67,984	1,906	2,82,611
2011-12	47,515	1,61,712	-	85,053	2,099	2,96,379
2012-13	45,102	1,61,084	-	1,02,406	2,615	3,11,207
2013-14	39,348	1,54,742	-	96,285	3,209	2,93,584
2014-15	36,950	1,41,241	-	66,570	881	2,45,642
2015-16	31,669	1,25,140	-	77,962	1,249	2,36,020
2016-17	27,611	1,07,392	-	81,886	1,430	2,18,319

COMPOSITION OF THE COUNCIL**COUNCIL (2017-2018)**

Members of the Council (2017-18)		
President	Elected Members	
CA. Nilesh S. Vikamsey	CA. Agarwal Ranjeet Kumar	Kolkata
	CA. Agarwal Sanjay	New Delhi
	CA. Agarwal Shyam Lal	Jaipur
Vice-President	CA. Agrawal Manu	Kanpur
CA. Naveen N.D. Gupta	CA. Babu Abraham Kallivayalil	Kochi

Period 12 th February, 2017 onwards	CA. Bhandari Anil Satyanarayan	Mumbai
	CA. Chaudhary Sanjiv Kumar	New Delhi
Secretary to the Council Mr. V. Sagar	CA. Chhaira Jay	Surat
	CA. Chhajed Prafulla Premasukh	Mumbai
	CA. Devaraja Reddy M.	Hyderabad
	CA. Ghia Tarun Jamnadas	Mumbai
	CA. Goyal Sushil Kumar	Kolkata
	CA. Gupta Atul Kumar	Delhi
	CA. Gupta Naveen N.D.	New Delhi
	CA. Gupta Vijay Kumar	Faridabad
	CA. Hegde Nandkishore Chidamber	Mumbai
	CA. Jambusaria Nihar Niranjana	Mumbai
	CA. Khandelwal Dhiraj Kumar	Mumbai
	CA. Kinare Mangesh Pandurang	Thane
	CA. Kumar Sripriya	Chennai
	CA. Kushwah Mukesh Singh	Ghaziabad
	CA. Madhukar Narayan Hiregange	Bengaluru
	CA. (Dr.) Mitra Debashis	Guwahati
	CA. Sekar G.	Chennai
	CA. Shah Dhinal Ashvinbhai	Ahmedabad
	CA. Sharma Prakash	Jaipur
	CA. Sharma Rajesh	Delhi
	CA. Soni Kemisha	Indore
	CA. Vasudeva Sanjay	New Delhi
	CA. Vijay Kumar M.P.	Chennai
	CA. Vikamsey Nilesh Shivji	Mumbai
	CA. Zaware Shiwaji Bhikaji	Pune
Nominated Members		
	Mr. Manoj Kumar (till March, 2017)	New Delhi
	Mr. K.V.R. Murty (w.e.f. April, 2017)	New Delhi
	Mr. Vithayathil Kurian	New Delhi
	Dr. Guruprasad Mohapatra (till March, 2017)	New Delhi
	Dr. Sudhanshu Pandey (w.e.f. April, 2017)	New Delhi
	Mr. Chandra Wadhwa	New Delhi
	Dr. P.C. Jain	Delhi
	Mr. Sunil Kanoria	New Delhi
	Ms. Indu Malhotra (till March, 2017)	New Delhi
	Dr. Ravi Gupta (w.e.f. April, 2017)	New Delhi
	Mr. Vijay Kumar Jhalani	New Delhi

ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

Hingorani M. & Co.
Chartered Accountants

Khanna & Annadhanam
Chartered Accountants

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Council of the Institute of Chartered Accountants of India

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute"), which comprise the Balance Sheet as at March, 31, 2017, the Statement of Income and Expenditure and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (herein after referred to as "Financial Statements").

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Institute's Management is responsible for the preparation of these Financial Statements in accordance with The Chartered Accountants Act, 1949 that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Institute of Chartered Accountants of India in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This

responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Institute and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors' consider internal control relevant to the Institute's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Institute has in place an adequate internal control system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements for the year ended March 31, 2017 are prepared in all material respects in accordance with the Chartered Accountants Act, 1949, and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Institute as at March, 31, 2017, its surplus and its cashflow for the year ended on that date.

Other matter

We did not audit the financial statements of the Institute's Decentralised offices, Computer Centre, Students Associations, Regional Councils and their Branches (collectively known as Branches) whose financial statements reflect total assets of Rs.41,131 lakhs, total revenues of Rs.19,725 lakhs and net cash flows / (outflow) amounting to Rs.(136) lakhs are considered in the financial statements, have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management. Our opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Branches are based solely on the reports of the other auditors.

Report on Other Regulatory Requirements

Further, we report that:

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose our audit;
- b) In our opinion proper books of account as required by Chartered Accountant Act, 1949 have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the decentralised office, computer centre, students association, regional council and their branches.
- c) The Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

For Hingorani M. & Co.
Chartered Accountants
Firm Reg. No.006772N

For Khanna & Annadhanam
Chartered Accountants
Firm Reg. No.001297N

Sd/-

Sd/-

CA. Sanjay Kumar Narang

CA. B.J. Singh

Partner
Membership No.090943

Partner
Membership No.07884

Place: New Delhi.
Date: September, 14, 2017

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002 BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2017						
	Particulars			Note number	As at March 31,	
					2017	2016
					(₹ in Lakhs)	
I	SOURCES OF FUNDS					
	i	SURPLUS AND EARMARKED FUNDS				
		a.	Reserves and surplus	3	1,13,941	1,12,493
		b.	Earmarked funds	4	34,329	29,199
	ii.	NON - CURRENT LIABILITIES				
		a.	Other long-term liabilities	5	731	801
		b.	Long-term provisions	6	16,338	9,691
	iii.	CURRENT LIABILITIES				
		a.	Trade payables	7	3,191	3,971
		b.	Other current liabilities	8	19,345	18,787
		c.	Short-term provisions	6	937	328
	TOTAL				1,88,812	1,75,270
II	APPLICATION OF FUNDS					
	i.	NON - CURRENT ASSETS				
		a.	Fixed assets			
		i)	Tangible assets	9	51,615	51,939
		ii)	Intangible assets	10	19	23
		iii)	Capital work-in-progress	11	13,875	13,202
		b.	Non-current investments	12	24,631	-
		c.	Assets held for Earmarked and others	13	3,630	11,816
		d.	Long-term loans and advances	14	2,987	3,721
		e.	Other non-current assets	15	1,684	1,755
	ii.	CURRENT ASSETS				
		a.	Current investments	12	8,091	-
		b.	Assets held for Earmarked and others	13	70,388	80,636
		c.	Inventories	16	1,001	1,243
		d.	Cash and bank balances	17	5,035	5,085
		e.	Short-term loans and advances	14	2,252	3,970
		f.	Other current assets	15	3,604	1,880
	TOTAL				1,88,812	1,75,270

See accompanying notes 1 to 26 forming part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava	V. Sagar	CA. Naveen N. D. Gupta	CA. Nilesh Shivji Vikamsey
Joint Secretary	Secretary	Vice-President	President

In term of our Report attached

For Hingorani M. & Co.

Chartered Accountants

Firm registration number: 006772N

For Khanna & Annadhanam

Chartered Accountants

Firm registration number: 001297N

Sd/-
CA. Sanjay Kumar Narang
 Partner, Membership No. 090943
 New Delhi, September , 2017.

Sd/-
CA. B.J. Singh
 Partner, Membership No. 007884

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

	Particulars	Note number	For the year ended March 31,	
			2017	2016
			(₹ in Lakhs)	
I	INCOME			
	a) Fees	18	48,585	49,088
	b) Seminars		5,529	5,943
	c) Other income	19	10,989	11,393
	Total income		65,103	66,424
II	EXPENSES			
	a) Seminars and training programmes		6,108	6,745
	b) Employee benefit expense	20	17,190	13,569
	c) Printing and stationery		6,704	6,967
	d) Professional fees paid to examiners and consultants		6,812	8,171
	e) Depreciation and amortisation expense	9-10	2,334	2,463
	f) Other expenses	21	19,639	21,689
	Total expenses		58,787	59,604
II	Net surplus (I-II)		6,316	6,820
I				
IV	Appropriation to funds / reserves			
	a) Education Fund [See Note 2.6 (iii)]		3,158	3,410
	b) Employees Benevolent Fund [See Note 2.6 (iv)]		43	41
	c) Earmarked Fund (Net of expenses)		2,281	2,171
	d) General reserve		834	1,198
	TOTAL		6,316	6,820

See accompanying notes 1 to 26 forming part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/- CA. Sudeep Shrivastava Joint Secretary	Sd/- V. SagarCA. Secretary	Sd/- Naveen N. D. Gupta Vice-President	Sd/- CA. Nilesh Shivji Vikamsey President
--	---	---	--

In term of our Report attached

For Hingorani M. & Co.

Chartered Accountants

Firm registration number: 006772N

For Khanna & Annadhanam

Chartered Accountants

Firm registration number: 001297N

Sd/-

CA. Sanjay Kumar Narang

Partner, Membership No. 090943

New Delhi, September, 2017.

Sd/-

CA. B.J. Singh

Partner, Membership No. 007884

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

	Particulars	For the year ended March 31,	
		2017	2016
		(□ in Lakhs)	
I	Cash Flow from Operating Activities		
	Net surplus after prior period adjustments	6,316	7,155
	<u>Adjustments for:</u>		
	Depreciation and amortisation expense	2,334	2,463
	Provision no longer required written back	(114)	(172)
	Interest income	(7,686)	(7,734)
	Admission fees from members directly allocated to reserve	242	202
	Operating surplus before Working Capital changes	1,092	1,914
	Changes in working capital:		
	Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
	Inventories	242	457
	Long-term loans and advances	416	210
	Short-term loans and advances	1,718	(129)
	Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:		
	Other long-term liabilities	(70)	(160)
	Long-term provisions	6,647	4,333
	Trade payables	(666)	(1,682)
	Other current liabilities	634	612
	Short-term provisions	609	78
		10,622	5,633
	Income tax deducted at source (recoverable)	318	(207)
	Cash generated from operating activities (A)	10,940	5,426
II	Cash Flow from Investing Activities		
	Purchase of non-current investments	(24,631)	-
	Purchase of current investments	(8,091)	-
	Capital expenditure on fixed assets	(2,858)	(7,459)
	Proceeds from sale of fixed assets	103	94
	Decrease in earmarked and other funds	18,434	(6,058)
	Interest income received	6,033	7,180
	Cash (used in) investing activities (B)	(11,010)	(6,243)
III	Cash Flow from financing Activities		
	Donation received for buildings	18	1
	Contribution received	3	173
	Other fund received/(utilisation)	(1)	36
	Cash from financing activities (C)	20	210
	Net decrease in cash and cash equivalents (A+B+C)	(50)	(607)
	Cash and Cash Equivalents at beginning of the year	5,420	6,027
	Cash and Cash Equivalents at closing of the year	5,370	5,420

See accompanying notes 1 to 26 forming part of the financial statements

Notes:

- 1) Cash and Cash Equivalents represent cash on hand and balances with banks (Refer Note. 17).
- 2) Figures in brackets represent outflows.

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava	V. Sagar	CA. Naveen N. D. Gupta	CA. Nilesh Shivji Vikamsey
Joint Secretary	Secretary	Vice-President	President
In term of our Report attached			
For Hingorani M. & Co.		For Khanna & Annadhanam	
Chartered Accountants		Chartered Accountants	
Firm registration number: 006772N		Firm registration number: 001297N	
Sd/-		Sd/-	
CA. Sanjay Kumar Narang		CA. B.J. Singh	
Partner, Membership No. 090943		Partner, Membership No. 007884	
New Delhi, September , 2017.			

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

1. General Information

The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute or ICAI"), having its Head Office at New Delhi, was established on 1st July 1949 under an Act of Parliament viz The Chartered Accountants Act, 1949 for the purpose of regulating the profession of Chartered Accountants in India. In terms of the said Act, the Council of the Institute is entrusted with the task of managing the affairs of the institute. For the purpose, the Council has constituted 5 Regional Councils, one each at Mumbai, Kolkata, Kanpur, Chennai and New Delhi, 18 Regional Offices and Decentralised Offices, 163 branches and one overseas office.

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Basis of Accounting

The financial statements that comprise Balance Sheet, Income and Statement of Expenditure and Cash Flow Statement together with Notes, are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with applicable Accounting Standards issued by the Institute. The financial statements are prepared under the historical cost convention on going concern and on accrual basis unless other wise stated. The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year.

2.2 Use of Estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ due to these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known / materialise.

2.3 Inventories

Inventories comprises inventory of publications, study materials, stationery and other stores. Inventories are valued at the lower of cost calculated on first in first out ("FIFO") and the net realisable value after providing for obsolescence and other losses, where considered necessary.

Cost includes all charges in bringing the goods to the point of sale, including octroi and other levies, transit insurance and receiving charges.

2.4 Cash and cash equivalents (for purposes of Cash Flow Statement)

Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term balances (with an original maturity of three months or less from the date of acquisition), highly

liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

2.5 Cash Flow Statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby net surplus is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

2.6 Appropriation to Reserves and Allocation to Earmarked Funds

- i) Fee received from members for admission as fellow of the Institute is credited to Infrastructure Reserve Account.
- ii) Donations received for buildings and for research are credited directly to the respective reserve account.
- iii) 25% of the Distance Education Fee, not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education Fund.
- iv) 0.75% of Membership Fee (Annual and Certificate of Practice Fee) received during the year is transferred to the Employees' Benevolent Fund.
- v) From the earmarked funds the following transfers are made to Education Reserve Account:
 - a) From Accounting Research Building Fund 100% of cost of additions (net of deductions if any) to Building relating to Accounting Research Building.
 - b) From Education Fund 50% of cost of additions (net of deductions if any) to other Fixed Assets
- vi) Income from investments of Earmarked Funds is added to Earmarked Funds. The income is allocated based on opening balances of the respective Earmarked Funds on weighted average basis.

2.7 Depreciation and amortisation

Depreciable amount for assets is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its estimated residual value.

Depreciation on tangible fixed assets has been provided on the written down value method as per the useful life as approved by the Council of the Institute.

The useful life of the assets has been assessed as under based on technical advice, taking into account the nature of the asset, the estimated usage of the asset, the operating conditions of the asset, past history of replacement, anticipated technological changes, manufacturers warranties and maintenance support, etc. The amortisation rates used for the amortisation of fixed assets are as follows:

Class of Assets	Rate of Depreciation
i) Buildings	5%
ii) Lifts, electrical installations and fittings	10%
iii) Computers	60%
iv) Furniture and fixtures	10%
v) Air conditioners and office equipments	15%
vi) Vehicles	20%
vii) Library books	100%

Leasehold land is amortised over the duration of the lease.

Intangible assets are amortised over their estimated useful life on straight line method as follows:

Computers software - 3 years

The estimated useful life of the intangible assets and the amortisation period are reviewed at the end of each financial year and the amortisation period is revised to reflect the changed pattern, if any.

2.8 Revenue recognition

The Institute recognises revenue as follows:

- i) Distance education fee are recognised pro-rata over the duration of the respective courses.
- ii) Class room training fee comprises fee received for General Management and Communication Skills Programme ("GMCS"), Information Technology Training ("ITT") and Orientation Programme ("OP"), the income recognised when services are rendered and related costs are incurred.
- iii) Examination fee is recognised on the basis of conduct of the respective examinations.
- iv) Seminar fee is recognised on the basis of conduct of the respective activity.
- v) Membership fee comprising of Annual membership fee (including fee for certificate of practice and restoration fee) and entrance fee recognised as:
 - a) Annual membership fee (including fee for certificate of practice) is recognised as income when it becomes due for the year. Restoration fee income is recognised when it is received.
 - b) Entrance Fee:
 - One third of entrance fee collected at the time of admission of person as Associate Member is recognised as income in the year of admission and the balance is recognised in Infrastructure Reserve.
 - Entrance fee collected at the time of admission of person as Fellow Member is recognised in Infrastructure Reserve.
- vi) Students registration income are recognised pro-rata over the duration of the respective courses.
- vii) Student Association income are recognised when student admitted for the course.
- viii) Post qualification courses and certificate courses revenue are recognised in the period in which services are rendered.

2.9 Other income

- a) Income from sale of publication are recognised when the risk and rewards are transferred to the buyer which normally coincides with delivery of goods. Income includes consideration received or receivable, net of discounts and other sales related taxes (if any).
- b) Income from students news letter and journal subscription is recognised on pro-rata basis over the period of subscription.
- c) Income from campus interview and expert advisory fee are recognised when services are rendered and related costs are incurred.
- d) Interest income comprises interest received on deposit with banks in general and earmarked funds. Interest income is accounted on accrual basis.
- e) Interest income on loan to employees is accounted on accrual basis.

2.10 Fixed Assets**a) Tangible Assets**

Tangible assets are carried at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of fixed assets comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, any import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), any directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying fixed assets up to the date the asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on tangible assets after its purchase / completion is capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

b) Intangible Assets

Intangible assets are carried at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if any. The cost of intangible assets comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, any import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), any directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying fixed assets up to the date the asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on intangible assets after its purchase / completion is capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

c) Capital Work in Progress

Expenditure incurred on construction of assets which are not ready for their intended use are carried at cost less impairment (if any), under Capital Work-in-Progress. The cost includes the purchase cost including import duties and non-refundable taxes, any directly attributable costs .

2.11 Investment

- a) The ICAI is investing in Government of India securities, State Development Loans ("SDLs"), Fixed Deposits, PSU Bank Bonds and PSU Bonds.
- b) Fixed Deposits are valued at cost.
- c) Investments in Government securities and Bank Bonds are carried at acquisition cost. The premium paid at the time of purchase is amortized over the remaining period to maturity. A amortization of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".
- d) Accrued Interest paid at the time of purchase is set off against first receipt of interest.
- e) A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

2.12 Foreign Currency Transaction

Transactions in foreign currencies entered into by the Institute are accounted at the exchange rates prevailing on the date of the transaction or at rates that closely approximate the rate at the date of the transaction.

Foreign currency monetary items (other than derivative contracts) of the Institute, outstanding at the balance sheet date are restated at the year-end rates. Non-monetary items of the Institute are carried at historical cost.

Exchange differences arising on settlement / restatement of foreign currency monetary assets and liabilities of the Institute are recognised as income or expense in the Statement of Income and Expenditure.

2.13 Employee benefits

Employee benefits include provident fund, gratuity fund, compensated absences, long service awards, pension scheme and post-employment medical benefits.

i) Defined Contribution Plans

The Institute contribution to provident fund scheme as contributions to The Institute of Chartered Accountants of India Provident Fund Trust ('the Trust') are considered as defined contribution plans and are charged as an expense based on the amount of contribution required to be made and when services are rendered by the employees. The Trust is managed by the Governing body elected by The Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI').

ii) Defined Benefits Plans

For defined benefit plans in the form gratuity and post retirement pension, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognised in the Statement of Income and Expenditure in the period in which they occur. Past service cost is recognised immediately to the extent that the benefits are already vested and otherwise is amortised on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested. The retirement benefit obligation recognised in the Balance Sheet represents the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognised past service cost, as reduced by the fair value of scheme assets. Any asset resulting from this calculation is limited to past service cost, plus the present value of available refunds and reductions in future contributions to the schemes.

Gratuity liability is funded with Life Insurance Corporation of India. The present value of these defined benefit obligations are ascertained by an independent actuarial valuation as per the requirements of Accounting Standard (AS) - 15 Employee Benefits.

iii) Short term employee benefits

The undiscounted amount of short-term employee benefits (ie. salary, allowances, ex gratia etc) expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the year when the employees render the service. The short-term employee benefits are expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service.

The cost of short-term compensated absences is accounted as under :

- a) in case of accumulated compensated absences, when employees render the services that increase their entitlement of future compensated absences; and
- b) in case of non-accumulating compensated absences, when the absences occur.

iv) Long-term employee benefits

Compensated absences which are not expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service are recognised as a liability at the present value of the defined benefit obligation as at the balance sheet date less the fair value of the plan assets out of which the obligations are expected to be settled.

v) Other benefits

a) Pension scheme

The Institute offers its employees benefits in the form of pension. The present value of the obligation as at the balance sheet date is recognised based on the actuarial valuation from the actuary.

b) Post retirement medical scheme benefit to retired employees and spouse

The Institute offers its employees benefits in the form of medical scheme. The present value of the obligation as at the balance sheet date is recognised based on the actuarial valuation from the actuary.

2.14 Leases

Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the lessor are recognised as operating leases. Lease rentals under operating leases are recognised in the Statement of Income and Expenditure on a straight-line basis over the lease term.

2.15 Impairment of tangible and intangible assets

The carrying value of assets at each balance sheet date are reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor. When there is indication that an impairment loss recognised for an asset in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the statement of income and expenditure.

2.16 Taxes on income

The Institute has been granted exemption from Income Tax under section 10(23C) and Section 11 of the Income Tax Act, 1961.

2.17 Assets held for Earmarked and others

Earmarked fund and others in the form of deposits with banks maturing after a period of twelve months from the date of balance sheet are classified as non-current and others are classified as current. These are available for use freely at the discretion of the Council of the Institute except to the extent of total of the earmarked and employee benefit funds.

2.18 Provisions and Contingencies

A provision is recognised when the Institute has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

Contingent liability is a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute, or is a present obligation that arises from past event but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
NOTE # 3 RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Lakhs)

Particulars	General		Education		Infrastructure		Others*		Total	
	As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Balance at the beginning of the year	71,810	71,133	34,874	32,150	5,068	4,726	741	652	1,12,493	1,08,661
Add: Appropriation from Statement of Income and Expenditure	834	1,198	-	-	-	-	-	-	834	1,198
Transfer from / (to) General Reserve, Infrastructure Reserve and Other Reserve	-	(59)	-	-	-	20	-	39	-	-

Transfer from / (to) Earmarked Funds	(848)	(272)	980	2,724	(24)	(1)	247	(56)	355	2,395
Admission fees and allocated Entrance fees	-	-	-	-	242	202	-	-	242	202
Donation received for buildings	-	-	-	-	18	1	-	-	18	1
(Utilization)/Addition	-	(190)	-	-	-	120	(1)	106	(1)	36
Balance at the end of the year	71,796	71,810	35,854	34,874	5,304	5,068	987	741	113,941	112,493

* Others comprises Library Reserves, Class Room Training Reserves, Foreign Currency Translation Reserve (Dubai branch) etc.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
NOTE # 4 EARMARKED FUNDS

(₹ in Lakhs)

Particulars	Research Funds		Accounting Research Building Fund		Education Fund		Medals and Prizes Funds		Students Scholarship Funds		Employees Benevolent Fund		Other Funds		Total	
	As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Balance at the beginning of the year	2,094	1,920	727	667	21,107	18,726	222	184	120	112	572	487	4,357	3,703	29,199	25,799
Add: Opening balance of Earmarked Funds of Student Associations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Appropriation from Statement of Income and Expenditure	-	-	-	-	3,158	3,410	-	-	-	-	43	41	-	-	3,201	3,451
Transfer from / (to) Reserves and Surplus	-	-	-	-	(980)	(2,724)	-	-	-	-	-	-	625	329	(355)	(2,395)
Contribution received / Addition during the year	-	-	-	-	-	-	3	35	-	20	-	-	-	118	3	173
Interest income during the year appropriated through Income and Expenditure	188	174	66	60	1,919	1,695	16	17	11	10	52	44	92	259	2,344	2,259
Utilised during the year	-	-	-	-	-	-	(5)	(14)	(4)	(22)	(6)	-	(48)	(52)	(63)	(88)
Balance at the end of the year	2,282	2,094	793	727	25,204	21,107	236	222	127	120	661	572	5,026	4,357	34,329	29,199

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE # 5: OTHER LONG-TERM LIABILITIES						As at March 31,	
						2017	2016
						(₹ in Lakhs)	
a) Fees received in advance							
i) Education fees						723	793
ii) Journal subscription						8	8
Total						731	801

NOTE # 6: PROVISIONS				As at March 31,		As at March 31,	
				2017	2016	2017	2016
				(₹ in Lakhs)		(₹ in Lakhs)	
				Long-term	Long-term	Short-term	Short-term
Provisions for employee benefits :							
a) Post employment defined benefits							
i) Gratuity				-	-	186	66
ii) Pension				10,710	5,074	406	12
b) Provision for leave encashment				3,528	3,217	345	250
c) Other Provisions				2,100	1,400	-	-
Total				16,338	9,691	937	328

NOTE # 7: TRADE PAYABLES				As at March 31,	
				2017	2016
				(₹ in Lakhs)	
Trade payables				3,191	3,971
Total				3,191	3,971

NOTE # 8: OTHER CURRENT LIABILITIES					
a) Fees received in advance					
i) Examination fees				7,106	5,601
ii) Journal subscription				16	17
iii) Membership fees				1,886	1,575
iv) Education fees				7,327	8,267
v) Post qualification courses fees				110	67
vi) Certificate courses fees				40	73
vii) Seminar fees and other collections				929	789
Sub Total (A)				17,414	16,389
b) Other liabilities					
i) Creditors for purchase of fixed assets				4	80
ii) Employees recoveries and employer's contributions (Contributions to PF, ESIC, Professional tax etc.)				166	191
iii) Statutory dues (Withholding taxes)				258	328
iv) Security and earnest money deposit				787	612
v) Others				716	1,187
Sub Total (B)				1,931	2,398
Total (A+B)				19,345	18,787

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
NOTE # 9: TANGIBLE ASSETS

(₹ in Lakhs)

PARTICULAR	Freehold land		Leasehold land		Buildings		Lifts, electrical installations and fittings		Computers		Furniture and fixtures		Air conditioners and office equipments		Vehicles		Library books		Total	
	As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Cost at the beginning of the year	18,817	####	5,683	5,399	27,789	####	1,806	1,757	4,868	4,463	4,072	3,765	4,585	4,236	135	134	966	907	68,721	63,283
Additions	397	3,148	197	284	680	857	63	64	301	416	151	388	259	378	1	1	41	59	2,090	5,595
Deletions	-	(21)	-	-	(28)	-	(6)	(15)	(39)	(11)	(29)	(81)	(44)	(29)	(1)	-	-	-	(147)	(157)
Cost at the end of the year	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	135	135	###	966	###	###
Accumulated depreciation at the beginning of the year	-	-	583	499	5,492	4,325	973	873	4,384	3,958	1,758	1,535	2,534	2,219	92	82	966	907	16,782	12,179
Charge for the year	-	-	86	84	1,127	1,167	92	105	399	436	237	258	320	328	9	10	41	59	2,311	2,447
Deletions	-	-	-	-	(19)	-	(2)	(5)	(15)	(10)	(3)	(35)	(5)	(13)	-	-	-	-	(44)	(63)
Accumulated depreciation at the end of the year	-	-	669	583	###	###	###	973	###	###	###	###	###	###	101	92	###	966	###	###
Net book value at end of the year	###	###	###	###	###	###	800	833	362	484	###	###	###	###	34	43	-	-	###	###

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE # 10: INTANGIBLE ASSETS		As at March 31,	
Computer Software		2017	2016
		(₹ in Lakhs)	
Cost at the beginning of the year		646	637
Additions		19	9
Deletions		(2)	-
Cost at the end of the year		663	646
Amortisation at the beginning of the year		623	607
Charge for the year		23	16
Deletions		(2)	-
Amortisation at the end of the year		644	623
Net book value at the end of the year		19	23
Net book value at the beginning of the year		23	30

NOTE # 11: CAPITAL WORK IN PROGRESS		As at March 31,	
		2017	2016
		(₹ in Lakhs)	
Opening balance		13,202	11,387
Add: Addition during the year		673	1,815
Less: Amount capitalised/adjusted during the year		-	-
Closing balance		13,875	13,202

NOTE # 12: INVESTMENTS		As at March 31,		As at March 31,	
(at cost)		2017	2016	2017	2016
		(₹ in Lakhs)		(₹ in Lakhs)	
		Non-current	Non-current	Current	Current
a. Central Government Securities					
i. 8.27% Government of India 2020		2,628	-	-	-
ii. 7.46% Government of India 2017		-	-	1,651	-
iii. 7.49% Government of India 2017		-	-	861	-
iv. 7.80% Government of India 2021		-	-	-	-
		2,618	-		
Book Value		5,246	-	2,512	-
Market Value		5,214	-	2,514	-

b. State Government Securities				
i. 8.47% Tamil Nadu SDL 2017	-	-	3,042	-
ii. 8.21% Rajasthan UDAY SDL 2018	-	-	2,537	-
iii. 7.75% Rajasthan UDAY SDL 2018	-	-	-	-
	2,532			
Book Value	2,532	-	5,579	-
Market Value	2,527	-	5,574	-
c. Public Sector Subordinate of Perpetual Basel III Bonds				
i. 10.75% IDBI Bank Ltd.	3,018	-	-	-
ii. 10.95% Oriental Bank of Commerce	1,021	-	-	-
iii. 10.95% Oriental Bank of Commerce	1,532	-	-	-
iv. 9.00% State Bank of India	511	-	-	-
v. 9.00% State Bank of India	4,576	-	-	-
vi. 11.00% Bank of India	1,047	-	-	-
vii. 11.00% Bank of India	1,047	-	-	-
viii. 10.99% Andhra bank	3,101	-	-	-
Book Value	15,853	-	-	-
Market Value	15,878	-	-	-
d. Investment in equity instruments of subsidiary (fully paid up)				
- Institute of Insolvency Professionals of ICAI	1,000	-	-	-
10,00,000 Ordinary shares of Rs. 100 each				
Total	24,631	-	8,091	-

NOTE # 13: Assets held for Earmarked and others	Non-current	Non-current	Current	Current
Fixed deposits with banks (see note below)	3,630	11,816	70,388	80,636
Total	3,630	11,816	70,388	80,636
Note:				
Assets held comprise:				
-Earmarked funds (Note # 4)	3,630	11,816	30,699	17,551
-Employee benefits (Note # 6)	-	-	17,275	10,019

- Others	-	-	22,414	53,066
Total	3,630	11,816	70,388	80,636

NOTE # 14: LOANS AND ADVANCES (Unsecured, considered good)	As at March 31,		As at March 31,	
	2017	2016	2017	2016
	(₹ in Lakhs)		(₹ in Lakhs)	
	Non-current	Non-current	Current	Current
a) Security deposits		282	145	141
b) Tax deducted at source	254	2,172	-	-
c) Other loans and advances	1,854			
i) Loans and advances to employees		746	561	538
ii) Other receivables	634	521	1,878	3,291
Less: Provision for doubtful debts and advances	245	-	(332)	-
Total	2,987	3,721	2,252	3,970

NOTE # 15: OTHER ASSETS	Non-current	Non-current	Current	Current
a) Interest accrued				
i. on fixed deposits with banks		1,636	3,449	1,870
ii. on investments	452	-	123	-
iii. on loans to employees	1,111	119	32	10
Total	1,684	1,755	3,604	1,880

NOTE # 16: INVENTORIES (At lower of cost and net realisable value)			As at March 31,	
			2017	2016
			(₹ in Lakhs)	
a) Publication and study materials			949	1,112
b) Stationery and stores			52	131
Total	Total		1,001	1,243

NOTE # 17: CASH AND BANK BALANCES			
a) Cash on hand		36	58
b) Balances with banks		4,999	5,027
Total	Total	5,035	5,085

NOTE # 18: FEES		For the year ended March 31	
		2017	2016
		(₹in Lakhs)	
a) Distance education		18,971	19,570
b) Class room training income		7,609	8,414
c) Examination		13,099	12,680
d) Membership		5,869	5,636
e) Students' registration		515	459
f) Entrance		74	71
g) Students' association		386	344
h) Post qualification courses		797	560
i) Certificate courses		1,265	1,354
Total	Total	48,585	49,088

NOTE # 19: OTHER INCOME			
a) Interest income			
i. on bank deposit held in general funds		4,098	5,405
ii. from investments		1,172	-
iii. on bank deposit held for earmarked funds		2,344	2,259
iv. on loans to employees		72	70
b) Sale of publications		1,540	1,634
c) News letters		149	185
d) Journal subscription		52	70
e) Campus interview		759	567
f) Expert advisory fee		25	12
g) Provision no longer required written back		114	172
h) Miscellaneous income		664	1,019
Total	Total	10,989	11,393

NOTE # 20: EMPLOYEE BENEFIT EXPENSE		For the year ended March 31	
		2017	2016
		(₹ in Lakhs)	
a)	Salary, pension and other allowances	16,151	12,690
b)	Contribution to provident and other funds	847	707
c)	Staff welfare expenses	192	172
Total	Total	17,190	13,569

NOTE # 21: OTHER EXPENSES			
a)	Postage and telephone	2,639	2,861
b)	Rent, rates and taxes	3,868	4,026
c)	Travelling and conveyance - domestic	1,418	2,105
d)	Overseas related :		
i)	Overseas travelling	256	297
ii)	Membership fees for foreign professional bodies	342	326
iii)	Others	52	23
e)	Repairs and maintenance	1,775	1,895
f)	Publications	1,101	1,136
g)	Class room training expenses	4,833	4,685
h)	Advertisement and publicity	398	413
i)	Meeting expenses	595	564
j)	Merit scholarship	124	131
k)	Audit fees : Head office	11	11
	: Other offices	33	32
l)	Payments from earmarked funds	63	88
m)	Prior period adjustments (Net) (Note- 22)	227	5
n)	Provision for Doubtful Debts and Advances	332	-
o)	Miscellaneous expenses	1,572	2,756
Total	Total	19,639	21,354

NOTE # 22: PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS (NET)			
i)	Income		
		(173)	(70)
ii)	Expenses	400	410
Total	Total	227	340

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

23 Additional information to the Financial Statements

23.1	Contingent liabilities and commitments	2017	(₹ in Lakhs) 2016
a. Contingent liabilities			
i)	Claims against the Institute not acknowledged as debts	1,216	1,358
ii)	Income tax demand - Intimation u/s 143 (1) (Refer Note # 23.2)	4,142	4,142
Future cash flow in respect of the above matters are determined only on receipt of judgement / decision pending at various forums.			
b. Commitments			
i)	Capital commitments (net of advances)	4,252	4,744
23.2	For the assessment year 2014-15, an intimation has been received from the Income Tax Department raising a net demand of ₹ 4,142 Lakhs, wherein the statutory claims made by the Institute have not been allowed. An appeal against the same has been filed before the First Appellate Authority which is pending as on date. The Institute has been advised that it has a good case and the demand is likely to get deleted.		
23.3	Other Receivables in Note 11 # Long term loans and advances include ₹ 243.75 Lakh for stamp duty refund receivable on cancellation of principal and supplementary agreements of acquiring property at Nagpur which has been rejected by the Joint District Registrar (JDR), Nagpur. The Institute has filed two appeals before the Chief Controlling Revenue Authority, Pune under section 53 of Maharashtra Stamp Act challenging the orders passed by JDR, Nagpur which are still pending for final adjudication. The Institute has been advised that it has a good legal case to receive the refund of stamp duty.		
23.4	Directly attributable expenses on the seminar activity have been charged to seminar expenses and related indirect expenditure is charged to functional heads of expenditure.		
23.5	Out of the fee received from the students towards Students Association fee, a sum of ₹ 250 per student, in respect of students registered after 1st April, 2009, is remitted to Chartered Accountants Students Benevolent Fund.		
23.6	Leasehold land value includes ₹ 6.17 lakhs paid for the plot of land in Indraprastha Estate, New Delhi (adjacent to existing head office) allotted by Land and Development Authority, New Delhi for which execution of Memorandum of Agreement and Lease Deed is in progress.		

23 Additional information to the Financial Statements

23.7 The Institute had initiated a process for digitization of entire activities including members, students and other professional activities by undertaking a project referred as 'Project Parivartan'. For this purpose, Institute had appointed a global integrated service provider (vendor) supervised by a globally reputed project management consultant at a total cost of ₹ 3,981 lakhs. A sum of ₹ 867 lakhs was incurred up to March 31, 2015.

As the integrated service provider did not carry out the development as per the requirement even after extended periods, Institute raised a dispute and cancelled the contract. Pending final settlement, Institute invoked and encashed the bank guarantee of ₹295 lakhs in the month of June 2015 and the balance amount of ₹572 lakhs was provided for in the financials for the year ended March 31, 2015.

Last year, service provider has sent a notice demanding settlement of the balance dues against hardware supplied and refund of the bank guarantee amount encashed by the Institute. However Institute has taken a stand that in absence of the requisite software, the hardware supplied was of no utility hence balance payment cannot be considered. Further the bank guarantee was encashed to mitigate the losses incurred on account of the cancellation of contract. Institute is now in the process of filing a counter claim. During the year, a number of meetings were held with the officials of vendor at their instance for amicable settlement of the matter. Vide letter dated July 26, 2016, the vendor submitted a proposal requiring the Institute to pay ₹605 lakhs in addition to the amount of bank guarantees invoked by the Institute. The above offer has been rejected by the Institute as well as the Master Business Agreements with the service providers have been terminated by the Institute vide its letter dated February 08, 2017 and no further communication has been received from vendor in this regard.

23.8 A piece of land measuring 225 sq. mtrs area of ICAI Bhawan Faridabad, had been acquired by DMRC in January 2013 for which, Faridabad branch had requested for another piece of land, adjacent to the branch in compensation against the acquisition by DMRC. The matter is currently under consideration by HUDA (Haryana).

23.9 Certain instance of non-accounting of shortage of stock/receipts have been noticed in Chandigarh branch for which a provision as considered necessary by the management has been made at Head Office in this regard.

23 Additional information to the Financial Statements

23.10 Other expenditure includes ₹278 lakhs being the reimbursement of costs incurred by Quality Review Board Constituted under section 28-A of The Chartered Accountants Act, 1949. Other expenses also include contribution of ₹25 lakhs made to the Appellate Authority constituted under Section 22 of the Chartered Accountants Act, 1949 Expenses of the Quality Review Board and the Appellate Tribunal are to be borne by the Institute. Other expenses also includes grant of ₹70 lakhs made to ICAI Accounting Research Foundation (ICAI-ARF).

23.11 A detailed review of the various reserve funds and earmarked funds created in the earlier years and earmarked investments has been taken up to restructure these funds as per the present requirements and functioning of the Institute.

23.12 During the year pension liability of retirees has also been actuarially determined resulting in additional provision of ₹ 4,920 lakhs including ₹ 4,207 Lakhs upto March 31, 2016.

- 23.13** During the year The Institute has invested ₹15,500 Lakhs in Non Convertible Perpetual, Subordinated, Unsecured BASEL-III Compliant Additional Tier-I Bonds in the nature of Debentures issued by the public sector Banks and ₹15,869 Lakhs in Government securities. The Bonds are not redeemable but the issuer Bank has a call option which can be exercised subject to certain conditions. The premium paid amounting to ₹779 Lakhs is being amortised over the remaining period to maturity.
- 23.14** Certain investments exceed the limits approved by the Central Government under section 18(2) of the Chartered Accountants Act 1949. Steps are being taken to regularize this matter.
- 23.15** Although the income of the Institute is fully exempt under section 10(23-C)(IV) of the Income Tax Act, 1963, some of the entities have deducted tax at source on payment made to the Institute. The refund of tax deducted at source of ₹1,855 Lakhs including ₹ 452 Lakhs for the assessment year 2014-15 is likely to be received on final outcome of the appeal pending with Commissioner of Income Tax (Appeal).
- 23.16** During the year The Institute has subscribed 10,00,000 equity shares of ₹10 crore towards the share capital of its wholly owned subsidiary Indian Institute of Insolvency Professionals Ltd. ICAI a Company registered u/s 8 of the Companies Act, 2013. The investment has been classified as a long term investment and valued at cost.
- 23.17** During the year the Institute has migrated to Online Centralised Accounting Software and the reconciliation of transactions with branches and other offices has been mostly completed, the management is of the opinion that the impact of the pending reconciliations will not materially affect the Financial Statements.
- 23.18** After the close of the year, the fixed assets at most of Branches have been physically verified and the reports are being analyzed for appropriate adjustments, if any, on reconciliations of physical balances compared with the book balances. However management is of the opinion that the impact of the same will not materially effect the financial statements.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Disclosure under Accounting Standards

24 Employee Benefits

Defined Contribution Plans

The Institute has recognised an amount of ₹ **432.54 lakhs** for the year ended March 31, 2017 (Previous year ₹ 432.46 lakhs) towards contribution to Provident Fund.

Defined Benefit plans

The Institute has provided the following defined benefit plans to its employees

Gratuity :	Funded
Post retirement Pension :	Non-Funded
Compensated Absence:	Non-Funded

24.1 Details of the Gratuity Plan are as follows

Description					2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1.	Reconciliation of opening and closing balances of obligation							(₹ in Lakhs)
	a. Obligation as at beginning of the year				2,358	2,213	2,057	1,957
	b. Current service cost				202	184	167	147
	c. Interest cost				166	169	154	171
	d. Actuarial (gain)/loss				44	(53)	32	(63)
	e. Benefits paid				(260)	(155)	(197)	(155)
	f. Obligation as at end of the year				2,510	2,358	2,213	2,057
	Change in fair value of plan assets							
	a. Fair value of plan assets as at beginning of the year				2,292	2,232	2,103	1,950
	b. Expected return on plan assets				183	191	184	174
	c. Actuarial gain/(loss)				2	6	3	10
	d. Contributions made by the Institute				132	78	239	91
	e. Benefits paid				(285)	(215)	(297)	(122)
	f. Fair value of plan assets as at end of the year				2,324	2,292	2,232	2,103
3.	Reconciliation of fair value of plan assets and obligations							
	a. Present value of obligation				2,510	2,358	2,213	2,057
	b. Fair value of plan assets				2,324	2,292	2,232	2,103
	c. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability)				(186)	(66)	19	46
4.	Expenses recognised during the year							
	a. Current service cost				202	184	167	147
	b. Interest cost				166	169	154	171
	c. Expected return on plan assets				(183)	(191)	(184)	(174)
	d. Actuarial (gain)/loss				42	(59)	29	(73)
	e. Expenses recognised during the year				227	103	166	71
5.	Investment details				%	%	%	%
	a. Others - Funds with Life Insurance Corporation of India				invested	invested	invested	invested
					100	100	100	100

6. Assumptions					
a. Discount rate (per annum)	7.45%	7.92%	7.85%	9.00%	
b. Estimated rate of return on plan assets (per annum)	8.25%	8.85%	8.85%	9.00%	
c. Rate of escalation in salary	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%	
d. Attrition rate	5%	5.00%	5%	5%	
e. Mortality table	IAL 2006-08 Ultimate	IAL 2006-08 Ultimate	IAL 2006-08 Ultimate	IAL 2006-08 Ultimate	

24.2 Details of the Post Retirement Pension Plans

Description	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation				(□ in Lakhs)
a. Obligation as at beginning of the year	5,086	2,684	1,406	1,489
b. Interest cost	358	211	110	134
c. Actuarial (gain)/loss	6,063	2,210	1,169	(215)
d. Benefits paid	(391)	(19)	(1)	(2)
e. Obligation as at end of the year	11,116	5,086	2,684	1,406
2. Reconciliation of fair value of plan assets and obligations				
a. Present value of obligation	11,116	5,086	2,684	1,406
b. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)	(11,116)	(5,086)	(2,684)	(1,406)
3. Expenses recognised during the year				
a. Interest cost	358	211	110	134
b. Actuarial (gain)/loss	6,063	2,210	1,169	(215)
c. Expenses recognised during the year	6,421	2,421	1,279	(81)
4. Assumptions				
a. Discount rate (per annum)	7.30%	7.90%	7.90%	7.80%
c. Rate of escalation in salary	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%
d. Attrition rate	5%	5.00%	5%	5%
e. Mortality table	LIC 1996-98 Ultimate	LIC 1996-98 Ultimate	LIC 1996-98 Ultimate	LIC 1996-98 Ultimate

**24.3 Employee Benefits (Contd.)
Details of Leave Encashment**

(₹ in Lakhs)

Description	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation				
a. Obligation as at beginning of the year				

		3,217	2,857	2,359	2,239
	b. Current service cost				
		305	280	338	104
	c. Interest cost				
		227	216	175	199
	c. Actuarial (gain)/loss				
		127	115	259	(83)
	d. Benefits paid				
		(348)	(251)	(274)	(100)
	e. Obligation as at end of the year				
		3,528	3,217	2,857	2,359
2.	Reconciliation of fair value of plan assets and obligations				
	a. Present value of obligation				
		3,528	3,217	2,857	2,359
	c. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)				
		(3,528)	(3,217)	(2,857)	(2,359)
3.	Expenses recognised during the year				
	a. Current service cost				
		305	280	338	104
	b. Interest cost				
		227	216	175	199
	c. Actuarial (gain)/loss				
		127	115	259	(83)
	d. Expenses recognised during the year				
		659	611	772	220
4.	Assumptions				
	a. Discount rate (per annum)	7.45%	7.92%	7.85%	9.10%
	c. Rate of escalation in salary	Basic	Basic	Basic	Basic
		3% : DA	3% : DA	3% : DA	3% : DA
		6%	6%	6%	6%
	d. Attrition rate	5%	5.00%	5%	5%
	e. Mortality table	IAL	IAL	IAL	IAL
		2006-08	2006-08	2006-08	2006-08
		Ultimate	Ultimate	Ultimate	Ultimate

25. Segment Reporting

The Institute's operations are confined to "furtherance of the profession of Chartered Accountancy" and predominantly spread in India. Hence all its operations fall under single segment within the meaning of Accounting Standard (AS) - 17 Segment Reporting.

- 26.** Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava
Joint Secretary

Sd/-
V. Sagar
Secretary

Sd/-
CA. Naveen N. D. Gupta
Vice-President

Sd/-
CA. Nilesh Shivji Vikamsey
President

In term of our Report attached
For Hingorani M. & Co.
Chartered Accountants

Firm registration number: 006772N

Sd/-
CA. Sanjay Kumar Narang
Partner, Membership No.
090943
New Delhi, September , 2017.

For Khanna & Annadhanam
Chartered
Accountants
Firm registration number:
001297N

Sd/-
CA. B.J. Singh
Partner, Membership No.
007884

V. SAGAR, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./246/17]